(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 ] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 35वां दिवस [ संख्या 18



बृहस्पतिवार,

दिनांक 7 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

—

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न। श्री जनार्दनसिंह गहलोत

### जयपुर नगर के लिए विकास प्राधिकरण का गठन

385. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)** : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जयपुर नगर के लिए विकास प्राधिकरण के गठन का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसका क्या स्वरूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**नगर आयोजना मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)** : यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सदन में कई बार आ चुका है। यह जयपुर शहर के विकास से जुड़ा हुआ है। नगर विकास न्यास, नगर परिषद और टाउन प्लानिंग विभाग इन तीनों विभागों का कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जयपुर नगर के विकास की गति रुकी हुई है। माननीय मन्त्री महोदय, जयपुर के विकास की गति तेज करने के लिए क्या विकास प्राधिकरण का जल्दी गठन करने की कोई योजना रखते हैं या सरकार के विचाराधीन है?

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : सबसे पहले 14-2-76 को मन्त्रिमण्डल ने जयपुर में विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। उसके बाद अन्य ऐसे कई अवसरों पर भी इस प्रश्न पर विचार किया जाता रहा। अभी भी यह पत्रावली पुन: मेरे पास आई है। अब इसमें प्रश्न कई जुड़े हुए हैं। नगर विकास न्यास, म्युनिसिपैलिटी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी आदि कई विभाग ऐसे हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न यह है कि जो विकास प्राधिकरण बनाया जाये इसको क्या योजना बनाने तक सीमित रखा जाये या जो योजनाएं बनें उनका क्रियान्वयन भी अपनी एजेन्सी के ग्रू किया जाये। यदि वह बात की जाती है तो नगर

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

विकास न्यास, म्युनिसिपैलिटी और टाउन प्लानिंग के प्रश्न उससे लिंक्ड हैं। इस संबंध में अलग अलग राय प्राप्त हुई है। उनके ऊपर विचार करने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा। मैं माननीय सदस्य महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न वाकई जयपुर के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वह स्वयं अनुभव करेंगे कि देश में भी अलग अलग रूप इसके हैं। दिल्ली में अलग स्थिति है, बंगलौर में अलग स्थिति और बम्बई में अलग स्थिति है, कई जगह एजेन्सी योजनाएं बनाकर देती हैं और संबंधित विभाग उसको पूरा करते हैं। कई जगह सारे काम वह स्वयं भी करती हैं उसके बाद इसका रूप कैसा हो इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता होगी। तो जैसा मैंने कहा कि 1976 से यह प्रश्न चल रहा है। इसके बाद अभी 1979 में भी काफी विचार हुआ। उस समय इसका रूप भी कुछ प्रस्तावित किया गया था लेकिन केवल रूप प्रस्तावित करने से काम नहीं चलेगा। इसका कार्य क्षेत्र क्या हो और क्रियान्विति कैसे हो इस दृष्टि से इस पर महत्वपूर्ण विचार करना होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने मॉडल टाउन प्लानिंग एक्ट तैयार किया है उसका भी इस प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान करना होगा। मेरा निवेदन यह है कि जयपुर के विकास की दृष्टि से जितनी चिन्ता माननीय सदस्य महोदय को है उतनी ही चिन्ता राज्य सरकार को भी है। जयपुर देश का प्रमुख नगर पर्यटकों की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से और प्रान्त की राजधानी होने की दृष्टि से हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसके विकास के सम्बन्ध में जागरूक होकर विचार करना होगा। जैसा मैंने कहा कि कई प्रश्न जुड़े हुए हैं उन सब दृष्टि से विचार करने के बाद ही अन्तिम निर्णय करना होगा।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत**: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय स्वयं कह रहे हैं, 1976 के अन्दर इस सदन के अन्दर श्री श्रीरामजी और मैंने भी एक प्रश्न उठाया था। श्री भंवरलालजी, जो जनता पार्टी के विधायक थे, ने भी इस प्रश्न को उठाया था। उस समय राज्य सरकार ने इस योजना को अपने हाथ में लिया था। आगे 28 महीने जनता पार्टी की सरकार रही उस समय इसके लिए आवाज उठी थी। क्या 28 महीने में भी राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया? जिस प्रकार जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना हुआ है वह अब बचा ही नहीं सहकारी समितियों के माध्यम से, कच्ची बस्तियों के माध्यम से। बार बार सदन के सामने प्रश्न उठता है कि नाजायज अतिक्रमण हो रहे हैं आज भी शहर का प्लान बिगड़ रहा है उसको रोकने के लिए विकास प्राधिकरण तो लेट बनेगा लेकिन कोई एजेन्सी बनानी पड़ेगी। एक दूसरे से कोआर्डिनेट कैसे होगे मंत्री महोदय?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह जानना चाहता था कि 14-2-76 को इस प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन कर दिया उस समय प्रस्ताव के प्रारूप को मन्त्री मण्डल के सामने अवश्य रखा होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 14-2-76 को अनुमोदन करने के पश्चात अब इसमें

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

क्यों विलम्ब हो रहा है ? क्या कठिनाइयां हैं कि जिनकी वजह से अथॉरिटी नहीं बन पा रही है ?

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** अध्यक्ष, महोदय, 14-2-76 को मंत्रिमण्डल ने जो प्रस्ताव का अनुमोदन किया था उसको बिल के रूप में विधान सभा में भी प्रस्तुत करने का उसमें उल्लेख किया गया था, उसमें निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण है :

1. जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् नगर विकास न्यास जयपुर समाप्त किया जावे।

2. राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर का विंग अथॉरिटी की एक विंग के रूप में कार्य करेगा।

3. नये क्षेत्रों में नगरपालिका के कर्त्तव्य प्रस्तावित अथॉरिटी द्वारा सम्पादित किए जायेंगे लेकिन ये कर्त्तव्य नगरपालिका द्वारा भी किए जा सकेंगे यदि अथॉरिटी इसका पेमेन्ट करे।

4. राज्य सरकार द्वारा अपनी सम्पत्ति पर नगरपालिका का गृह कर दिया जावे।

5. विधि विभाग इस बात की जांच करे कि केन्द्रीय सरकार के भवनों पर क्या इसी प्रकार का गृह कर लगाया जा सकता है।

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग नगरपालिका सड़कों की सूची तैयार करें ताकि उनके द्वारा अलग अलग रख, रखाव किया जा सके।

7. अन्य नगरों में स्थापित विकास प्राधिकरण के बारे में अध्ययन किया जावे और जल बिजली आदि के बारे में देखा जावे कि प्रस्तावित विकास प्राधिकरण से इन संस्थाओं का क्या संबंध हो सकता है।

8. पुनर्वास विभाग के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं वे विकास प्राधिकरण को दिये जावें।

9. औद्योगिक विभाग द्वारा भी औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे का अनुमोदन विकास प्राधिकरण से कराया जावे।

10. इस बात पर भी निर्णय लिया जाना है कि मास्टर प्लान के अधीन क्षेत्रों की खेती की जमीन क्या विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी जावे।

यह दस बिन्दु थे जिनको देखते हुए उस पर निर्णय किया गया है। फिर जैसा मैंने कहा कि इसके बाद परिस्थितियां बदलती रहीं। परिस्थितियां बदलने के बाद में 1979 में इस प्रश्न पर चार बार विचार हुआ। विचार होकर इसके प्रारूप के संबंध में चर्चा हुई, लेकिन निश्चितरूप से कि इसको बनाया जाय या नहीं बनाया जाये, क्या आधार हो क्या कार्यक्रम हो, किस तरह से कार्पोरेशन हो, इन सारे प्रश्नों पर उसके बाद विचार नहीं हो सका।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** एक प्रश्न और है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अध्यक्ष महोदय, छोटी सी बात यह और पूछना चाहता हूं कि अब सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? दिल्ली की योजना आ गयी माडल टाउन के बारे में और यह भी आ गया। कई बार मंत्री महोदय जयपुर के बारे में एक मीटिंग बुलाकर निर्णय करने का सोच चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रारूप 1976 में पेश किया गया था उसका अनुमोदन मंत्री परिषद ने किया था उसको देखते हुए सरकार कब तक इस कार्यवाही को पूरा करने का संकल्प रखती है ?

**श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :** और भी तो शहर है राजस्थान में।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** मैं इस संबंध में व्यक्तिशः चर्चा कर चुका हूं कि जयपुर के विकास की दृष्टि से जितना जल्दी सम्भव हो सकेगा हम प्रयत्न करेंगे। अन्य जो भी सदस्य बन्धु हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल जयपुर शहर का प्रश्न है बल्कि और भी कई राजस्थान के महत्वपूर्ण नगर हैं। इन सब प्रश्नों पर बैठ कर चर्चा करनी होगी। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि एक बार मन्त्री मण्डल का निर्णय हो चुका है, तो कार्यान्वित करने की दृष्टि से हम जल्दी से जल्दी कदम उठा सकेंगे इसकी एक निश्चित अवधि बताने की स्थिति में नहीं हूं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** डेट तो बता सकते हैं ?

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** मैं निवेदन कर चुका हूं कि निश्चित अवधि बताना कठिन है।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाना**

386. **श्री दाऊदयाल जोशी (टोगोद):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट कारखाने में गत 6 माह में कुल कितना सीमेंट उत्पादित हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि यह उद्योग गत कई वर्षों से घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों के लाभ-हानि के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें

**उप मन्त्री उद्योग (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) :** (1) सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट कारखाने में गत 6 माह में कुल 11,73,355 टन सीमेंट उत्पादित हुआ।

(2) जी हां। यह उद्योग गत आठ वर्षों से घाटे में चल रहा है। गत 3 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(आंकड़ों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अध्यक्ष महोदय, इस घाटे के कारण क्या हैं, मंत्री महोदय जवाब देने की कृपा करें।

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, घाटे के मुख्य चार कारण हैं, जो मैं आपको बता देता हूं :

(1) भारत सरकार द्वारा सीमेंट भरने के लिए पुरानी बोरियों के प्रयोग की छूट दे रखी थी। वह मई, 79 में निरस्त कर दी गई। इसकी वजह से 69.75 लाख का घाटा हुआ।

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

(2) भारत सरकार ने कोयले की कीमत 17 जुलाई, 79 से बढ़ा दी थी परन्तु उसकी तुलना में सीमेंट की प्रोडक्शन प्राइस नहीं बढ़ी है इस कारण से 70.65 लाख का घाटा हुआ।

(3) मजदूरों के महंगाई भत्ता, वेतन में बढ़ोतरी के कारण 17.61 लाख का घाटा हुआ।

(4) सीमेंट का उत्पादन 1979-80 में काफी गिर गया। यह गिरावट इस फैक्ट्री में नहीं बल्कि देश की सभी फैक्ट्रियों में आई है। इसका मुख्य कारण कोयला व बिजली की कमी है। यदि कोयला और बिजली की कमी नहीं होती तो इस फैक्ट्री में उत्पादन लगभग 7 लाख 27 हजार टन होता जो कि क्षमता का 85 प्रतिशत है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या इस कारखाने में मैनेजमेंट की अव्यवस्था के कारण घाटा हुआ, यह महसूस नहीं करते ?

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी** : मैनेजमेंट की अव्यवस्था के कारण नहीं है। बिजली की कमी के कारण है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह कारखाना कब तक लाभ में चलता रहा और कब से नुकसान में गया ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : (किशनपोल, जयपुर) आपके आते ही नुकसान में आ गया।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

**श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : इस फैक्ट्री में 100 कर्मचारी बिना काम के फोकट की तनख्वाह लेते हैं ?

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी** : मैं आपको बता चुका हूं।

**श्री चुन्नीलाल** : जो आपके कांग्रेस से वास्ता रखते हैं।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : 28 महीने में जनता पार्टी ने काफी लोग पाले हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर प्रश्नकर्ता।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : इस कारखाने के घाटे की पूर्ति के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी** : मैंने आपको बताया कि इसमें घाटे के कारण हैं बिजली और कोयले की कमी। बाकी उसका जो एक्सपेंडीचर है वह काफी पहले कम कर दिया गया है। पिछले तीन साल के रिकार्ड को देखा जाय तो मालूम होगा कि जो घाटा चला आ रहा था वह काफी कम हुआ। पिछले साल ही ज्यादा घाटा हुआ जिसका कारण बता दिया गया है। बाकी कोशिश जारी है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : राजस्थान सरकार की इस कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता, माननीय सदस्य।

अन्य प्रश्न।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अध्यक्ष महोदय, इस कारखाने में सरकार की करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है। कारखाना डूबता जा रहा है ....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री अनंग कुमार

**श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन) :** अध्यक्ष महोदय, 8 साल से जो घाटा चला आ रहा है, इसके और कौन कौन से कारण थे? इसके समानान्तर दूसरे सीमेंट उद्योग चल रहे हैं वे बन्द नहीं हुए। जो कारण दिये गये हैं क्या इन्हीं के कारण से घाटा हुआ है या और भी कोई कारण थे? राजस्थान सरकार ने क्या प्रयत्न किये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ...

**एक माननीय सदस्य :** जवाब आने दीजिये

**श्री अध्यक्ष :** आपस में बात नहीं करें। स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय।

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी :** घाटे के कारणों की मैं आपको डिटेल दे चुका हूं किस कारण से घाटा हुआ। गवर्नमेंट ने रिलीफ टेक ओवर किया। बोर्ड आफ मैनेजमेंट और डाईरेक्टर जो है पहले के हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के तीन मेम्बर्स हैं। जैसा मैंने बताया, घाटे के कारणों को दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। जितना मैनेजमेंट अच्छा कर दिया है वह करेंगे। कारण पहले दे चुका हूं।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :** आपने यह बताया कि कोयले के भाव बढने के कारण घाटा हुआ। क्या यह बता सकते हैं कि कोयले के भाव बढ़े? हिन्दुस्तान में और कितने कारखाने हैं जो घाटे में चल रहे हैं? दूसरे बन्द नहीं हुए, यही बन्द क्यों हुआ? इसका मैनेजमेंट जब आपने हाथ लिया तो क्या योजना बनाई है?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा):** इसी से रेलेवेन्ट एक क्वेश्चन है चारों कण्डीशन्स जो बताई हैं उसके कारण बाकी जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनमें घाटा रहा है, उन फैक्ट्रियों में यही कारण प्रिवेल करते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन चार कारणों के अलावा भी कोई और कारण हैं?

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सवाई माधोपुर सीमेंट उद्योग के अन्दर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई थी। घाटे की वजह है, पिछले तीन साल में जब भयंकर घाटा था, उस सेठ का मैनेजमेंट लगाया गया था? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि अब तक जो भयंकर घाटा चल रहा है क्या सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि उस फैक्ट्री को राजस्थान सरकार सीधे नियन्त्रण में लेकर चलायेगी और उस घाटे को पूरा करने के प्रयत्न किये जायेंगे?

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी** : इसमें घाटा चल रहा था। रिलीफ टेक ओवर किया गया था। इसका मैनेजमेंट तो चल रहा है। तीन प्रतिनिधि हमारी स्टेट के थे, दो सैन्ट्रल के थे, एक एल. आई. सी. का, दो शेयर होल्डर के और दो स्टेट बैंक आफ इण्डिया के। इस मिल को इस तरह से चला रहे हैं। कम्पलीट टेक ओवर की जो बात है वह अभी नहीं हैं। विचार चल रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : गला प्रश्न।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : One relevant question, Sir. मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा जैसा उन्होंने कहा कि है कि पिछले तीन सालों में घाटा कम हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि जो पहले की स्थिति थी उन्हीं हाथों को सौंपने की प्रक्रिया तो प्रारम्भ नहीं होगी?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : (करोली) अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय इस मामले में स्पेसिफिक बतायेंगे कि भारत सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है या राजस्थान सरकार अपने नियन्त्रण में लेने को मन्शा रखती है?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग भी यही है कि इसको राज्य सरकार अपने हाथ में ले।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री जी।

**श्री अब्दुल रहमान चौधरी** : अध्यक्ष महोदय जहां तक सवाल इसको टेक ओवर करने का है यह मामला अभी विचाराधीन है। यह मामला केवल राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का ही नहीं है बल्कि इसमें और भी हैं। जहां तक सवाल घाटे की पूर्ति का है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले से इसमें अब घाटा कम हुआ है। या यों कह सकता हूं कि पहले से घाटे में कमी आई है। पिछली साल जरूर घाटा अधिक हुआ था। उसके कारण मैं आपको बता चुका हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सदन को गुमराह कर रही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करिये, सभी माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, इसको राज्य सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। इसमें राज्य सरकार का बहुत भारी षड्यन्त्र है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : आ।की सरकार के समय मोरारजी भाई की चिट्ठी लेकर आया था।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, यह अहम् प्रश्न है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है। क्या राज्य सरकार उन्हीं लोगों को वापस इस फैक्ट्री को दे देगी ? राज्य सरकार इसको अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

**श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)**: अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है यह लगातार सदन में शोर कर रहे हैं। आप इन्हें ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज।

**श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर। आर्डर अंकित नहीं हो आर्डर, आर्डर, आर्डर आर्डर। प्लीज।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। आर्डर आर्डर।

**श्री दाऊदयाल जोशी**: × × ×

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर आर्डर आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × ×

आर्डर प्लीज।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री सूरजपालसिंह**: अध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये। यह क्या कि एक नहीं दो, तीन, चार-चार सदस्य खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। आप इन्हें ताड़ना दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं प्रश्न काल का समय सीमित होता है। मैं समझता हूं कि जो भी प्रश्न यहां माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं वह सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रश्न पर मैंने पहले ही माननीय सदस्यों को 10-15 मिनट का समय दे दिया था। इसमें जितने भी माननीय सदस्यों को सम्बन्धित प्रश्न पूछने थे सभी ने पूछ लिये और मन्त्री महोदय को जानकारी देनी थी, मैं समझता हूं, पूरी जानकारी दे दी। इससे अधिक जानकारी, मैं समझता हूं, उनके पास नहीं है। अब आपने कहा कि कितना रुपया इसमें लगा है और अब कितना रुपया और लगेगा।

(व्यवधान)

**श्री सूरजपालसिंह** : आसन पैरों पर है अध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)** : आप 28 महीने तक क्या सो रहे थे ? आपको नींद आ रही थी क्या ? आपने क्यों नहीं किया ? आज आप बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

---

××× अध्यक्ष माननीय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री सूरजपालसिंह:** अध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

इस सदन की कार्यवाही में जो माननीय सदस्य बार-बार बाधा डाल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह सभी माननीय सदस्य आपस में सहयोग करें। सभा के जो नियम है काफी सख्त हैं। अंत में मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी ·····

(व्यवधान)

मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था का आदर करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री सूरजपाल सिंह :** यह प्रश्नकाल है, भाषण नहीं चल सकता है।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

**एक माननीय सदस्य :** यह पूंजीपतियों की सरकार है।

**श्री अध्यक्ष:** कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, मैं कोई प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्न संख्या 387।

**जयपुर नगर में सरकारी भूमि पर कच्ची बस्तियों का निरन्तर प्रसार।**

387. **श्री श्रीराम गोटेवाला :** किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1975 के बाद जयपुर शहर में कितनी कच्ची बस्तियां नई बसी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इन बस्तियों में सड़क, नल व बिजली की सुविधायें प्रदान कर दी हैं ? यदि हां, तो कृपया बताने का कष्ट करें कि प्रतिदिन बसती जा रही नई कच्ची बस्तियों का सरकार कब तक नियमितीकरण करती रहेगी ?

(3) सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति कब तक निर्धारित करेगी ?

**नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर) :** (1) ऐसा कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार ने नहीं करवाया है, जिससे कि यह ज्ञात हो कि 1975 के पश्चात कितनी कच्ची बस्तियां नई बसी हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** सुना नहीं दुबारा से पढ़ें।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया दुबारा उत्तर दीजिये।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** (1) ऐसा कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार ने नहीं करवाया है जिससे कि यह ज्ञात हो कि 1975 के पश्चात् कितनी कच्ची बस्तियां नई बसी हैं।

(10)



(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(2) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा कोई राशि नल, बिजली एवं सड़क की सुविधायें प्रदान करने के लिए ऐसी बस्तियों के लिए स्वीकृत एवं व्यय नहीं की है। अभी तक प्रभावशील आदेशों के अनुसार 21-8-71 तक के कब्जों को नियमित की जाने की नीति है।

(3) जयपुर शहर के विकास के विभिन्न पक्षों पर राज्य सरकार ने विचार प्रारम्भ कर दिया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था, जैसे मंत्री महोदय ने फर्माया पहले प्रश्न के उत्तर में कि 1975 के बाद जयपुर में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। 1971 के सर्वेक्षण के बाद 20 हजार नई झोंपड़ियां लग चुकी हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूं कि 1971 से पूर्व की कच्ची बस्तियों को नियमित कर दिया गया है या आज भी उसी प्रकार नियमित करवाने की कार्यवाही करवा रहे हैं?

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** अधिकृत रूप से तो जैसा मैंने कहा जयपुर शहर का 1971 के बाद सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। 1975 के बाद न्यास के अतिक्रमण निरोधक निरीक्षकों द्वारा जो सूचना प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर निम्न लिखित 13 कच्ची बस्तियां बसी प्रतीत होती हैं। (1) जे. पी. कालोनी, नाहरी का नाका (2) भट्टा कालोनी नाहरी का नाका (3) तेलियों की बस्ती बेरियों में नाहरी का नाका (4) शिवाजी कालोनी, नाहरी का नाका (5) जवाहर नगर के पीछे पहाड़ी के पास (6) मजदूर नगर, अजमेर रोड (7) हटवाड़ा खातीपुरा रोड (8) राय, कालोनी हसनपुरा के पास (9) टाटा नगर, आमानी शाह के नाले के पास (10) बस्ती सीता रामपुरा (11) सत्यसाई कॉलेज, आगरा रोड के पास (12) आमागढ़ के निकट लकड़ी पत्थर की योजना (13) नाहरी का नाका राय नगर के पास कच्ची बस्ती। ये 13 योजनाएं अधिकृत नहीं है हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है, 1971 के बाद ये बस्तियां एग्रीकल्चर लैंड पर न होकर जो सोसायटीज ने बनाई थी उनमें करीब 56 सोसायटीज हैं। उनको कहा गया था 27) रु० वर्ग गज डवलपमेंट कास्ट जमा कराकर रेगुलर करवा लें 9 ने तो करवा लिये हैं। जैसा मैंने निवेदन किया 1971 को एक आधार वर्ष दिया गया था तो उसका काफी लोगों को लाभ उठाना चाहिये था, लेकिन नहीं उठाया। अब 13 कच्ची बस्तियों की बात है– जयपुर शहर में हजारों मकान बन रहे हैं, जिनके लिये वार बार चर्चा होती है और शहर के विकास की दृष्टि से प्रश्न सामने खड़े होते हैं। मैं सदन को निवेदन कर सकता हूं जयपुर नगर के सारे प्रश्नों पर सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा निर्णय पर विकास प्राधिकरण विचार करेगा या नगर विकास न्यास करेगा अथवा म्युनिसिपल कौन्सिल जहां थी उनका भी प्रश्न इसमें है। जब तक यह रूप तय न हो जाय तब तक एक दायित्व का प्रश्न हमारे सामने रह जाता है। ऐसी कोई नीति

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

घोषित करने के या न करने के क्या परिणाम होंगे, क्या आर्थिक व्यवस्था होगी इन सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार उनका नियमन करना चाहती है, तो उसके आर्थिक आधार क्या होंगे ये सभी मसले उसमें होंगे यदि इन सब बातों के पहले निर्णय करने की घोषणा की जाय तो मैं समझता हूं जिस ऐजेन्सी को हम यह काम देना चाहते हैं उसके सामने भी ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे और ऐसी अवस्था में जांच करना मुश्किल होगा।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : मेरा निवेदन है जयपुर के विकास की दृष्टि से, कच्ची बस्तियों के समाधान की दृष्टि से राज्य सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी, इसमें शंका नहीं होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार के आवास मंत्री श्री प्रकाश चन्द जी सेठी ने भी कच्ची बस्तियों के समाधान के लिये कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : तो उसके भी हमें सारे आर्थिक पहलुओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं यह निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय ने जिन 13 कच्ची बस्तियों का जिक्र किया है। हमारी पार्टी की तरफ से राज्यपाल महोदय के समक्ष भी हमने विरोध किया था। मैं आज यह जानना चाहता हूं जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 250-250 रुपये लेकर भू-खण्डों पर झौंपड़े लगवा दिये थे उसके खिलाफ कई बार जांच की मांग की है। इस प्रकार सरकारी जमीन बेचे जाने के खिलाफ कब कार्यवाही होगी ?

(व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)**: हजारों रुपये लेकर जो थड़ियां लगवा दी, उनका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न कर्ता ने प्रश्न उठाया है कि जयपुर शहर में अगस्त, 1971 तक का सर्वे हो चुका है। प्रश्न यः नहीं है, प्रश्न तो यह कि रोज कच्ची बस्तियां बस रही हैं, हजारों मकान बन रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं, पूरक प्रश्न के रूप में ही पूछें।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : भाषण नहीं दे रहा हूं भाषण देना होगा तो मैं डिमान्ड पर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, रोज कच्ची बस्तियां बस रही हैं, इसके लिये सरकार की क्या क्या योजना है? अगर सर्वे नहीं होगा तो शहर का विकास रुक जायगा। यह बताने की कृपा करें कि कच्ची बस्तियों में बसाने की योजना को सरकार किस प्रकार लेगी, उनको रोकेगी अथवा क्या करेगी ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)**: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस तरह से माननीय सदस्यों ने और माननीय मंत्री महोदय ने बताया, काफी जटिल प्रश्न है! इसका समाधान कितना ही कर लें लेकिन

(12)



(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार की तरफ से सन्तोष नहीं हो सकता है। सरकार के सामने जब मैं मुख्य मंत्री था तब भी यह समस्या जबर्दस्त थी। जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया उनको रेगूलर किया जाय अथवा नहीं किया जाय। अगर किया जाय तो किस दिन के बाद रेगूलर किया जाय। हमने भी कई बार प्रयत्न किये कि कोई कच्ची बस्तियां न बसें उसके बाद भी एनक्रोचमेंट हुआ है। अब प्रश्न यह है कि 1971 के पहले वालों को रेगूलर किया जाता है तो उसके बाद जो नये आ गये हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का समाधान प्रश्नोत्तर से नहीं हो सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की एक समिति गठित कर दें। वह कमेटी इन सारी कच्ची बस्तियों का सर्वे करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी, फिर सरकार को जो कुछ एक्शन लेना हो, वह ले ले। आज यह समस्या केवल जयपुर शहर की ही नहीं है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा जैसे शहरों में भी बराबर बढ़ रही है। सभी बड़े बड़े शहरों के सामने यह समस्या है।

जिसकी मैंने पिछली बार जांच करवायी थी। इसी असेम्बली की एस्टीमेट कमेटी को यह काम दिया गया था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** श्री मथुरा दास जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे मुझे अफसोस है कि मथुरादास जी उस रिपोर्ट को समय पर नहीं दे सके। मैंने यह प्रश्न रेज किया था कि प्राइवेट कालोनीज को बनाने की स्वीकृति दे दी जाय। महाराष्ट्र को, गुजरात को इस प्रकार का अनुभव है, जो प्राइवेट कालोनीज को उचित मानते हैं। प्राइवेट कालोनीज को उन्होंने उचित माना है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करे और माननीय मन्त्री महोदय की यदि इच्छा हो तो, इस कमेटी का गठन कर दिया जाय, यदि ऐसा किया गया तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** आप लोग बोले जा रहे हैं जब कि प्रश्न तो मेरा है।

मैं कमेटी के बारे में मन्त्री महोदय से एक सवाल जानना चाहूंगा कि किसी काम को यदि टालना हो तो उसके समाधान के लिए आप कमेटी बना दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मन्त्री महोदय से मैंने एक पर्टीकूलर प्रश्न पूछा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, क्या सरकार ने उसकी जांच करवायी है? चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह हमारी पार्टी का हो या चाहे जनता पार्टी का हो। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि हमारी बार बार इस बात की मांग रही है कि आप उनके खिलाफ जांच को कार्यवाही क्यों नहीं करवाते? मैं सदन के अन्दर आश्वासन चाहता हूं कि उनके खिलाफ जांच की कार्यवाही करें और जो लोग अपराधी हैं, उन अपराधियों को दण्ड दें और आगे से कच्ची बस्तियों के विकास को रोकें। जितने लोग उन कच्ची बस्तियों में बैठे हैं उनको निय-

13



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मित करके जो हमारी घोषणा है, जो हमारे घोषणा पत्र में कहा है, सड़क, नल, बिजली और भवन बनाये जाने की व्यवस्था करें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अब तीन प्रश्न हैं। एक तो यह है कि इस समस्या का समाधान समिति के द्वारा करवाया जाय, सदन की समिति द्वारा। दूसरा यह कि सरकारी जमीन पर जो अधिकृत कब्जे है उनके सम्बन्ध में किया जाय। तीसरा यह है कि आज तक जो कच्ची बस्तियां बन गयी है उन सब को कुछ सुविधाएं दी जावें और उनको उन जमीनों पर नियमित किया जाय। ये तीन प्रश्न उठाये गये हैं।

पहले प्रश्न का जहां तक सवाल है, सरकारी जमीन पर जे. पी. कालोनी के सम्बन्ध में पहले प्रश्न आया था। मैंने उस समय भी निवेदन किया था, मेरी स्मृति शायद ठीक ही है, उसमें कुछ रेवेन्यू बोर्ड के ट्रिब्यूनल में कुछ केसेज चल रहे हैं, फिर भी हमने लोकल सेल्फ सेक्रेटरी को इस सारे प्रश्न की विस्तृत जांच करने की दृष्टि से आदेश उसी दिन दिये थे। मेरे खयाल से प्रश्न का, चूंकि कुछ भाग अदालत में विचाराधीन है, उसको छुआ नहीं जा सकता। बाकी जैसा कहा गया कि इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनायी जाय तो जहां तक समिति जयपुर के लिये बनाने की बात है तो यह तो हो नहीं सकता, सारे राजस्थान के प्रश्न पर समिति बने, वह समिति कैसे बने, क्या बने, यह मैं मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखूंगा, तभी इसका निर्णय हो सकेगा। तीसरे, आज तक जो कच्ची बस्तियां बन गयी हैं उनको नियमित करने की बात है इसके लिए हम जयपुर में प्राधिकरण बनाना चाहते हैं। जयपुर में विकास के लिए यदि नहीं बनाते तो उसका आधार विचार करने का दूसरा होगा, मुझे तब तक समय दीजिए और जैसे ही समय हो जायेगा मैं आपको सूचित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

## होम्योपैथिक दवाओं का पुनर्भरण

348. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को होम्योपैथिक दवाइयों का पुनर्भरण नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक इन दवाइयों का पुनर्भरण शुरू कर दिया जायेगा।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। इसके लिए नियमों में अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की मन्शा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने की है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अवश्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो कब तक इस पर फैसला किया जायगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एलोपैथी और आयुर्वेदिक पद्धति के पुनर्भरण तक की व्यवस्था है। यदि उनकी है तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

(श्रीमती उजला अरोड़ा) :

के जो बिल है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, उनके पुनर्भरण की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक रूल्स में इसका प्रावधान नहीं था। इसके लिए सरकार ने एक स्टेण्डिंग कमेटी बनायी है, उसकी रिकमण्डेशन्स 30 मार्च, को प्राप्त हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष है, मुझे जानकारी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमेटी की रिपोर्ट तो आ गयी है, सरकार के पास अभी 30 मार्च को आयी है, वह विचाराधीन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या उसकी मन्शा नहीं रखी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के विचाराधीन है, इसकी ओर मन्त्री परिषद का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सूरज पाल सिंह।

**किसानों को घटिया आयल देने वाले पैट्रोल पम्प डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही**

389. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पैट्रोल पम्प वाले किसानों को घटिया किस्म का आयल देते हैं ? यदि हां, तो चैकिंग की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विषयक सरकार के आपूर्ति मन्त्री को भीनमाल में काश्तकारों ने इस आशय का एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी यह शिकायत मिलने पर कि अमुक पैट्रोल पम्प वाला घटिया किस्म का आयल दे रहा है उस आयल का नमूना लेकर जांच हेतु भेजने के लिए सक्षम है। यदि नहीं, तो अन्य कौन अधिकारी सक्षम है ?

(4) क्या सरकार काश्तकारों को घटिया किस्म का आयल बेचने वाले डीलर्स के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आपूर्ति मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : राजस्थान में स्थित विभिन्न तेल कम्पनियां अपने अपने पैट्रोल पम्पों से समय समय पर तेल के नमूने लेकर रसायन शालाओं को जांच हेतु भेजती हैं।

(2) जी हां, कार्यवाही की जा रही है

(3) शिकायत मिलने पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों की सहायता से ऐसे नमूने लेकर जांच करवायी जाती है। रसद विभाग के अधिकारी इस हेतु सक्षम नहीं है।

(4) राज्य सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही वैधानिक रूप से करने के लिए सक्षम नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या एक में आपने यह बताया कि कम्पनियां उनके नमूने लेती हैं। मगर

(श्री सूरजपालसिंह)

कम्पनियों का माल तो बिकता ही नहीं है. वह नमूने क्या लेंगी ।पैट्रोल पम्प वाले वह माल बेचते है जो खराब होता। हमारी शिकायत उस माल के प्रति हैं जो खराब होता है। हमारी शिकायत उस माल के प्रति है जो हेल 30, 40 पैसे लीटर खरीदते हैं. उस जले हुए माल को खरीद कर उसको रिफाइन्ड करके डेढ़ और दो रुपये लीटर खराब तेल बेचते हैं। ग्राप कहते है कि भारत सरकार इसके लिए सक्षम है। किसानों का जो गला काट रहे हैं, उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं उसके प्रति ग्रापको ग्रधिकार नहीं है या है और अधिकार की बात आप करते हैं। हर प्रश्न का एक ही जवाब दिया जाता है कि राज्य सरकार इसको करने में सक्षम नहीं है। जहां औचित्य है, जहां अधिकारों की आवश्यकता है तो हम अपने अधिकारों के लिए भारत सरकार से लड़े। जो हमारे इन्सपेक्टर्स हैं, डी. एस. ग्रो. हैं उनको इस चीज का ग्रधिकार दिया जाय। किसान रोता रहे कि घटिया किस्म का तेल मिल रहा है। साथ में लाइन पिस्टन का खर्चा जो 800 रु. होता है तो उसे उठाये तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार किसानों का शोषण हो रहा है उसके बारे में कुछ करेगी ? अगर ग्रापका अधिकार नहीं है तो भारत सरकार से ग्राप अधिकार लीजिए और किसानों का जो शोषण हो रहा है किसानों को जो घटिया तेल बेचा जा रहा है, उस शोषण को मिटाइये। ग्रापने यह कहा कि वह नमूना लेते है, जैसे वर्मा सैल वाले हैं, वर्मा सैल का माल बेचते है तो वर्मा सैल का तो बस ढोल पड़ा रहता है।

**श्री रतना राम चौधरी (रानी वाड़ा) :** वह तो अध्यक्ष महोदय, बम्बई से डायरेक्ट मिलता है। घटिया तेल में डीजल और कैरोसिन मिलाकर घटिया किस्म का माल ये लोग बेचते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** किसी में यह होता है और सारे देश को इसकी सप्लाई होती है। इसके ऊपर कार्यवाही की जाय नहीं तो लोगों के एक एक लाख रुपये की मशीन खराब हो जायगी और लोगों का भट्टा बैठ जायेगा।

**श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क):** अध्यक्ष महोदय, तेल इस्तेमाल करने बाद जला हुआ होता है उसे दोबारा रिफाइन्ड करके लोगों ने बेचने का धन्धा बना रखा है। बाजारों के अन्दर और पैट्रोल पम्प के ऊपर, कारखाने बड़े बड़े जयपुर शहर में और बाहर लगे है, इसकी चैकिंग होनी चाहिये। कास्टिक सोडा और कई चीजें डालकर इस तेल को पीपों में बन्द करके खुले ग्राम बाजारों में बेचा जाता है। इसकी जांच करानी जानी चाहिये, तेल के नमूने लिये जाने चाहिए नहीं तो मशीनों का सत्यानाश हो जाता है और लाखों रुपये की मशीनों का नुकसान हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करा ली जाय।

**श्री रामधन ( लाडनूं ):** अध्यक्ष महोदय, यह जो तेल वाला मामला है, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। किसानों का इससे सम्बन्ध है। इस तेल में इतनी मिलावट होती है। एक तो तेल टाइम पर मिलता नहीं है और जो कुछ मिलता है वह भी मिलावटी मिलता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि

(श्री रामधन)

इसकी आप सारे मामले की जांच करायें भारत सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था करावें जिससे किसानों को जो दिक्कत हो रही है तेल के बिना खेती करने से रह जाते हैं...

**श्री अध्यक्ष**: भाषण नहीं माननीय सदस्य।

**श्री रामधन** : तेल में मिलावट नहीं हो, इसकी व्यवस्था करावें।

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं जिससे सारे सप्लीमेंट्रीज का जवाब एक सार आ जाय।

**श्री अध्यक्ष** : पूछिए।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़): क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1979 के अन्तर्गत पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक आर्डर निकाला गया था जिसके जरिये डीलर्स को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया गया था और यह पावर्स भारत सरकार ने लेली थी, उनसे कान्ट्रेट लेने की। क्या आप इस आर्डर के अन्तर्गत जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत जो असेंशियल कमोडिटीज को वायलेट करता है उस लाईसेंसी के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते ? मै समझता हूं कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : जहां तक मैंने आपसे कहा कि सरकार स्वयं इस प्रश्न पर काफी चिंतित है और इसीलिए अभी 15 जुलाई, 80 को ही एक मीटिंग यहां पर फूड सैक्रेटरी के चैम्बर में हुई थी, सारे प्रश्नों के साथ आयल का एक प्रश्न भी उठाया गया था। भारत सरकार के प्रतिनिधि भी थे। उसमें यह लिखा हुआ है: –

Without proper Legal cover, nothing substantial can be done. Prosecution of such anti-social elements can not be made under essential commodities Act, 1955 and prevention of Food Adulteration Act 1954. This is a subject which is within the purview of the Government of India."

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह नहीं है, मन्त्री महोदय। यदि चांदी के नाम पर कोई गिलट बेचे तो आप क्या करेगें ? ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

(व्यवधान)

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : इस सम्बन्ध में राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्ट, 1979 है, इसके अलावा मूल्यांकन स्टाक प्रदर्शन एक्ट, 1977 है। ये दो कानून हमारे पास में है।

**श्री अध्यक्ष**: जो कानून है आई. पी. सी. का उसके अन्दर सीधे सीधे चालान किया जा सकता है।

(व्यवधान)

**श्री सूरजपालसिंह** : तेल के नाम पर जो मिलावट करते हैं –

**श्री अध्यक्ष :** श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री माणकमल मेहता** (पाली): यह तो सरासर चीटिंग है और चीटिंग करने वाले को आप कैसे पकड़ेंगे, यह तो साफ है।

**श्री सुरजपालसिंह** : अगर समझते हैं कि चालान करने का अधिकार आपको नहीं है तो फिर इतने इंस्पेक्टर क्यों रख रखे हैं? इस सप्लाई डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। इस तरह से भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और आपने उनको पूरी छूट दे रखी है। कालाबाजारी करने वाले, मिलावट करने वालों को बचाना ही है तो फिर इतने इंस्पेक्टर क्यों रख रखे हैं आपने?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): माननीय मन्त्री महोदय, लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? यह जो एसेंशियल कमोडिटीज् एक्ट है, उसके अन्तर्गत आप कार्यवाही कर सकते हैं और इस प्रकार से केस चालान हो सकते हैं, तो फिर आप कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि जब आपको यह संदेह होता है कि पैट्रोल में, डीजल में और मिट्टी के तेल में मिलावट हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या राज्य सरकार उस पर छापा नहीं मार सकती है? पहले भी कई बार इस तरह के छापे मारे गये हैं और छापे मार कर कई डिपोज के लाइसेंस कैंसिल किये हैं। क्या आप उन मिलावट करने वाले कारखानेदारों के खिलाफ राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते हैं?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामसिंह विश्नोई।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले पांच सालों के अन्दर मिलावट करने वाले पम्प डिपोज के खिलाफ क्या कार्यवाही की, कितने डिपोज के चालान किए? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सेम्पल लिए जाते हैं और सेम्पल लेने के बाद टेस्टिंग के लिए सामान यहां लाया जाता है, सेम्पल भरने के बाद भी रात रात में बदल दिए जाते हैं। तो आप यह बताये कि पिछले पांच सालों में कितने पेट्रोल पम्पों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितने चालान किए गए, कितने सेम्पल लिए गए और उनके आधार पर क्या कानूनी कार्यवाही हुई? उसके आधार पर आपको मालूम हो जायगा कि आप व्यापारियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

**श्री माणकमल मेहता :** जब अडल्ट्रेशन होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हम क्यों सक्षम नहीं हैं?

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर) : एक प्रश्न मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(18)



श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया कि यदि हम विचलित नहीं होते तो जैसा मैंने अभी कहा कि 15 जुलाई, 80 को ही इस सारे प्रश्न पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठकर बातचीत की। हम भी जानते हैं कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ काफी मिलावट होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज 420 में किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, यह लीगल आस्पेक्ट है। अगर चांदी की जगह गिल्ट बेचता है तो उसके खिलाफ 420 का केस हो सकता है या नहीं, उसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह किसानों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।...कृपया बैठ जावें। आप आसन के साथ सहयोग करें। बिलकुल हरएक प्रश्न के साथ ऐसा हो......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री हरीसिंह (महुआ): जहां तक मिलावट का प्रश्न है इसमें रिश्वत ली जाती हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री सूरजपालसिंह : किसानों का शोषण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। इससे ज्यादा अवसर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री माणकलाल मेहता : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। कोई प्रश्न स्थगित नहीं हुआ।

(व्यवधान)

सचिवालय की व्यवस्था के विरुद्ध माननीय सदस्य को कहना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया मर्यादाओं का ध्यान रखें। आप जिम्मेदार सदस्य हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। लाटरी से निकाले जाते हैं। कौनसा प्रश्न पहले आयेगा, कौनसा बाद में आयेगा। आपको शंका हो तो आप स्वयं जाकर उपस्थित हो सकते हैं।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया विराजमान रहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक एक करके बोलें।

**श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने कई बार माननीय सदस्य का नाम पुकारा था, यदि आपने नाम पुकारा था, तो उत्तर आना चाहिये था।

**श्री अध्यक्ष** : समय समाप्त हो गया है।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : स्थगित कर दें।

**श्री रामकुमार बैरवा** : तीन चार प्रश्न ही रोज होते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है। आपको बोलने का अवसर दे देंगे। लेकिन बात सुन लीजिये।

मैं बराबर निवेदन करता रहा हूं, समय का अभाव रहता है। एक घण्टे का समय है, काफी बड़ी संख्या में प्रश्न यहां पर होते हैं। थोड़े समय के अन्दर यदि पूरी सूचना प्राप्त करलें तो ज्यादा प्रश्न हो सकते है। लेकिन आप जानते हैं कि एक प्रश्न पर इतना विवाद खड़ा हो जाता है कि अगले प्रश्न तक हम नहीं पहुंचते हैं। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों को प्रश्न के विषय में जानकारी है, वे ही पूरक प्रश्न पूछें, अन्यथा प्रश्नकर्ता को इस प्रश्न में स्वयं जानकारी लेने दें।

दूसरे प्रश्नों के माध्यम से आप सीमित जानकारी ले सकते हैं। आप यहीं हल निकालना चाहें कि गवर्नमेंट इसी वक्त तत्काल कोई निर्णय दे उस विषय के बारे में तो यह सम्भव नहीं है। इसलिए जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, उनको इसकी सीमा समझनी चाहिये। प्रश्न की सीमा, प्रश्न की ही सीमा है और महत्वपूर्ण विषय अन्य किसी तरीके से उठायें तो उस पर विस्तार से चर्चा हो जायगी।

मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अफसोस है कि बहुत कम प्रश्नों का उत्तर दिला सके। बगैर माननीय सदस्यों के सहयोग के आसन के लिये कठिन है कि और प्रश्नों के उत्तर आ सकें।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

### अतारांकित प्रश्नोत्तर

### जैसलमेर शहर के पानी के निकासी की योजना

345. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जैसलमेर शहर के पानी के बहाव से होने वाली हानि के बचाव हेतु अण्डरग्राउण्ड निकासी के लिए कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

जी नहीं!

### ग्राम पंचायत सुल्यास के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

346. **श्री रामकंवार बैरवा (फागी)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सुल्यास पंचायत वांतारामगढ़ के सरपंच की शिकायत मंत्री जी के पास भूतपूर्व विधायक श्री मदन सिंह ने की थी? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(20)



उत्तर

जी नहीं। जिलाधीश, सीकर की एक रिपोर्ट दिनांक 19–3–81 को प्राप्त हुई। उसमें श्री मोहन दास सरपंच, ग्राम पंचायत सुल्वास के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में ग्रामीणों की शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त होने पर इसकी जांच जिलाधीश सीकर ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा कराई गई। सरपंच के विरुद्ध अनियमिततायें व पद का दुरुपयोग करने का आरोप हैं। जिलाधीश ने सरपच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने को प्रस्तावित किया है। जांच रिपोर्ट के साथ जांच की मूल पत्रावली एव आरोप–पत्र नहीं होने से जिलाधीश को लिखा गया है। आरोप-पत्र एवं जांच पत्रावली प्राप्त होने पर सरपंच के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

**ईसाई समाज के राज्य में चल रहे स्कूल व कालेज**

347. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ईसाइयों के कितने स्कूल व कालेज हैं व उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

(2) क्या उन स्कूल्स में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है? क्या उन स्कूल्स में राष्ट्र भाषा हिन्दी पढ़ाई जाती है ?

उत्तर

(1) राज्य में केवल एक सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर तथा लगभग 29 सहायता प्राप्त विद्यालय ईसाइयों के है। इनमें क्रमश: 415 एव 9100 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

(2) इन संस्थाओं में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने की कोई शिकायत विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कालेजेज में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी पढ़ाई जाती है। जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान में बोर्ड से मान्यता प्राप्त है उनमें हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य रूप से होता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार हिन्दी अनिवार्य विषय है।

**जिला चित्तौड़गढ़ के स्कूल में खोले जाने वाले वैकल्पिक विषय**

348. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

वर्ष 1980–81 में चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी प्राथमिक शालाएँ, उच्च प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएँ तथा नये वैकल्पिक विषय खोलने का प्रावधान है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

स्थान विशेष की आवश्यकता, जनसंख्या, भवन की व्यवस्था, अन्य स्कूलों की दूरी, भौगोलिक स्थिति एवम उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य में विद्यालय एवं विषय खोले जाने का प्रस्ताव है ।

**निम्बाहेड़ा क्षेत्र में क्रमोन्नत किये जाने वाले स्कूल**

349. **श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1980-81 में निर्धारित आधार पर निम्बाहेड़ा क्षेत्र में कितने नये विद्यालय इस सत्र में खोले या क्रमोन्नत किये जा रहे हैं ?

**उत्तर**

जी हां। इस वर्ष 600 प्राथमिक, 200 उच्च प्राथमिक एवं 200 माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। उच्च माध्यमिक एवं कालेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार स्थान विशेष की आवश्यकता, जनसंख्या, भोगोलिक स्थिति, भवन व्यवस्था एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए नये विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

अन्य स्थानों के साथ साथ निम्बाहेड़ा के बारे में भी उक्त आधार पर विचार किया जावेगा।

**प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग का आगार कार्यालय खोलना**

350 **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से मन्दसौर, प्रतापगढ़ से रतलाम प्रतापगढ़ से धरियावद, प्रतापगढ़ से बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ एवं चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा वाया धरियावद बान्सी मंगलवाड़ मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हैं ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या प्रतापगढ़ में राज्य पथ परिवहन निगम का आधार कार्यालय खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसके खुलने की संभावना है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से धरियावाद, प्रतापगढ़ से बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ एवं चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है प्रतापगढ़ से मन्दसौर तथा प्रतापगढ़ से रतलाम अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं। राजस्थान की सीमा तक इन मार्गों की योजना भी राज्य सरकार के विचाराधीन है इन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता होने पर ही वाहन संचालन सम्भव होगा।

(2) जी नहीं।

**पंचायत समिति मूंडवा (नागौर) में चल रहे स्कूल**

351. **श्री महाराम चौधरी (नागौर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर में कुल कितने प्राथमिक, मिडिल, सैकण्डरी व हाई स्कूल हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(22)



(श्री महाराम चौधरी)

(2) इन स्कूल्स में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों व अध्यापकों का अनुपात पिछले वर्षों में क्या रहा है ?

उत्तर

(1) मूंडवा पंचायत समिति में 75 प्राथमिक, 17 उच्च प्राथमिक, तीन माध्यमिक एवं 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय है।

(2) इन स्कूल्स में पिछले दो वर्षों का छात्र अध्यापक अनुपात निम्न प्रकार रहा है :—

| | |
|---|---|
| वर्ष 1978-79 | 1:38 |
| वर्ष 1979-80 | 1:34 |

## केशोरायपाटन क्षेत्र की स्वीकृत सड़कें

352. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केशोरायपाटन, कापरेन, लबान उप खण्डों में कितनी सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है तथा उपखण्डों द्वारा कितनी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

केशोरायपाटन, कापरेन एवं लबान क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत हैं:—

1—कालाजी का चराना गांव तक सड़क निर्माण।

2—लिंक रोड अरनेहा

इस क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें प्रस्तावित हैं :—

1—पापरी से बढ़ासेरा

2—कापरेन से रोटेड़ा

## राजगढ़ से जामडोली सड़क का निर्माण कार्य

353. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ से जामडोली वाया पुराना राजगढ़ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को जामडोली से बांदीकुई वाया डेरा तक बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

राजगढ़ से जामडोली वाया पुराना राजगढ़ सड़क की कुल लम्बाई 12 कि.मी. है जिसमें से शुरु के 10 कि.मी. ग्राम भूलेरी तक (स्वीकृत कार्य) मार्च तक पूर्ण हो जायगा।

(2) जी नहीं।

ग्राम गोनेर (सांगानेर) में नालियों का निर्माण

354. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांगानेर पंचायत समिति के ग्राम गोनेर में नाली निर्माण योजना का कार्य कब स्वीकृत हुआ ? उक्त कार्य हेतु टेण्डर कब आमंत्रित किये गए थे तथा यह कार्य किस ठेकेदार को किस तिथि व किन शर्तों के साथ अवार्ड किया गया ?

(2) वर्तमान में इस कार्य की क्या प्रगति है ? टेण्डर की शर्तों के अनुसार यह कब तक पूर्ण हो जाना चाहिये था ?

उत्तर

(1) नाली निर्माण योजना के नाम से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। तथापि "स्ट्रेन्थनिंग आफ गोनेर रोड" के नाम से एक कार्य 5-00 लाख रु. की लागत का 15-12-78 को स्वीकृत हुआ था। सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य भी इसी काम में सम्मिलित किया गया था। इन कार्य के टेण्डर 6-12-78 को आमंत्रित किये गये थे। यह कार्य श्री अजयकुमार गोयल, ठेकेदार को दिनांक 6-3-79 को आवंटित किया गया था। उक्त कार्य को 12 माह में पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी।

(2) वर्तमान में नाली का कार्य लगभग 550 मीटर लम्बाई में से लगभग 400 मीटर लम्बाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। टेण्डर की शर्त के अनुसार यह कार्य 6-3-80 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था।

चित्तौड़ तालाब (पाली) के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता

355. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जनवरी, 77 के बाद पाली जिले के चितौड़ तालाब के निर्माण कार्य का ठेका किसे दिया गया तथा किन शर्तों के अधीन कार्य कराया गया ? कितनी राशि का भुगतान निर्माण कार्य के सन्दर्भ में किया गया ? क्या ठेका व निर्माण कार्य में कोई अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जनवरी 1977 के बाद पाली जिले के चिताड़ तालाब का निर्माण नहीं किया गया व उसके स्थान पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य चिताड़ एनीकट का निर्माण कार्य का ठेका श्री जोगाराम ठेकेदार भूठा को अधिशासी अभियन्ता जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के पत्र संख्या 14568 दिनांक 23-1-77 के द्वारा रुपये 5001.66 का आवंटित की गई। जिन पर उन्हें 2483/-का भुगतान किया गया व ठेका निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

बनास नदी क्षेत्र में भू-आवंटन संबंधी नियम

356 श्री महावीर प्रसाद (टोंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बनास नदी क्षेत्र में भूमि आवंटन किये जाने के नियम तथा दूसरी किस्म की जमीन के आवंटन नियम क्या एक से हैं ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? इन नियमों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

(24)



उत्तर

(1) नदी पेटा भूमि के आवंटन तथा दूसरी किस्म की जमीनों के आवंटन के नियम अलग अलग है। नदी पेटा में भूमि आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तल भूमियों का कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत किया जाता है एवं दूसरी किस्म की सिवाय चक जमीनों का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत किया जाता है।

(2) नदी पेटे की भूमि को अस्थाई तौर पर आवंटित किया जाता है जब कि अन्य किस्म की जमीन को स्थाई रूप से आवंटित किया जाता है।

उपरोक्त दोनों नियमों का प्रकाशन राजपत्र में क्रमशः राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 14-12-1961 व राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) (1) दिनांक 21-7-70 को हो चुका है।

## चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्व अभियान में आवंटित भूमि

357. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनता शासन के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में चलाये गये राजस्व अभियान के अन्तर्गत कितने भूमिहीनों, श्रमिकों एवं अन्त्योदयी को भू-आवंटन किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी है उनको अभी तक मौका कब्जा नहीं दिया गया है ?

(1) जनता शासन के दौरान चित्तौड़ में चलाये गये राजस्व अभियानों के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों एवं अन्त्योदयी परिवार को निम्न प्रकार भूमि आवंटन की गई:—

भूमिहीन श्रमिक

| संख्या | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| 4099 | 9150 |

अन्त्योदयी परिवार

| संख्या | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| 2332 | 8217 |

(2) जिन लोगों को भूमि आवंटन की गई उनमें से 250 व्यक्तियों को कब्जा देना शेष है। उपरोक्त में से 49 व्यक्तियों को प्रतापगढ़ सब डिवीजन में कब्जा देना शेष है, एवं बेगूं सब डिवीजन में 201 व्यक्तियों ने भूमि नापसन्द होने से कब्जा लेने से इन्कार किया है। प्रतापगढ़ सब डिवीजन में आवंटीगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जो मजदूरी की तलाश में अपने गांव को छोड़ कर आस पास के इलाकों में मजदूरी करने चले जाते हैं जिन्हें तलाश किये जाकर शीघ्र ही कब्जा दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

## जिला टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतकरण

358. श्री महावीर प्रसाद (टोंक): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले के किन किन ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री महावीरप्रसाद)

(2) जिन जिन गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है क्या उन सभी गावों का विद्युतीकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो किस कारण से किन किन गांवों में कार्य पूरा नहीं हुआ और अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा?

उत्तर

(1) माह जून, 1980 तक टोंक जिले के 113 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। योजना माह फरवरी, 1980 में स्वीकृत की गई है जिसका कार्य काल पांच वर्ष का है। योजना के प्रथम वर्ष में प्रस्तावित 28 ग्रामों का विद्युतीकरण इस वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मण्डल के सामान्य कार्यक्रम में स्वीकृत एक ग्राम का विद्युतीकरण भी इसी वर्ष में प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

## जिला पाली में भू-आवंटन संबंधी विचाराधीन मामले

359. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला पाली में तहसीलवार कितने कितने मामले भू-आवंटन नियम 14 (4) के तहत जिलाधीश के पास कब से विचाराधीन है? उनमें से एक साल में पुराने मामलों में अब तक फैसला न करने का क्या कारण है? अब कब तक उन पर निर्णय ले लिया जायगा?

उत्तर

(1) पाली जिले में सात तहसीलें हैं उनमें विचाराधीन भू-आवंटन नियम 14 (4) के तहत मामलों की संख्या आगे दर्शाई गयी है:-

| नाम तहसील | वर्षवार विचाराधीन मुकदमों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 1 पाली | 9 | 10 | 10 | 495 | 6 |
| 2 बाली | 3 | 91 | 4 | 249 | 3 |
| 3 सोजत | 6 | 7 | 4 | 153 | 4 |
| 4 जैतारण | 3 | — | 2 | 79 | — |
| 5 रामपुर | 4 | — | 1 | 23 | 77 |
| 6 खारची | 2 | 2 | 6 | 68 | — |
| 7 देसूरी | 4 | 2 | 2 | 46 | 2 |
| | 31 | 112 | 29 | 1112 | 92 |

कुल योग:- 1376

पिछले एक वर्ष में एक वर्ष पुराने 495 एवं 2 वर्ष पुराने 88, कुल 547 मुकदमे निपटाये गये हैं। इसके साथ साथ अन्य 92 मुकदमे भी निपटाये गये, जबकि उक्त दूसरे वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदंड के अनुसार 81 मुकदमें ही निपटाये जाने चाहिए थे।

बकाया विचाराधीन मुकदमों को भी शीघ्रातिशीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा द्वारा निर्मित नायलोन धागे का मूल्य

360. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद):

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा नगर स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स प्रतिवर्ष किन किन वस्तुओं का निर्माण कितनी कितनी मात्रा में कितने वर्षों से कर रहा है ?

(2) कोटा नगर में जे. के. समूह (ग्रुप) के कौन कौन से कारखाने को किस किस नाम से लाईसेंस दिये हुए हैं ?

(3) जे. के. सिन्थेटिक्स द्वारा निर्मित नायलोन धागे का उत्पादित मूल्य क्या है व बाजार में किस भाव बेचा जाता है ? क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि उत्पादन मूल्य व बिक्री मूल्य में काफी असमानता है ? यदि हां, तो इस भारी मुनाफे को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कोटा नगर में जे. के. समूह को नीचे अंकित नामों से उनके आगे दर्शाये गये उत्पादनों के लिए भारत सरकार द्वारा लाईसेंस दिये हुए हैं :—

(क) जे. के. सिन्थेटिक्स लि. (नायलोन डीविजन)- नायलोन फिलामेन्ट यार्न एण्ड पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न।

(ख) जे. के. टायर कोर्ड—टायर कोर्ड यार्न एण्ड टायर कोर्ड फैबरीक

(ग) जे. के. स्टेपल एण्ड टोज— पोलिस्टर स्टेपल एण्ड टोज—

(घ) जे. के. एक्रेलिक फाईबर

(ङ) सर पदम पथ रिसर्च सेन्टर · रिसर्च संस्थान

(3) मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स द्वारा कई तरह के नायलोन धागे उत्पादित किये जाते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कास्ट आफ प्रोडक्शन ब्यूरो द्वारा समय समय पर कास्ट आफ प्रोडक्शन की जांच की जाती रहती हैं। वर्तमान में नायलोन यार्न व पोलिस्टर यार्न का उत्पादित मूल्य क्रमशः रु. 54/- व रु. 62/- प्रति किलो एक्साईज ड्यूटी अतिरिक्त हैं। बाजार में बेचने की किमत 119.67 से 134.68 रु. प्रति किलो है। पोलिस्टर यार्न की कीमत 132.55 प्रति किलो निर्धारित है। मुनाफा सम्बन्धी विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

132 के. वी. सब स्टेशन राजगढ़

361. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 132 के. वी. का एक सब-स्टेशन राजगढ़ (अलवर) में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह सब-स्टेशन कब तक तैयार हो जायगा ?

उत्तर

जी, हां। इस सब स्टेशन का कार्य चालू है व जून, 1981 तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

**लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण**

362. **श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र के गांव खारा, जयमलसर, बेलासर, उदासर, सिंथल के ग्रायूणावास एवं रामदेवजी मंदिर के पास घुड़ाराम नेमाराम हरिजन मोहल्लों का कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ?

**उत्तर**

लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जयमलसर व सिंथल की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु एस्टीमेट बना लिये गये हैं तथा आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है। ग्राम जयमलसर के हरिजन मोहल्ले में खम्बे खड़े कर दिये गये हैं। ग्राम उदासर के हरिजन मोहल्ले के विद्युतीकरण हेतु अभी हाल ही में आवेदन प्राप्त हुआ है। एस्टीमेट बनाया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के पश्चात कार्य हाथ में लिया जायेगा। ग्राम खारा तथा ग्राम बेलासर की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु ग्राम पंचायत से अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इनकी स्वीकृत एवं विद्युतीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

**झालावाड़ जिले के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खेती पर सवर्णों का कब्जा**

363. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की खेतीबाड़ी पर कितने सवर्ण लोगों ने कब्जे कर रखे हैं ? नाम व ग्राम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) झालावाड़ जिले के अनुसूचित जाति के लोगों की कृषि भूमि पर बड़े लोगों के कब्जों की सूची संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति के लोगों की कृषि भूमि पर बड़े लोगों द्वारा कब्जे करने की शिकायतें प्राप्त होने पर उचित रूप से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सूची में उल्लेखित व्यक्तियों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः इन प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के आदेशानुसार की जा सकेगी।

( सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें )

**केशोरायपाटन क्षेत्र की सिंचित तथा असिंचित भूमि**

364. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केशोरायपाटन क्षेत्र में कितनी भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा असिंचित भूमि कितनी है ? असिंचित भूमि को सिंचित में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

**उत्तर**

केशोरायपाटन क्षेत्र में चम्बल नहरों के कुल 1,70,000 हजार एकड़ कृषि योग्य (C.C.A.) भूमि में लगभग 1,45,000 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। लगभग 25,000 हजार एकड़ क्षेत्र असिंचित रहता है।

उत्तर

असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिये दो परियोजनायें प्रस्तावित हैः-

(1) बूंदी ब्रांच केनाल विस्तार योजना (22,870 एकड़)

(2) कुंहाडी डिस्ट्रीब्यूटरी विस्तार योजना (2,400 एकड़)

**नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड अधिनियमान्तर्गत प्रबन्ध मंडल द्वारा लेखा-जोखा प्रकाशित करना**

365. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध मण्डल को प्रतिवर्ष अपना लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना चाहिये ?

(2) यदि हां, तो क्या आज दिन तक यह लेखा-जोखा प्रकाशित हुआ ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सम्वत् 2033 तक के लेखों का आडिट चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा किया जा चुका है तथा यह आडिट रिपोर्ट मंदिर मंडल के विचारार्थ रखी गई। मंदिर मंडल ने विचार विमर्श के पश्चात् बेलेन्स शीट तैयार कराये जाने का निर्णय लिया है और इस नियमानुसार बेलेन्स शीट का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य के सम्पन्न होने के बाद ही प्रकाशन का कार्य कराया जा सकेगा।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**प्रश्न की सूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रश्नों की लाटरी**

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन पर व्यवस्था।

**श्री देवेन्द्रसिंह** : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि जो प्रश्न आते हैं, वह लाटरी से निकाले जाते हैं। मैंने परसों प्रश्न शाखा से पूछा है, ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हो रही है। उन्होंने यह कहा कि हम उन प्रश्नों को भेजते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको पहले ले लेते हैं। यह डिसक्रस उन पर छोड़ना, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसी कोई त्रुटि हमारे यहां से हुई है, तो मैं देख लूंगा। यह नहीं होता है कि अमुक माननीय सदस्य हैं, इसलिए उनका प्रश्न पीछे रख दिया जाये।

(व्यवधान)

इस पर यहां बहस नहीं होगी। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। इस सेक्रेटेरियेट में इस तरह से काम होता है, यदि इसके बारे में आपको शिकायत है, तो आप मुझसे अलग से मिलें।

**एक माननीय सदस्य** : आज तक झालावाड़ जिले के कितने प्रश्न आये हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : सेक्रेटेरियेट के लिये व्यवस्था है, नियमों में दिया हुआ है। उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती है। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप वहां बतायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अध्यक्ष बनने के बाद भी किसी को चाय पर नहीं बुलाया इसलिये घर का दरवाजा नहीं खुला है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। माननीय सदस्य कृपया सहयोग कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले हम आठ-दस एम.एल.ए. बैठे थे। हमने कहा हमारे प्रश्न है। उन्होंने यह खुद कहा कि आप पीछे आइये। हम लाटरी डाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसी व्यवस्था ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसकी उचित व्यवस्था करेंगे। माननीय, सदस्य अलग-अलग दल के बुला लेंगे। वह जो सुझाव देंगे वही हम कर लेंगे।

### व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

### श्री श्रीराम गोटेवाला का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ पर्सनल क्लेरिफिकेशन

प्रश्न संख्या 387 के दौरान जब यहां बात हो रही थी, डग से आने वाले माननीय सदस्य, श्री बालचन्द आर्यवीर, ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि मैंने जयपुर के बाजारों में थड़ी लगाने पर हजारों रुपये खाये हैं। इस तरह का उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मैं विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले इस बात को कहा था चुनौती दी थी, या तो माननीय सदस्य दाऊदयाल जोशी जी का मामला था, उस समय मैंने चुनौती दी थी, मेरे खिलाफ कहीं पर भी एक भी पैसा खाने का आरोप प्रमाणित करदे या माननीय अध्यक्ष महोदय को संतोष हो जावे, तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं तथा राजनीति से सन्यास लेने को तैयार हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, लाखों लोग हमको निर्वाचित करके भेजते हैं, लाखों लोगों के हम नुमाइन्दे हैं, लाखों लोगों की हम अपेक्षाएं हैं। इस प्रकार के गलत-सही आरोप माननीय सदस्य सदन के अन्दर लगाये, उन आरोपों के बारे में मेरा विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से निवेदन है कि वह मेरी चुनौती को स्वीकार करें। कहीं पर भी मेरे विरुद्ध एक पैसे का भी वह आरोप प्रमाणित कर दें, अगर आरोप प्रमाणित होता है तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं अन्यथा माननीय सदस्य बालचन्द आर्यवीर, जिन्होंने बिना सोचे समझे इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाये हैं, खैर इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने की क्या हिम्मत होगी वह कम से कम क्षमा याचना तो करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, माननीय सदस्य बालचन्द आर्यवीर ने क्वेश्चन के दौरान कोई बात कहं और आपके नाम का उपयोग किया। माननीय सदस्य बहुत भावुकता से यह कह रहे है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं माननीय सदस्य बालचन्द आर्यवीर द्वारा वह यदि आरोप

(30)



(श्री गोपाल पचेरवाल)

साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। यह कहां तक सही है, यह तो माननीय सदस्य दोनों जानते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जनपथ समाचार साप्ताहिक है इसमें माननीय सदस्य के नाम का समाचार छपा है, मैं इसको पढ़कर आपको……

**श्री अध्यक्ष** : इसकी इजाजत नहीं दी जायगी।

(व्यवधान)

**श्री गोपाल पचेरवाल** : आप को चुनौती दे रहे हैं, सदन में ……

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार गैर जिम्मेदारी पूर्ण माननीय सदस्य द्वारा ‥

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : आपके मुख्य मंत्री है, आपकी सरकार है। अगर कोई अखबार आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया व अ[illegible] कुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राजकीय आयुर्वेद छात्रों व उपवैद्य संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन व हड़ताल के विषय में।

इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(2) श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में पथ परिवहन निगम की अव्यवस्था के विषय में।

इस विषय में कल अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान काफी चर्चा हो चुकी है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर में प्रमुख बाजारों व फुटपाथों पर पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से थड़ियां व ठेले लगाने की घटनाओं के विषय में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति इटावा तथा अन्य कई स्थानों पर कुछ सचिवों को 16—17 महीनों की नौकरी के बाद नौकरी से हटाने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बूंदी में गत 8 माह से सैण्ड स्टोन के खनन पट्टे विभाग द्वारा नहीं दिये जाने के विषय में।

(6) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में गत कुछ दिनों से बच्चों के अपहरण की घटनाओं के विषय में।

(7) श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 3 अगस्त को कोटा से जयपुर आने वाली एक बस में हुई मारपीट के विषय में।

(8) श्री जीतमल जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर नगर में मोहल्ला सेठ की बावड़ी में हरिजन युवक श्री मदन लाल की हत्या के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले में कुण्डली ग्राम में एक पागल कुत्ते के काटने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई थी और प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब मुख्य मन्त्री जी सदन में कुछ सूचना देना चाहेंगे।

## व्यवस्था का प्रश्न

### कार्य सूची में अंकित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं पहले वक्तव्य दे दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य दे रहे हैं या सूचना दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

मुख्य मन्त्री जी सूचना दें या कोई वक्तव्य दें वह पहले बिजनैस में आना चाहिए। आज के बिजनेस आफ हाउस में मुख्य मन्त्री जी कोई वक्तव्य देंगे इस तरह का कोई संकेत नहीं है। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काल अटेंशन मोशन दिया है उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं। उसके लिये उचित यही होगा कि पहले मोशन मूव करने दें उसके बाद वक्तव्य देना चाहें तो दें।

एक माननीय सदस्य : यह आज की कार्य सूची में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो जानकारी चाही गई है उसकी प्रति आपने · ·

(32)



**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : रूल 295 में रेज करने के बाद आपके चेंबर में चर्चा हुई तो आपने कहा कि ...ल अटेंशन....

(व्यवधान)

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि उस समय आपने फरमाया कि रूल 295 में रेज कर लिया जाय तो उचित होगा। मैंने लिख कर यह दिया था कि इसको रेज करना चाहता हूं। आपकी अनुमति मांगी है। यदि इस संबंध में मुख्य मन्त्री जी को कुछ कहना है तो पहले मुझे क्वेश्चन रेज करने दिया जाय।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक)** : वक्तव्य होने के बाद।

(व्यवधान)

आपने भी जब आप मुख्य मन्त्री थे, ऐसा किया है। पहले आप वक्तव्य देने दीजिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं चीफ व्हिप का बड़ा आभारी हूं कि मेरी बात पर बोलने के लिये वे तैयार रहते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में ऐसी परम्परा नहीं रही है। वे अगर बोलते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होगी लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को अचानक कोई वक्तव्य देने के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये। किसी तरह से जिस पर सदन में कोग्नीजेंस ली जा सकती है, नोटिस में ला सकते हैं। इस तरह से सदन में कोई सूचना दिये बिना वक्तव्य नहीं दे सकते। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तो यही चाहता था कि मैंने जो प्रश्न रेज किया है उस पर बोलने के बाद मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे दें।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मुख्य मन्त्री ने कल दो बजे अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया था।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय ने हमें कोई सूचना नहीं दी कि उनके और अध्यक्ष महोदय के बीच में क्या बातें हुईं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : और आपके और अध्यक्ष महोदय के बीच में क्या बातें हुई इसकी हमें सूचना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : यदि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था की बात आती है और सरकार को वक्तव्य देना होता है तो उस हालत में सरकार पहले वक्तव्य देती है, पहले स्पष्टीकरण नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : लेकिन आपकी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति इस बात की है कि जिस क्वेश्चन को मैंने रेज किया और जैसा कि माननीय चीफ व्हिप ने सदन को सूचना दी कि मुख्य मन्त्री जी ने आपको दो बजे सूचना दे दी थी कि वक्तव्य देना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी अधिकार होता है कि मुझे भी कॉंफिडेंस में लेकर कहते कि मुख्यमन्त्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं। यह आपने नहीं दी तो मैं समझता हूं आपकी क्या नाराजगी है यह मुझे नहीं पता।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : ध्यान से निकल गई होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय आपके लिये सचेतक महोदय कह सकते हैं ध्यान से निकल गई होगी लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय काफी सतर्क हैं, ध्यान से कोई चीज नहीं निकल सकती। उनकी बुद्धि में बड़ा अन्तर है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा पड़ेगी कि हाउस में .....

श्री अध्यक्ष : यदि सरकार किसी महत्व पूर्ण विषय पर वक्तव्य देना चाहे तो......

स्थगन प्रस्ताव की प्राथमिकता

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मेरा दूसरा पॉइन्ट आफ आर्डर है। जब तक एडजॉर्नमेंट मोशन पर निर्णय नहीं हो जाता, इस संबंध में किसी प्रकार का दूसरा बिजनेस नहीं लिया जाता।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस व्यवस्था पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

हाउस में जब तक बिजनेस नहीं होता उस समय तक चाहे लोक सभा की चाहे किसी विधान सभा की परम्परा निकाल कर देख लें कोई नया आइटम इंट्रोड्यूस नहीं होता। मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं तो पहले बिजनेस आ जाय उसके बाद में कोई आइटम अजेण्डा में इन्क्लूड हो सकता है लेकिन यह एडजॉर्नमेंट मोशन के बीच में वक्तव्य देना बिजनेस में व्यवधान है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप तो व्यवधान रोकने की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री जी को व्यवधान करने की इजाजत नहीं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : एडजॉर्नमेंट मोशन पर बोलने की अनुमति है, लेकिन कोई भी माननीय सदस्य इस विषय को नहीं उठा सकता जब तक कि मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य न दें। आप इस विषय पर कोई भी प्रश्न नहीं उठायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने रूल्स तो कहीं देखे नहीं। किताबों के पोथे देखें हैं। आप निकलवाइये रूल 295 पुरानी वाली किताब का नहीं नई का निकलवाइये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : 295 बहुत क्लियर है। A member who wished to bring to the notice of the House any matter, which is not a point of order.....

सक्रेटरी को देना चाहिये, अध्यक्ष को देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : (भोपालगढ़): स्पीकर की कन्सेन्ट है आपको ?

भैरोंसिंह शेखावत : कन्सेन्ट मुझको दा है।

श्री माणकमल मेहता : Rule 295 is very clear. " ....shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it ...... "

The reason is very clear.

(34)



**एक माननीय सदस्य :** स्पीकर महोदय, आपने रूल 295 के तहत माननीय सदस्य को कन्सेन्ट तो दी है, परन्तु आज के बिजनेस में वह चीज नहीं आई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय. . . .

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** माननीय सदस्य ने जो कुछ अभी कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य हमारे पेनल के सदस्य भी हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** आप समय मुकर्रर कर सकते हैं। अभी चर्चा नहीं होगी जीरो अवर में एडजॉर्नमेंट मोशन के अलावा भी मुख्य मन्त्री वक्तव्य दे सकते हैं। वह भी जीरो अवर का पार्ट ही है। जीरो अवर के अन्दर स्टेटमेंट देने का अधिकार है। मुख्य मन्त्री स्टेटमेन्ट दे सकते हैं।

**श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :** ऐसा कोई वक्तव्य, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने आपको सूचना दी है...

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।......

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसा कोई भी व्यवधान जिसको उठाने के लिए माननीय सदस्य ने आपको सूचना दे दी है, जब तक आप उसके बारे में व्यवस्था न दे दें तब तक सरकार की तरफ से उस मामले पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है।

**श्री माणकमल मेहता :** ऐसा कौनसा रूल है वह कोट कर दें ?

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय हमें यह अभी तक नहीं मालूम है कि मुख्य मन्त्री किस विषय पर वक्तव्य देंगे। आपकी तरफ से भी यह नहीं बताया गया है कि मुख्य मन्त्री किस विषय पर वक्तव्य देने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

हमेशा यह बताया जाता है कि अमुक अमुक मन्त्री अमुक विषय पर अपना वक्तव्य देगा लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम है कि किस विषय पर मुख्य मन्त्री वक्तव्य देंगे। कोई भी माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव देता है और जब तक उस पर आपकी व्यवस्था न हो उसके पहले कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** इस पर अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है। इसके पेज 290, 291 को आप पढ़े तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जनता शासन के दौरान तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मंत्रीगण अध्यक्ष की अनुमति से वक्तव्य दे सकते हैं। इसमें उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार से एडजॉर्नमेन्ट मोशन के पश्चात् इसको मैं पूरा पढ़ देता हूं : "माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी जो नियम है उसके नियम 290 के अन्तर्गत किसी मंत्री महोदय द्वारा पब्लिक इन्ट्रेस्ट के विषय पर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से स्टेटमेन्ट दिया जा सकता है। इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नियम के अन्तर्गत ही उनके द्वारा मंत्री महोदय को स्वीकृति दी गई है । इसलिए इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहिए ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

विपक्ष के नेता महोदय द्वारा मुख्य मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में यहां पर आपत्ति उठायी है कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था पहले दी जानी चाहिए थी और चर्चा भी पहले होनी चाहिए उसके बाद ही कोई वक्तव्य दिया जा सकता है क्योंकि जो स्थगन प्रस्ताव है वह सबसे ऊंची प्रायोरिटी रखता है। यह है आपका मतलब ? तो इसमें मेरा निर्णय यह है कि स्थगन प्रस्तावों पर जहां तक व्यवस्था का प्रश्न हैं वह व्यवस्था आसन ने दे दी है । अब सवाल यह है कि कुछ माननीय सदस्यों को नियम विरुद्ध परन्तु परम्पराओं के आधार पर बोलने की इजाजत दी जाती है कि यदि कोई शिकायत है तो वे एक-दो मिनिट में अपनी बात को कह दें । अब प्रश्न यह है कि जीरो अवर में जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर निर्णय हो चुका है। वह तो हो चुका है । आसन ने कह दिया है । उसके बाद मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की प्रायोरिटी का सवाल मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बीच में नहीं आता है । इसलिए मैं यह निर्णय देता हूं कि आपकी जो आपत्ति है उसका कोई नियम में आधार नहीं है । इसलिए मुख्य मंत्री को इजाजत देता हूं कि वह जो वक्तव्य देना चाहते हैं वह दें ।

**गुजरात में बनने वाले सरोवर के सम्बन्ध राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखने विषयक प्रकाशित समाचार**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री)**: अध्यक्ष महोदय, कल 6 अगस्त को प्रेस के सैक्शन में यह समाचार छपा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने वर्ल्ड बैंक को एक पत्र लिख कर उनसे निवेदन किया कि गुजरात में बनने वाले सरोवर की स्वीकृति या उसकी धनराशि न दी जाए क्योंकि राजस्थान ने उस पर अपना क्लेम पेश किया है और आपसी झगड़ा है । श्रीमान्, कल के ही अखबार के अन्दर गुजरात के सिंचाई मंत्री के नाम से दूसरा वक्तव्य छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बात कही गयी है वह सत्य नहीं है । सत्यता यह है कि वर्ल्ड बैंक को राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कोई पत्र नहीं लिखा है । केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को पत्र लिखा है उसकी कॉपी भेजी है । कल जैसे ही मेरे ध्यान में लाया गया, मैंने केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से बातचीत की, गुजरात के मुख्य मंत्री से बातचीत की और प्रधान मंत्री के कार्यालय से बात की । और इस बात को उनके ध्यान में लाया कि इस तरह का जो समाचार छपा है वह निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है । मैंने कोई पत्र न तो वर्ल्ड बैंक को लिखा है और न उस पत्र की कॉपी भेजी है। श्रीमान् मैं यह क्लेम तो नहीं करता कि सभी कायदे, कानूनों को मैं जानता हूं लेकिन इतना आपको निवेदन कर दूं और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से प्रेस को कि कम से कम माननीय सदस्य भरोसा रख कर चलें कि किसी प्रकार का कोई औपचारिक पत्र लिखा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जाता है तो वह पहले विभागीय सचिव या उस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनके पास से होकर जाता है और उसके बाद ही भेजा जा सकता है। किसी प्रकार से किसी अधिकारी द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। न मैंने वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखा है और न उसकी कोई कॉपी दी है। यह समाचार निराधार है। यह शरारत पूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन की ओर से सदन के माध्यम से पुनः प्रेस को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस समाचार का कोई आधार नहीं है। इस पर ध्यान न दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत**: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह उचित है। कल ही यह वक्तव्य आ जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब कल वक्तव्य आ गया तो तुरन्त ही इसका खण्डन किया जाना चाहिए था। आज इस समाचार का खण्डन कर रहे हैं। सदन के बाहर भी खण्डन कर देते तो वह इसके साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाता। इसलिए यह ज्यादा उचित है कि सरकार इस सम्बन्ध में और सतर्कता बरते।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमारे ध्यान में लाया गया तो इस सदन के सामने और प्रेस के सामने खुलासा करने की सोची थी लेकिन जब तक सारे मामले की जानकारी न हो, बैक ग्राउंड की जानकारी न हो, तब तक कोई वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। गुजरात के मुख्य मंत्री को स्वयं को जानकारी नहीं थी। गुजरात के मुख्य मंत्री और हमारे सिंचाई मंत्री की जानकारी में नहीं है। यह आज तक हमारे सामने नहीं आया तो कैसे खंडन कर सकते हैं?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : यह बदनाम करने के लिए किया गया है।

### स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्रीमती उजला अरोड़ा--कोटा में परिवहन निगम की अव्यवस्था के बारे में।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)** : बहुत संक्षेप में, माननीय अध्यक्ष महोदय।

कोटा जिले में 5 महीने से हैजे की बीमारी का भारी प्रकोप हो रहा है। सैंकड़ों जानवर मर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपने ध्यान नहीं रखा यह तो आपका कोई स्थगन प्रस्ताव है, रोडवेज के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उस पर बोलें।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : अध्यक्ष महोदय, वैसे कल राजस्थान रोडवेज पर काफी चर्चा हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस असंतोष को स्वीकार करते हुए कहा था यदि दवा-दारू से काम नहीं चलेगा, तो चोर पकड़े भी जायेंगे। राजस्थान में रोडवेज में काफी अव्यवस्था है और उसमें भी कोटा जिला सबसे अधिक पीड़ित है। इस अव्यवस्था के कारण ही यदि मैं यह कह दूं कि कोटा जिले में अव्यवस्था का दूसरा नाम ही

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

रोडवेज है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी बस में स्टेपनी नहीं है। इस भारी बरसात के मौसम में रात को बस कहीं भी खड़ी हो जाती है, और महिलायें, बच्चे और आदमी वहां परेशान होते रहते हैं। एक भी बस में स्टेपनी नहीं है, टूल बाक्स नहीं है तिरपाल नहीं है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। यह किसी भी रोडवेज की बस में नहीं है जबकि इस संबंध में कानून है। पुलिस वाले टैक्सी वालों और प्राइवेट बस वालों का इस बात पर चालान करते हैं पर रोडवेज का नहीं करते हैं। यह कानून को सरेआम अवहेलना है। बसों की यह हालत है कोटा रोड पर, वैसे कोटा जिले के कई रूट हैं, लेकिन वहां पर इतनी अव्यवस्था है कि चार-चार और छः-छः घंटे तक बस नहीं मिलती है और मिलती है तो तीन-तीन बसें एक साथ जाती हैं। रास्ते में सवारियां लेते नहीं हैं। कोटा सारेली रोड पर ऐसा होता है। बारां झालावाड़ मार्ग पर रोडवेज की बसें बंद कर दी हैं, क्योंकि इस गांव के लड़के गड़बड़ करते हैं और गड़बड़ के कारण बसें नहीं चलती हैं। अगर ऐसी हालत है और आप बसें नहीं चला सकते हैं तो उस मार्ग को प्राइवेट बस वालों को दे देना चाहिये। झालावाड़ तक बस नहीं जा रही है। बड़ा खराब रूट है जहां कोई बस नहीं चलती है। यह आज स्थिति हो गयी है कोटा जिले की रोडवेज के बारे में ··· ···

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये वरना वहां के गांव वालों ने यह तय किया है कि रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे, धरना देंगे, बसें हैं उनको बंद कर देंगे।

बसों में स्टेपनी नहीं होती है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरेआम उल्लंघन नहीं है कानून का? कोटा जिले की किसी भी बस में स्टेपनी नहीं है, तिरपाल नहीं है, रस्से नहीं हैं, टूल बाक्स नहीं है। इस कानून की अवहेलना करने के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और कोटा जिले में जो अव्यवस्था है रोडवेज में उसको ठीक करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की अव्यवस्था के बारे में श्री कौशल जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, यदि सरकार इस काम को समुचित ढंग से नहीं कर सकती है इसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये तो प्राइवेट बस वालों को दे या फिर सख्ती से कदम उठाये ···

**श्री अध्यक्ष** : कोटा के बारे में है। कोटा आपका पधारना हुआ है क्या?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : राजस्थान विधान सभा की मेम्बर हूं, सारे राजस्थान में जाती रहती हूं। आप क्या समझते हैं कि कोटा जयपुर से दूर है या मेरी परिधि से दूर है? मैं वहां जा नहीं सकती? मुझे अव्यवस्था का पता नहीं है? राजस्थान विधान सभा की सदस्य होने के नाते कितनी जानकारी रखनी चाहिए, उसके बारे में कहना चाहिये उसको क्या आप मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हैं?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है कि स्टेपनी नहीं है, बरसात के दिनों में बसें खड़ी हो जाती है तो लोग क्या करेंगे ? फर्स्ट एड बाक्स नहीं है। जहां लिखा रहता है फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर वह होता नहीं है। शिकायत पुस्तिका, जहां लिखा रहता है, वहां पर वह मिलती नहीं है। कोई व्यवस्था रोडवेज में नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि जो यूनियन है वहां की मान्यता प्राप्त उसका समय कभी का खतम हो चुका है। सरकार डर रही है उनको सुविधा पूरी दे रही है। वह वहां व्यवस्थित रूप से रखी गई है। मैंने सरकार का अनेकों बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया है कि जिन लोगों को सुविधा दी जानी थी, जितनी दी जानी थी, उससे अधिक आपने सुविधाएं दी हैं। जितने आफिसर दिये जाने थे, उससे अधिक आफिसर्स दिये गये हैं। जो मान्यता आपको रद्द कर देनी चाहिए थी, वह रद्द नहीं की है। इस तरह से गलत प्रबन्ध करके आपको रोडवेज की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का अधिकार नहीं है। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि वे गम्भीरता पूर्वक इस अव्यवस्था में सुधार करें। रोडवेज की बसें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई थीं, वह असुविधा बन कर रह गयी है। जो यात्री बैठ चुका है उसके बाद वह रास्ते में प्राइवेट बस में बैठे और प्राइवेट बसें भी चलती नहीं है। बीच रास्ते में ऐसा भी नहीं है कि कोई आटो रिक्शा या टैम्पो वगैरह चलते हों। ऐसी हालत में वे मार्ग में अटक जाये तो क्या करें। रोडवेज की अव्यवस्था इतनी है कि जहां पर बस स्टेण्ड हैं वहां पर सुविधा देने की कोई जरूरत ही नहीं समझी गई है। बसेज के किराये तो बढ़ा दिये जाते हैं पर कोई आल्टरनेटिव सुविधा बढ़ाई नहीं जाती है। इस तरह कोटा बारां, झालावाड़ के इलाकों में अव्यवस्था है अन्ता और बारां के अन्दर चक्का जाम करने की बात कही गई है। वहां वास्तव में जन आक्रोश है, आखिर क्या करें वह परेशान हैं। कभी चार-चार बसें जाती नहीं हैं और कभी चार चार बसें एक साथ चली जाती हैं। यात्रियों की सुविधा मिले इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्री महोदय शीघ्र व्यवस्था करके जो कोटा से झालावाड़ चलने वाली बसें बंद की हैं, उनको चालू करें। वह क्या व्यवस्था करेंगे पुलिस की व्यवस्था करेंगे या अन्य कुछ करेंगे मुझे इसमें नहीं जाना है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है वह बन्द नहीं की जाय वरना आन्दोलन खड़ा हो सकता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि आन्दोलन खड़ा नहीं हो।

श्री अध्यक्ष; समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और जो मैंने कहा आपसे मान्यता के बारे में उसके बारे में निश्चित रूप से बतायें कि आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल पचेरवाल। जयपुर के प्रमुख बाजारों में फुटपाथों पर अवैध रूप से थड़ियां और ठेले लगाने के संबंध में ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर एक ऐसा नगर है जिसे सारे देश में गुलाबी नगर कहा

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जाता है। सन् 1974–75 में जयपुर के सौन्दर्यकरण के नाम से अवैध रूप से जो थड़ियां लगायी गयी थीं उनको हटा दिया गया था। आज उसी जगह पर इतनी तेज गति से, श्रीमान, थड़िया ठेले लगाये जा रहे हैं कि जिससे जयपुर का सौंदर्यकरण बढ़ने के बजाय जयपुर कुरूपता की ओर जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी थड़िया फैली हैं, मैंने देखी हैं जहां छोटे छोटे शिवजी के मंदिर बने हुये हैं, वहां लोग दिन में एक छोटे से सामियाने में तिरपाल तानकर कीतन करते हैं। कीतर्न करने के बाद यहां पुजारी रहने लगता है, फिर छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं। सामान बिकने लगता है। मन्दिरों का दुरुपयोग हो रहा है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहां तक सत्य है, यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन अभी एक माननीय सदस्य गोटेवाले साहब बड़े जोर शोर से बोल रहे थे। एक समाचार पत्र में उनके नाम से समाचार छपा है कि जयपुर में थड़ियों पर कब्जा करने के लिये लोगों से कहा जा रहा है, आप इस पर कब्जा कर लीजिये फिर जो जनता बाजार और इन्दिरा बाजार में नगर परिषद और नगर विकास न्यास द्वारा दुकानें दी जा रही हैं जब आपको यहां से हटा दिया जायेगा तो मैं आपको वहां दुकानें दिलवाऊंगा। मैं यह समाचार पढ़ कर सुनाना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त करें। समाचार पढ़ कर सुनाने की इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : मै निवेदन करना चाहूंगा कि इनके नाम से उनके कार्यकर्त्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कब्जा दिलाने के लिये पैसे ले रहे हैं. पांच पांच हजार ले रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने एक बात बड़े जोर शोर से कही एक क्वेश्चन के दौरान कि जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कई जगह जमीनें दिलवाने के लिये 250-250 रुपये-लिये हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह इसकी जांच कराले किसी के खिलाफ ऐसा प्रश्न आये तो उसकी जांच किये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए चाहे वह कांग्रेस के एम. एल. ए. के खिलाफ समाचार पत्रों में छपा हो। नगर परिषद् के प्रशासक और मन्त्री चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। कोई एक्शन नह लिया जाता है। नगर विकास न्यास भी कोई कार्यवाही नहीं करता है। उनको यह कहा जाता है कि तुम दुकान लगा लो। जब नयी दुकान बनेगी तो आपके नाम से दुकान दिलायेंगे। आज कई लोग गन्दी नालियों में जा रहे हैं। कोई ठेला चला कर अपना पेट भरता है। उनकी रोटी रोजी चले इसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन जिम्मेदार लोगों द्वारा इस प्रकार से लोगों को कह कर कब्जा कराया जाता है तो ठीक नहीं है। नगर परिषद् और नगर विकास न्यास के लोग चुपचाप बैठे हैं। समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार आते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : नगर परिषद् के अधिकारी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। चाहे वह गोटेवाला हो या कोई भी हो उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिये। जयपुर का सौंदर्य खराब नहीं किया जाय। जयपुर में छोटी

(40)



(श्री गोपाल पचेरवाल)

चौपड़ है वहीं पर कोतवाली भी है अधिकारी भी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करता है।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : ऐसे लोग गैर कानूनी काम करवाते है, पार्टी में रहते हुए ऐसे काम करवाते है तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य। ग्रुप सचिवों के सम्बन्ध में।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल जी ने प्रश्न उठाया है, क्या उस पर मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, हम मजबूर हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के विकास विभाग द्वारा कुछ ग्रुप सचिवों की यह कह कर नियुक्ति की गई थी कि जब तक चयन आयोग द्वारा नियुक्ति नहीं होगी तब तक उनको हटाया नहीं जायगा। पिछले वर्षों में विकास विभाग के आदेश से जिलाधीशों द्वारा सैकड़ों ग्रुप सचिवों को नियुक्ति दी गई। मेरे यहां कोटा में ही नहीं, पूरे प्रान्त में ऐसी नियुक्तियां की गईं। हमारे क्षेत्र पीपल्दा में कई ग्रुप सचिव ऐसे थे जिनकी नियुक्ति जिलाधीश द्वारा की गई थी। 6 महीने के लिए उनको नियुक्ति दी गई थी। फिर उनकी नियुक्ति की अवधि को बढ़ा दिया गया था। उनको कहा गया था कि जब तक चयन आयोग द्वारा नियुक्ति नहीं होगी, उनको नहीं हटाया जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनको चयन आयोग द्वारा नियुक्ति से पूर्व ही हटा दिया गया है जिससे उन लोगों के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। वे लोग बेरोजगार हो गये हैं। उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। उनके सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं हो। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उनको नौकरी से नहीं हटाया जाय। उनको सेवा में रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, उनकी नियुक्ति को 16-17 महीने हो गये हैं। नियमानुसार इतनी लम्बी अवधि हो जाने पर हटाना नहीं चाहिये। उनकी नियुक्ति शासन सचिव, सामुदायिक विकास की आज्ञा से हुई है। यदि उनको हटाया जाता है तो उनके साथ में अन्याय होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बेरोजगारी की समस्या का सवाल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नौकरी को निरन्तर रखा जाय, ताकि उनके सामने आर्थिक कठिनाई नहीं हो तथा उधर पंचायतों का काम भी सफर नहीं करे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी। सैण्ड स्टोन के खनन के पट्टों के बारे में।

श्री बन्शीलाल पटवा।

**एक माननीय सदस्य** : वह पीछे खड़े होकर बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप अपने स्थान पर ही रहा करें तो अच्छा है।

(श्री अध्यक्ष)

ऐसे ही बोल दें अगर कागज नहीं मिल रहे हैं।

**श्री बाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, कागज मिल नहीं रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बन्शीलाल पटवा।

**भीलवाड़ा में बच्चों के अपहरण के मामले में**

**श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कुछ समय से भीलवाड़ा में बच्चों का निरन्तर अपहरण हो रहा है। एक वर्ष से निरन्तर ऐसा जारी है। पिछले दो सप्ताहों में 8 बच्चों का अपहरण किया गया है। उनमें से 3 का पता लगा है बाकी का अभी तक पता नहीं लगा है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को उड़ाया जाता है, अपहरण किया जाता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि कोई एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है वह इस काम में लगा हुआ है। किसी को मैसमेरिजम के लिए लोमड़ी आदि बनाने हेतु ले जाया गया। किसी को बर्तन धोने के लिए नौकर बनाया गया। इस तरह के कार्यों में उपयोग किया जाता है। वहां की पुलिस निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जब बच्चों का अपहरण किया जाता है उनके पैरेन्ट्स थाने में जाते हैं, तो उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जाती है। किसी प्रकार से एफ. आई. आर. दर्ज होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से गये हैं। 13–14 व पन्द्रह साल के बच्चे हैं, अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं। जब पुलिस पर कोई दबाव डाला जाता है, तो कुछ कार्यवाही होती है। सामान्यतया बच्चों का अपहरण होता है। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं तो आये दिन घटती रहती हैं। अपराधियों को संरक्षण दिये जाने के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री बन्शीलाल पटवा** : जिन बच्चों का अपहरण किया जाता है, उनका पता लगाया जाय। वहां की पुलिस पता लगाने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कोतवाली के एस. आई. है, ए. एस. आई. हैं, कोतवाल हैं, जो भी वहां पर निष्क्रिय अधिकारी हैं, उनको वहां से बदला जाये। उनके स्थान पर उन व्यक्तियों को लगाया जाय जो इस बारे में सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। लोग आतंकित हैं। पुलिस की ठीक तरह से व्यवस्था कराई जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री जीतमल जैन,

**श्री जीतमल जैन** (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस सदन के अन्दर और बाहर चर्चा हुई कि इस प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति राजस्थान में बढ़ती जा रही है। बलात्कार की चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, अलवर के अन्दर भी मोहल्ला सेठ की बावड़ी में हरिजन युवक मदनलाल की रात में कुछ लोगों ने उसके घर में हत्या कर दी लेकिन पुलिस ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है कि हरिजन युवक हमारे राज्य में सुरक्षा नहीं पा सकते। यह शासन के लिये बहुत ही शर्मनाक विषय है। मैं यह निवेदन

(42)



(श्री जीतमल जैन)

करना चाहता हूं कि अपराधों की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की प्रवृत्तियां न बढ़ें। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री छीतरलाल आर्य।

(अनुपस्थित)

**श्री त्रिलोकसिंह** (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले की ही यह समस्या नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की समस्या है। इसकी ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में कुत्ते हैं उनमें से कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो वह बच्चों को और दूसरे लोगों को काट लेता है। इस कारण बहुत से व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। गांवों में इसके इलाज की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जिला हैडक्वार्टर्स पर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें पहली बात तो यह है कि कुत्ते काटे के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर व्यवस्था है तो वह काबिले यकीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खुद सीकर, जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं, में जिला हैडक्वार्टर होने से एक बड़ा अस्पताल है, कल्याण अस्पताल के नाम से। यहां पर 6 व्यक्तियों को कुत्ते ने काट लिया, तीन आदमियों को इन्जेक्शन लगाये गये उसके बाद भी वे मौत के शिकार हो गये। उनमें से दो हाइड्रोफोबिया से ग्रस्त हो गये और एक की हालत खतरनाक है, उसका जिन्दा रहना भी मुश्किल है। यह हालत खाली हमारे यहां की ही नहीं है पूरे राजस्थान की है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कि क्या वजह है कि इन तमाम कुत्तों को सरकार मार नहीं सकती। इस तरह के खतरनाक जानवरों से कितने ही मासूम इन्सानों की मौत हो जाती है। इन्सानों को तो खाने को रोटी नहीं मिलती फिर क्यों इस तरह के खतरनाक जानवर रखे हुए हैं। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा कि सरकार पूरे राजस्थान में जितने भी कुत्ते हैं, उनको शूट करवादे।

**श्री नाथसिंह** : कुत्ते की कई तरह की कैटेगरी होती है।

**श्री त्रिलोकसिंह** : कुछ लोग ऐसे निठल्ले हैं जो दूसरों की कमाई पर कुत्ते पालते हैं। एक तरफ तो गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती, बीमारी के लिये पैसे नहीं मिलते, और दूसरी ओर भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग हैं जो शौकिया कुत्ते पालते हैं, यह कैसा अजीब बात है। लोग रोटी के लिये तरसते हैं, बच्चों को रोटी नहीं मिलती और दूसरी तरफ लोग कुत्ते पालते हैं, इससे हजारों तरह की बीमारी होती है, बच्चों को खांसी खुजली हो जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में, माननीय सदस्य

**श्री त्रिलोकसिंह** : इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय के मार्फत कि देश के तमाम कुत्तों को शूट कर दिया जाय, सरकार के द्वारा ऐसे आदेश निकाले जायं, जिस किसी को कुत्ता मिले उसको वहीं शूट कर दिया जावे, यह हमारी मांग है। किसानों के पास जो दुधारू पशु होते है वे भी कुत्तों के काटने से मर जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करिये, माननीय सदस्य,

**श्री त्रिलोकसिंह** : यह बात सरकार अच्छी तरह से जानती है फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती। गरीब लोगों का इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं होता, इसलिये मेरा निवेदन है कि कुत्तों का सफाया कर दिया जाय।

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

**आमेर स्थित संग्रहालय व महल में ऐतिहासिक महत्त्व की चीजों का गायब होना व टिकट बेचने में अनियमितता**

**श्री अध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सैयद मोहम्मद अयाज महाराज – आमेर में स्थित राजकीय संग्रहालय व महल से ऐतिहासिक महत्व की चीजें गायब होने एवं टिकटों के बेचने में अनियमिततायें होने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** (मसूदा) : मन्त्री का वक्तव्य हो जाय।

**श्री अध्यक्ष** : पहले आप मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कीजिये।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आमेर में स्थित संग्रहालय व महल से ऐतिहासिक महत्त्व की चीजें गायब होने एवं टिकट बेचने में अनियमिततायें होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मन्त्रीजी के पास रिपोर्ट आई होगी, पहले उनसे जानकारी मिल जाय, उनका वक्तव्य हो जाय तो ...

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव में ऐसा होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पहले ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। आपकी ... है पहले वह आनी चाहिये।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आमेर के किले व संग्रहालय में टिकटों की अनियमिततायें हो रही हैं उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहीं पर जो टिकट दिये जाते हैं उनको गेट पर ले लिया जाता है और उनकी दुबारा बिक्री की जाती है। मेरे पास टिकटों की फोटो स्टेट कापी है जो दो बार आये, बिना रिसेल किये। दूसरी बात वहां पर जो संग्रहालय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ शिकायत की गई तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। चिमनभाई अमीन का यह पत्र लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई'

(12.58 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

"सविनय निवेदन है कि, आज हमने आमेर महल का अवलोकन किया, प्रवेश द्वार पर टिकट बेचे जाते हैं वे प्रवेश करते समय पूरे के पूरे वापस ले लिये जाते हैं और वही प्रवेश टिकट बुकिंग पर बेचने के लिये दे दिये जाते हैं, हमने उसे पकड़ लिया है उसके नमूने और व्यवस्थित अन्य जानकारी अहमदाबाद जा कर लिखूंगा।

आपका
चिमनभाई

यह पत्र दिनांक 17-10-79 को लिखा गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, ये दो टिकट मैं आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

(४४)



(श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज)

दूसरी चीज में जो निवेदन करना चाहूंगा, वह फिल्मों की शूटिंग के बारे में है। एक रिपोर्ट के तहत यह लिखा गया कि "बगावत" फिल्म की शूटिंग के समय एक बहुत ही प्राचीन जाली टूट गई जिसका जुर्माना रामानन्द सागर से रु. 10,500/- लिया गया और वह जाली आज तक लापता है। माननीय सभापति महोदय, पुरातत्व अधिनियम, 1972 के तहत नुकसान होता है, तो उसका जुर्माना लिया जाता है और उसको संग्रहालय में ही सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जाली का आज तक कोई पता नहीं है।

इसी प्रकार वहां पर बंगाली फिल्म "सीता" की शूटिंग हुई थी उसके लिये 200 टिकट 50 पैसों के हिसाब से वसूल किये उन्हीं टिकटों को दुबारा बेचा गया, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं की गई। मैं सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी के पास इसकी जानकारी है। पिछली बार भी मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने भ्रमात्मक रिपोर्ट दी। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

एक शिकायत और इस प्रकार की आई है जिसको भी मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा—"I, A.R. Gupta accompanying Periplo Grenta (X19) hereby give it in writing that the tickets issued to me had no date."

इसी प्रकार से जो संग्रहालय में ईमानदार कर्मचारी हैं उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संग्रहालय के जो अध्यक्ष हैं वे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

यह उन्हीं के शब्द हैं। मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं रिपोर्ट की एक बात कहना चाहता हूं। यह बहुत महत्व की बात है। इसके लिए दर्शकों को नागरिकों को परेशानी होती है। वहां के कर्मचारियों को परेशानी होती है। वहां के अधिकारी के साथ साठ-गांठ करके यह सब चल रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि उन सब बातों की जांच करें, जो तथ्य है वह मैं सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि इसकी जांच विभाग द्वारा न करवा कर किसी दूसरे विभाग के अधिकारियों से करवाई जाय ताकि जांच निष्पक्ष और ईमानदारी से हो सके। सभापति महोदय, जो शीश महल की जाली की बात है, उसकी भी मन्त्री महोदय कृपया जांच करायें और यह देखें कि वह जाली मौजूद है या नहीं। यह मैं सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूं। जो रिपोर्ट निकली है वह इस प्रकार है।

सभापति महोदय, फिल्मों की शूटिंग के दौरान तमाशाइयों की भारी भीड़ के कारण जहां महलों की कई प्राचीन वस्तुओं का नुकसान हुआ है वहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी महलों को देखे बिना मायूस लौटना पड़ता है क्योंकि वे निर्धारित समय के लिए ही गुलाबी

( श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज )

नगर में आते हैं। शूटिंग के लिए संग्रहालय विभाग 5 सो रुपये रोज का किराया लेता है पर देशी–विदेशी पर्यटकों के निराश लौटने से उसे कहीं अधिक नुकसान पैसे और साख दोनों में होता है। तो ऐसा करने से तो बहुत हानि होती है। इस प्रकार कोई चीज तोड़ी जाय तो उसका विशेष नुकसान होता है। इसकी जांच करायें और देखें कि जाली है या नहीं ?

**सुश्री पुष्पा जैन** ( आमेर ) : On a point of Information, Sir, माननीय सभापति महोदय, मैं···

**श्री सभापति :** माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण करें।

**सुश्री पुष्पा जैन:** मै बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि शायद माननीय सदस्य सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं की। उन्होंने कहा कि रामा नन्द सागर 10 हजार रुपये देकर जाली साथ ले गये। यह तथ्य बिलकुल गलत है जाली टूटने पर फिल्म बगावत के डायरेक्टर श्री रामानन्द सागर ने 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया लेकिन जाली आज भी आमेर महल में पड़ी है। सदन में रखे जा रहे गलत तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं फिर अदब के साथ आपसे कहना चाहती हूं जो भी तथ्य, जो भी फिगर्स आप इस सदन में रख रहे हैं वह पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेदारी से रखें।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्या स्थान ग्रहण करें। मन्त्री जी का वक्तव्य आ जाय, तब मैं प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज:** माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो तथ्य पेश कर रहा हूं वह बिलकुल सही है। यदि आपके अधिकारी हों, यदि आप चाहते हों कि उनके खिलाफ कोई जांच न हो तथा दर्शक परेशान होते रहें तो आपकी जनता पार्टी के समय में भी घोटाले होते रहे है। आप उनकी जांच नहीं होने देना चाहते।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। आप बोलिये।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** मेरे पास जो तथ्य हैं वह मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आप भी··

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, कृपया बोलने दीजिये।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** एक रिपोर्ट की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से, गत वर्ष दिनांक 8-7-79 को श्री ताराचन्द वर्मा जो कि अनुसूचित जाति के हैं, आप बड़े हिमायती बनते हैं हरिजनों के, सन् 1976 से प्रमाणित गाइड हैं जिनका विभाग में लाइसेन्स फीस जमा करवाने के पश्चात् भी आज तक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया है। यह 79 की बात है।

**श्री नाथूसिंह :** तब आप हमारे साथ थे।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** यह सब आपके समय के घोटाले हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच हो जायगी तो आप तमाम तथ्य देखेंगे...

(46)



**सुश्री पुष्पा जैन** : माननीय सदस्य, मैंने तमाम तथ्य नहीं कहे ।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज़ महाराज** : जाली के बारे में निवेदन कर रहा हूं ।

**श्री सभापति** : सरकार जांच करेगी, आप स्थान ग्रहण करें ।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : श्री मांगी लाल आर्य भी उस समय थे, मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण के लिए उनसे पूछ सकते हैं । जो मौजूदा सरकार में उप कृषि मंत्री थे यह उस समय की बात है । उनको महलमें प्रविष्ट नहीं होने दिया गया । माननीय मांगी लाल जी भी इस बात को सपोर्ट करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने दिया था । उस बात पर उनके मेहमानों के साथ संग्रहालध्यक्ष की काफी बोलचाल हो गयी थी उस समय अम्बर गाइड्स यूनियन के अध्यक्ष डा० अमर चन्द भी उपस्थित थे । यह सब उनकी मौजूदगी में, उनके साथ हुआ । इसकी भी मंत्री महोदय जांच करवायें ।

जैसे गाइड के बारे में नियम बने हैं । उनका उल्लंघन हो रहा है । प्रथम तो ए और बी कैटेगिरी के होते हैं । लेकिन आज सी कैटेगिरी को प्राथमिकता दी जा रही है । यह किस कानून के तहत में दिया जाता है ? इस की भी माननीय मंत्री महोदय, जांच करवाएं । मेरा मानीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि जो तथ्य मैं रख रहा हूँ उनकी जांच करवायें । यह जांच सम्बन्धित विभाग से न होकर, किसी दूसरे विभाग से कराई जाय ताकि जांच निष्पक्ष हो ।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री)** : राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की यह परम्परा रही है कि सभी स्मारकों पर पूर्ण ईमानदारी एवं शांति से कार्य सम्पादन हो और संग्रहालयों की सामग्री एवं स्मारकों की पूर्ण रूपेण सुरक्षा हो ।

आमेर के किले में प्रति व्यक्ति 50 पैसे टिकट लेकर प्रवेश दिया जाता है । टिकट विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेचे जाते हैं । समय-समय पर अचानक उच्चाधिकारियों द्वारा इस स्मारक का निरीक्षण किया जाता रहा है । टिकटों की बिक्री में कोई गड़बड़ न हो इस विषय में कभी अन्दर घूमते हुए यात्रियों की टिकटे चैक की जाती हैं, तो कभी रोकड़ चैक की जाती हैं । इस प्रकार किये जाने वाले अचानक निरिक्षणों के दौरान कोई अनियमितता अभी तक पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने नहीं आई ।

बिना टिकट प्रवेश सम्बन्धी एक शिकायत श्री चिमन भाई, अहमदाबाद की प्राप्त हुई थी । उसकी मण्डलीय अधीक्षक पुरातत्व द्वारा इन्क्वायरी की गई जिसके अन्तर्गत श्री चिमन भाई को उनके पत्र में उल्लिखित पुष्ट प्रमाण निश्चित अवधि में भेजने हेतु लिखा गया, जहां से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इसके पश्चात् जांच के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हुई । बिना टिकट लिये आदि मामलों के बारे में, आमेर के किले के ही एक कर्मचारी द्वारा संग्रहालयाक्ष, आमेर के विरुद्ध की गई शिकायत राज्य सरकार के विचारार्थ दिनांक 1-8-1980 को आई । इस पर राज्य सरकार ने निर्देशक को आवश्यक जांच करने के लिये लिख दिया है । जांच रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी ।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आमेर में एक खोमचे वाले का दुकान सम्बन्धी मुकदमा चल रहा है तथा कुछ अन्य पार्टियों के भी मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। सरकारी कार्यवाही के प्रति इन पार्टियों एवं व्यक्तियों का रुष्ट होना स्वाभाविक है। खोमचे वालों ने एक शिकायत की थी कि गत नव रात्रा में उन्हें अपना खोमचा आमेर महल में नहीं लगाने दिया गया और खोमचा लगाने हेतु संग्रहालयाध्यक्ष, आमेर ने दो सौ रुपये पेशगी की मांग की। इस सम्बन्ध में भी अधीक्षक, पुरातत्व जयपुर वृत ने जांच की तो शिकायत को सही नहीं पाया गया।

जहां तक फरवरी, 1980 में आमेर में फिल्म शूटिंग के वक्त जाली के टूट जाने का मामला है जिसके समाचार राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27 मार्च, 1980 को मय चित्रके प्रकाशित हुए थे, इस के सम्बन्ध में मंडलीय अधीक्षक, जयपुर वृत्त से जांच करवाई गई। जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि शूटिंग के समय दर्शकों की भीड़ द्वारा शीश महल के सामने के बगीचे के कटघरे की पत्थर की जाली का एक भाग दिनांक 18-2-1980 को सायं टूट गया था। इस टूटी जाली के बड़े टुकड़े तो मौके पर लगे हुए हैं तथा भीड़ हटने के बाद छोटे टुकड़े संग्राहालयाध्यक्षद्वारा एकत्र करके रख दिए गए थे। शूटिंग के दौरान दर्शकों की भीड़ द्वारा जाली टूटने के कारण शूटिंग पार्टी के सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर के अनुमान के अनुसार 10,500) रु. की राशि हर्जाने के रूप में वसूल कर चालान संख्या 206 दिनांक 22 फरवरी, 1980 द्वारा राज्य कोष में जमा करा दी गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आमेर के महलों में प्रवेश पत्रों के द्वारा कुल आय वर्ष 1978-79 में 2 लाख 15 हजार 450 रु. हुई थी जो वर्ष 1979-80 में बढ़कर 2 लाख 22 हजार 141 रुपए हुई। अतः स्पष्ट है कि आमेर में सरकारी आय में कोई क्षति नहीं हुई।

यह तो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया। कुछ तथ्य आपने और दिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो आपने सामग्री मेज पर रखी है वाकयात आपने कहे, इस सम्बन्ध में और जांच आवश्यक हुई तो कर ली जाएगी, लेकिन एक प्रश्न आवश्यक है कि प्रारम्भिक जांच तो विभागीय अधिकारियों द्वारा ही सम्भव होगी। यदि प्रारम्भिक जांच के अन्दर कोई बात पाई जाती है तो दूसरी इन्कवायरी करवा लेना, यह बात समझ में आने वाली है, बाकी प्रारम्भिक जांच ही दूसरे विभाग से करा लें, यह परम्परा प्रारम्भ करेंगे, तो सभी विभागों में नई समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारंभिक जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्पन्न होगी यदि उसमें वह दोषी पाया गया, तो दूसरी जांच करा ली जाएगी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन जो बात उन्होंने कही कि विभाग के अधिकारी द्वारा ही जांच की जाएगी, उस

18



(श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज)

बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब उसके खिलाफ इतने सीरियस एलीगेशन्स लगे हुए हैं तो निष्पक्ष जांच कभी भी नहीं हो सकती।

दूसरे, आपने कहा कि चिमन भाई पटेल की शिकायत आई है, उनको लिखा गया है कि शिकायत के डिटेल्स दें। मैं चाहूंगा कि उनको लिखे गए पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें, कब लिखा गया ?

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : कल ही सदन की मेज पर उस पत्र की प्रति रख दूंगा यदि आप चाहते हैं।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है, उसमें कहा गया है कि उनके पास ऐसी शिकायत आई है। शिकायत श्री आर. गुप्ता की है जिसकी फोटो स्टेट कापी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, एक मिनट स्थान ग्रहण करें। आप चाहें तो सदन की मेज पर रख सकते हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि आप जितने डाकूमेंट्स हैं मंत्री महोदय को दे दें तो उनकी जांच करवाने में सुविधा रहेगी। यह मेरा सुझाव है अगर स्वीकार करें तो।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : आपका सुझाव मैं स्वीकार करता हूं लेकिन सदन को भी इसकी जानकारी मिल जाए इसके लिए मैं तथ्य बता रहा हूं। मंत्री जी के पास कागज जाएंगे, उनको पूर्ण जानकारी मिलेगी और पूर्ण जांच करवाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अचानक चैकिंग होती है और चैकिंग के दौरान टिकटों में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। तो मैं वहां के कर्मचारी की शिकायत आपके सम्मुख इस सदन को सुनाना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर लिया। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं मैं डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। आपको यदि एकाध प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए वरना डाकूमेंट्स दे दीजिए, वह जांच करा लेंगे।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : जो यह गलत रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि यह गलत रिपोर्ट दी है, मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है और यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट मैटर है, सारी पब्लिक का इन्ट्रेस्ट है, सभी सदस्यों को मालूम हो जाए कि क्या गड़बड़ी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, अचानक चैकिंग की जाती है। मैं उस बारे में रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, सभापति जी, आप परमिशन दीजिए।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : मैंने स्वयं ने मंजूर किया है कि 1 तारीख को शिकायत आई है, आज 7 तारीख है।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज** : मंत्री महोदय बता दें कि कितने लोगों को बिना टिकट....

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : उसने शिकायत की है कि 32 आदमी बिना टिकट

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

थे। यह मुझे एक तारीख को मिली है, उस पर मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद...

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : यह जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा न कराएं। किसी इण्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी के थ्रू करायें तो बेटर होगा वरना कभी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। उनके खिलाफ एलीगेशन्स हैं और मैं समझता हूं तमाम एलीगेशन्स सही हो सकते हैं। ये अधिकारीगण जितने भी हैं सब अपने कर्मचारियों के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं देंगे। इसलिए आप इण्डिपेन्डेंट एजेन्सी के द्वारा जांच करायें या कमेटी अपाइंट करें जिससे निष्पक्ष जांच हो।

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

## शासकीय वक्तव्य

### कोटा जिले में पशुओं की एच. एस. (गलघोटू) बीमारी से मृत्यु

**श्रीमती कमला** (पशुपालन मंत्री) : सभापति महोदय, प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर कोटा जिले में पशुओं में एच. एस. (गलघोटू) की बीमारी फैली हुई थी। यह बीमारी प्रति वर्ष वर्षा प्रारम्भ होने के साथ साथ पशुओं में संक्रामक रूप में फैलती है। इस वर्ष वर्षा होने के साथ ही इस रोग की सूचनायें प्राप्त होने लगी है। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न स्थानों पर यह बीमारी फैली हुई है:

खेड़ली, हीरान, इटावा, बावरी कीलान, रतनपुर, केथवाड़ा, अटरू, मेडदिरा, सेमल्या।

सभी स्थानों पर पशुपालन विभाग के चिकित्सक एवं पशुधन सहायक पहुंच गए हैं तथा टीके लगाए जा रहे हैं। जिला पशुपालन अधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति से निपट रहे हैं। साथ ही कोटा जिले की चार पशु चिकित्सा इकाई भी कार्य कर रही हैं। एच. एस. (गलघोटू) के टीके पशुपालन विभाग द्वारा ही बनाये जाते हैं। इस वर्ष अप्रेल से जुलाई के अन्त तक कोटा जिले के लिए 67,000 टीके भेजे जा चुके हैं। अतिरिक्त मांग पर कल दिनांक 1 अगस्त, 1980 को 15,000 टीके और भिजवाये गए हैं। ये टीके पशुओं के लगाये जा रहे हैं। अत: टीकों की कमी की कोई सम्भव सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, फिर भी आवश्यकता होने पर और टीके भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं। जिला पशुपालन अधिकारी से क्षेत्र में सम्पर्क करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी जायगी। विभाग के उप-निदेशक को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वे कोटा जाकर इस संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठायें। अब स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है और आगे भी बीमारी फैलने की कोई आशंका नहीं है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : मैं इस बात के लिए मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं किन्तु संक्रामक रोग, जैसा आपने बताया है, उसके बावजूद मैं जानना चाहता हूं कि जिला पशुपालन अधिकारी ने कितने टीके की मांग की और किस तारीख को की और कितने टीके किस तारीख को भेजे ?

(50)



**श्रीमती कमला** : मैंने आपके सामने निवेदन किया कि पूर्व में 67,000 टीके भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 1 अगस्त को 15 हजार टीके और भेजे हैं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : पहले डी.एस.टी. पाउडर के बारे में कहा था, 4 महीने से बीमारी फैल रही है, । जिन गांवों के नाम आपने गिनाए हैं, उनके अलावा और भी कई ऐसे हैं वहां पशुपालन विभाग एकदम निकम्मा है । सुलतानपुर में 47, जीमांग्या में 11, मन्डाना में 27, पटावा में 11, नया-खेड़ा, गिरधरपुरा में 8, अन्ता में 25 पशु मर गए । यह सूचना विभाग से मैं लेकर आया हूं, आपको मिसगाइड किया गया है। 4 माह पूर्व 60,000 टीकों की मांग की गई थी, और 15 दिन पूर्व 15 हजार टीके पहुंचे।

**श्रीमती कमला** : 67 हजार टीके भेजे हैं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आपने 67 हजार बाद में भेजे हैं। पर कब कब भेजे ?

**श्रीमती कमला** : 15 हजार टीके एक तारीख को अगस्त में और भेजे हैं। इसके पहले 67 हजार टीके भेजे गये थे।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : इन टीकों की मांग कब की गई थी ? इसका उत्तर तो आपने अपने स्टेटमेन्ट में दिया नहीं है। इसको तो आप टाल गये बाकी जो स्टेटमेन्ट था वह आपने दे दिया ।

**श्रीमती कमला** : सभापति महोदय, एग्जेक्ट डेट तो मुझे याद नहीं वह कब मांग की गयी पर मैं कह सकती हूं कि मांग आने पर यहां से 67 हजार टीके तो पहले भेज दिये गये और एक अगस्त को 15 हजार टीके और भेजे गये ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : सभापति महोदय, मन्त्री महोदया को यह मालूम होना चाहिये कि यह बीमारी तीन महीने से यहां पर फैल रही है ।

**श्रीमती कमला** : आपने जो कहा कि कब कब भेजे, उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जून के अन्दर 12 हजार टीके भेजे गये थे और जुलाई के अन्दर 40 हजार टीके भेजे गये । इसके बाद अगस्त में 15 हजार और भेजे गये ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मांग कब की गयी ? जब मांग की गयी तो, आपके डिपार्टमेन्ट ने नहीं भेजे। आपका विभाग इस ओर बिलकुल निष्क्रिय रहा । समय पर कोई कार्यवाही नहीं की और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती रहीं क्योंकि वह तो संक्रामक रोग है ।

**श्रीमती कमला** : अब आप बार बार कह रहे हैं कि मांग कब की गयी, तो मैं आपसे यह बताद्‌ूं कि आपके यहां से 30-6-80 को मांग की गयी थी ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : सभापति महोदय, उसके बाद में कितने दिन में आपने भेजे ? वह छूत की बीमारी है। आपको मालूम है कि यह हर वर्ष वर्षा आती है तो फैलती है, तो फिर आपके विभाग ने पहले से ही इसके लिये अग्रिम कार्यवाही क्यों नहीं की जिससे की बीमारी नहीं फैलती ?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सभापति महोदय, जब यह संक्रामक रोग वहां पर फैलने लगा तो हमने सात दिन तक वहां से लगातार टेलीफोन किये, पर आपके डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की आपका डिपार्टमेन्ट बिलकुल निकम्मा डिपार्टमेन्ट है। इस बीमारी की तरफ बिलकुल पर्टीकूलर नहीं रहा। अब आपने आदेश दिये है, देखते हैं आपके आदेश की पालना आपका विभाग किस प्रकार करता है। आपके डिपार्टमेण्ट ने जो गांवों की सूचना दी है, उन गांवों के अलावा मेरे पास सूचना और है जो आपने नहीं दी है। इसमें सुलतानपुर और सिमलिया के गांवों में पशुओं में यह बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है। पर आपने कोई सूचना नहीं दी आपके विभाग ने आपको गुमराह किया। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदया इसके लिये उन एरियाज में विशिष्ट दल भिजवा कर इस रोग को वहां रोकने की व्यवस्था करेंगी। जिससे कि वहां के पशुओं की रक्षा हो सके।

**श्रीमती कमला** : सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरे पास विशिष्ट सूचना है और जो मैने गांवों के नाम बताये हैं उनके अलावा उनके पास सूचना है। सभापति महोदय, शायद माननीय सदस्य का कोई अलग से विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिये खुफिया सूचना विभाग होगा जिससे इनको जानकारी मिलती होगी। पर, सभापति महोदय, मेरे पास तो जो सूचना है वह सूचना लेटेस्ट डिपार्टमेंट ने मंगा कर दी है, मैं समझती हूं कि जो विभाग द्वारा सूचना दी गयी है राज्य सरकार को, वही अधिकृत सूचना है। बाकी सूचना अगर माननीय सदस्य के पास है, हो सकता है, हमारे पास सूचना आने के बाद वहां पर कोई रोग फैला हो तो वह सूचना आप हमें दे दें।

सभापति महोदय, दूसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि भयंकर संक्रामक रोग फैला हुआ है, विभाग बिलकुल निकम्मा है और निष्क्रिय है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी ज्यों ही विभाग के पास सूचना आई विभाग द्वारा वहां पर टीका लगाने के दलों को भेज कर उन इलाकों में 22 हजार टीके पशुओं के लगाये और साथ ही स्थिति को नियन्त्रण में लिया। मैं यहां सदन को यह जानकारी देना चाहती हूं कि इतना भयंकर संक्रामक रोग होने के बावजूद विभाग ने तत्परता से टीके लगाये जिसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 28 पशु ही मर सके बाकी सभी पशुओं को बचा लिया गया। इतना ही नहीं ज्यों ही यह बीमारी फैलने लगी विभाग ने आस पास के गांवों के भी टीके अग्रिम रूप से लगाये जिससे कि वह आगे नहीं फैल सके।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपने तो मन्त्री महोदया से प्रश्न पूछ लिये हैं अब जरा बाऊदयाल जोशी जी चाहे तो दो-चार प्रश्न मन्त्री जी पूछ सकते हैं।

**श्री बाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, मन्त्री महोदया ने जो जवाब दिया वह बिलकुल ही गलत जवाब दिया। उन्होंने गलत जवाब देकर सदन को गुमराह किया। उन्होंने जो सूचना दी उसके अलावा कोटा डिवीजन के सुलतानपुर और सिमलिया के गांवों में यह बीमारी भयंकर रूप से फैली।

52



(श्री दाऊदयाल जोशी)

वहां पर इस बीमारी से 118 पशु मर गये। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, उस एरिया में करीब एक हजार पशु इस रोग से पीड़ित हैं।

**श्रीमती कमला** : माननीय सदस्य, एक हजार ही क्यों और ज्यादा बताते तो ठीक होता।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप चाहें तो जाकर देख लें।

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : आप इतनी बीमारी फैलने का कह रहे हैं, माननीय सदस्य। पर मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार उस बीमारी से सिर्फ 28 पशु मरे हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि वहां पर 118 पशु मरे हैं। सुलतानपुर मे और सिमलिया में मरे। आपका विभाग समय पर ठीक व्यवस्था नहीं करता है। आपके डिपार्टमेंट की निष्क्रियता से वहां पशु बीमार होकर मर रहे हैं। आपको मेरा निवेदन है कि ज्यों ही सूचना मिले आपके विभाग को तुरन्त यहां से विशिष्ट दल भिजवाने चाहिये ताकि समय पर उन पशुओं के वैक्सीन लग जावे और पशु नहीं मरें। सभापति महोदय, मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में कहा कि जिला पशु अधिकारी से सम्पर्क करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आज दस दिन हो गये हैं और आपका डिपार्टमेंट सम्पर्क ही नहीं कर पा रहा है। वहां पर यह महामारी फैल रही है और आप अभी कार्यवाही नहीं करके सिर्फ सम्पर्क ही साधने की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं तो सोचता हूं कि जब तक आपके विभाग वाले सम्पर्क साधने की कार्यवाही करते रहेंगे तब तक तो वहां हजारों पशु मर चुके होंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस संक्रामक रोग को रोकने के लिये आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। आपका विभाग इस ओर बिलकुल ही निष्क्रिय है, वहां पर तो सिर्फ नियुक्तियां की जा रही हैं। आपका डिपार्टमेंट सिर्फ नियुक्तियों में इन्ट्रेस्ट लेता है। अभी तक आपने आने के बाद में 101 व्यक्तियों को नियुक्तियां दे दी हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे है।

**श्रीमती कमला** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बीमारी से तकलीफ नहीं है नियुक्तियां हो रही हैं उनसे तकलीफ हो रही है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, यहां से कोटा में भंगी भेजे जा रहे हैं यहां से सईस भेजे जा रहे हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि आप विषयान्तर नहीं हों। यह अलग से प्रश्न है आप चाहें तो इसको अलग से प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, पशुपालन विभाग बीमारी को रोकने के लिये कुछ भी नहीं कर रहा है सिर्फ इनका ऑब्लाइज करने के लिये तुरन्त नियुक्तियां करके इधर उधर लगा रहा है। जबकि होना यह चाहिये कि इस बीमारी को रोकने के लिये यहां से तुरन्त

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दल भेजे जाने चाहिये। जबकि आप यह नहीं करके यहां से सम्पर्क साधने की बात कर रहे हैं।

**श्रीमती कमला** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो और सूचना दी है उसके लिये तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि विभाग द्वारा पता लगा कर वहां पर दल भेजने की व्यवस्था करायी जायगी। पर जो विभाग अच्छी कार्यवाही कर रहा है उसके लिये माननीय सदस्य ने कहा है कि आपके विभाग वाले बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं बिलकुल ही निकम्मे हैं आपका विभाग निष्क्रिय है। उसके लिये तो मैं यह कहना चाहूंगी कि विभाग ने तत्परता से काम लिया।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें।

**श्रीमती कमला** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि डिपार्टमेंट में नियुक्तियां की जाती हैं तो, उसके लिये यह निवेदन है कि अगर नियुक्तियों में कोई अनियमिततायें हुई हों या और कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लें तो उसका जवाब अलग से दिया जायेगा।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : आपने कहा कि आप जो भी सूचना देगें उसके ऊपर आगे कार्यवाही की जायगी। सभापति महोदय, जो हम सूचना देते है वह तो माननीय मन्त्री महोदया मानने को तैयार नहीं हैं फिर हम जानकारी देकर क्या करें? मेरे पास जो सूचना है वह आपके विभाग की सूचना के अतिरिक्त सूचना है। मेरा निवेदन है कि वहां भी दल भेजे जाकर व्यवस्था की जावे।

**श्रीमती कमला** : व्यवस्था करेगें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रामगंज मन्डी, अन्ता क्षेत्र, इटावा और दीगोद के आसपास के क्षेत्र में यह बीमारी भयंकर रूप से महा-मारी के रूप में फैल रही है।

**श्रीमति कमला** : सरकार को जो भी सूचना मिलेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी,

**श्री भैरोंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा गांवों में डिपार्टमेंट वाले टीका लगाने आते हैं तो इसके लिये मेरा निवेदन यह कि डिपार्टमेंट वाले टीका लगाने तो जाते हैं पर एक गांव में जाकर दो चार टांके लगाकर वापिस आ जाते है। गांवो में जाते है वहां पर जाकर 5-10 घरों में टीका लगा आते हैं और वापस आ जाते हैं। जब उन्हें पूछा जाता है, तो वह यह कह देते हैं कि हमारे पास वहां पर रहने को व्यवस्था नहीं है इसलिये हमें तकलीफ होती है। तकलीफ होने के कारण हम वहां से दो-चार जगह टीके लगाकर वापस आ जाते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): सभा-पति महोदय, मेरा भी निवेदन है.....

(54)



**श्री सभापति** : माननीय सदस्य ।

**श्री सी. पी. जोशी** : जो मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, मैं भी फील्ड में जाता हूं, मुझे बताया है कि जयपुर में वेक्सीनेशन की फैक्ट्री है उसके जितने टीके मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं इस लिए यह महामारी कोटा में ही नहीं है बल्कि नाथद्वारा में भी है।

**श्रीमती कमला** : राजस्थान में ही टीके बनते हैं और कोई कमी नहीं है जितने चाहिए उपलब्ध कर सकते है।

**श्री सी. पी. जोशी** : ऐसा मुझे पशु-पालन विभाग के डाक्टर ने कहा है.....

**श्री सभापति** : आप मन्त्री महोदया को नाम बता दें कि किसने सूचना दी है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपने सूचना दे दी है।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगरार कस्बे में पशु चिकित्सालय है। मै वहां कई बार गया और अधिकारियों को भी मैंने कई बार निवेदन किया। वहां पर न कोई पशुओं की दवाए हैं और न कोई औजार है। झालावाड़ जिले में जो अधिकारी है वह अपने ही स्थान पर बैठे रहते हैं। न गांव में जाते हैं न और कहीं केवल मात्र औपचारिकता......

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कोटा के बारे में प्रश्न है उसको राजस्थान का प्रश्न नहीं बनायें। चर्चा समाप्त हुई।

**श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू): सभापति महोदय, मेरा रोडवेज के बारे में स्थगन प्रस्ताव है। माननीय सभापति महोदय, आये दिन लूटपाट, चोरियां और बलात्कार हो रहे हैं। 4 अगस्त के जननायक पत्रिका में प्रसारित समाचार का हवाला देना चाहता हूं कि 3 अगस्त को कोटा से जयपुर जाने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस को मध्याह्न रात में 10 12 लोगों ने भारी पथराव करके रोक लिया तथा परिचालक से लगभग 300 रुपये छीन लिये। प्राप्त विवरण के अनुसार पथराव से शीशे टूटने पर चालक ने मजबूरन बस रोकी तथा परिचालक जब नीचे उतरा तो उसके साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कि कुछ यात्रियों ने बीच में बोलने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। परिचालक बस लेकर हिण्डोली थाने पहुंचा लेकिन वहां पुलिस ने काफी देर आनाकानी के बाद रिपोर्ट दर्ज की जब तक हमलावर आसानी से फरार हो गये।

यह प्रस्ताव बहुत ही जनहित व लोक महत्व का है अत. सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जावे और कार्यवाही करने का कष्ट करें।

### इन्दिरा कालोनी में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा महिला के साथ बलात्कार

**श्री सभापति** : गृहमन्त्री जी। इन्दिरा कालोनी में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा महिला के साथ बलात्कार के संबंध में वक्तव्य।

**श्री रामपाल उपाध्याय** (उप मन्त्री गृह) : दिनांक 3-8-80 को सायंकाल 6.15 बजे मु. विजय पुत्री श्री बचनसिंह निवासी अलवर ने मय श्रीमती चांद देवी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

पत्नी श्री नाथूलाल ब्राह्मण निवासी इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क ने थाना बनीपार्क पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अलवर मे अपने भाई के साथ दिनांक 1-8-82 को जयपुर आई थी । राजेन्द्र कण्डक्टर जो पहले से उसके घर आता जाता था, उसे तलाश करने हेतु सिन्धी कैम्प आई । उसका पति 6 माह पूर्व मर चुका है इसलिए उसके पिता ने राजेन्द्र सिंह के साथ उसकी शादी करने के लिए कहा था जिस कारण वह राजेन्द्र सिंह से मिलती जुलती रही है। राजेन्द्र ने उसकी मां को मुझे जयपुर पहुंचाने हेतु पत्र लिखा था और वह अपने पिता के कहने पर राजेन्द्र को पति मानने लग गई। सिंधी कैम्प पर राजेन्द्र उसे मिला और वह अपने साथ दोस्त कैलाश के मकान पर इन्दिरा कालोनी में ले गया जहां कैलाश मौजूद था। कुछ देर बाद रुक कर राजेन्द्र नहाने का बहाना बना कर कैलाश के साथ बाहर चला गया । उसके जाने के बाद कैलाश अपने दो दोस्तों के साथ कमरे में आया उससे शराब हेतु 25 रुपये मांगे और उसके मना करने पर उसके बटुवे से जबर्दस्ती रुपये निकाल कर शराब मंगाई और उसे भी जबर्दस्ती शराब पिलाई । तत्पश्चात् सूरत सिंह ने उसका मुंह तौलिया से बांध दिया एवं बारी बारी से तीनों ने दो दो बार बलात्कार किया। वह टट्टी का बहाना कर बाहर निकली और उसने मकान मालकिन को यह बात बताई और उसे लेकर थाने पर आ गई ।

इस रिपोर्ट पर थाना बनीपार्क में उसी दिन अभियोजन संख्या 265 धारा 392, 376, 342 आई.पी.सी. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और उसी रोज मु० विजय का डाक्टरी मुआयना करवाया गया। मु० विजय ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर प्रथम सूचना में अंकित कुछ तथ्यों के विपरीत बयान देते हुए बताया कि उसका पति जिन्दा है एवं वह थाना-गाजी की रहने वाली है। 7-8 रोज पूर्व वह अलवर से भरतपुर गई थी। जहां से दिनांक 30-7-80 को बस द्वारा जयपुर आई थी । बस में कण्डक्टर राजेन्द्र ने उससे बातचीत की एवं शादी करने को कहा जिस पर उसने अपनी शादी हो चुकना बताया एव शादी करने से इन्कार कर दिया । सिंधी कैंप पर जाकर वह अपने भाई के दोस्त वीरेन्द्रसिंह के घर चली गई और कुछ दिन बाद वह सिंधी कैंप आई जहां पर उसका काका जात भाई अर्जुनसिंह व वीरेन्द्रसिंह आ गये। उन्होंने होटल में जाकर खाना खाया। जब वह रिक्शा में बैठकर अकेली सिंधी कैम्प पुनः आ रही थी तो रास्ते में राजेन्द्र व कण्डक्टर सूरतसिंह मिले जो उसे अपने कैलाश के मकान पर ले गये जहां ओमप्रकाश नाम का व्यक्ति भी मौजूद था। राजेन्द्र सिंह वहां से नहाने का कह कर चला गया। थोड़ी देर बाद कैलाश, ओम प्रकाश व सूरतसिंह उसके पास आये। मु० विजय ने अंत में अपने बयान में वही घटना बयान की है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाई है ।

मु. विजय का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सी.आर.पी.सी. में दि० 5-8-82 को पंजीबद्ध करा दिया गया है। जिसमें भी उसने पुलिस को दिये गये बयान की पुष्टि की है । वारिसान उपलब्ध न होने के कारण उसे महिला सदन में रखा गया है एवं परिजनों को सूचना भिजवा दी गई है ।

(56)



(श्री रामपाल उपाध्याय)

पुलिस ने मुल. राजेन्द्र सिंह को जयपुर से एवं कैलाश को अलवर से दिनांक 5–8–80 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दोनों अभियुक्त सूरतसिंह व ओमप्रकाश फरार है जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल भेजे गये हैं। यह सभी अभियुक्त रोडवेज कर्मचारी हैं। इन्हें रोडवेज निगम द्वारा 6-8-80 को निलंबित किया जा चुका है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक ही आग्रह करूंगी कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए सरकार स्पष्ट कदम उठाये। मेरा इतना ही कहना है कि इस बार तो सख्ती से कानून बनायें या कुछ भी करें या कानून में किसी तरह से सख्ती लायें–यह नहीं जानती। केवल यही कहना चाहती हूं इसकी पुनरावृत्ति राजस्थान में पुनः न हो।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या को मैं कहना चाहूंगा कि इस गम्भीर मामले पर सरकार अत्यन्त गम्भीरता से विचार कर रही है और तत्परता से कार्यवाही करने जा रही है, करना चाहती है और करेगी। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल राज्य सरकार बल्कि भारत सरकार भी इसमें गम्भीरता से विचार कर रही है। सारे देश के पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श करके नये परिपेक्ष में नये प्रकार के कानून बनाने पर विचार कर रही है। हमारे गृह मंत्रालय को हमने इस बारे में अधिक जागरुक कर दिया है और अधिक सतर्क कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि ऐसी बेशर्म घटनायें, जो कि हमारे समाज के लिए कलंक है, भविष्य में न घटें। मैं कम से कम यह प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं, माननीय सदस्य महानुभाव, समाज सेवी संस्थायें, बुद्धिजीवी एवं राजनैतिक दलों से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी सरकार को ऐसे कामों को रोकने के लिये अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

**श्री सभापति** : सारे फैक्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। दो मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं। इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं रहेगा।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : सभापति महोदय, इसमें एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कल जब इस पर यहां विचार हो रहा था तो ट्रेजरी बैन्चेज के लोगों ने जिस तरह से इसका मखौल उड़ाया। कितनी सच्ची बात आपके सामने आई? माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, ट्रेजरी बैन्चेज के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जब जब प्रश्न आयें तो इस पर गम्भीरता से विचार करें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आपका नाम स्थगन प्रस्ताव में नहीं है

**श्री मोहनलाल मोदी** : माननीय सदस्यों का अधिकार तो है ही।

**श्री सभापति** : जिनका प्रश्न था, उनसे निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ाने से क्या लाभ है। इस सदन का समय बहुत कीमती है।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस समय आसन पैरों पर होता है, माननीय सदस्य खड़े रहते हैं और बहस करते हैं। इस पर आप व्यवस्था दें।

**श्री सभापति :** आप स्थान ग्रहण कीजिये।

**सुश्री पुष्पा जैन :** सभापति महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करने जा रही हूं। जैसा मंत्री महोदय ने यह उम्मीद की सभी राजनैतिक दल इस अपराध को कम करने में सहयोग करें, हम हृदय से साथ देने को तैयार हैं और आभारी हैं कि इस केस में उन्होंने तफतीश को आगे बढ़ाया और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसे मामलात जब सदन में उठाये जाते हैं और यदि ट्रेजरी बैन्चेज के माननीय सदस्य उस समय यह कहें हम ऐसे मामलात इसलिये उठा रहे हैं क्योंकि अखबार में अपना नाम छपाना चाहते हैं तो मैं समझती हूं इससे बढ़कर महिलाओं का कोई अपमान हो नहीं सकता है। अगर आपके दल के माननीय सदस्य ऐसे समय संजीदगी से काम लें तो आप यह यकीन करें कि सभी राजनैतिक दल निश्चित रूप से ऐसे अपराध को कम करने में साथ देंगे। मैं समझती हूं यदि आपका दल आपके साथ नहीं है, ऐसे मामलात में, तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप अपने दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करें कि वे आपका साथ दें।

**श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** आपको क्या है ?

**सुश्री पुष्पा जैन** माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं लेकिन वे व्यवधान पैदा कर रहे हैं जब मैं बोल रही हूं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

**सुश्री पुष्पा जैन :** माननीय सभापति महोदय, नियमों का हवाला देने वाले माननीय सदस्य को स्वयं नियमों का ज्ञान नहीं है। ........

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री मानालाल (राजसमन्द) :** सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी माननीय सदस्य को डाइरेक्ट आदेश देने का राइट नहीं है.....

(व्यवधान)

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी :** आर्डर दे रहे हैं। .....

**श्री सभापति :** आप आसन को सम्बोधित करें। आप उधर नहीं देखें, आसन को देखें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर।

**सुश्री पुष्पा जैन :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से फिर दरख्वास्त करना चाहती हूं कि ऐसे संजीदगी के मामलात जब इस सदन में उठाये

(सुश्री पुष्पा जैन)

जाय तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को मदद करनी चाहिये कि ऐसे मामलात में सरकार जांच कराने के लिये पुरजोर कोशिश करे, उनसे अनुरोध करे, बलपूर्वक कहें कि इसमें जांच कीजिये ताकि राजस्थान में ऐसे काम न हों। यदि सत्ता पक्ष ने सरकार का साथ न दिया तो मुझे डर है, कहीं ऐसी स्थिति न हो जाय कि राजस्थान भी बागपत बन जाय।

धन्यवाद।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति**

**श्री सभापति**: परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81, अनुदान की मांग पर विचार।

**शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)**: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 81 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 अरब 34 करोड़ 21 लाख 11 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

**मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या-24, मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

**श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)**

1. राज्य के स्कूल्स में आर. एस. एस. के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)**

2. खेलकूद मन्त्रालय प्रकोष्ठ का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**

3. ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने में सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

4. गांवों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

5. प्रत्येक गांव में प्राथमिक शाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. सीमावर्ती छात्रावासों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

7. सैकण्डरी स्कूल्स का हायर सैकण्डरी स्कूल्स में क्रमोन्नत न होने से छात्रों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

8. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के खोलने में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)**

**श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)**

9. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने एवं पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय पर एक कॉलेज सुविधा उपलब्ध कराने तथा अच्छे अध्यापकों का फायदा ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री रतनाराम चौधरी ( रानीवाड़ा )**

10. प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशाला एवं पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक पाठशाला तथा रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

**श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)**

**श्री रतनाराम (रानीवाड़ा)**

11. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये ।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक शाला खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

13. बाली ग्राम में माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)**

**श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)**

**श्री माधूसिंह (बागीडोरा)**

**श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)**

**सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)**

14. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाय एवं उच्च शिक्षा को व्यवसायान्मुख किया जाय, इस हेतु चर्चा के लिये ।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)**

15. निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं के समान वेतन एवं अन्य सुविधायें नहीं दिये जाने से निजी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

16. बीकानेर डिवीजन मुख्यालय पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**

17. सीकर जिले में नये स्कूल्स खोलने एवं वर्तमान स्कूल्स को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

**श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर–पश्चिम)**

18. निजी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**

19. संगीत कला अकादमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

**श्री जीतमल जैन (अलवर)**

20. कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में वाणिज्य विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

21. ग्राम शाहपुर (जिला अलवर) में दसवीं कक्षा में विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

22. विद्यालय भवनों की जीर्ण क्षीण अवस्था सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बारे में चर्चा के लिए ।

(श्री जीतमल जैन)

23. अकादमियों में धांधली एवं कला के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं के कारण इनको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

24. बेरोजगारी दूर करने हेतु शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाने तथा छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

25. प्राथमिक शिक्षा को विकास विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग को सुपुर्द करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)

26. इटावा में महाविद्यालय खोलने के लिए तथा इटावा में हायर सैकण्डरी स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में वाणिज्य विषय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

27. शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की कमी से सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी कक्षाओं में प्रवेश की कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

28. राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा की उपेक्षा बरतने एवं संस्कृत स्नातकों के प्रति भेदभाव बरतने के विरुद्ध चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

29. भाषा विभाग द्वारा हिन्दी राष्ट्र भाषा को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रयोग में लाने का प्रयास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

30. अध्यापकों के स्थानान्तरण व शाला भवनों की कमी तथा अध्यापकों के शालाओं से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये।

32. 14 वर्ष तक के बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

33. कालेज तथा स्कूल्स के छात्रों में संस्कृत के प्रसार की समुचित व्यवस्था न करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्तियां देने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

35. प्रौढ़ शिक्षा पर हुये अपव्यय पर चर्चा के लिए।

36. केशवरायपाटन सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़)

37. नवलगढ निर्वाचन क्षेत्र में सैकन्डरी स्कूल्स खुलवाने हेतु चर्चा के लिए ।

38. नवलगढ़ क्षेत्र में सैकन्डरी स्कूल्स में कामर्स एवं साइन्स सबजेक्ट खुलवाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

39. मारवाड़ जंक्शन पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं शिक्षकों को आवास की सुविधा उपलब्ध करने तथा पंचायतों से शिक्षा को हटा कर शिक्षा विभाग के ही तहत रखे जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

40. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

41. साहित्य एवं ललित कला अकादमियों की दुर्दशा सुधारने हेतु उनको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल (धोलपुर)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

42. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर इसे व्यवसायोन्मुख बनाये जाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

43. शिक्षा को राजनीति से दूर रखने के लिये पंचायत समिति से शिक्षा वापस ली जाय, इस पर चर्चा के लिए ।

44. शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ठीक करनेके लिए प्राइमरी एवं मिडिल की परीक्षा बोर्ड के माध्यम से ली जाय तथा सैकेन्डरी एवं हायर सैकेन्डरी परीक्षा के बाद व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाय, इस पर चर्चा के लिए ।

45. अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति को ताक में रखकर पार्टी कार्यालयों में ट्रांसफर की सूचियां तैयार कर भारी संख्या में तबादले किये जा रहे हैं जिससे शिक्षा के बजट का अधिकांश पैसा यात्रा भत्ता देने में व्यय किया जा रहा है, इसे रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

46. शहरी क्षेत्र में विशेष कर उदयपुर नगर में विद्यालय भवनों की कमी है एवं जो भवन हैं उनकी दयनीय दशा सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए ।

47. नगरपालिका उदयपुर ने अपने बजट वर्ष 79-80 में 1.10 लाख रुपये राजकीय विद्यालय भवन के निर्माण एवं सुधार हेतु स्वीकृति किया है उसे उपयोग में लेने की स्वीकृति दिलाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

48. राज्य भर में विद्यालयों में बढ़ रहे उद्दंडता के वातावरण को समाप्त करने के लिये कारगर कदम उठाने व परीक्षाओं से बार बार बायकाट करने के मामले पर विचार करने के बाबत चर्चा के लिए ।

49. संस्कृत भाषा के स्नातकों के साथ भेदभाव समाप्त कराने एवं एक और संस्कृत महाविद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

(62)



(श्री दाऊदयाल जोशी) दीगोद

50. सरकार द्वारा राजस्थान की दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को मान्यता न देने बाबत चर्चा के लिए।

51. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने बाबत चर्चा के लिये।

52. महिला पॉलीटेक्नीक कालेज, कोटा नगर में स्थापित करने व पूर्व सरकार द्वारा जो कोटा नगर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की दिशा में कदम उठाये थे उसे लागू करने बाबत चर्चा के लिये।

53. राज्य के अनेक गैर सरकारी महाविद्यालय व विद्यालय भारी सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद भी छात्रों से भारी शुल्क राशियां प्राप्त कर शिक्षार्थियों का शोषण कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा संस्थाओं की सहायता तुरन्त बन्द करने बाबत चर्चा के लिये।

54. प्रत्येक स्तर के शिक्षा संस्थानों में खेलकूद को अनिवार्य व शिक्षा का ही अंग बनाकर अच्छे विद्वान के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के प्रति घोर उपेक्षा बरते जाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

56. प्रौढ़ शिक्षा पर होने वाले धन के अपव्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. नसीराबाद क्षेत्र में सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूल्स में साइन्स विषय खोलने एवं छात्राओं के लिए कॉलेज खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

58. नये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोलने व प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जेठमल (परबतसर)

59. परबतसर क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

60. छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये मकराने में डिग्री कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री बालचन्द्र (डग)

61. सवाई माधोपुर कालेज में कृषि, विज्ञान व लॉ विषय खोलने तथा इस कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक किया जावे इस पर चर्चा के लिए।

62. खंडार निर्वाचन क्षेत्र के स्कूल्स में अध्यापकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

63. ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का विशेष विस्तार किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

64. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राज्य की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज (गोगुन्दा)

66. प्राइवेट संस्थाओं को विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

67. अनुदानित सनातन धर्म पंचायती माध्यमिक विद्यालय, मण्डावा में अव्यवस्था के कारण पढ़ाई न होना तथा प्रबन्ध समिति की मनमानी पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

68. अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में स्कूल खोलने में भेदभाव बरतने और अध्यापकों के राजनैतिक आधार पर तबादले करने पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

69. ग्राम भदलिया, बेड़वा, खरेस और भीषवा आदि के स्कूलों को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (माण्डल)

माण्डल निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्राथमिक शाला खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

71. वित्तीय अनियमितताओं के मामले वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्रिमनल कार्यवाही हेतु पुलिस में दर्ज करवाना अनिवार्य होते हुये भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के ऐसे मामलें पुलिस में न देने व भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये।

72. पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा राजकीय व सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये निर्धारित कमीशन से कम कमीशन पर पुस्तकें खरीदने पर चर्चा के लिये।

73. भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष, सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर व कोटा द्वारा किये गये गबन, मिसएप्रोप्रियेशन व वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई विभागीय जांच के माध्यम से दिये गये दण्ड को कार्यरूप में परिणित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बाऊदयाल जोशी (दं गोद)

74. राज्य कर्मचारियों की भांति नगर परिषद व पालिका एवं जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों के बच्चों की भी विद्यालय शुल्क से मुक्ति दिलवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

75. टोंक तहसील के प्रत्येक गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

76. अननिया माल राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कमरों पर छत ढलवाने के लिये विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

77. टोंक महाविद्यालय में एम. ए. में हिन्दी एवं राजनीति शास्त्र विषय खोलने एवं एल-एल. बी. की कक्षाएं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69



**श्री नरपत राम बरवड (सूरसागर)**

78. सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिये और विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)**

79. प्रौढ़ शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्राथमिक विद्यालय आबादी के आधार पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री धाराराम (सिवाना)**

82. सिवाना क्षेत्र में स्कूलों व अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

**श्री अमीन खां (शिव)**

83. बाड़मेर जिले की रायसर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में क्रमोन्नत कराने व सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये।

**श्री तेजपाल यादव (चौमू)**

84. राजकीय संस्कृत स्कूल चौथवाड़ी को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री नानालाल (राजसमंद)**

85. प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. ग्रामीण स्कूलों में छात्रों के बैठने के फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. ग्रामीण स्कूलों में योग्य अध्यापक नियुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री कनकराज मेहता (सांचौर)**

88. सांचौर तहसील के तांतड़ा-बागली रामपुरा, शिवपुरा, आकोदा, वताणा, कीलूपीयर, डेडवा पुरोहितों की ढाणी, पालड़ी देवड़ा, वाला की नाडी खास गांवों में प्राथमिक शालाएं खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. सांचौर तहसील के ग्राम गुधाऊ व दाता में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कराने के संबन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बहादुरसिंह (दानपुर)**

90. राज्य सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

91. राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

92. राज्य सरकार गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

93. राज्य सरकार द्वारा ग्राम नवागाम छोटी सरवन में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

94. राज्य सरकार गांव उकाला में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

95. राज्य सरकार कसारवाड़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

96. राज्य सरकार गांव सानिसरो में सेकन्डरी स्कूल खोलने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

97. राज्य सरकार घोषणा करने के पश्चात भी कुशलगढ कस्बे में महाविद्यालय खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

98. राज्य सरकार गांव डूंगरा में उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

99. राज्य सरकार गांव सज्जनगढ़ में घोषणा करने के पश्चात भी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स विभाग खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

100. राज्य सरकार छोटी सरवा में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

101. राज्य सरकार मिडिल स्कूल सागवा को सेकन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

102. राज्य सरकार डूंगरा हायर सेकन्डरी स्कूल में कॉमर्स विषय खोलने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

103. राज्य सरकार डूंगरा छोटा में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

104. नीम का थाना में उच्च शिक्षा के योग्य छात्रों के लिये महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव तथा विद्यार्थियों के लिये सामान्य सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के के लिये।

106. राज्य में ललित कला शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर)

107. जन सामान्य में प्रारम्भिक शिक्षा की कमी के निवारणार्थ जिला सिरोही में शिक्षण संस्थाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)

108. सरकार की शिक्षा नीति अस्पष्ट होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा)

109. प्रौढ़ शिक्षा की समस्त राशि से प्राथमिक शालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

110. करौली निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्राईमरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

66



**श्री हंसराज ( सवाई माधोपुर )**

111. शिक्षा विभाग में हजारों की तादाद में शिक्षकों के राजनैतिक बदले की भावना से हो रहे स्थानांतरणों से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

112. सवाई माधोपुर क्षेत्र में नये स्कूल नहीं खोले जाने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

113. शिक्षा नीति में आमूल – चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री ईश्वरलाल सैनी ( लछमनगढ़ )**

114. अध्यापकों के स्थानांतरण से होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये।

**श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा)**

115. असमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर इसे गुणात्मक के बनाने व छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री समर्थलाल (राजगढ़)**

116. राजगढ़ महाविद्यालय को पोस्ट ग्रेजुएट बनाने के क्रम में चर्चा के लिये।

**श्री सूर्यकुमार जैन (नैनवा)**

117. राजकीय माध्यमिक विद्यालय नैनवा जिला बून्दी को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कराने के बारे में चर्चा के लिये।

118. बून्दी जिले में कृषि का विषय किसी भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

119. शिक्षा के क्षेत्र में 10+2+2 की शिक्षा नीति को अंगीकार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने के पश्चात् फर्नीचर एवं भवन की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये।

**श्री अमराराम (पचपदरा)**

121. बाड़मेर जिले के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक माध्यमिक शालाएं एवं कालेज खोलने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

122. बालोतरा में कालेज व पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में 7 मिडिल स्कूलें, चार सकेण्डरी स्कूल व एक हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. आसोतरा एवं असाड़ा माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)**

124. स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर)**

125. श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, तालाब गांव तहसील लालसोट को सरकार द्वारा अधिगृहीत नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना)

126. कस्बा अकलेरा, जिला झालावाड़ के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

127. झालावाड़ जिले के प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तथा कन्या शालाओं में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी)

128. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बून्दी में 11 वीं कक्षा में कृषि एवं कामर्स की कक्षा शुरू करने तथा सेकेण्डरी स्कूल बालचन्द पाड़ा में विज्ञान की कक्षा शुरू करने के बारे में चर्चा के लिये।

129. राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

130. खानपुर हाइ स्कूल में कमरों की कमी पर चर्चा के लिये।

131. 30 वर्ष पुराने हाइ स्कूल खानपुर को हायर सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल तांबी (जहाजपुर)

132. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार तथा विद्यालय भवनों की समस्या हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास (चौहटन)

133. जिला बाड़मेर में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल्स के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानीसिंह (भादरा)

134. रोजगार पर आधारित शिक्षा प्रणाली को चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर)

135. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

136. आमेर क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला खोलने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

137. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं के साथ विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल एवं सेकेण्डरी स्कूल की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

139 नाथद्वारा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

140. नाथद्वारा की चित्रकारी शैली तथा संगीत विद्या को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

(68)



(श्री सी.पी.जोशी)

141. विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

142. प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने तथा गतिविधियों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

143. हर ग्राम में प्राथमिक शाला प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

146. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 मील की परिधि में एक हायर सैकेण्डरी स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

148. नये प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने की दोष पूर्ण प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये।

148. प्राथमिक स्कूल्स में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. वर्षा ऋतु में ग्रामीण प्राथमिक स्कूल्स में छात्रों की उपस्थिति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

150. प्राथमिक स्कूल्स में पुस्तक, कॉपी सलेट राज्य सरकार की ओर से मुफ्त देने हेतु चर्चा के लिये।

151. ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक स्कूल्स में अध्यापकों की नियमित उपस्थिति न होने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

152. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा शुल्क की विषमताओं को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

153. प्रदेश में इन्जिनियरिंग कालेजों की कमी पर चर्चा के लिये।

154. 80% या इससे अधिक सहायता प्राप्त करने वाली गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा अधिगृहीत कराने हेतु चर्चा के लिये।

155. ललित कला व नाट्य कला अकादमियों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

156. बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)

157. प्राथमिक शिक्षा को अगले पांच वर्षों में अनिवार्य करने के विषय में चर्चा के लिये।

158. प्राथमिक शिक्षा के लिये पृथक निदेशालय स्थापित करने के विषय में चर्चा के लिये।

159. कोटा में इन्जीनियरिंग महाविद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

160. शिक्षा में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित कराने के विषय में चर्चा के लिये।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

161 घोषित स्थानान्तरण नीति की अवमानना करते हुये राजनैतिक आधार पर बड़े पैमाने पर हजारों अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

162. अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवम् अशैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के विषय में गत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को क्रियान्वित कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

163. विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

164. विद्यालय भवनों के निर्माण व मरम्मत में शिक्षा विभाग द्वारा उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये।

165. अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवम् कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राजकीय स्तर के समान होने पर भी उन्हें उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

166. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं को निरन्तर सेवा में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. कुचामन, रतनगढ़, नोहर, बयाना, फलोदी आदि स्थानों पर नये महाविद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डौन)

168. पंचायत समिति हिंडोली जिला बूंदी में कम से कम 12 प्राथमिक शालायें 4 उच्च प्राथमिक शालायें और चार माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी)

169. वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवसायोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

170. शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े टोडारायसिंह में शिक्षा के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

171. अजमेर नगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

172. अजमेर नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूंडवा)

173. कला के मद में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग कराने हेतु चर्चा के लिये।

174. शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम (डूंगरगढ़)

175. प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

176. ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में अध्यापकों की कमी व अध्यापकों की लापरवाही से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

177. राज्य के विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर।

178. पुरातत्व विभाग को पुनः सक्रिय करने और संस्कृति के प्रतीकों के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव क्रमानुसार वक्ताओं का क्रम

श्री सभापति : श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको न बुलाकर दूसरों को बुलाया जा रहा है, यह परम्परा ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि हम कटौती प्रस्ताव देते हैं उस क्रम में आप नहीं बुलाते हैं आप व्यवस्था दे दें तो आइंदा कोई कटौती प्रस्ताव नहीं देगा। अगर कटौती प्रस्ताव देते हैं तो उसी ढंग से बुलाइये। बीच में बुला रहे हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : यह आपके दल की आन्तरिक व्यवस्था है। इसमें हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूं। आप अपने सचेतक से इस बारे में बात कीजिये मेरे पास जो सूची है ··

श्री रामसिंह बिश्नोई : मामला घर का नही है। मामला रूल्स का है। माननीय सदस्य जब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है तो कटौती प्रस्ताव देने की जरूरत नहीं है। दल के सचेतक जो सूची दे देंगे उस हिसाब से चलेगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की पिछली बैठक के अंदर जब बजट की मांगों पर विचार किया गया था, कौन सी मांग किस दिन रखी जाये, उस दिन यह चर्चा हुई थी कि आम तौर पर पहले कट मोशन दे देते हैं हमेशा हर डिमाण्ड में उनका नाम पहले ही आता है····

एक माननीय सदस्य : आयेगा ही।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा एतराज है।

श्री सभापति : आप अपना एतराज बाद में पेश कीजियेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये यह तय किया गया कि आम तौर पर हर एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिलना चाहिये हर एक यह चाहता है कि 4।।, 5 बजे से पहले बोलूं तो अच्छा है। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह किया था कि हर एक पार्टी के व्हिप सूची देंगे और वे सूचियां इस आधार पर ली जायेंगी कि उनके दल के कौन कौन सदस्य पहले बोल चुके हैं, कुछ सदस्य तो इस डिमाण्ड पर बोल चुके हैं, कई बोल नहीं पायेंगे, उनका नम्बर भी आना चाहिये। आज फिर बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग है। विरोधी दल के नेता भी होंगे। इस पर फिर विचार कर लेंगे।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी** : हम जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं सतर्क रहकर समय पर प्रस्तुत इसीलिये करते हैं कि हमें बोलने का समय मिले। जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी पार्टी की संख्या को देखते हुए आपने समय का वितरण किया था। उसमें भी आपने यह फर्माया था कि उसमें थोड़ासा रिलेक्सेशन करके एडजस्टमेंट करने का प्रयत्न किया जायेगा। आपने यह व्यवस्था नहीं दी थी कि कटौती प्रस्तावों का जो क्रम है उसको तोड़ दें। यह उनके दल की ताकत से हो सकता है, विपक्ष वालों ने जो क्रम दिया है, हमारा क्रम क्यों तोड़ते हैं। आप व्यवस्था दें। नहीं तो कटौती प्रस्ताव देने का कोई मीनिंग नहीं रहता। हर दल की एक लिस्ट आपको प्राप्त हो जाये उसके अनुसार आप बुलवा दें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य वह लिस्ट दे दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने कटमोशन पेश किये हों, ऐसी बात नहीं है कि इस आसन से बोलने की इजाजत नहीं दी गई हो। जिन्होंने कटमोशन पेश नहीं किये हैं उनके लिये जो आपने भावना व्यक्त की है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि अब वाद-विवाद का शुभारम्भ किया जाय।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : व्यवस्था का प्रश्न।

मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं। जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव पेश ही नहीं किये, क्या उन लोगों को पहले बोलने का अधिकार है?

**श्री सभापति** : ऐसा नहीं है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : इनका नाम नहीं है।

**श्री खेतसिंह राठौड** : हीरालाल देवपुरा का कट मोशन में नाम है।

**श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)** : सभापति महोदय, जब आपने दलों का समय निर्धारित कर दिया तो अब यह दलों पर ही छोड़ना होगा कि वे किन माननीय सदस्यों की सूची देते हैं?

**श्री सभापति** : पिछले दिनों जो डिबेट का क्रम चला है उसी के अनुसार चल रहा है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं असमर्थ हूं।

माननीय हीरालाल देवपुरा।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**एक माननीय सदस्य** : ये आदत से बाज नहीं आते हैं।

**श्री सभापति** : इस तरह के रिमार्क्स पास नहीं करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपने यह व्यवस्था दी है कि कटौती प्रस्ताव द्वारा समय दिया जायगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। सबको समय देने की बात नहीं कही गई है। समय फिक्स किया है आसन के द्वारा फिर भी मैंने यह कहा है कि आसन की कोई रिजिडिटी नहीं, फ्लेग्जिबिल हैं और आपके दल को सबसे अधिक समय दिया गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बेकार उलझन में माननीय सदस्यों का समय बर्बाद होगा, सदन का समय बर्बाद होगा।

(72)



**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं-

(व्यवधान)

**श्री त्रिलोक सिंह** : जब दलों को समय दिया गया है तो···

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : बोलने के लिए किसी भी सदस्य का कटमोशन माना आवश्यक है क्या ?

**श्री त्रिलोक सिंह** : फिर दलों को समय देने का क्या मतलब हुआ ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : सभापति महोदय, जो समय निर्धारण की बात कही गई उसके विषय में मैंने अध्यक्ष महोदय से भी चेम्बर में निवेदन किया था, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं आज के दिन 178 कटौती प्रस्ताव हैं, भारतीय जनता पार्टी के 70 कटौती प्रस्ताव हैं चार जनता पार्टी के सदस्यों ने 19 प्रस्ताव दिये हैं, तीन सदस्यों ने 8 कटौती प्रस्ताव दिये हैं लोक-दल ने और प्रगतिशील दल के चार सदस्यों ने 7 प्रस्ताव दिये हैं—इस तरह कुल 178 प्रस्ताव आये हैं । मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं जब 70,39 और 77 प्रस्ताव दे रहे हैं तो आधा समय हमको दें – एक व्यवस्था तो यह दें···

(व्यवधान)

पहले जिसने प्रस्ताव दिया है, वह पहले बोले··

(व्यवधान)

जिस प्रकार माननीय राम रघुनाथ जी ने कहा है, वह सच है पहले जो नाम दिये गये हैं उनके नाम हैं दो कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के 7, कांग्रेस (अर्स) 1 और प्रगतिशील पार्टी का एक तो कम से कम जो सूची आती है उसमें यह व्यवस्था भी करे ताकि नियमों का भी पालन हो।···

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है, वह सुझाव है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह सदन की परम्परा रही है कि डिबेट सुचारू रूप से चल सके इसलिए एक सत्ता पक्ष से और एक विपक्ष से बोलें । आपकी भावना से मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा । मैं निवेदन करूंगा अब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय····

(व्यवधान)

**श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)**: कट मोशन तो इण्डिविजुअल राइट है, इसमें पार्टी का सवाल नहीं आता है ।

(व्यवधान)

**श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)** : फिर देने का मतलब क्या है ?

(व्यवधान)

आप हमें समय कम देते है।···

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज । आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

( 1.44. म.प. )

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गलत फहमी हो गई है। कटमोशन्स पर एक प्रश्न तो यह

(श्री अध्यक्ष)

उठाया गया कि जिन माननीय सदस्यों ने अधिक संख्या में कटौती प्रस्ताव दिये है उनको सर्वप्रथम अवसर मिलना चाहिये। हमने व्यवस्था यह दी है कि सब कटौती प्रस्ताव मूव हुए मान लिये जाय, जो सदन के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव सदन में आये हैं वे सदन की सम्पदा बन गये। माननीय सदस्य अभी एतराज कर रहे हैं कि पहला अवसर मिलना चाहिये-जब पहले रखा है तो। मेरा निवेदन है कि सब कटौती प्रस्ताव सदन के सामने आ गये और यह मान लिया कि सदन के सामने पढ़ लिये गये। जहाँ तक डिबेट का प्रश्न है जो भी विषय सदन के सामने हैं उस पर सब माननीय सदस्यों को वाद-विवाद करने का, चर्चा करने का अधिकार है। जब कटौती प्रस्ताव मूव कर दिये हैं तो अब हमने व्यवस्था यह की है कि दल के व्हिप साहबान हैं वे अपनी अपनी सूची दे देंगे और हम यह मान कर चलते हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं दल के व्हिप साहबान उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे। हमेशा से ऐसा होता है इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है पहले या पीछे का प्रश्न नहीं उठता है। सबके सब कटौती प्रस्ताव सदन के सामने आ गये यानि उनको मूव समझिए और सदन को पढ़ कर बता दिया। अब उस पर चर्चा करनी है। जो व्यवस्था दी है उसमें व्हिप साहबान कटौती प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, किस क्रम में वे सूची देना चाहते हैं, दे दें उसी के अनुसार डिबेट होगी। पिछले दो तीन दिन डिबेट चली है और शायद किसी माननीय सदस्य को यह शिकायत नहीं रही होगी कि हमारे कटौती प्रस्ताव थे और हम नहीं बोले। अब भी कोई शंका रह गई है तो फिर फर्मा दें, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन है जिन जागरूक सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पहले मूव किये हैं उनका फर्स्ट नाम होना चाहिये। इस व्यवस्था से कांग्रेस के दो, प्रगतिशील दल के एक....यह सब सूची में दिये हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जो जागरूक सदस्य हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिये....

(व्यवधान)

दो उधर से बोलें, 6 भारतीय जनता पार्टी के बोलें फिर एक प्रगतिशील दल के सदस्य बोले....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जो समय दिया है इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अमुक दल की कितनी संख्या है। चूंकि इनके दल के माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव ज्यादा दिये हैं तो उसमें हम यह उनको नहीं कहेंगे कि उनका समय समाप्त हो गया और यह वाद विवाद में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह तो नहीं है कि पहले इनको अवसर मिले या इनको मिले। डिबेट का कायदा है, डिबेट उसी समय अच्छी होती है जब उत्तर और प्रत्युत्तर साथ साथ होता रहे, यही सुन्दर ढंग है डिबेट का। तो मेरे खयाल में इस प्रकार से होना चाहिये कि दूसरे दलों को भी अवसर मिल सके। अगर आप इसको लागू करेंगे तो आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। कठिनाई के बारे में आप विचार कर रहे हैं इसलिए

(श्री अध्यक्ष)

यह कठिनाई दिखाई देती है। कठिनाई नहीं आयेगी, माननीय सदस्य। कल भी आपका यह एतराज था लेकिन कल भी कोई कठिनाई नहीं आयी इसलिए जो तरीका हमने तय किया है उसी तरीके से अपन करें।

**श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल):** पहले-10 में से 6 कांग्रेस आई के हैं वह गलत बता गये। ये सदन को गुमराह करने वाले हैं।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):** अध्यक्ष महोदय, कटमोशन देना तो इण्डिविजुअल का राइट है, इसमें दल का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम शिक्षा पर बोलना चाहें और किसी दूसरे विषय पर बोलने चाहें।

**श्री अध्यक्ष:** ऐसा कोई माननीय सदस्य, कायदा नहीं है कि आपने कोई कट मोशन रख दिया और दूसरे माननीय सदस्य की ओर से रखा नहीं तो वे आपके कटमोशन पर बोले ही नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है। यह नहीं कि जो आपने कह दिया दूसरे ने कहा ही नहीं तो सदन उसको खारिज कर देगा, सदन का ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं। सिद्धान्त यह है कि वह उस विषय को इन्ट्रोड्यूस कर सकते है, कट मोशन का सारा मतलब इतना है लेकिन सदन को अधिकार है वाद-विवाद अथवा चर्चा करने का। बिना चर्चा किये एक पक्ष से कटौती प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव जो रखे गये, उसमें दूसरों को कोई वाद विवाद या चर्चा का अधिकार न हो, ऐसा नहीं है। यह भी बात कही गयी थी कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं क्या वे बोल सकते हैं? बेशक वे भी बोल सकते है, मान लीजिए उसमें बहुत गलत हो तो दूसरे माननीय सदस्य उस गलती की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकेंगे। बराबर करेंगे।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी):** अध्यक्ष महोदय, मामला ऐसा नहीं है, मामला यह है कि माननीय सदस्य जो तारांकित प्रश्न देते हैं तो उनको क्रम से रखते हैं या बीच में ही काट देते है।

**श्री अध्यक्ष:** थोड़ा आप धीरे से बोलिये।

**श्री रामसिंह विश्नोई:** मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य जो यहां पर तारांकित प्रश्न रखते हैं उसको आप नम्बर से बोलते है जैसे नं. 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। उसके बाद अध्यक्ष पुकारते हैं नाम। क्या मुख्य सचेतक को अधिकार है कि उसमें चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा हो सकता है कि वे ऐसा कर सकें तो हमारा भी सुझाव है उसको भी ध्यान में रखें। दूसरे जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं उनको पता होता है कि मेरा नाम अमुक स्थान पर आयेगा तो वह उसी हिसाब से बाहर जो उनके मिलने वाले वाले आते हैं, समर्थक आते हैं उनसे मिलने जाते हैं चाय पीने भी जाते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं लेकिन जो हमारे मुख्य सचेतक महोदय हैं, वे नाम दे देते है, मालूम रहता नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

मैं खिलाफ बोला, इतना ही मेरा अपराध है। कटौती प्रस्ताव जो दिये हैं बिलकुल उसी के हिसाब से डिबेट होनी चाहिये। उसमें किसी को एतराज नहीं है जिन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं बोलने का अधिकार है। वे बोलें, उसमें कोई बात नहीं है लेकिन जिन माननीय सदस्यों के क्रम संख्या में नाम दिये है वह सही हैं। मैं समझता हूं कि मेरी मन्शा क्या है यह आप समझ गये हैं। आप बिलकुल क्रमवाइज ही चले यही उचित रहेगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री महावीर प्रसाद।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : (टोंक) माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्य सचेतक महोदय सचेत न हों तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पहले दिये हैं उनको अवसर पहले मिलना चाहिए यदि माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं दिया, उनको भी बोलने का अवसर देना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दें लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जो जागरूक हैं और जिन्होंने पहले कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिए। किसी कारण से मुख्य सचेतक महोदय सचेत न हों तो उनके अधिकारों की रक्षा आप करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी,...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कठिनाई बतायी कि क्रम से नाम नहीं पुकारने से हम किसी अन्य कार्य में लगे होते हैं जिस वक्त हमारा नाम पुकारा जायगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि किस वक्त हमारा नाम आयेगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आपको किसी प्रकार को कठिनाई हो कहीं कोई कठिनाई हो तो समय की हमको सूचना दे सकते हैं कि इतने बजे हम बोलना चाहते हैं तो 2-4 मिनट इधर उधर करके हम ऐडजस्ट करके अवसर दे देंगे। यह नहीं कि आप गैरहाजिर है हमने नाम आपका पुकार लिया आप उस वक्त उपस्थित नहीं थे और फिर आप कहे कि अवसर नहीं दिया, यह बात नहीं है। लेकिन आप जो फर्मा रहे हैं कि जिस क्रम में कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसी क्रम में पुकारा जाय तो मैं समझता हूं यह सम्भव नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां है, इसमें कई तरीके की कठिनाइयां आ जायेगी। यह जो तरीका हमने अपनाया है काफी लम्बे अनुभव के बाद में अपनाया है और काफी लम्बे समय से यह चल रहा है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं वह सदन के सामने प्रस्तुत हुए समझे जायं। उसके बाद में उन तमाम विषयों के ऊपर जो कोई भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, जो कहना चाहें वे कह सकते हैं। मै समझता हूं कि यह सही तरीका है डिबेट का। इसमें एक इधर का बोले, एक इधर का बोले। माननीय सदस्य को कहीं कार्यवश जाना हो तो वे हमें सूचना दे दें, हम इसमें जल्दी बोलना चाहते है, अवसर हम दे देंगे। इससे अधिक मैं समझता हूं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है

(श्री अध्यक्ष)

जो आप तरीका फर्मा रहे हैं, काफी लम्बे समय के बाद यह नयी प्रणाली है, यह अपनाई गयी है और काफी लम्बे समय से यह प्रणाली चल रही है। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वाद विवाद की चर्चा को पुनः प्रारम्भ किया जाय और कहीं भी कोई कठिनाई आये आपको, जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनको कोई कठिनाई आये तो आसन का ध्यान आप उसी वक्त आकर्षित कर सकते हैं। आपको सुविधा प्रदान की जायेगी अधिक से अधिक सदन में वाद विवाद अथवा चर्चा के अन्दर, इसका ध्यान रखा जावेगा।

श्री माधवसिंह दीवान : हमारी बारी 3 बजे आयेगी या रात को 10 बजे आयेगी, कौन से क्रम में है, कब आयेगी हमको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम 3 बजे से 10 बजे तक यहां बैठे रहें पता नहीं क्रम में तीसरा नम्बर है या दसवां नम्बर है अथवा पांच सौवां नम्बर पर है। इसलिए आप सूची पढ़कर सुना दें।

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि आप सूची पढ़ कर सुना देंगे तो माननीय सदस्य अपने अपने कामों से सदन से बाहर चले जायेंगे और सदन में कोरम भी नहीं रहेगा, इसलिए सूची पढ़ी नहीं जाय। नाम आ जायेगा और जो बोलना चाहें वे बोलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): एक बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री राम रघुनाथ चौधरी ने पहले प्रस्ताव दिया है, कटौती प्रस्ताव। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहला मौका उन्हीं को दें। उनकी जागरूकता के अनुसार।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अगर आप यह कहते हैं तो पहला नम्बर मेरा है मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं अनुशासन के अन्दर हूं चूंकि मै आसन के ऊपर था नाम होते हुए भी मैंने इनको काल किया, आपकी दल की तरफ से कोई सूची नहीं थी। इन बातों को कहना चाहता तो कह सकता था। मैंने कर लिया है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस समय असमर्थ थे।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनकी पार्टी को तो हां में हां करनी है। उनके बोलने या न बोलने का तो महत्व ही नहीं है इसलिए विपक्ष के सदस्यों को ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह जी उस समय बोलने में असमर्थ थे क्योंकि वे अपने स्थान पर नहीं थे। उनके

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बाद मेरा नाम पहले था। इसलिए वाद-विवाद और कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य का नाम पहले है। मगर उनका नाम पुकारा जाय और वे चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, छः सात माननीय सदस्यों की यह पार्टी है और सबसे ज्यादा समय चाहते हैं। आप सोचिये कि हमारी 134 सदस्यों की पार्टी है और उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो अपना समय चाहता हूं। मुख्य सचेतक महोदय से मेहरबानी नहीं मांगी है।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर... आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय देवपुराजी का नाम पहले पुकार लिया था इसलिए अब मैं पहले नहीं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मदेरणा साहब कुछ कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह सब मान्य व्यवस्था है लोक सभा में और राज्य सभा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी चली आ रही है और खास तौर से माननीय सदस्य जो कोटा से आ रहे हैं इसलिए पिछले...

श्री अध्यक्ष: लूणी से।

श्री परसराम मदेरणा : आपको लूणी वालों की गलतफहमी हो रही है, मुझे कोटा वालों की हो रही है।

मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले तीन सालों में यहां पर जो गलत तरीके की प्रक्रिया स्थापित की गई, वह प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही थी। इस प्रक्रिया को बदल कर जैसा कि आप चाहते हैं, वह प्रक्रिया इसलिए लाई गई कि आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं था और अनुशासन नहीं होने से जो पहले बोलते थे वही बाद में भी बोलते रहे। एक दफा मैं लीडर आफ अपोजिशन था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि हम संख्या के अनुसार समय देंगे और उस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने भी यह तय किया। मैंने तीन आदमियों के बोलने के लिए नाम दिए, आपने अवसर नहीं दिया और दूसरे ही बोलते रहे। दूसरे दिन हमने जिस तरह से नाम दिए उसके अनुसार चलता रहा। क्रम से चलते रहे तो क्रम से चलना यह कोई जागरुकता नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से यह याद है कि पहले दिन डिमाण्ड आई थी, तो आप कुम्भकरण की नींद में सोये हुए थे। आपके तीन आदमियों ने कटौती प्रस्ताव दिये थे। फिर आपने रातों रात स्कूल खोल दिए और दिन भर में नाम भर दिए। यह कोई जागरुकता का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या...

(78)



(श्री परसराम मदेरणा)

में लोग बोल सकें और पार्टीसिपेट कर सकें, पहले यह व्यवस्था थी और जिसने कट मोशन मूव नहीं किये हैं तो भी आसन के द्वारा समय समय पर बोलने की अनुमति दी जाती रही है, कट मोशन और मांगों के विवाद के समय जो कुछ भी व्यवस्था तय की गई है उसमें अच्छी डिबेट हो सकेगी। पहले से मेरा नाम दे दिया पहले से तैयार रहने हैं कि ज्यों ही बजट भाषण हुआ कि नाम दे दिए; दूसरे दिन लेट भी आए या जो भी आज पहले बोल चुके हैं दूसरे दिन उनको समय नहीं दे करके उनको ही समय देना यह उचित नहीं है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है उस पार्टी में सभी लोगों के नाम दिए हुए हैं, वही लोग बोलेंगे। कुछ लोग आज बोल लें तो कुछ लोग बाद में बोल लें। चतुर्वेदीजी चूंकि आप शिक्षा मंत्री रह चुके है और पहले का अनुभव भी ज्यादा रहा है। कटौती के जितने भी प्रस्ताव हैं वह जिस वक्त आपकी बारी आएगी, सभा में आपके ज्ञान का अनुभव डिबेट में निश्चित रूप से सदन को मिलेगा। जो व्यवस्था दी गई है, वह व्यवस्था ठीक है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिल जायगा अपने विचार रखने का कटौती प्रस्तावों के जरिये।

## मांग संख्या 24 पर विचार

**श्री अध्यक्ष** : हीरालाल देवपुरा।

**श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांग के ऊपर विवाद हो रहा है। मैं शिक्षा नीति के सम्बन्ध में इस सदन में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन की बात काफी लम्बे अर्से से हम करते आए हैं। लेकिन कोई ठोस कदम, ठोस परिणाम हम उसमें नहीं ला पाए। आजादी के पहले शिक्षा के बारे में यह कहा जाता रहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो शिक्षा दी जाती है वह केवल बाबू पैदा करने के लिए शिक्षा दी जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यदि कहूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमने कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की लेकिन परिणाम अभी तक वही सामने आया है कि चाहे हमने उच्च स्तर की शिक्षा दी हो चाहे मध्यम स्तर की शिक्षा दी हो और चाहें वह प्रारम्भिक या सैकण्डरी शिक्षा प्राप्त करायी हो, आज भी स्थिति यही है कि आम तौर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वही नोकरी की ओर मुंह देखता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज जो शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है उस शिक्षा प्रणाली के अन्दर हम इस बात को प्रस्तुत कर सकेंगे कि हमारी शिक्षा आज इस दृष्टि से हो सके या देश के अन्दर बेरोजगारी फैली है इस बेरोजगारी को हम कम कर सकें। क्या हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो सकी है कि जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने आप स्वतः अपने पांवों पर खड़ा हो सके और अपनी जीविकोपार्जन के लिए और किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। अपने आप को बेरोजगारों की लिस्ट में, बेरोजगारों की सूची में शामिल नहीं करें, आज यह सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से केवल हायर, उच्च शिक्षा हम एक प्रकार की कर दें, उससे तो हम विद्वान पैदा कर दें, वैज्ञानिक पैदा कर दें, उसी से काम चलने वाला नहीं है। इस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दृष्टि से अगर हम नीचे से प्रारम्भ करें, जहां से प्रारम्भिक शिक्षा चालू होती है वहीं से हमें शुरुआत करनी होगी, वही से हमें देखना होगा कि जो शिक्षा देना चाहते हैं वह किस ओर ले जाना चाहते हैं। हम देश में किस प्रकार के नागरिक पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए प्राइमरी एजूकेशन पर, प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये। वह ध्यान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक नहीं दिया गया है। कहा जा सकेगा कि देश में तीस वर्षों तक शासन रहा, उन्होंने क्या किया ? हम इसको कबूल करते हैं कि हम कुछ करना चाहते थे लेकिन जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। लेकिन बीच में जो तीन साल का, 28 महीनों का शासन जनता पार्टी का आया है उस जनता पार्टी के शासन में शिक्षा विभाग को एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। शिक्षा प्रणाली की और संस्कृति की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करने वाले और यह चर्चा करते हुए कि हम संस्कृति को आगे बढाना चाहते हैं वे सस्कृति को तो भूल गए, लेकिन इस शिक्षा विभाग के माध्यम से उन्होंने अपना राजनैतिक दृष्टिकोण, अपना राजनैतिक ध्येय पुरा करने का रखा। शिक्षा जगत में शिक्षा के अंदर और खास तौर से हमारी प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूलों की जहां पर हम नींव डालते है जहां पर कि हम नागरिक बनाने की तैयारी करते हैं, प्रारम्भ करते हैं, वहीं से उन्होंने उसको राजनैतिक दृष्टि से उस हिसाब से शिक्षकों की भर्ती प्रारम्भ की और उस शिक्षा को जो गति हम देना चाहते थे उनसे आगे बढ़ाना चाहते थे, उसके अन्दर बहुत बड़ा फर्क पैदा किया, बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर दी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षण संस्थाओं के अन्दर नौकरी करने के लिए कौन व्यक्ति आ रहे हैं। ये चारों तरफ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी कोशिश कर लेते हैं कि हमें कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाय, दूसरे महकमों में नौकरी मिल जाय और भटकते भटकते जब थक जाते हैं, दूसरा उपाय मिलता नहीं, तब शिक्षा विभाग के अन्दर चले आते हैं क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमें प्राइमरी स्कूलों में सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत होती है, वहां पर जाकर शरण लेते हैं। वहां जा करके अध्यापक के रूप में आपके सामने आते हैं। इससे अन्दाजा लग जायगा कि आज शिक्षा के प्रति क्या हमारा दृष्टिकोण है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्राइमरी एज्यूकेशन जो अध्यापक आते हैं वे काफी ट्रेंड और इस दृष्टि से हायर शिक्षा प्राप्त अध्यापक हों, ताकि जो हम शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, वहां पर मैट्रिक, एस. टी. सी. ट्रेंड व्यक्ति को लेते हैं जो लोयेस्ट लेवल उसका रखना चाहते हैं, लेकिन जो अपने आप में खुद परिपक्व नहीं हो पाया .....

उससे अपेक्षा करते है कि छोटे से बच्चे को वह तैयार करेगा, उसको अच्छा नागरिक अच्छा विद्यार्थी तैयार करके भेजेगा। यह अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती है। प्राइमरी शिक्षा के अन्दर आपको सोचना होगा, कि वहां पर जो शिक्षक रखें वह शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त हो। खास तौर पर बच्चों को किस प्रकार का शिक्षण देना है, किस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रकार से लोगों को मोल्ड करना है। आप एक कच्ची टहनी को मोड़ करके शेप देना चाहते हैं तो आप दे पायेंगे, लेकिन टहनी मजबूत हो जाती है, उस वक्त शेप देना चाहते हैं तो नहीं दे सकेंगे। इसलिए वहीं से प्रारम्भ करना पड़ेगा, वहां किस प्रकार के टीचर हों। इस सम्बन्ध में आपको सोच कर, तय करके एक नया प्लान करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं आज यहां पद्धति चल रही है या नहीं चल रही है। कांग्रेस राज के वक्त में कुछ प्राइमरी स्कूल्स को हमने इस प्रकार प्रारम्भ किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको हमने शहरों तक सीमित रखा. प्राइमरी स्कूल में जो सैकेण्डरी स्कूल के हैडमास्टर थे, उनको इन्चार्ज बनाकर के उन प्राइमरी स्कूलों को चलाना प्रारम्भ किया था, लेकिन वह शहरों के अन्दर ही किया गया था। मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इसको दुबारा देखें। यह चीज शहरों तक सीमित न रखें कर गांवों तक पहुंचायें। और इसमें कामयाब होते हैं; और वह अच्छे परिणाम देने वाली पद्धति लगती है, उसके आधार पर इन स्कूलों को प्रारम्भ करना शुरू कर दिया जाये।

दूसरी बात मैं प्राइमरी शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हमारा प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है। और सही भी है; आंकड़े बताते हैं। पर्सेन्टेज के अन्दर हम बहुत नीचे हैं। यहां सदन के अन्दर चर्चा में एक बार आया बच्चियों की शिक्षा पूरी नहीं देने के कारण हमारा यह पर्सेन्टेज नीचा हो जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिये, बालिकाओं की शिक्षा के लिये, जितना ध्यान ग्राम समाज का जाना चाहिये था वह ध्यान नहीं जा पाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि यहां हमने कोशिश की है काफी प्राथमिक स्कूल गांवों में खोल दिये, लेकिन बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिये था, वह नहीं मिलता है। अभी जागरूकता नहीं आ पायी है हर किसान, हर आदिवासी, छोटे छोटे व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल के अन्दर पढ़ने के लिये भेजें। वह नहीं भेज पा रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है, दूसरी कठिनाई हो सकती है। यह सब बातें अनुभव के आधार पर देखते हैं। तो हमें सोचना होगा कि किस मिनिमम स्टेज को लेकर हम चलते हैं कि कम से कम हमारा नागरिक इतना शिक्षित हो। आज सैकण्डरी की बात कहूंगा तो शायद वह बहुत दूर जाने की बात हो जायेगी। लेकिन कम से कम प्राइमरी शिक्षण तक तो यह मानें कि कम्पलसरी एज्यूकेशन रखें। उसको स्वीकार करके, निर्णय लेकर, हमको आगे चलाना चाहिये। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हमारा देश, हमारा राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से दूसरे प्रान्तों से हमेशा-हमेशा के लिये पिछड़ता चला जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक किसान एक आदिवासी का बच्चा अगर पांचवी पढ़ जाता है तो उसके मन में जागृति आयेगी कि उसको पांचवी तक पढ़ाया है तो आगे क्यों नहीं पढ़ाया जाये। अपने आप वह प्रयत्न करेगा। पांचवी तक हमारा प्राइमरी शिक्षण है, उसको हम कम्पलसरी करेंगे, यह हमको निर्णय लेना चाहिये।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है, हमारे देश में गरीबी है। आदिवासी इलाके पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हमारे आदिवासियों के अलावा हमारे कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत दबे हुए हैं, उनके सामने समस्याएं हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये। उस संबंध में मैं, निवेदन करना चाहता हूं, हमने कुछ फैसले किये हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, बालिकाओं के लिये, कुछ फैसले हमारे किये हुए हैं, हम उनको कुछ सुविधाएं देते हैं, पुस्तकों के रूप में देते हैं स्कालरशिप के रूप में देते हैं। या किसी और रूप में देते हैं। लेकिन मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक मापदंड आर्थिक दृष्टि से बनायें कि हम किसको आर्थिक दृष्टि से गरीब के रूप में लेते हैं, गरीब की श्रेणी में लेते हैं। निश्चित स्थायीपन देकर उसके बालक को दस रुपया दीजिये, इससे शुरू कीजिये कि तुम अपने बालक को स्कूल में भेजते हो तो उसके लिए 10 रुपया प्रतिमाह हम देंगे। सरकार की ओर से दिया जायेगा। इसकी शुरूआत करके हमें शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये, अगर यह नहीं करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि पहले ही बहुत पीछे हैं और पीछे रह जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से प्राइमरी एजूकेशन को स्ट्रेन्दन करें, प्राइमरी एजूकेशन के उपर हम ज्यादा ध्यान दें। तो आगे की शिक्षा हमारी उस दृष्टि से बनती चली जायेगी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा की दृष्टि से प्राईमरी एजूकेशन, सैकण्डरी एजूकेशन, हायर सैकण्डरी, और हायर एजूकेशन में, आज तक हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि मिनिमम स्टेंडर्ड निकालें सैकण्डरी हायर सैकण्ड्री पर निकालें तो वह कम से कम अपने आपको इस बूते पर पाये कि वह जीवन में कुछ काम कर सकता है, जिससे वह आगे बढ़ सके? हमारी शिक्षा जॉब ओरियेन्टेड शिक्षा होनी चहिये। वह शिक्षा हमने किसी जमाने में शुरू की थी, उस दृष्टि से पुन: की जाये, हम प्रारम्भ से एक बालक को अक्षर ज्ञान देने के लिये तैयारी करवाते हैं, आज बिना अक्षर ज्ञान प्राप्त किये भी, आज ट्रेडिशनल दृष्टि से लोग कुछ काम करते है। गांवों के अन्दर, अक्षर ज्ञान नहीं होते हुए भी वह बालक अपने ट्रेडिशनल काम को सीखकर आगे बढ़ सकता है, क्या वह स्कूल के अन्दर अक्षर ज्ञान के साथ साथ जो गांव का रहने वाला है, गांव में काम करता है जिसको, उसकी टेन्डेंसी, उसका झुकाव हो उसके झुकाव के आधार पर उसके काम को शिक्षा हम अपने अक्षरज्ञान के साथ साथ प्रारम्भ करदें। इस तरह तैयार करके बालक को निकालें। आज यह दुविधा रहती है, कि एक किसान का लड़का अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके पास काफी जमीन है, बहुत बड़ा फार्म हो सकता है, जिसमें खेती करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है, लेकिन अगर वह लड़का, बी. एस.सी. एग्रीकल्चर हो गया, वह ग्रेजुएट हो गया, उसका फार्म अच्छा होते हुए भी उसकी यह टेन्डेंसी नहीं रहेगी कि वह अपने पिता के साथ खेत में काम करें। उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे अब हल नहीं चलाना है। मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कहीं न कहीं एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट बनना चाहिये, मुझे दूसरी नौकरी तलाश करनी चाहिये। एक तरफ हमने उसको शिक्षा दी एग्रीकल्चर की इस दृष्टि से कि देश के अन्दर खेती करके उत्पादन बढ़ाने में सहायक बनेगा, दूसरी तरफ किसान उम्मीद करता है कि यह लड़का, मेरा बहुत बड़ा फार्म है, उस पर काम करेगा। फार्म पर उसकी जो पैदावार होती है, उसको जितना सहयोग मिलना चाहिये था, वह नहीं मिलता है। गांव के अन्दर एक लुहार का लड़का मैट्रिक पास करके निकलता है, वह अध्यापक या पटवारी बनने की कोशिश करता है। उसका पिता जो लुहारी का काम करता था, उसका जो ट्रेडिशनल धन्धा है, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं निवेदन करूं गांवों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जॉब्स को जोड़ दिया जाये तो निश्चित रूप से हमारे गांव के लोगों की जो टेंडेंसी बनी हुई है, शहरों की तरफ देखने की, नौकरी पर जाने की टेन्डेंसी बनी हुई है, वह उनसे दूर हटेंगें, गांवों में रहने लगेंगे, और गांवों की इकोनोमी बढ़ेगी। और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। गांवों में शिक्षा ने क्या किया। आपके शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई भी सरकार इस स्थिति में नहीं हो सकती है कि जितने भी शिक्षित निकलें, उनको नौकरी दी जाये। इसलिये इस दृष्टि से भी यह जरूरी है। हम उनको इस तरह से रि-ओरियेन्टेड करें, इस तरह से शिक्षा को प्रारम्भ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हायर स्टेडीज के लिए हम चैक लगादें। आज हो गया है कि मैट्रिक पास, हायर सैकण्डरी पास हर व्यक्ति को छूट है चाहे वह किसी भी श्रेणी से पास हुआ हो कि वह हायर स्टेडीज में आ जाये। मैं उसके अन्दर रुकावट पैदा नहीं करना चाहता हूं, हर व्यक्ति को आजादी है, वह आगे आये, आगे बढ़े, लेकिन उसका रुझान देखना होगा, किस तरह की उसकी टेंडेंसी है, क्या वह साइंस स्टूडेंट बन सकता है, क्या वह कामर्स स्टूडेन्ट बन सकता है या उसको किसी स्तर पर लाकर के किसी और दूसरे धन्धे की शुरूआत कर देनी चाहिये, तो एक चैक ऐसा बीच में आना चाहिये, जिससे कि एक स्टेज पर आकर, हायर सैकण्डरी की स्टेजपर आकर के कुछ चैक लगा सकें, कि किस व्यक्ति को, किस दृष्टि से किस तरह से किन विषयों के अन्दर जाना चाहिये। इस दृष्टि से भी हमने चैक किया और यहीं पर लोगों को अलग-अलग डालना शुरू किया, तो निश्चित रूप से हायर एजूकेशन के अन्दर आगे जाकर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर चैक लगेगा। और लोगों अपने रुचि के हिसाब से शिक्षा की दृष्टि से बढ़ते हुए चले जायेंगे आज इन जॉब्स के बारे में हमारे जो अपने खयालात बने हुए हैं, यह काम निम्न श्रेणी का है इस तरह से ये जो तीन श्रेणियां हैं इन तीनों ही चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा इस दृष्टि से हमें इस बात को चलाना होगा और सरटेन चैक्स लगा कर इसमें डायरेक्शन दें और सुधार करवावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हायर एजूकेशन के लिए, आप घन्टी बजा रहे हैं, मैं अपनी बात को संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आज हमारी हायर एजूकेशन, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की बात करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटीज आटोनोमस हैं लेकिन आटोनोमस का यह मतलब कदापि नहीं होना चाहिये कि वे हर तरह से स्वच्छंद है जो चाहें करें। पालिसी डिसीजन में गवर्नमेंट को भी से (Say) होना चाहिये। वह नहीं होता है और आज यूनिवर्सिटीज में किस तरह का पॉलिटिक्स का वातावरण है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यूनिवर्सिटीज आटोनामस जरूर है लेकिन वे चलती किसके द्वारा है? कितनी उनको यू. जी. सी. से सहायता मिलती है और कितनी गवर्नमेंट से मिलती है वह देख लें सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट से आता है। जब गवर्नमेंट सर्वेन्ट पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते, उन पर रोक है पॉलिटिकल पार्टीज में भाग नहीं ले सकते तो यही रोक यूनिवर्सिटीज पर भी होनी चाहिये। जो यूनिवर्सिटीज में शिक्षा लेने आते हैं वे पॉलिटिकल पार्टीज में हड़ताल और झगड़े हमको देखने को मिलते हैं। तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर देखें और यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल पार्टीज के भाग लेने के विरुद्ध कदम उठावें। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं यूनिवर्सिटीज के अलावा भी जितनी भी एडेड संस्थाएं हैं, जिनको 80-90 प्रतिशत एंड मिलती है उन सब के ऊपर प्रतिबन्ध लगाइये कि वे पालिटिकल पार्टीज से दूर रहें और केवल शिक्षण का काम करें शिक्षा देकर अच्छे नागरिक तैयार करें ताकि जिस ओर देश को ले जाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं, उसमें सहयोगी बन सकें तब तो शिक्षा की दृष्टि से कुछ कर पायेंगे अच्छे नागरिक बना पायेंगे और देश को सुचारू रूप से चलाने में सफल हो सकेंगे।

ये सुझाव अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने दिये। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से हमारे शिक्षा मन्त्री जी, राज्य सरकार सोच कर शिक्षा की नीति में परिवर्तन करने की सोचेगी। आमूल चूल परिवर्तन की बात बहुत कही गई। आमूल चूल न करके प्रारम्भिक परिवर्तन करना है। इस दृष्टि से कुछ करें तो बहुत कुछ लाभ होगा।

धन्यवाद

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनलाल शर्मा।

**श्री मोहनलाल शर्मा** (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, नागरिक शिक्षा और स्कूल कॉलेज खोलना आदि बहुत क्षेत्र आते हैं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ इलाका है और शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत पिछड़ा है इसलिए हमारे राजस्थान में जितने स्कूल, विद्यार्थी होने चाहिये वे नहीं हैं। जितने हमारे विद्यार्थी और लोग शिक्षित होने चाहिए वे नहीं हैं जितनी महिलाएं हमारे क्षेत्र में शिक्षित होनी चाहिये वह नहीं है, इससे हमारे समाज पर और देश में उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है। इसलिए हमारा राजस्थान मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है।

मेरा निवेदन यह भी है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो घोषणा की गई है सरकार द्वारा कि 600 प्राथमिक विद्यालय

(84)



( श्री मोहनलाल शर्मा )

खोले जायेंगे। तो हमने यह आशा की थी कि पिछली जनता सरकार ने पहली बार में 1192 स्कूल खोले थे और दूसरी बार में 1089 स्कूल खोले थे और इस बार यह उम्मीद की जाती थी कि यह सरकार इस प्रकार से स्वस्थ परम्परा की होड़ में आकर कम से कम दो हजार स्कूल खोलेगी या जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विश्वास दिलाया गया था कि हम प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के लिए वचन-बद्ध हैं लेकिन जो प्रोविजन रखा है, उससे तो यही मालूम होता है कि 600 गांवों या शहरों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 600 जगहों पर ही प्राथमिक स्कूल खोल सकेंगे। राजस्थान में 33 हजार गांव हैं और इस तरह से हम तो उम्मीद करके चले थे कि इस बार सरकार सारे ही राजस्थान में जितने भी गांव हैं उन सभी में प्राथमिक स्कूल खोलेगी जिस प्रकार से पिछली जनता सरकार ने नींव डाली थी कि 400 से दो हजार और 3 हजार की आबादी वाले गांवों में क्रमशः प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जायेंगे और इस तरह से उन्होंने अपनी नीति का पालन भी किया। इसलिये इस बार यह उम्मीद की जाती थी कि जो बाकी आबादी के 400 से नीचे के जो गांव हैं उन सब में प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सरकार असफल रहेगी। यह मेरा पूरा विश्वास है। उचित तो यह होता कि यह सरकार, कांग्रेस सरकार जो 30 वर्षों से शासन करती रही है, बहुत अनुभव के आधार पर और जनतापार्टी की होड़ के अन्दर हर गांव में स्कूल खोल करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे होती लेकिन इससे निराशा ही हुई है। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी जो विश्वास दिलाया था उससे भी निराशा हुई है।

मैं अब थोड़ा सा मेरे क्षेत्र के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे यहां सरदार-शहर क्षेत्र में गांधी विद्या मन्दिर नाम की संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी हुई है। गांधी विद्या मन्दिर ने करीब पांच साल पहले एक योजना दी थी कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये जिससे बेरोजगारी न हो, युवक बेरोजगार न रहें और शिक्षा के साथ साथ उद्योग धन्धा सामान बनाना या किसी तरह से ऐसी शिक्षा दी जावे जिससे कि नवयुवकों को शिक्षित होते ही या तो सर्विस मिले या न मिले तो इण्डस्ट्री में चला जाय या व्यापार, उद्योग धन्धा शुरू कर दें। लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार से परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में किया जाय, इसके लिये एक समिति बनाई जाय जो जैसा उचित समझे निर्णय करें कम से कम ऐसी शिक्षा दी जाय कि शिक्षित होते ही या कालेज से निकलते ही जो विद्यार्थी हैं वे नौकरी की तरफ न जाकर काम पर लग जायं अगर मिले तो ठीक है वर्ना काम कर लें तो बेरोजगारी मिट सकती है। तो शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये सरकार योजना बनाये और इस प्रकार से शिक्षा दी जाय।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका बहुत अच्छा शिक्षा का क्षेत्र है, लोगों को पढ़ाती आई हैं, शिक्षा में फायदा भी होता है लेकिन बहुत सी ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि बिजनेस करती हैं, धन्धा, व्यापार करती

(श्री मोहनलाल शर्मा)

है। तो एक इस प्रकार की समिति बनाई जाकर राजस्थान में सर्वेक्षण कराया जाय। जो शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार का धन्धा करती हैं उनको बन्द किया जाय और यह जो सही तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं उनको और योगदान दिया जाकर सरकार बढ़ावा दे जिससे लोगों को लाभ हो और सही शिक्षा मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि बजट में महिलाओं के लिये न तो कहीं गर्ल्स स्कूल का प्रावधान रखा है और न सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान रखा है। तो मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति उदार रवैया अपनाया जाना चाहिए। सरकार को उदार होकर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल महिलाओं के लिए खोलने की कोशिश करनी चाहिए।

राजस्थान में हमारे यहां पर एक और कमी है एक तो हाइ स्कूल की शिक्षा दी जाती और एक हायर सैकण्डरी की शिक्षा दी जाती है। मेरा निवेदन सरकार को यह है कि जहां सैकण्डरी स्कूल हैं वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिए जाएं। जहां पर हाइ स्कूल हैं, वहां पर बच्चों को पी.यू.सी. करनी पड़ती है और इससे विद्यार्थियों को प्रवेश में दिक्कत होती है। अच्छा तो यह है कि दस + दो, की शिक्षा व्यवस्था की जाए। फिर जैसा भी सरकार उचित समझे करे परन्तु कम से कम हाइ स्कूल जहां पर है वहां हायर सैकण्डरी स्कूल कर दें ताकि बच्चों को जो प्रवेश में दिक्कत आती है वह न हो। इस शिक्षा में भी फर्क है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था की जाए कि हायर सैकण्डरी स्कूल सभी जगह हों।

सरदारशहर में बी.ए. तक की शिक्षा की सुविधा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर एम. ए. की कक्षाएं भी खोली जाएं और जिन गांवों की जनसंख्या 400/300 है वहां पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं और जो गांव बाकी रह गये हैं वहां पर शीघ्र प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। कम से कम आपको एक नीति बनानी चाहिये कि इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। पहले जो नीति थी वह ठीक थी। कल मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि एम.एल.एज. जहां के लिए कहेंगे वहां पर खोले जाएंगे। वे जन प्रतिनिधि हैं इससे जनता का फायदा हो रहा है।

इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष : रतना राम**

(अनुपस्थित)

श्री नाना लाल।

(अनुपस्थित)

**श्री राम रघुनाथ।**

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे समय का कुछ ध्यान रखें। ज्यादा लम्बा न हो भाषण।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव है। अभी माननीय देवपुरा जी ने जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ने बहुत विस्तार से निवेदन किया है। इसलिए एक दो बिन्दु ही मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

(86)



( श्री राम रघुनाथ चौधरी )

राज्य सरकार को चाहिए कि प्रति गांव में प्राथमिक शाला हो और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चिलचिलाती धूप में एक किलोमीटर दो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यह उनके लिए सम्भव नहीं है। होता यह है कि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते और जब तक उनकी आयु 7-8 साल की नहीं होती वे अनपढ़ रहते हैं। जब वे उस अवस्था में पहुंचते हैं कि वे एक दो कोस पैदल चल सकें तब उनको शिक्षा मिल पाती है इसलिए निश्चित रूप से ही सरकार को चाहिए कि हर गांव में प्राथमिक शाला खोले। अगर यह सभव न हो तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो एडेड स्कूल चलते हैं उनको अनुदान देकर गांवों में प्राथमिक शालाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जब तक आप अपने तरीके से उस गांव में पाठशाला न खोल सकें। इस दिशा में जो ग्राम पंचायतें हैं वे पहल करें, इनिशिएटिव लेकर अपने-अपने गांवों में एडेड स्कूल खोल दें और जब तक आप आर्थिक स्थिति में न पहुंचे- प्राथमिक शाला खोल सकें तब तक इन एडेड स्कूलों को चालू रखा जाए ताकि गांवों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो प्राथमिक शालाएं खोली गई है वहां पर अध्यापकों की कमी है। आपने जो नियम बना रखे हैं वह यह है कि 40 बच्चों पर एक अध्यापक होगा और 80 विद्यार्थियों के बाद दो अध्यापक होंगे। 40/80 का यह प्रावधान आपने रखा है, यह जो सीमा रखी है उसके अनुसार एक स्कूल में पांचवीं कक्षा तक 70 विद्यार्थी है तो एक ही अध्यापक होगा। अध्यक्ष महोदय, आप विचार कर सकते हैं कि एक अध्यापक पांच कक्षाएं किस तरह से पढ़ा सकता है। एक-दो कक्षाएं तो वह पढ़ा सकता है परन्तु पांच-पांच कक्षाएं एक अध्यापक द्वारा पढ़ाना संभव नहीं है। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या उनको यह अधिकार नहीं है कि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग अध्यापक हों ताकि ग्रामीण जनता अपने बालकों को मेहनत करके पढ़ा सकें और उनका अच्छा भविष्य बना सके? यह जो 40/80 की सीमा रखी है उसको न रखें और अधिक से अधिक अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स को उपलब्ध करावें ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

एस. टी. सी. शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इन स्कूलों में एस.टी.सी. ट्रेन्ड अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए आपने जगह 2 स्कूल खोल रखे है। कई बार तो हम को एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक नहीं मिलते हैं और कई बार ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी नहीं मिलती है। कभी कम हो जाते हैं तो कभी अधिक हो जाते है। इनका कोई समन्वय नहीं है। कई बार अध्यापक उपलब्ध होते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि जो एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक हैं उनका एक पैनल बनाया जाए और उस पैनल के अनुसार उनको अपने आप नियुक्ति मिल जाय। अगर मान लें किसी अध्यापक ने एस. टी. सी. ट्रेनिंग ले ली उनको तत्काल नौकरी नहीं मिली और बाद में वह 28 साल का हो गया तो अधिक उम्र होने की वजह से वह सर्विस से वंचित रह जाता है। इसलिए उम्र का यह जो प्रति-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बन्ध है वह हटा देना चाहिए। जिसने एस. टी.सी. पास की है तो यह मान लेना चाहिए कि वह अध्यापक की नौकरी करना चाहता है। तो निश्चित तौर से उम्र ज्यादा है और जगह खाली है। जब पैनल में उसका नम्बर है और यदि वह 28 साल से ऊपर का हो गया तो भी उसको अवसर मिलना चाहिए ताकि उसकी बेरोजगारी दूर हो। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे कि पटवारी है, रोडवेज है, इनमें जितने स्थान उपलब्ध होते हैं उतनी ही ट्रेनिंग दी जाती है और इस प्रकार वह अपने आप नौकरी में आ जाता है। हो सकता है कि यह शिक्षा विभाग के लिए सम्भव न हो। आज एस. टी. सी. को भी एक शिक्षा मान लिया गया है परन्तु जो एस. टी. सी. की शिक्षा लेगा, यह मान कर चलना चाहिए कि वह अध्यापक ही होगा। इसलिए उसको अधिकार होना चाहिए कि कुछ समय बाद उसको नियुक्ति मिल जाए।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि उच्चतर माध्यमिक शालाएं बहुत दूरी पर हैं हर तीन किलोमीटर की दूरी पर ये शालाएं होनी चाहिए ताकि पांचवीं कक्षा पास करते ही बच्चों को छठी कक्षा की पढ़ाई के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। ये स्कूल्स बहुत दूर दूर है। छोटे बालक चार, पांच किलो मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इस लिए आप ऐसी व्यवस्था करें और ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखना है तो हर दो हजार की जनसंख्या पर एक माध्यमिक स्कूल खोलें। जैसा कि पिछली सरकार ने निर्णय लिया था हर चार सौ की जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा। लेकिन बाद में वे भी राजनीति में फंस गये और वे भी अपने बनाये हुए नियम के अनुसार नहीं चल सके। मैंने भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री महोदय को बताया था कि ये गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2000 से ज्यादा है फिर भी वहां पर शालायें नहीं खुली हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिना राजनीति में अटके बिना द्वेष भाव के प्राथमिकता के आधार पर पाठशालाएं, उच्चतर माध्यमिक शालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायं।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिडिल स्कूल में पी. टी. आई. नहीं हैं। चूंकि बुनियादी तौर पर बालक जब 8-9 साल की उम्र में आता है तो उस की खेल प्रवृत्ति बढ़ती है और कौन बालक अच्छा खेल सकता है उसके लिए आवश्यक है कि मिडिल स्कूल में पी.टी. आई हों। जो बच्चे खेलने में तेज हैं वे पी.टी. आई. के सहयोग से खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। इस लिए हर उच्चतर प्राथमिक शाला में पी.टी. आई. होनी चाहिए। जहां पर बालिका शालाएं हैं वहां पर भी पुरुष पी टी. आई लगा दिये गये हैं। उस वक्त महिला पी.टी. आई उपलब्ध नहीं होती थी परन्तु अब उपलब्ध हैं। इसलिए जहां तक सम्भव हो बालिका विद्यालय में पुरुष पी. टी. आई. न लगाकर महिला पी.टी.आई. को ही लगावें।

इसके साथ ही हाइ स्कूल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार उच्चतर प्राथमिक शाला तीन किलो मीटर की परिधि में हो उसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक शाला 5 किलो मीटर की परिधि में होना चाहिए। जब आप न कर सकें तो तो सब जगह पर छात्रावास की व्यवस्था करें ताकि वहां पर गरीब निर्धन बच्चे रह सकें। सात आठ मील तक स्कूल नहीं हैं। गांव में सड़कें नहीं हैं। बसें नहीं चलती हैं। इससे

( श्री राम रघुनाथ चौधरी )

बच्चे साइकिल से इतनी दूर आ जा नहीं सकते हैं। इसलिए सभी स्कूल्स के साथ छात्रावास होना चाहिये। पांच किलो मीटर की परिधि में स्कूल हो इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। अधिक नजदीक न खोल सकें तो कम से कम पांच किलो मीटर की परिधि में तो स्कूल खुल ही जाए।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी** : बहुत संक्षेप में, माननीय अध्यक्ष महोदय।

कमजोर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को दोपहर का भोजन और कपड़ा मुफ्त दिया जाते हैं। इसके साथ साथ पंचायत समितियां एक पोषाहार कार्यक्रम भी चलाती है। लेकिन दुख है कि वह 3-4 स्कूल्स के बीच में या 3-4 गांवों के बीच में एक गांव में चलता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बतायें कि खाने मात्र के लिए बच्चे 3-4 किलोमीटर जायेंगें और विशेषकर छुट्टियों में ? हर गांव में यह व्यवस्था कम से कम कर दी जानी चाहिए ....

**श्री अध्यक्ष** : खाना कैसा है यह उस पर निर्भर करेगा।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी** : खाना तो पेट के लिए है। अध्यक्ष महोदय, जो पेट में जाय, जो भूख को मिटा सके और स्वास्थ्य हैल्थ को बढ़ा सके। तो उस स्वास्थ्य-कर खाने के लिए बच्चा 3-4 किलोमीटर आयेगा और जायेगा। फिर उसको मिलेगा थोड़ा सा दलिया वह भी तेल में बना हुआ। वह भी जाने के बाद समय पर मिलेगा या नहीं, अध्यापक वहां पर होंगे या नहीं। इसलिए इस व्यवस्था को भी सुधारें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाह रहा था कि विश्वविद्यालय के संबंध में वैसे माननीय देवपुरा साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। परन्तु मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज विश्वविद्यालयों में जो असन्तोष व्याप्त हो रहा है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं इसके लिए कोई न कोई योजना बना कर के हमेशा हमेशा के लिए विद्यार्थियों के बीच में से हटाइये। मैं इस संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि जो मारपीट होती है वह इस लिए होती है कि उनके पास काम नहीं है, लड़के बहुत ज्यादा हैं पढ़ाई बहुत कम होती है। उनको कुछ न कुछ करने को चाहिए। यह तो उम्र ही ऐसी होती है इसलिए उन को आप डाईवर्ट करदें। उनके लिए आप एन. सी. सी. कम्पलसरी करें। गेम्स कम्पलसरी करदें और उनको डाइवर्ट करें। कोई लड़का बाल बाल बढ़ा कर आता है तो उसके लिए कोई नाट्यशाला की व्यवस्था करदें या संगीत की व्यवस्था करदें, पेंटिंग की व्यवस्था करदें ऐसी व्यवस्था करदें जो उसके लिए आवश्यक हो और जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सकें। जिससे कि उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से डाईवर्ट किया जा सके बजाय इसके कि वहां वह लड़ाई करे हड़तालें करें, अफसरों को घेरे आपको घेरे, यूनिवर्सिटी के अध्यापकों और चांसलरों को घेरें वे अपने काम में लग जायें ताकि उनकी शक्ति का सदुपयोग किया जा सके।

इसके साथ साथ मैं लेक्चरार्स के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो लेक्चरार एडहाक बेसिस पर रखा है उसका पी. एस. सी. 3-4 साल तक इन्टर-व्यू नहीं लेती है और फिर 3-4 साल बाद

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जब वह इन्टरव्यू लेती है तो उनको यह कह कर कि तुम्हारा सलेक्शन नहीं हुआ उसको हटा दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है इसलिए प्रतिवर्ष नहीं तो कम से कम हर दो वर्ष के बाद पी. एस. सी. के इन्टरव्यू होने चाहिए ताकि हां या ना की बात न चल सके।

इसके साथ ही मैं कुछ खेलकूद के बारे में मुख्यतः आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था। हमारे लिए खेलों का कितना महत्व है। अभी हाल ही में ओलम्पिक खेल हुए उनमें वर्षों बाद हमारी टीम जीती। उसको सबकी ओर से बधाई दी गई। हमारे इस सदन में भी उनको धन्यवाद और बधाई दी गयी। तो आप खुद सोच लीजिये कि हमें कितनी प्रसन्नता होती है फिर भी हम इतने महत्व की चीज को भी सिरयसली नहीं ले रहे हैं। इसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं? और इसके लिए यह आवश्यक है कि खेलकूद का अलग मंत्रालय होना चाहिए।

हमारे यहां क्रिकेट का बहुत महत्व है क्योंकि हिन्दुस्तान में हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है कि हम 3-4 दिन तक क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। जयपुर में जब क्रिकेट का मैच हुआ था तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था करदी कि जिसके पास सीजन टिकिट है यानि 3-4 दिन का टिकट है वह अपने आफिस रिण्टेण्डेंट से अपने अधिकारी से पूछकर टिकट दिखाकर क्रिकेट देखने जा सकता है। आपने क्रिकेट के लिए कितनी सुविधा दी। अंतिम दिन तो छुट्टी कर दी। बहुत अच्छी बात है करिये। क्योंकि हमारे पास बहुत समय है कि हम 4 दिन तक वहां बैठकर ही मनोरंजन करलें और होता क्या मैच में? आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं हैं कि मैच क्या है? एक महानुभाव से पूछा कि मैच देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कौन बढ़िया खेला तो उसने कहा कि आज तो मिड आन इतना बढ़िया खेला कि सारे के सारे रन ही उसने बनाये। उन साहब को यह पता नहीं कि मिडआन किसी आदमी का नाम नहीं किसी जगह का नाम है। क्रिकेट देखने वाले ऐसे ही हैं। रोज कमेंटरी आती है। सरकार खूब पैसा खर्च करती है। स्पोर्ट्स कौंसिल पैसा देती है। जरूर दीजिये लेकिन मेरा निवेदन यह है कि विकास अन्य खेलों का भी हो जो अन्य खेल हैं जो जनता के लिए हैं उनके लिये आवश्यक है जिसमें गरीब आदमी इन्वाल्व्ड रहता है। इसी तरह वह मनोरंजन करता है। हमारे यहां पर खेल जो होते हैं फुटबाल, हाकी, बास्केटबाल वालीबाल, कबड्डी, एथेलेटिक्स खेल है। ऐसा भी नहीं है कि इन खेलों में राजस्थान किसी से पीछे हो। ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन खेलों के लिये स्पोर्ट्स कौंसिल कर क्या रही है? मैं निवेदन करूं बस 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक फुटबाल मैच हो रहा था आयोजकों ने बहुत अच्छी टीमें बुलवायी थी बाहर से भी अध्यक्ष महोदय टीमें आ रही थीं। तो उन्होंने सोचा कि उसके लिए एक अच्छा अतिथि होना चाहिये। उन्होंने अतिथि के लिये कोई बड़े अफसर की महिला को इन्वाइट किया। वह महिला बहुत ज्यादा कार्य में व्यस्त होने के कारण समय पर वहां

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं पहुंच पायी । वहां पर आयोजकों ने सोचा कि हमारे मेहमान नहीं आये । जब मेहमान आकर के पहुंचा तो मेहमान ने आते ही कहा I am sorry, I am little late" आप लिटिल लेट क्या सारा टाइम निकल गया है अब तो आफ टाइम भी हो गया है । फिर पूछा उस महिला ने कि कोई गोल तो नहीं हुआ कोई पाइन्ट तो नहीं बना । आयोजकों ने कहा ऐसा तो नहीं हुआ । तो मैंने कोई मिस नहीं किया इतनी देर तो हो गयी । इस बातचीत में ही खेल भी खत्म हो गया । तो माननीय अध्यक्ष महोदय देखिये कि इन लोगों को यह पता नहीं है कि फुटबाल का गेम कितने समय का है उसमें एक क्षण कितना कीमती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं । एक एक क्षण के लिये लोग चिल्लाने लग जाते हैं । वह लोग समझते हैं जो वास्तव में खेल प्रेमी है जिनको क्रिकेट पसन्द नहीं है उन लोगों को घंटा आधा घंटा मिलता है और उसमें वे अपना मनोरंजन करते हैं बाकि में वे अपनी रोटी रोजी और कमाते हैं वे अपना पूरा दिन निकाल कर खेल देखने जा नहीं सकते हैं । अगर आप उनके लिये चाहते हैं कि वे अधिकाधिक मनोरंजन कर सकें तो उनके लिये, खिलाड़ियों के लिये यहां फुटबाल, हांकी के फील्ड बनायें जो अभी नहीं हैं । हमारे जयपुर में जो कैपीटल है, इस शहर में भी फुटबाल और हाकी का कोई फील्ड नहीं है । आपका जो स्टेडियम है वह तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिये बहुत अच्छा है । आपके सारे राजस्थान के मेहमान बैठ सकते हैं और जयपुर वाले भी जो देखना चाहते हैं, जाना चाहते है, वहां बैठ सकते हैं । वे जरूर जाते हैं और वहां अच्छा खासा खेल-कूद हो जाता है । लेकिन हांकी और फुटबाल के लिये एक विशेष तरह का मैदान होना चाहिये जिसमें देखने वाले न ज्यादा दूर हों और न ज्यादा पास हों । इसी तरह से इन्डोर स्टेडियम आपका अधूरा पड़ा है । जो ट्रेक आपका बना हुआ है वहां तो बालू मिट्टी और घास है । उसमें मेहनत करने वाले जो स्वत: मेहनत करने वाला आदमी है वह क्या करेगा ? कुछ भी नहीं कर सकता है । आप क्या सोचते हैं आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल ने या राज्य सरकार ने गोपाल सैनी और श्री राम सैनी जैसे एथलेटिक्स पैदा किये हैं? नहीं यह तो अपने आप मेहनत करके आगे बढ़े हैं । वर्ना होना तो यह चाहिये कि बालक जब 6 साल से 13 साल का हो और मिडिल स्कूल में पढ़ता हो तो उसकी ऊंचाई क्या है किस खेल के लिये किस तरह का खिलाड़ी चाहिये बल्कि आवश्यकता है कि यह जांच जाय कि उसकी पर ईयर ग्रोथ क्या है यह देखना चाहिये कि भगवान ने कुदरतन जो खेल के प्रति रुचि और गति दी है उसको किस तरह से निखार कर और अच्छा बनाया जा सकता है । राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां कि कुदरतन लोग अच्छे हृष्ट-पुष्ट नौजवान और बालक मौजूद हैं, अच्छे छांट कर उनकी कोचिंग की जानी चाहिये । पुलिस और फौज में आदमी 18 साल के बाद जाता है उसके बाद उनको छांट कर अलग अलग खेल के लिये खिलाड़ियों की टीम बनायी जाती है । फौज और पुलिस ने अच्छी अच्छी टीमें दी हैं । चाहे वह बी. एस.एफ. हो या राजस्थान पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो । उनमें अच्छे खिलाड़ी हुये हैं और अच्छी टीमें दी है । राजस्थान पुलिस ने भी बड़ा नाम किया है । आप सोचिये कि 18 साल के बाद एक नौजवान नौकरी करें-

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

दो तीन मिनट और। इसके बाद उम्र पकने लग जाती है उसकी फिर कोचिंग होती है और वह अपना प्रदर्शन दिखाता है। जब कि होना तो यह चाहिये कि 14-15 सालका बच्चा है उसको अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिये 20 साल का समय उसका सबसे अच्छा समय होता है। और 25 साल के बाद अच्छे से अच्छा खिलाड़ी रिटायर हो जाता है। अगर आप विदेशों की स्टडी करें तो पता चलेगा और शर्म आयेगी कि हमारी स्पोर्ट्स कौन्सिल क्या कर रही है, जब देखते हैं और सोचते हैं हम तो। अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यू. एस.ए. में क्रिकेट को कोई पसन्द नहीं करता है। वहां मुक्केबाजी लोग देखते हैं। एक मुक्केबाजी का मैच हो रहा था। यह एक ऐसा खेल होता है जो एक मिनट चलेगा दो मिनट चलेगा लोग 100 डालर 500 रुपये खर्च करके देखने आते हैं। वहां एक महानुभाव देखने आये और अपने पीछे बैठे एक व्यक्ति से बात करने लगे तो खेल खत्म हो गया और लोग बाहर निकल रहे थे। इतना रोमांचक होता है लोग 500-500 रुपये देकर भी देखते हैं। आप क्रिकेट को लेकर बैठे हैं राज्य सरकार और स्पोर्ट्स कौन्सिल सारा पैसा खर्च कर देती है। आफिसर वगैरह चीफ सैक्रेटरी तक उसके इन्तजाम में लग जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा डाइवर्शन करके अन्य जो खेल हैं जो हमारी जनता के मनोरंजन की प्रमुख आवश्यकता है उसकी ओर भी आप ध्यान दें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं राजस्थान खेल परिषद् को आप जिलों तक पहुंचायें। जिला परिषदें पहले हुआ करती थीं और आपकी राजस्थान खेल परिषद् उनको अनुदान भी देती थी। उसके आधार पर वे अलग अलग केन्द्रों में पैसा दिया करते थे। आपका बजट देखा है उसमें एक क्लब का नाम दिया हुआ है गांधी नगर क्लब। आपके राजस्थान भर में एक ही क्लब है जिसको आप पैसा दे रहे हैं और वह गांधी नगर क्लब कौन से खिलाड़ी पैदा करता है? कैसे खिलाड़ी आज तक निकाले गये है या निकाल रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर बजट बनाने वालों के दिमाग में एक नाम आ गया तो उस नाम का प्रार्थीजन कर दिया। राजस्थान में और कितने ही खिलाड़ी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप एक वालीबाल ले लीजिये। नागौर जिले में कितने खिलाड़ी हैं? कितना उन्होंने नाम कमाया है? कबड्डी मे कितना नाम कमाया है? भीलवाड़ा में कितने आदमी हैं। वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मेहनत को देख कर, उनके खेल को देख कर वहां के लोगों को यह महसूस हुआ कि हमें इन खिलाड़ियों की कुछ मदद करनी चाहिये इसलिए भीलवाड़ा में कुछ हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। नागौर की कबड्डी से सीखिये। भीलवाड़ा से सीखिये। राजस्थान में उन्होंने नाम कमाया है। आप फुटबाल की हालत देखिये।

**श्री अध्यक्ष :** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी :** राजस्थान की फुटबाल टीम पूरे देश में जाती है। दक्षिण में मगनसिंह जाता है तो उसके बड़े-

(९२ :



(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बड़े पोस्टर लगाये जाते हैं। जैसे कि फिल्म स्टारों के लगाते हैं। कलकत्ता में लग जाते है। वहां लोग तरसते हैं कि राजस्थान पुलिस की फुटबाल टीम कब आने वाली है क्या आपको यह पता है? राजस्थान में यूनियन का झगड़ा है। इसलिए लोग आंखें बन्द करके बैठ जाते हैं। आपको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट होना चाहिये। खेल की स्थिति क्या है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिये और विचार करना चाहिये। अभी मैं निवेदन करूं कि माउण्ट आबू में स्पोर्ट्स कौन्सिल की ओर से एक कैम्प लगता है। उसमें खिलाड़ी रह जाते हैं और दूसरे चले जाते है। माउण्ट आबू में ऐसे लोग जायेंगे जो वहां घूमने के लिए जायेंगे। वही जाते हैं, जिनको व्यक्तिगत प्रभाव से लोग भिजवा सकते हैं। खेल की संस्थाओं में राजनीति नहीं घुसनी चाहिये। खेल की संस्थाओं में राजनीति घुसे तो यह राजस्थान में खिलाड़ी का काम नहीं है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो खेल में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिसिंह।

(व्यवधान)

आपको बाद में। आपका नाम पहले पुकारा गया है।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बजट पर विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान में शिक्षा पर बजट की राशि रखी गई है। शिक्षा का जो स्तर है, भारत वर्ष में उस स्तर को देखते हुए यह बहुत कम है। राजस्थान में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनका शिक्षा का औसत 54.7% है अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है। यह 6 से 7 वर्ष के बच्चे की शिक्षा के बारे में है। 11 से 14 वर्ष के बच्चे 26.3% पढ़ने जाते है। यह भी कुल भारत वर्ष की स्थिति से देखें तो बहुत ही कम है।

(3.05 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

हम शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष से पिछड़े हुए हैं। हमारी शिक्षा का औसत 19.9% है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब प्रदेश है, पिछड़ा हुआ है। राजस्थान को इस समय जो आवश्यकता है, वह प्राईमरी एजूकेशन की है। प्राईमरी एजूकेशन में अधिक ध्यान दें इसमें हम पीछे है। इसमें अगर हम पिछड़े रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे। हमने अभी प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों को सौंप रखी हैं। पैसा सरकार देती है व्यवस्था पंचायत समिति करती है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि प्राइमरी एजूकेशन के लिए एक अलग डायरेक्टरेट होना चाहिए जो प्राइमरी एजूकेशन पर अच्छी तरह से ध्यान दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जितना ध्यान होना चाहिए वह नहीं होगा। सभापति महोदया, ग्रामों में प्राइमरी स्कूल्स की हालत देखिये। बहुत से स्थानों पर भवन तो बने ही नहीं है। भरतपुर जिले में पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। कई गांवों की आबादी एक हजार है। लेकिन वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे समस्त गांवों में, जहां प्राइमरी

( श्री हरिसिंह )

स्कूल नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्कूल खोले जायें। प्राइमरी स्कूल्स में बैठने के लिए टाट पट्टी मिलती नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका इन्तजाम 80 से ही होना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले सालों में राजस्थान के शिक्षा जगत में एक प्रकार का पोल्यूशन हुआ है उस पर ध्यान दिया जाय। पिछली सरकार ने अपने विचारों को फैलाने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया पिछली सरकार ने शिक्षा जगत को माध्यम बनाया अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में आज जो पोल्यूशन हो चुका है इसको मिटाने के लिए शिक्षा मन्त्री महोदय प्रयास करें।

इस सम्बन्ध में आपको और निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा जगत से राजनीति जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। पिछले तीन सालों में राजनीति आई है। हमारे यहां जो एडेड स्कूल हैं, उनमें जो अध्यापक होते हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। मैनेजमेण्ट को सरकार से एड मिलती है। अध्यापकों को जो वेतन मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। जैसे किसी अध्यापक का 500 रु. वेतन है उसको दिया जाता है 250 रु.। अधिक पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं। जहां पर चैक प्रणाली है, वहां पर दूसरे तरीकों से यह काम कर लिया जाता है। उनसे एडवांस ले लिया जाता है या अन्य दूसरे प्रकार से लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, एडेड स्कूल्स में सरकार ध्यान दे। अध्यापकों को तनख्वाह पूरी दिलाई जाय। यह स्कूल न होकर एक दुकान बने हुए हैं। लोगों के वैस्टेड इण्ट्रेस्ट जुड़े हुए हैं। व्यापार का साधन बना हुआ है।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। औद्योगिक प्रशिक्षण के बारे में। राजस्थान में 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये कितने आदमियों को शिक्षा दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक तीन हजार या साढ़े तीन हजार को प्रशिक्षण दे सकते हैं। राजस्थान में आबादी है साढ़े तीन करोड़ के लगभग और केवल साढ़े तीन हजार व्यक्तियों को औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सके यह अत्यन्त ही सोचनीय बात है। वर्ष 79—80 में इन संस्थाओं के द्वारा केवल 710 व्यक्तियों के लिए डिप्लोमा का प्रबन्ध किया गया था। यह एक ऐसी स्थिति है जो काफी सोचनीय है। इसलिए इस क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान शिक्षा के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं कि अभी तक राजस्थान में जो भी शिक्षा है, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो वह सिमट कर बड़े बड़े शहरों में ही रह गई है। विश्वविद्यालय बड़े शहरों में ही, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में ही है इसके अलावा दूसरे स्थानों पर न तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं न एग्रीकल्चर कालेज है और न कोई विश्वविद्यालय की बात ही है। इस वजह से दूसरे क्षेत्रों के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बाकी राजस्थान उपेक्षित है और ये शहर ही ऐसे हैं जहां पर शिक्षा के लिये अधिक ध्यान दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जहां कृषि अधिक होती है वहां पर एक कृषि कालेज खोलने की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं

( श्री हरिसिंह)

वहां पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। वहां के जो छात्र हैं वे भी कृषि के सम्बन्ध में अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए सभापति महोदया, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर में एक कृषि कॉलेज की स्थापना शीघ्र की जावे इस के लिए वहां पर काफी भूमि उपलब्ध है, सैंकड़ों बीघा भूमि कृषि कॉलेज के लिये उपलब्ध की जा सकती है। वहां पर सैकण्डरी स्कूल में कृषि का विषय भी पढ़ाया जाता है। जो छात्र वहां से पास करके निकलेंगे उनको कॉलेज की सुविधा मिल सकेगी।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट बड़ी देरी से निकलता है और उसके कारण हमारे विद्यार्थी जो बाहर शिक्षा लेना चाहते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनिट और वहां पर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। यही नहीं वे काम्पीटिशन में भी रह जाते हैं। हमारे यहां से अभी पांच छ: लड़कों का मिलिट्री कमीशन में सलेक्शन हो गया था लेकिन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं निकलने के कारण वे महरूम रह गये और उनको इस कारण नुकसान हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आप के माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से और उनके माध्यम से विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट से कि रिजल्ट समय पर निकाले जाने चाहिये जिससे हमारे यहां के विद्यार्थी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पा सकें और काम्पीटिशन का लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी एजूकेशन की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जावे और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाई जावे।

श्री सभापति: माननीय श्री पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री त्रिलोकसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भंवरसिंह।

**श्री भंवरसिंह** (नवलगढ़) : सभापति महोदया, शिक्षा की मांगों पर आज बहस चल रही है, मैं प्राथमिक शिक्षा के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब विद्यार्थी स्कूल में आता है, उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक फर्लांग से ज्यादा बच्चों को ना जाना पड़े और स्कूल पूरी तादाद में खोले जाने चाहिए जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके, उनको पुस्तकें भी मुफ्त दी जानी चाहिये जिससे प्राइमरी स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं वे आसानी से पढ़ सकें। स्कूल में जो सैकण्डरी स्कूल की व्यवस्था है, सैकण्डरी स्कूल तक शिक्षा बिलकुल फ्री होनी चाहिए ताकि गांवों के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई का अच्छा अवसर मिल सके।

(श्री भंवर सिंह)

मान्यवर, हरिजन विद्यार्थियों को कुछ सहायता दी जाती है जिससे वे एजूकेशन प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जो अन्य वर्ग के गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको भी सरकार से मदद मिलनी चाहिए ताकि अन्य गरीब वर्गों के बच्चे भी सेकण्डरी तक आसानी से पढ़ सकें, अपने कार्यकलापों में प्रेक्टिकल जीवन में वे साक्षरता का उपयोग कर सकें। साक्षरता का जो सम्बन्ध है पढ़ाई का, पढ़ने के बाद जब व्यवहारिक जीवन में विद्यार्थी जाता है तो उसके सामने रोजगार का प्रश्न खड़ा होता है। वह यह भी नहीं सोच सकता कि अब क्या काम करे, व्यवहारिक जीवन और पेट पालन किस प्रकार से करें। इसलिये इस व्यवस्था पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल पढ़ाई व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है. रोजगार की व्यवस्था भी उनको सुलभ होनी चाहिये। रोजगार में भी जो अच्छे घर के लड़के होते हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक): सरकार की तरफ के एक माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): जगा दो सरकार को।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी: मनन कर रहे हैं शिक्षा नीति का।

श्री भंवरसिंह: जो गरीब बच्चे होते हैं उनको व्यवहारिक जीवन में भी अवसर नहीं मिलता इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा झुंझुनूं इतना बड़ा जिला है लेकिन वहां पर एक भी कॉलेज नहीं है, सात लाख की आबादी है, वहां पर एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय बिराज रहे हैं मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि खेतड़ी साइड में एक कालेज खोलना आवश्यक है, काफी लोग काम करते हैं, इसलिये वहां एक कालेज की व्यवस्था अवश्य की जाय। खेरोड़ गांव है वहां पर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोलने के लिए निवेदन करूंगा, वहां पर एक कुआ और 20 बीघा जमीन गांव वाले फ्री देने को तैयार हैं।

इसके साथ ही जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें पर्याप्त घोटाले हैं। मान्यवर, प्राइवेट संस्थाओं को 90 पर्सेन्ट एड दी जाती है फिर वहां पर बहुत बड़ी फीस छात्रों से ली जाती है, उस पर यहां चिंता व्यक्त की गई है। जब वे 90 पर्सेन्ट एड लेते है और इस तरह से आंकड़े बिठाते है कि 110 पर्सेन्ट से भी ज्यादा एड ले लेते हैं। अगर इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो इससे शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसको रोकना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षण संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा 75 पर्सेन्ट एड दी जावे, इससे ज्यादा नहीं दी जानी चाहिये। अगर इससे ज्यादा एड दी गई तो वे सेवा नहीं कर सकतीं, केवल व्यापार ही करेंगी।

अतः खेल के विषय में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रांत में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उन्हें भरण-पोषण के लिये कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन जब खिलाड़ी खेल छोड़ देता है उसके बाद जब उसके कोई

(श्री भंवर सिंह)

बीमारी हो जाती है या टी.बी. हो जाती है तो उससे अपना जीवन गंवा देता है। लेकिन उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके लिए एक खेल मंत्रालय आवश्यक है और उसकी तरफ से अच्छे खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाय उसे अच्छे अवसर दिये जायं। आज हालत यह हो रही है कि अलग संस्थायें बन रही हैं, अलग से चेयरमेन बन रहे हैं और अपने आपको अध्यक्ष घोषित करते हैं अपनी टीमें भेजते हैं। राजस्थान की जो टीमें बाहर जाती हैं उसमें अव्यवस्था हो रही है खेलों में। उसे कन्ट्रोल करें और जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें अवसर दिया जाय।

हमारी एक संस्था जो पिछले 35 वर्षों से स्पोर्ट्स को अच्छा बढ़ावा दे रही है और राजस्थान स्तर की और भारत स्तर के खेल कूद करवाती है ऐसी संस्था पर अगर सरकार ध्यान दे तो खिलाड़ी मिल सकते हैं।

जय-हिन्द धन्यवाद।

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : मैं बाहर चला गया था, आपने मेरा नाम पुकारा होगा।

**श्री सभापति** : आप बोलिये।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : माननीय सभापति महोदया, मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने कई कटौती प्रस्ताव दिये हैं और कटौती प्रस्तावों के माध्यम से इन मुद्दों की ओर, सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है।

सभापति महोदया मैंने कई माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संस्थाओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज देश में जिस गति से शिक्षण संस्थायें बढ़ रही हैं उस गति से पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल बड़ा अजीब सा लगा होगा माननीय सदस्य को। देश में शिक्षण संस्थाओं से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों की शिक्षा में कमी होती जा रही है। यह बड़ा अजीब सवाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश में जितने भी पब्लिक स्कूल हैं क्या इन पब्लिक स्कूल में या गैर सरकारी स्कूल में एक छोटे मजदूर का बच्चा या ठेले चलाने वाले मजदूर का बच्चा, एक सफाई कर्मचारी म्यूनिसिपेलेटी में काम करने वाले के बच्चा 30 रुपया मासिक या 40 रुपया मासिक प्रवेश शुल्क देकर उस शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर सकता है? नहीं कर सकता है। जिस गरीब को एक समय की रोटी नसीब नहीं है ऐसे गरीब का बच्चा गैर सरकारी स्कूल में प्रवेश लेकर अध्ययन नही कर सकता और जो अध्ययन नहीं कर सकता शिक्षा में बहुत उपेक्षित रहेगा, शिक्षा में पिछड़ा रहेगा तथा सामाजिक दृष्टि से वह समाज में उपेक्षित रहेगा। श्रीमान, जनता सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों सरकारों ने गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को या महाविद्यालयों को जो एड दी है उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार ने भी अपने पिछले बजट में 79-80 में 12.00 लाख रुपये का अनुदान दिया और इस कांग्रेस सरकार ने भी इतनी एड दी है जो जनता पार्टी की सरकार देना चाहती थी और दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा नीति के बखान किये। मैं भी जनता पार्टी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

का विधायक रहा था और आज भी जनता पार्टी का हूं। लेकिन हर राजनैतिक दल में राज सवर्ण लोगों का रहा है, बड़े लोगों का रहा है, पूंजीपतियों का रहा है। उनका कई लोगों से ताल्लुक नहीं रहा। यह बात अलग है कि अपने चुनाव घोषणा-पत्र में अपनी पार्टी की नीतियों में कोई अलग बात कही गई हो, लेकिन जहां अमल में लाने का सवाल उठता है ! देश का कोई भी बड़ा वर्ग इस तरह से अलग हो जाय, ऊंचे वर्ग का आये वह कभी भी पिछड़े वर्ग के बारे में नहीं सोचेगा। इसी कारण जो शिक्षण संस्थाओं को एड दी जा रही है विद्यालय को जो सहायता दी जा रही है दोनों पार्टियों की विचारधारा में, नीतियों में भिन्नता हो, वह मुझे नजर नहीं आई। इसलिए जनता सरकार ने जितनी एड दी है उतनी कांग्रेस ने दी। कांग्रेस सरकार बड़ी दुहाई देती है। जनता सरकार के लोग कहते हैं, कांग्रेस सरकार के लोग कहते हैं, जो इधर बैठते थे कि यह जनता सरकार पूंजीपति या सामन्तवादी या प्रतिक्रियावादी लोगों की है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज का समर्थन किया, यह एक उदाहरण है कि आपने इस बजट में जो एड दी है जो जनता पार्टी ने माना हैं, वह आपने भी माना हैं। आपमें और हममें अन्तर नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान, इस तरह माध्यमिक विद्यालयों को जो एड दी जाती है उस तरह से जितनी उन्होंने दी उसको बढ़ा दी। जनता पार्टी ने कम दी थी। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनता पार्टी ने इन गैर सरकारी संस्थाओं को 227.5 लाख रुपये का अनुदान दिया था। इस तरह से सरकार को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इसको बढ़ा कर उन्हें 246.72 लाख रुपये कर दिया है। यह जनता सरकार कर गई जो पिछड़े वर्ग के हमदर्द की बात करती है। उस पिछड़े वर्ग का वोट लेकर उनकी दुहाई देती है। कांग्रेस सरकार इन्दिरा गांधी दिन प्रति दिन लोगों के नाम पर न मालूम क्या क्या बातें कहती है ? मैं श्रीमन, निवेदन करूं कि जिस तरह से दुहाई देती हैं, जिस तरह की चर्चायें करती है वह सब अमल में लाने का सवाल आता है। पिछड़े वर्ग को आगे लाने की बात आती है तो फिर क्या सोचा जाता है ? अब आप उन शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन देंगे, उनको पनपाने के लिए अन्धा धुन्ध पैसा देंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो पिछड़े वर्ग का आदमी, गरीब तबके का आदमी, मजदूर वर्ग का आदमी, अल्प संख्यक परिवार का सदस्य या उनके बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर पायेंगे ?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि यह खुशी की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी आज इसीका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। उनके दर्द दुख को, उनको गरीबों को या मजदूरों को शिक्षा में जिस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाते उन मुद्दों को जानते हैं या जानकारी महसूस करते है। इस पद पर आने के बाद, वह अपने आपको अगर अलग नहीं समझते हैं तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं को विशेष पैसा दिया जाता है, जो विशेष बजट दिया जाता है उसमें कटौती करेंगे और संस्थाओं को बन्द करायेंगे। मेरा निवेदन है, मेरे कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि हमारे देश में अध्यापक का अपमान होता है, क्यों होता है ? आज की स्थिति में जो

( श्री गोपाल पचेरवाल )

परिणाम आ रहे हैं बड़े अजीब आ रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मांटेसरी पद्धति से पढ़ने वाले विद्यार्थी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी दोनों ने विद्यालयों में एक से लेकर दसवीं तक का अध्ययन अंग्रेजी में किया पर जब सर्विसेज के इन्टरव्यू के लिए जायगा तो श्रीमानजी, जो पब्लिक स्कूल में अध्ययन करके आया है वह अंग्रेजी में तो अच्छा जवाब दे पायेगा उसका चयन होगा, उसका सलेक्शन होगा और यह जो आपके अधिकारी हैं यह कह कर उनको अयोग्य घोषित कर देंगे कि उसमें योग्यता नहीं है। उसमें योग्यता आये कैसे ? जिस बड़े व्यक्ति के बच्चे ने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक अंग्रेजी का अध्ययन किया है और जिस गरीब के बच्चों ने छठी से 10वीं तक अंग्रेजी का अध्ययन किया है उन दोनों में अंग्रेजी के सवाल का उत्तर कौन दे पायेगा ? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह महत्व का मुद्दा है। आप उसको नौकरी में नहीं लेगे, उसकी पदोन्नति नहीं होगी। तो जो आप इस तरह से शिक्षा में दोहरी नीति रखना चाहते हैं और पिछड़े वर्ग को आगे नहीं आने देना चाहते हो। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप बता सकते है कि आज राजस्थान में कितने आई. ए. एस. अफसर हैं एस. टी. के कितने मुसलमान है ? आप बता सकते हैं ? देश में दोहरी शिक्षा नीति रखेंगे, पब्लिक स्कूल अलग चलायेंगे, सरकारी स्कूल अलग चलायेंगे और जो नौकरियों की अनिवार्यता में अंग्रेजी रखी गई है ? इसको जबतक समाप्त नहीं किया जायेगा इसको समाप्त नहीं करेंगे तो पिछड़े वर्ग का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कभी आई. ए. एस. अफसर नहीं बन सकता। बड़ी नौकरियों में नहीं जा सकता। इसलिए जो अनिवार्यता अंग्रेजी के माध्यम से नौकरी देने की है, मैं आग्रह करूंगा सरकार से और विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुन: उन हरिजनों के वोट से, उनका विश्वास प्राप्त करके इस आधार पर कि आपको शिक्षा में प्रगति देंगे, आर्थिक परिवर्तन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन, करेंगे इन सारे आधारों पर आप आये है। आप उनको विश्वास दिलायेंगे कि हम तत्काल ऐसी शिक्षा पद्धति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जिसके माध्यम से गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता है। श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब दोनों विद्यार्थी आते हैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ है वह जो उत्तर देता है उसकी प्रशंसा होती है समाज में और छोटे ग्रामीण के बच्चे का अपमान होता है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होने कहा कि मैट्रिक पास अध्यापक को लगाया जाता है, वह अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है। यह सही नहीं है। पब्लिक स्कूल से जो पढ़ कर आता है और सरकारी स्कूल से जो मैट्रिक पास कर आता है दोनों में अंतर मिलेगा जब शिक्षा पद्धति में अंतर रखना चाहते है तो फिर पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल में तुलना करते हैं। आपको उस अध्यापक को समाज में सम्मान देना चाहिए इसलिए दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करनी होगी। इसके लिए इस देश का पिछड़ापन समाप्त करें।

यहां सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की बात कही गई है। यह जिक्र किया है कि मांग को आगे लाने के लिए,

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मैं जनता पार्टी से अकेला ही बोल रहा हूं इसलिए निर्धारित समय से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए।

श्री सभापति : कितना समय ?

श्री गोपाल पचेरवाल : आपकी सूची में है।

श्री सभापति : तभी तो घंटी बजा रहा हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : आरक्षण के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था सामाजिक कल्याण की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए जो पैसा रखा था उसको बढ़ाने के बजाय, सामाजिक परिवर्तन की बात या अन्य कई बातें जो कही जाती हैं, हमें भी बहुत आशायें थीं कि राजस्थान में पहली बार जनता सरकार ने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया और कांग्रेस सरकार ने भी पहली बार राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया तो हम लोगों में, पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्गों में मानस बना था कि मुख्य मंत्री हमें कोई नई दिशा देंगे। प्रदेश के लिए नया कार्यक्रम देंगे लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए जनता पार्टी ने 1979-80 में 2185.84 का प्रावधान रखा था लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको घटाकर 1799 रखा। आप इस तरह की बातें करते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। एक तरफ आप कटौती कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं समाज में उनको आगे लाना चाहते हैं, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो विकलांग हैं उनका क्या इलाज करना चाहते हैं ? कैसी शिक्षा देंगे ? किस नीति से उनको आगे लायेंगे ? आप उनके लिये बजट में कितना रख रहे हैं ? मुझे आशा थी कि मुख्य मन्त्री उसको बढ़ाकर दुगुना करेंगे लेकिन उसके बजाय कटौती की किस तरह से बात कर सकते हैं ? जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक देश की यह शिक्षा पद्धति रहेगी, कैसे गरीब लोगों को आगे ले जायेंगे ?

आज शिक्षा से जुड़ा हुआ मैं एक अहम सवाल रखना चाहता हूं ! आज देश का नौजवान जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बड़े घर का आदमी शिक्षा लेकर आता है तो उसको एकदम रोजगार मिल जाता है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री सभापति: 45 आदमी बोलने वाले बैठे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल: मै निवेदन कर रहा था कि देश का नौजवान जब चार दीवारी के बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह विद्यार्थी राजस्थान की राजनीति में आकर किसी मंत्री की कोठी के चक्कर लगाता है रोजगार के लिए, एम. एल. ए. के बंगले पर चक्कर लगाता है, उसकी जेब का खर्चा बंद हो जाता है तो फुटपाथ पर जब सोता है तो उसको पुलिस अधिकारी तंग करते हैं ? क्या कारण है ? जब तक शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब

(100)



(श्री गोपाल पचेरवाल)

तक देश के करोड़ों नौजवान 107 व 109 में बंद होकर रहेंगे, गुंडा एक्ट में बंद रहेंगे। तो आप शिक्षा को रोजगार से जोड़िये और ऐसा समाज कायम करें जिससे नौजवान जब चार दीवारी से निकल कर सड़क पर आए तो उसको एहसास हो कि मैंने शिक्षा रोजगार के लिए प्राप्त की है। ऐसा समाज कायम करें ताकि देश का विकास हो सके और पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ सके।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है केशोरायपाटन, वह ऐसा इलाका है जो सिंचित है और माननीय सदस्य जो बूंदी से आए हैं, वह कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं उन्होंने बजट को प्रशंसनीय बताया। मुझे आश्चर्य था। वह कांग्रेस के नेता रहे हैं और सरकार के मंत्री रहे हैं जब उन्होंने भाषण दिया तो कहा कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, चिकित्सा सुविधा में भी विकास नहीं हुआ है। केशोरायपाटन में 1944 में मिडिल स्कूल बना, 1947 में उसको सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित किया गया और आज उस स्कूल में 543 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। 5 कमरे नए सरकार ने बनाए है। सन् 1947 से आज तक नए नए सेकन्डरी स्कूल हायर सैकेन्डरी में बदले गए है तो क्या कारण है कि केशोरायपाटन के गरीब लोगों के लिए उस छोटे गांव में आज तक वही सेकेन्डरी स्कूल बना हुआ हैं? आपके राजनीतिक कारण हो सकते है। मैं मानता हूं कि आपकी जो नीति है वह यह है कि वहां से विरोधी दल का सदस्य चुन कर भेजा है इसलिए उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन आशा है वास्तव में आप जनता की भावनाओं को समझेंगे और वहां हायर सैकन्डरी स्कूल खोलेंगे, वहां प्राथमिकता के आधार पर हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने की कृपा करेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति:** मुझे दुख है लेकिन क्या करूं? औरों को भी समय देना है।

**श्री गोपाल पचेरवाल:** जो मैंने महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखे हैं, आप मेरे विचार, भावनाएं सरकार तक पहुंचायेंगे, सरकार उस पर विचार करके केशोरायपाटन में हायर सैकन्डरी स्कूल को खोलने का विचार करेगी।

**श्री सभापति:** श्री केसरीचंद।

**श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़):** सभापति महोदया, मैं मांग संख्या—24, शिक्षा के संबंध में सरकार का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता था कि तीन वर्ष पहले जब जनता सरकार बनी, ऐसा मानता था कि अच्छी शिक्षा नीति होगी और वह अभिभावकों और हमारे बालकों का आर्थिक वजन कम करेगी लेकिन तीन वर्ष में न बालकों का किताबों का वजन कम हुआ न पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ, न अभिभावकों के मासिक व वार्षिक बजट में कोई कमी हुई। हुआ यह कि शिक्षकों में वर्ग बना दिए गए। जिस शिक्षक को अपने स्थान पर रहना हो तो आर. एस. एस. की वर्दी पहने और ट्रांसफर्स का काम करे। उसका नतीजा है कि चुनाव के बाद आप उस तरफ बैठे हैं हम इस तरफ बैठे है। मैं शिक्षा मन्त्री को इस बात की दाद देना चाहता हूं कि जिन आधारों पर चुनाव लड़कर आए उस नीति का ठीक ढंग से क्रियान्वियन कर रहे हैं।

(श्री केसरी चन्द चौधरी)

श्रीमन्, मेरे जिले में राजस्थान में शिक्षा का जहां तक प्रश्न है सबसे ज्यादा लिटरेसी अजमेर जिले में मानी जाती है लेकिन पिछले 25 वर्षों में जहां तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल का सवाल है, स्कूल्स की कमी नहीं लेकिन करीब करीब सभी स्कूल किराये के भवनों में चल रहे हैं और उन भवनों की जीर्ण अवस्था हो गई है। कई स्कूल गिरने की स्थिति में हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में उन्होंने भवन निर्माण के लिए कहीं भी रकम नहीं रखी है। आप स्कूल खोलें लेकिन भवन नहीं होंगे तो जहां नगर पालिकाओं की सीमा है, वहां बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है।

. . . . . . .

सभापति महोदया, आज जो भी स्कूल्स हैं वह प्राइवेट मकानों में ज्यादातर हमारे यहां पर हैं। कभी भी मैनूपलेशन करके उन भवनों को खाली कराया जा सकता है। यह स्थिति हो सकती है कि उन स्कूल्स के बच्चे आपको सड़कों पर मिलेंगे और, सभापति महोदया, वह स्कूल बन्द हो जायेंगी। इसके साथ साथ सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 77 में सरकार ने यह घोषणा की थी कि किशनगढ़ में हायर सैकण्डरी स्कूल और सैकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे। पर बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वह स्कूल जो किशनगढ़ में खुलने वाले थी वह किशनगढ़ में नहीं खुल कर दूसरी जगह पर खोले गये। सभापति महोदया, मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की और पता लगाने की कोशिश भी की पर बाद में मुझे पता लगा कि राजनैतिक कारणों से जनता पार्टी की सरकार ने किशनगढ़ में हायर सैकण्डरी स्कूल व सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोले। इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार ने जो किशनगढ़ में हायर सेकण्डरी और सेकण्डरी स्कूल नहीं खोलकर अनियमितताये की है उन्हें आप दूर करके किशनगढ़ में हायर सैकण्डरी स्कूल और सैकण्डरी स्कूल इस साल खोलने की व्यवस्था करें और जो आपने इसके लिए क्राइटेरिया बनाया है उस में आप किशनगढ़ को प्रिफ्रेंस देंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदया, अजमेर में छात्राओं के लिए एक महाविद्यालय है जिसमें करीब 1500 छात्रायें पढ़ती हैं। सभापति महोदया, यह प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाया जाता है आज उस कालेज की स्थिति बहुत खराब हो रही है जिससे छात्राओं की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है इसलिए मेरा सभापति महोदया, आपके माध्यम से राज्य सरकार के शिक्षा मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि उस सावत्री कालेज को राज्य सरकार द्वारा टेकओवर किया जाय।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो साल से जो शिक्षा चली आ रही है वह दोष पूर्ण है और जनता सरकार ने यह लागू की है। मेरा शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इसमें अमूल चूल परिवर्तन किया जाय। सभापति महोदया, जहां तक सवाल शिक्षा का है चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो पर निवेदन है कि शिक्षा हमेशा सही दी जाय, ऐसी व्यवस्था होनी

(श्री केसरी चन्द चोधरी)

चाहिये। अन्त में, मैं यह ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर राज्य सरकार ध्यान दें।

**श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह। (अनुपस्थित)**

**श्री त्रिलोक चन्द चतुर्वेदी।**

मुझे विश्वास है आप समय का ख्याल रखेंगे।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): सभापति महोदया, शिक्षा की मांगों पर कुछ कटोती प्रस्ताव मैंने सदन में रखे हैं। इन कटोती प्रस्तावों के माध्यम से और आप के जरिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, हालांकि वह इस समय यहां पर सदन में मौजूद नहीं है। सभापति महोदय, मैंने 11 कटोती प्रस्ताव रखे हैं और उनके जरिये मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी उनसे पूर्ण रूप से सहमत हो जावें सभापति महोदया, प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र को ठीक से चलाने के लिए चुनावों के समय शराब और पैसे की कोई कीमत नहीं रहे, झूठे वायदे करके पानी की टूंटी लगा कर और बिजली के खम्भे जगह जगह गाड़ करके वोट नहीं लिए जाए इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो,

सभापति महोदया, शिक्षा के लिए कम से कम हर व्यक्ति को अक्षरज्ञान और प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा बनाया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। सभापति महोदया, मैंने कुछ सुझाव इसके लिए रखे है। मेरा सुझाव है कि जहां भी दो सौ लोगों की आबादी है वहां पर तीन वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। यह खोलना सभापति महोदया, बहुत ही आवश्यक है और पांच वर्ष में प्रत्येक बच्चे को स्कूल में लाया जा सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिये। इसके लिए सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पांच साला योजना बनाने की जरूरत है।

सभापति महोदया मुझे, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जिक्र किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। सभापति महोदया, उन्होंने अपने भाषण में इस साल 600 प्राथमिक स्कूल खोलने की बात बताई है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी के पास यह मेरा सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि वह इस बात पर पुनः विचार करें। जिस समय बजट पास किया जावें और यह प्रश्न आवे तो उस समय मैंने जो यह सुझाव दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पांच साल योजना बनादी जाय और उसको यहां पर लागू किया जाय। इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस साल 1200 या 1400 प्राथमिक स्कूल और खोले जाय। मैं चाहूंगा, सभापति महोदया, कि मन्त्री महोदय यह घोषणा करें;

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्राथमिक शिक्षा शहरों को छोड़ कर बाकी दूसरी जगह गांवों में पंचायत समितियों के पास है। सभापति महोदया, तीन वर्षों तक जनता पार्टी का शासन रहा हम बड़े असमंजस में थे हमने वैसे पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिये। उनको जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय प्रति व्यक्ति सरकार से कुछ पैसे अनुदान मिलता था उसको बढ़ा कर हमने ढाई रुपये किया और फूड फॉर वर्क को उसके साथ मिला कर हमने उसे पांच रुपये प्रति व्यक्ति करने की कोशिश की गयी। हम यह सोचते थे कि पंचायतों को और अधिकार दिये जायं और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देना हम अत्यन्त आवश्यक समझते थे। पर सभापति महोदया, मैं यह चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा उनके हाथ में है वह उनके पास नहीं रहनी चाहिये। सभापति महोदय, इस बात पर तीन साल तक हमारे अन्दर विचार विमर्श चलता रहा। सभापति महोदया, इसलिये मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से अपील है कि आप चाहे सभी प्रकार के अधिकार विकास करने के लिये पंचायत समितियों को दें पर जैसा कि यहां पर सदन में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितीयों के पास नहीं रखनी चाहिये और प्राथमिक शिक्षा के लिये एक अलग से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय खोला जाना चाहिये, वह सही है। मेरा निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से लेकर अलग से एक निदेशालय खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है। सभापति महोदया, प्राथमिक शिक्षा से ही किसी भी इन्सान की जिन्दगी बनती है। सभापति महोदया, प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे का सोचने का दृष्टिकोण तैयार होता है उसका विकास ही प्राथमिक शिक्षा से होता है। इसलिये सभापति महोदया, मेरा पुरजोर राज्य सरकार से निवेदन है राज्य सरकार से अपील है कि वह पंचायत समितियों से लेकर इसके लिये अलग से निदेशालय खोला जाना चाहिये। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिये कि पांच साला योजना जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारे प्रदेश के सभी गांवों के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। सभापति महोदया, इसके लिये हमारे लिये यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि हम बच्चों के एडमिशन और ड्राप आउट के बारे में सदन में विचार करें। आज सभापति महोदया, ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्कूलें खोलने की जरूरत है उसके साथ साथ ऐसे तरीके सरकार अपनाये जिससे कि गांवों में बच्चों के ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हों। इसके लिये सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि हमें इसके लिये ग्राम काकीयों की व्यवस्था करने की अत्यन्त आवश्यकता है। सभापति महोदय, यह ग्राम काकीयें छोटे गावों में जहां किसानों के बच्चे होते हैं उन्हें उनके घरों में जाकर उनके परिवार वालों को प्रेरित करें कि वह अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिये स्कूल में भेजें। इसके लिये हमें ग्राम काकियों का महिलाओं में से चयन करने की आवश्यकता है, वह गांवों में घूम घूम कर लोगों में उत्साह पैदा करें। इसके लिये वातावरण तैयार करे जिससे कि गांव के बच्चे अधिक से अधिक प्राथमिक स्कूल में जाकर

(104)



(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ज्ञान प्राप्त करें। आज जो यह ड्राप आउट बच्चों को किया जाता है वह बन्द होने की आवश्यकता है। इसलिये आज राज्य सरकार को इस ओर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, आज व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता है पर, सभापति महोदया, आज व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राज्य और राज्य से विश्व और विश्व से ब्रह्माण्ड तक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिये जिससे कि इन्सान का विकास हो सके। सभापति महोदया, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें आज व्यक्ति को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, वह नैतिक शिक्षा तभी दी जा सकती है जब कि हम बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दें। सभापति महोदया, आप चाहे टेअन प्लस टू प्लस थ्री की शिक्षा प्रणाली लागू करो टेअन प्लस टू प्लस थ्री के अलावा ए प्लस बाई प्लस टू कुछ भी लागू करें पर आप यह देखने की आवश्यकता है कि उनके कन्टेन्ट्स क्या हों। मैं टेन प्लस टू प्लस थ्री की ओर दूसरे विवाद में अभी नहीं पड़ना चाहता पर, सभापति महोदया, यह निवेदन करना बहुत ही अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि शिक्षा का कन्टेंट क्या हों उसका कैरीकूलम क्या हो। मेरा निवेदन है कि आप कैरीकूलम जो भी रखें उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी उसके साथ जरूर मिलावें। आज इस कैरीकूलम के साथ साथ नैतिक शिक्षा को जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। सभापति महोदया, नैतिक शिक्षा कैसे आयेगी उसके लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया प्राथमिक शिक्षा का होना अत्यन्त ही अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा के साथ, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्राथमिक शिक्षा का ही विकास करें और उच्च शिक्षा की ओर आप ध्यान नहीं दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा का विकास भी होना चाहिये। सभापति महोदया, आज शिक्षा का हाल हम देखें तो राजस्थान प्रान्त हमारे देश के दूसरे प्रान्तों, जहां तक माध्यमिक शिक्षालयों या महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी का सवाल है, के मुकाबले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर चूंकि पहले प्राथमिक शिक्षा की इम्पार्टेंस अधिक है इसलिये मैंने उस ओर विशेष तौर से कहा पर, सभापति महोदया, आज दूसरे प्रान्तों को आप देखलें राजस्थान की राजधानी से अगर आप तुलना करेंगे तो उन प्रान्तों की राजधानियों में आपको महाविद्यालय, विद्यालय, और यूनिवर्सिटीज बहुत अधिक मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालय खोले जांय और यूनिवर्सिटी भी ज्यादा से ज्यादा खोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा दी जा सके। लेकिन सभापति महोदया, उनको खोलने के पहले हमें प्राथमिक विद्यालय खोलने की अधिक से अधिक आवश्यकता है। किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुचामन 50 हजार की आबादी का है, रतनगढ़, कपासन, बयाना फलौदी आज 6 बड़े बड़े शहर हैं जिनकी अधिक आबादी हो गयी है। आज आप वहां कॉलेज नहीं खोलेंगे, यह गलत है, पुरानी सरकार ने तय किया था महाविद्यालय खोलने। का आप जरा विचार कीजिए कि इस तरह से बन्द कर दें महाविद्यालय खोलना और कहें कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, गलत है। मैं कहता हूं कि 6 स्थानों पर पापूलेशन के हिसाब से, सब बातों के विचार से 6 महा-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विद्यालय निश्चय ही खोलने चाहिये । आप हिम्मत करें । मैंने इस प्रकार का पहले निवेदन किया था कि आज तकनीक की दृष्टि से राजस्थान बहुत पीछे है । कोई भी इन्जीनियरिंग कालेज गवर्नमेंट का नहीं है । या तो यूनिवर्सिटी के हैं या फिर पिलानी में बिड़ला जी का है । कोटा एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक दृष्टि से आगे आ रहा है. हैवी इण्डस्ट्रीज, लाइट इण्डस्ट्रीज सब तरह की इण्डस्ट्रीज वहां डवलप हो रही हैं, पानी की व्यवस्था है । आज कोटा में मेडिकल कॉलेज नहीं, इन्जीनियरिंग कॉलिज नहीं । आज किसी भी दृष्टि से देख लें वहां पर केमिकल इन्जीनियरिंग हो कोई और टेक्नालॉजी हो सब का क्षेत्र उस स्थान पर है और इस नाते से आज कोटा सबसे अधिक उपेक्षित है--आप 6 डिविजनल प्लेसेस को देखें तो कोटा ही ऐसा लगेगा कि जहां यह कुछ नहीं है । और जगह मेडिकल कॉलेज मिल जायेगा, इन्जीनियरिंग कॉलिज मिल जायेंगे किन्तु वहां मेडिकल कालेज हैं, न इन्जीनियरिंग कालेज है और न ही विश्वविद्यालय है । इस नाते से सारी स्थिति को देखते हुए सब प्रकार की बातें वहां है । एक कमेटी ने कहा था कि कोटा ही उपयुक्त स्थान है इन्जीनियरिंग कालेज के लिए बहुत खुशी हुई थी जब मुख्य मंत्री जो, ने अपने जवाब में कहा था संजय के नाम से टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट खोलेंगे technical education is somewhat higher than engineering college और फिर बजट पर चर्चा हो गयी और उसके उत्तर में कहा गया कि महिलाओं का पोलीटेक्नीक स्कूल खोला जायेगा । बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह सुना कि महिलाओं का पोलीटेक्नीक स्कूल खुलेगा । आपने राज्यपाल महोदय के भाषण के प्रत्युत्तर में टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर खोलने की बात कही थी This is somewhat higher than this. और आज देखकर बड़ा कष्ट हुआ ।

श्रीमती शांति पहाड़िया : सभापति महोदया, यह संजय के नाम से क्यों नाराज होते हैं ? क्या यह चाहते हैं कि उनके नाम से किसी तरह की कोई चीज नहीं हो ? कुछ भी नाम रख सकते हैं । यह नाम बदलने वाली बात नहीं है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप एक नहीं दो खोलें और इन्दिरा पोलीटेक्निक नाम रख लें मुझे कोई तकलीफ नहीं है और कुछ चाहें तो मेनका नाम रख लो । चाहे इन्दिरा पोलीटेक्निक हो या मेनका पोलीटेक्नीक हो लेकिन जो पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की चर्चा की गयी मुझे बड़ी प्रसन्नता थी और मन में लगता था कि इसके लिए कोटा ही एकमात्र उपयुक्त स्थान है ...

( व्यवधान )

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिये बीच में नहीं बोलें, कृपया ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी निश्चित रूप से ध्यान करें और इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कोटा में की जाय ।

माननीय सभापति महोदया, शिक्षा की प्रगति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो शिक्षक हैं उनके जीवन में सिक्योरिटी हो, उनका जीवन झूलता जीवन न रहे, उनका जीवन ऐसा नहीं रहे कि क्या होगा ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अब देखिये कि इतना तो व्यवधान हो गया मैं सूक्ष्म रूप में कहूंगा····

**श्री सभापति :** यह आपका सूक्ष्म है तो फिर भाषण क्या होगा ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** 11 कटौती प्रस्ताव हैं।

**श्री सभापति :** इसके बाद मैं आपकी पार्टी वालों को बिलकुल समय नहीं दूंगी ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** मेरा टाइम आपको दे दीजिये ।

( व्यवधान )

**श्री सभापति :** माननीय सदस्या, आप व्यवधान न डालें ।

( व्यवधान )

आप इन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं क्या ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** माननीय सभापति महोदया, मैं चर्चा कर रहा था कि शिक्षकों के जीवन में सुरक्षा की भावना हो सभी दृष्टि से। प्राइवेट कालेजेज में और प्राइवेट स्कूल्स में तीन महीने का नोटिस देकर किसी को भी निकाल दिया जाय यह कतई उचित नहीं है शिक्षकों की अवस्था यह होगी तो वह क्या तो नौकरी करेंगे और क्या अपने बच्चों को पढ़ायेंगे और क्या दूसरे बच्चों के जीवन को बनायेंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदया, पिछले वर्षों में हम एजूकेशन बिल लाये थे, शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था हमने ताकि शिक्षकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। वह प्रवर समिति को सौंप दिया गया। नयी सरकार आई है मैं उसका स्वागत करता हूं वह शिक्षकों के संबंध में चाहे तो वही बिल ले आये या फिर दूसरा बनाये लेकिन शिक्षकों की सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर 20 वर्ष कहने में तकलीफ हो जायगी उस समय में कई शिक्षक निकाले गये। 5-6 कैसेज हमारे पास आये। 2 का निर्णय हो गया और चार के मामले अदालतों में चले गये। उनको किसी प्रकार से अनुबंधित करने से काम नहीं चलेगा। स्टेचुटरी प्रोविजन होना आवश्यक है। उनकी सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा करना आवश्यक है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, ऐसा कोई बिल अविलम्ब लायें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनको कभी भी निकाला नहीं जा सके। आज प्राइवेट कालेजेज और प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वालों के भत्तों का सवाल है, वेतन का सवाल है। कोषागार से भुगतान होता। हो सकता है उनको इस प्रकार की सहूलियत दी जा सकती है। आज शिक्षकों को सभी प्रकार की सहूलियतें देने की आवश्यकता है। मेडिकल भत्ते का प्रावधान होने की आवश्यकता है। उस प्रकार के प्रावधान जो कि गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं उनके साथ करने की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, मेरे खयाल से इसको भी करने की कोशिश करेंगे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज 860 प्राध्यापक और लेक्चरर्स ऐसे हैं जो कि टेम्प्रेरी हैं। टेम्प्रेरी शिक्षक भी रहते हैं प्राइमरी और सेकेण्डरी स्कूल्स में हर बार वह रख लिये जाते हैं। एक बार मेरिट लिस्ट बनती है उनकी लेकिन महाविद्यालयों में दूसरा तरीका पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। मेरिट लिस्ट बनेगी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और नौकरी पर लगाये जायेंगे और जैसे ही सत्र खतम होगा सबको विदा कर दिया जायगा और फिर दुबारा मेरिट लिस्ट बनेगी। एक साल, दो साल रहे हैं उनको निकाल दिया जायगा और नये व्यक्ति आ जायेंगे। इस तरह से उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे प्राध्यापकों को जो कि कार्य कर रहे हैं उनको लोक सेवा आयोग ले जायें और वहां से सलेक्शन करा लायें किन्तु टेम्प्रेरी लेक्चरर की इस प्रकार से दुर्गति करना उपयुक्त नहीं है। पिछले साल हमने बड़ा कदम उठाया कि जो पिछली साल टेम्प्रेरी नौकरी में थे उनको सबको एब्जार्ब किया। मेरी शंका है कि आगे आने वाले साल में 860 प्राध्यापक जो कि टेम्प्रेरी हैं उनको नयी मेरिट लिस्ट बनाकर विदा नहीं कर दिया जाये। ऐसा होता है तो यह उनके साथ अत्याचार होगा। आप उनको लोक सेवा आयोग के सामने जाने का मौका दीजिये और सलेक्शन हो जाता है तो रख लीजिये वरना निकाल दीजिए। यह ऐसी स्थिति है कि जिससे 1/3 प्राध्यापक हैं उनके साथ इस प्रकार का जीवन है उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, दो बातें कहकर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। विश्वविद्यालय के परिणाम देरी से आयेंगे। उन्होंने कहा कि 8 विद्यार्थी हैं जिनका सलेक्शन मिलिट्री में हो गया और अगर 15 अगस्त से पूर्व बी.ए. का रिजल्ट आ जाता है तो उनका प्रवेश हो सकता है। वह मिलिट्री सर्विस में जा सकते हैं। पिछले साल हमने प्रयत्न किया था और इसीलिए पिछले वर्ष अगस्त महीने में ही कालेज खुल गये थे। इस बार तो सितम्बर में खुलने जा रहे हैं। वह अलग है किन्तु अभी तक रिजल्ट आने का पता नहीं। उस समय सरकार ने एक व्यवस्था की थी विश्वविद्यालय के लोगों के साथ बैठ कर इस प्रकार का विचार किया था कि सैन्ट्रल इवेलुएशन किया जाय। पर्चे यहीं पर ही जांचे जाएं। उसके कारण रिजल्ट जल्दी निकले थे। किन्तु पता नहीं कौन सा भार पड़ा सेन्ट्रल इवेलुएशन समाप्त कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल इवेलुएशन हो। माननीय सभापति महोदया, एक और बात कहकर समाप्त करता हूं। चर्चा करते समय यह बहुत कहा गया है कि तीन साल में इतनी भर्ती की गई। आपके आफिसर्स बैठे हैं, सारा सलेक्शन सारा क्राइटेरिया है, मेरिट सूची बनती है शिक्षकों की भर्ती की। बड़ा अच्छा होता कई अच्छे माननीय सदस्य जिन्होंने राजनीति की चर्चा की है इस तरह की चर्चा करते। मेरिट सूची बनाने में यह तय किया था। यह चर्चा करते। उनको मालूम ही नहीं है, अंक कैसे बनते हैं। अंक कैसे जोड़े जाते हैं खाली राजनैतिक चर्चा कर दी कि आर. एस. एस. के लोगों की भर्ती की गई एक ही शब्द सुनने में आया है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** इसलिये भैरोंसिंह जी ने आपसे डिपार्टमेंट छीन कर श्री भंवरलाल शर्मा को दिया था।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** इसलिये मैं यह कह रहा हूं भर्ती में राजनीति को घुसा दिया है। मैं चाहता हूं जो नियम आपने बना दिये, क्वालिफिकेशन्स के नियम

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बने हुए है, आधा अंक इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के राज में स्थानान्तरणों की बाढ़ चली है। हमको कहते थे कि स्थानान्तरण किये गये। मेरे लिये कहा गया, भंवर जी के लिये कहा गया। मैं कहना चाहता हूं आज किस तरह से स्थानान्तरण किये जा रहे हैं और भी आरोप लगाये गये है जिसकी चर्चा करना नहीं चाहता मुझे तो डर लगता है कि एक्सपेन्शन के बाद शायद दूसरे शिक्षा मन्त्री जी आये और कितने ट्रांसफर्स होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा): सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जो लिटरेसी का पर्सेन्टेज है वह 20 पर्सेन्ट है। शिक्षा में राजस्थान का नम्बर हिंदुस्तान में सबसे नीचे आता है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को वोकेशनल प्रोफेशन दिलाना चाहिये।

मैं आपके सामने यह पर्सेन्टेज भी देना चाहता हूं। जितने स्टूडेन्टस हैं 6 और 11 साल के बीच के उसमें 85 पर्सेन्ट ब्वायज हैं और 29 पर्सेंट गर्ल्स। 11 से 14 साल के बीच में 41 पर्सेन्ट ब्वायज और 10 पर्सेन्ट गर्ल्स और 14 और 17 साल के बीच के 26 पर्सेंट और 6 पर्सेन्ट गर्ल्स है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है लिट्रेसी का पर्सेन्टेज डिक्रीज हो रहा है। इसलिये प्रेक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि हर आदमी इसलिये आगे पढ़ता है कि आगे जाकर उसको नौकरी मिल जायेगी आगे जाकर बडा फ्रस्ट्रेशन होता है। सभापति महोदय, सब से पहले प्राईमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिये। कई विद्यार्थी हायर सैकेंडरी के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। आगे जाकर अपने पांवों पर खडा होने की सुविधा मिले। प्राइमरी स्कूलों पर आजकल पंचायतों का मैनेजमेंट है। वह बिलकुल गलत बात है। राजनीति से गड़बड़ होती है। 10,12 साल इलेक्शन नहीं होता है काम कुछ होता नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय ताकि आगे चल कर काम कर सकें।

टीचर्स का जहां तक सवाल है, सभापति महोदया, बड़े दुख की बात है। राजस्थान के अन्दर टीचर्स की बड़ी अजीबो गरीबी स्थिति है। जो आदमी नौकरी चाहते हैं, जब सब जगह से निराश हो जाते हैं तो मास्टर बनने की सोचते हैं। जिस प्रोफेशन का यह हाल है, आप अंदाजा लगाये, नयी पीढ़ी का क्या हाल हो सकता है। आप देखेंगे, यूरोप के अन्दर प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इतना एम्फेसाइज किया जाता है कि पूरे देश के अन्दर टीचर का प्रोफेशन सबसे अच्छा होता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टीचर्स के जो पे-स्केल्स उस को चेन्ज करके अच्छी पे-स्केल बनाये ताकि बहुत ही अट्रेक्टिव प्रोफेशन बने अच्छे अच्छे आदमी इस प्रोफेशन में आये। ट्रांसफर्स राजनीति से होने लगते हैं वे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग का कहा, राजस्थान के अन्दर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकें। गांव में कोचिंग

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

हो, ढंग से कोचिंग हो ताकि कभी भी अपने काम पर जम सके। सभापति महोदया, बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नरपत राम

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूडी।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञान सिंह चोधरी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : सभापति महोदया, इस शिक्षा के बजट में करीब 137 करोड़ का प्रावधान रखा गया हैं और भी कई बातें इस बजट में कही गई। 200 मिडिल स्कूल खोलने की बात कही गई। 200 सेकण्डरी स्कूल खोलने की बात कही गई और 600 नए प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गई। कुछ सेक्शन कुछ विषयों में खोलने की बात कही गई लेकिन इसके साथ साथ जो बजट में प्रावधान रखा गया है, मोजूदा स्थिति में वास्तव में इस बात के लिए योग्य है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा जगत में अनुशासन हो। शिक्षा जगत में जो राजनीति के अड्डे बन गए हैं, छात्रों में असन्तोष है, उसको दूर किया जाए। आज इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए पहले की जो सरकारें हैं, कांग्रेस रही, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। मैं आपको 1974 में ले जाना चाहता हूं। उस समय हमारे स्वर्गीय बाबू जय प्रकाश जी ने एक नारा दिया था विद्यार्थियों का समग्र क्रांति का। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को इस्तेमाल किया और इस बात का नारा दिया कि हम देश के अन्दर युवकों को रोजगार देने का एक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। हम देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं। उस लुभावने नारे से हिन्दुस्तान में छात्रों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जनता पार्टी के राज में छात्रों और युवकों ने बहुत बड़ी आशा और विश्वास से समग्र क्रांति में भाग लिया। उस आशा और विश्वास के विपरीत उनको निराशा हाथ लगी। ज्यों ही जनता पार्टी आयी, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही और हमारे उस समय के प्रधानमन्त्री ने भी एलान किया कि हम 10 साल के अन्दर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। 30 महीने तक जनता पार्टी का राज रहा, जनता पार्टी की सरकार रही तो कम से कम 25 प्रतिशत बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। रोजगार मिलने के बजाय बेरोजगारी जनता पार्टी के शासन में बढ़ी।

तो इस प्रकार से जो आज देश के अन्दर शिक्षा जगत के अन्दर जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि जनता पार्टी और उस समय जो समग्र क्रांति का नारा था, उसने देश को अनुशासन हीनता दी और देश के अन्दर एक राजनैतिक अखाड़े बाजी पैदा की। इस प्रकार से जनता पार्टी का राज आया और उस समग्र क्रांति में हमारी शिक्षण संस्थाओं और हमारे विश्वविद्यालयों में आर० एस० एस० के लोगों ने भी अपनी राजनैतिक घुसपैठ पैदा की। विश्वविद्यालयों के अन्दर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

साल के अन्दर वातावरण बहुत खराब हुआ जगह जगह राजनैतिक रूप से, खुले रूप से राजनैतिक पार्टियां ने भाग लिया। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। क्योंकि विश्वविद्यालय की संस्थाएं और दूसरी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र रहा और मैंने छात्रसंघ की गतिविधियों में भाग लिया। लेकिन जितना 3-4 साल के अन्दर जिस तरह से छात्रसंघ के चुनाव के अन्दर बहुत हो, चाहे अध्यापकों की नियुक्तियों का प्रश्न हो, चाहे और सब मामलों का प्रश्न हो। राजनीति का खुला नृत्य विश्वविद्यालय के अन्दर और शिक्षा जगत के अन्दर हुआ है। यह हमारे लिए और उस समय की सरकार के लिए वास्तव में शर्मनाक बात थी। जहां तक आज हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रश्न है, हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और हमारी केन्द्र सरकार ने कई बार इसके सम्मेलन भी बुलाए। कई आयोगों की रिपोर्ट भी आयी। लेकिन आज तक हमारे युवकों की और छात्रों की जो आशा और उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमारे देश के अन्दर एक ऐसी शिक्षा हो, जो जॉब ओरियन्टेड एजूकेशन हो, जिसका रोजगार से सम्बन्ध हो, हम इस बात को अभी तक तय नहीं कर पाए।

सभापति महोदया, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज की हमारी बेकार शिक्षा से हमारे छात्रों का असन्तोष मिटने वाला नहीं है। छात्रों को रोजगार मिलने वाला नहीं है, और जिस आधार पर हम शिक्षा को चलाना चाहते हैं उससे देश का और छात्रों का भला होने वाला नहीं है तो हमें जॉब ओरियेन्टेड एजूकेशन अपनानी होगी। हम भी समझते हैं कि इसमें कई तरह की परेशानियां हैं लेकिन हमें यह कदम उठा कर इस प्रकार की शिक्षा को स्थापित करना होगा जिससे हमारे छात्र अध्ययन के बाद, चाहे छोटा धन्धा हो या बड़ा धन्धा हो, उस धन्धे के अन्दर लग सके और हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। इस बजट के अन्दर बेरोजगारी की समस्या की ओर भी इशारा किया गया है।

कुछ ग्रामीण संस्थाओं के अन्दर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की बात कही गई है और कुछ औद्योगिक संस्थानों के लिए कर्जे देने की बात भी कही गई है। लेकिन इससे हमारी यह समस्या पूरी होने वाली नहीं है।

सन् 1976 के अन्दर हमारे यहां राजस्थान में रोजगार के आंकड़ों के हिसाब से 278 हजार बेरोजगार थे। 3 साल के अन्दर सन् 1979 के अन्त में यह बेरोजगार 328 हजार तक बढ़ गये। इस प्रकार जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी मिटाने का नारा दिया था, उसके बाद 3 साल के अन्दर बेरोजगारी बढ़ी है, छात्र असन्तोष बढ़ा है और विश्वविद्यालयों के अन्दर और महाविद्यालयों के अन्दर राजनैतिक गतिविधियां और अन्य बातें, जैसे अनुशासनहीनता 3 साल के अंदर आई है।

जहां तक इन बातों का प्रश्न है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रश्न हो चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय का, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय का, पिछले तीन साल के अंदर हमने कई तरह की बातें यहां सुनी। कई तरह की बातों का यहां राजस्थान की विधान सभा में उल्लेख किया गया। लेकिन मुझे बड़े

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा समय था जब राजस्थान विश्वविद्यालय का हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों में चौथा, पांचवां नम्बर था यह बड़ा अनुशासित विश्वविद्यालय था, एक बड़ी शांति थी। लेकिन 3 साल के अन्दर जिस प्रकार से वाइस चान्सलरों की नियुक्तियां हुई, प्रोफेसर्स की पदोन्नतियां हुई उससे इस प्रकार का वातावरण हो गया कि यहां जो अच्छे प्रोफेसर थे, वह दूसरे विश्वविद्यालयों में चले गये। इस प्रकार से यहां पर जनता पार्टी ने विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति फैलाकर वाइस चान्सलरों की, प्रोफेसर्स की नियुक्तियों की जो परम्परा डाली उससे हमारे शिक्षा जगत को बहुत बड़ा आघात लगा है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से, निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रोफेसर्स की इस प्रकार की शिकायतें हैं, मुख्य मन्त्री महोदय को भी एक ज्ञापन इस सम्बन्ध में दिया गया है जिसमें इस प्रकार की नियुक्तियों के मामलों में, पदोन्नतियों के मामलों में उन्होंने काफी घोटालों की बात हमारे सामने प्रस्तुत की है। उसके आधार पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को वाइस चान्सलरों को, इस बात की छूट नहीं दे सकते कि विश्वविद्यालयों को वे राजनीति का अड्डा बनायें और इस प्रकार की ज्यादतियां करें। तो राज्यपाल महोदय को इस प्रकार का ज्ञापन दे करके विश्वविद्यालय के अन्दर जो इस प्रकार के तीन साल के अंदर जो घोटाले हुए हैं और जिस प्रकार से व्यवस्था को तहस नहस किया गया हैं उन घोटालों की जांच करने और दुबारा व्यवस्था और अनुशासन बनाने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से निवेदन भी करूंगा।

जहां तक प्राइमरी स्कूल का प्रश्न है, राजस्थान के अन्दर प्राइमरी स्कूल्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूल खोले भी गये हैं लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री महोदय, जब तक राजस्थान के अन्दर प्राइमरी स्कूल्स की एजूकेशन को पूरा नहीं किया जायगा, हम जिस उद्देश्य को लेकर चलना चाहते हैं उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। राज्यपाल महोदय के भाषण में इस चीज को हायर प्रायोरटी देने की बात कही गई है। सभापति महोदया, मैं आपके जरिये शिक्षा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस बात की व्यवस्था करे कि अगले 5 साल के अन्दर राजस्थान में प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। जिन गांव के लोगों ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें वोट दिये हैं, उनको भी इसका बहुत बड़ा सन्तोष होगा। दूसरी बात, हमारे यहां प्राइमरी स्कूल्स की पिछले सालों में संख्या बढ़ी है लेकिन जहां स्कूलों के अन्दर भवनों की व्यवस्था होनी चाहिये थी, जिस प्रकार से अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, छात्रों के लिए खेल मैदान होने चाहिए थे, वे खेल मैदान आज तक अधूरे हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो शिक्षा के आधार हैं उनकी शिक्षा का स्तर किस प्रकार सुधरे, उन छात्रों के लिए खेल-कूद की क्या व्यवस्था हो, सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा और जो काम अधूरे हैं वे सरकार को 5 साल के अन्दर पूरे करने पड़ेंगे।

जहां तक दो बातों का प्रश्न है हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्व-

(112)



(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

विद्यालय हैं। उदयपुर और जोधपुर की लोकल शिक्षण संस्थाएं हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय है। तो मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान के अन्दर 3-4 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाय। कुछ कालेज उदयपुर से एफीलिएटिड किये जायें, कुछ जोधपुर विश्वविद्यालय से और कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय से और यदि आवश्यकता हो तो एक नया विश्वविद्यालय भी खोला जाय। बीकानेर में भी विश्वविद्यालय खोलने की बात बहुत अर्से से हमारे सामने है। विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है बीकानेर उन सब को पूरा करता है और मेरा शिक्षा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है कि आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सारी शर्तें बीकानेर पूरा करता है। राजस्थान के अन्दर अगला खुलने वाला विश्वविद्यालय बीकानेर में हो और जल्दी से जल्दी विचार करके वहां विश्वविद्यालय खोला जाय। मेरा सुझाव है कि यहां क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। क्षेत्रीय कालेजों का क्या हो? हम विश्वविद्यालय की, आज बहुत बड़ी संख्या होने के बाद रिजल्ट आने की बात—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस तरह की बातें सुनते हैं उन बातों को दूर कर सकें। हमारे यहां हम एजुकेशन लेवल की बात कर रहे थे। शिक्षा स्तर की बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके जरिये कि जब उनको हमने सन् 1977 के अन्दर राज सौंपा था तो उस समय ढांचा क्या था। पिछले सन् 1977 के अन्दर 7 जुलाई से कॉलेज खोले गये, उस समय बड़ी शांति के साथ सारा काम चल रहा था लेकिन तीन साल के अन्दर जनता पार्टी ने उस सत्र को बढ़ाते बढ़ाते पिछले साल 17 सितम्बर को सत्र शुरू किया आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता पार्टी जिम्मेदार है।

दूसरी बात, आज हमारे यहां जिस प्रकार पिछले तीन वर्षों में किया गया है हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उन सब बातों को बारीकी से देखा जाय।

प्रौढ़ शिक्षा की बात भी इन तीन सालों के अन्दर बड़ी बढ़ा चढ़ाकर की गयी। सन् 1979 में 70 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गयी थी। जहां तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का प्रश्न है, वह नीतिगत प्रश्न है, हम इससे नीतिगत सहमत हैं कि प्रौढ़ शिक्षा ज्यादा फैलानी चाहिए। उन लोगों को शिक्षा का मौका मिलना चाहिए जो लोग स्कूल के अन्दर पढ़ाई नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रौढ़ शिक्षा को इस तरह का राजनैतिक अखाड़ा बनाये जिससे राजनैतिक लोगों को रोजगार मिल सके और जो उद्देश्य है वह पूरा न हो। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़े इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए लेकिन ऐसा शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप ईमानदारी से इस बात की जांच करायें कि वास्तव में जो शिक्षा से सम्बन्धित लोग हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा में रहने दें और जो राजनीति से प्रेरित है उनको कम से कम इस प्रौढ़ शिक्षा से मुक्ति दिलायें जिससे कि हमारा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वह पूरा हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

सभापति महोदया, जहां तक दूसरी बातों का प्रश्न है, हमारे यहां पर बजट के अन्दर इस बात का प्रोविजन किया गया है और यह कहा गया है कि जहां पहले पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पोशाकें और निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को उनको तीसरी कक्षा तक कर दिया गया है और उनको निशुल्क शिक्षा और कपड़े वगैरह देने का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में मेरा शिक्षा मंत्री महोदय को एक सुझाव है कि यह जो कपड़ों की और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है इसको कम से कम पांचवी तक आप रियायत दें ताकि यह सुविधा प्राइमरी शिक्षा तक हो सके। इसमें 70·75 लाख रुपये और लगेंगे और हमारे जो अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को यह सहूलियत मिल सकेगी। यह राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा कदम होगा।

जहां तक हमारी स्पोर्ट्स शिक्षा की बात है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, मेरे कई दूसरे साथियों द्वारा इस बारे में कहा गया है और भी कई बातें आपके सामने आई हैं। राजस्थान में जहां तक प्राइमरी एजूकेशन, सैकेन्ड्री एजूकेशन अन्य दूसरी हायर एजूकेशन और टेक्नीकल एजूकेशन का सम्बन्ध है, विश्व विद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है, इनको आज ठीक करने की आवश्यकता है। राजस्थान आज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और राजस्थान में शिक्षा को आगे बढ़ाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और विश्वास से हम लोगों को वोट दिया है, उन लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा आज लोगों को और शिक्षा मंत्री महोदय को यही सुझाव है कि अगले पांच सालों में हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिये जायं इस बात का लक्ष्य सरकार को लेकर चलना चाहिए। अगले सालों के अन्दर हम इस बात की कोशिश करें कि कुल मिला कर जितने प्राइमरी स्कूल्स की कमी को दूर कर सके इसके साथ ही विश्व विद्यालयों के अन्दर जो राजनैतिक घुस गयी है और जो राजनीति के अखाड़े बन गये है, ऐसा दूषित वातावरण बना रखा है उन गतिविधियों से छात्र दूर रहे। जिस उद्देश्य से हमने छात्र संघों का गठन किया था वह कायम रहे सके और वातावरण तीन सालों के अन्दर इस प्रकार का बना है उसको दूर कर सके। इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। तो शिक्षा मंत्रीजी, मैंने जो सुझाव दिए है मेरा विश्वास है कि आप उन सुझावों पर अमल करेंगे और अमल करायेंगे। इस प्रकार से कम से कम शिक्षा जगत में एक ईमानदारी के साथ इस प्रकार का वातावरण पैदा करेंगे जिससे कि राजस्थान का नाम ऊंचा हो और हम लोगो को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की सुविधा दे सके, उनको अधिक रोजगार की सुविधा और अवसर मिल सके.

इसके साथ मैं जो बेरोजगारों की समस्या है उसके बारे में

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समय बहुत हो गया है। आप विराजिए।

(व्यवधान)

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** : मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : श्री कनकराज मेहता।

(व्यवधान)

आपका नाम नहीं है. श्री कनकराज मेहता। आपका नाम सबसे पीछे है।

**श्री रेवतराम** : पहले नाम पुकार लिया था, मैं बाहर चला गया था।

**श्री सभापति** : जो मेरे सामने सूची है, उसमें आपका नाम बहुत नीचे है।

**श्री रेवतराम** : मेरा नाम आ चुका था माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : किसने दिया था।

**श्री रेवतराम** : अध्यक्ष महोदय ने।

**श्री सभापति** : देखने की बात है। श्री कनकराज मेहता।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सभापति महोदया, मेरा नाम भी है या नहीं ?

**श्री सभापति** : आपका नहीं है। श्री कनकराज मेहता। श्री गोटेवाला का नाम नहीं है।

**श्री कनकराज मेहता (सांचोर)** : माननीय सभापति महोदया, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा को हर देश के अन्दर बहुत भारी महत्व दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिये जिस समाज के अन्दर या देश के अन्दर शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, शिक्षा की सुविधायें बराबर नहीं हैं, जहां पर राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर ठीक ढंग से खर्चा नहीं किया जाता है उस देश का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि आपने राजस्थान के अन्दर बजट का बीस प्रतिशत शिक्षा के लिऐ रखा है, जो धनराशि शिक्षा की मद में रखी गई है, वह बहुत कम है यानि बहुत कम मात्रा में रखी गई है। क्यों कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है और डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत लम्बी चौड़ी फैली हुई हैं। खास तौर पर मैं अपनी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी तहसील गांवों में बसी हुई नहीं है बल्कि हमारी तहसील में छोटी छोटी ढाणियां है, छोटे छोटे (Goliya) गोलिए हैं छोटे छोटे क्षेत्र है जिनमें लोग बसे हुए हैं। वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो गरीब लोग हैं, कृषक समाज के लोग हैं उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक राजस्थान के कोने कोने के अन्दर, ढाणी-ढाणी के अन्दर स्कूल और प्राथमिक विद्यालय सरकार की तरफ से कायम नहीं किये जायेंगे, शिक्षा की समस्या लोगों की बनी रहेगी और यहां का गरीब वर्ग, पिछड़ा हुआ तबका और किसान वर्ग पीछे रह जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां की शिक्षा की समस्या को देखते हुए हमारी सरकार को यह समस्या मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका सांचौर है और सबसे पिछड़े हुए इलाकों में बसा हुआ है। सांचौर इलाका गुजरात के पास में और पाकिस्तान की सीमा पर आया हुआ है। इसके अन्दर

(श्री कनकराज मेहता)

एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही गांव के अन्दर इसकी आबादी उतनी नहीं है। इसलिए इस इलाके के अन्दर ढाणी ढाणी के अन्दर स्कूल कायम किये जावें ताकि काश्तकार और गरीब वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित नहीं रहें।

साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि जब से शिक्षा का कार्य भार पंचायत समितियों के सुपुर्द किया गया है तब से शिक्षा की बड़ी दुर्दशा हुई है। प्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी स्कूल खोली गये हैं उनका कोई आधार निश्चित नहीं किया गया है। स्कूल खोले गये गांवों के नाम से जहां पर पूरी ग्रामीण आबादी नहीं है। ढाणियों में लोग रहते हैं जिसकी वजह से झगड़े पैदा हो जाते हैं कि ये स्कूल कहां खोला जाय? यह मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्कूल या लोकेशन कहां रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि स्कूल का लोकेशन तय होना बहुत जरूरी है कई बार लोकेशन तय नहीं होने की वजह से झगड़े पैदा हो जाते हैं और स्कूल खुल नहीं पाता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा सत्र की जो शुरूआत है वह जुलाई में हो जाती है, मगर शिक्षण संस्थाओं को देर से खोलने से शिक्षण का कार्य बहुत देर से प्रारम्भ होता है। इससे शिक्षण में काफी क्षति होती है और समय पर शिक्षा सत्र प्रारम्भ नहीं हो पाता। अध्यापकों के अभाव के कारण भी वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जब स्कूल खोले जा रहे हैं यदि वे ठीक समय पर नहीं खोली जायेंगी तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। जैसा कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आपने नये स्कूल खोलने की घोषणा भी नहीं की है लेकिन अभी तक हमारे गांवों के अन्दर, हमारी तहसीलों के अन्दर, जहां जहां पर ढाणियां हैं वहां पर शालायें खोले जाने की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो मेरा यह निवेदन है कि वहां से प्रस्ताव भी आपके समक्ष आ चुके हैं, राज्य सरकार के समक्ष हमने भेजे हैं वहां पर स्कूल जल्दी खोला जाना बहुत जरूरी है ताकि गरीब ग्रामीण लोग शिक्षा से वंचित नहीं रहने पायें।

साथ ही मेरा यह निवेदन है कि आज कालेज खोलने की और हायर सैकण्ड्री स्कूल बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन साथ में यह भी निवेदन करता हूं कि आज जो कालेज और हायर सैकण्ड्री स्कूल खुल रहे हैं वे एक तरह से फैक्ट्रियां खुल रही हैं, हजारों लाखों की तादाद में पढ़े लिखे लोग पढ़ाई समाप्त करने के बाद बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके सामने और कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण और कोई उनकी दिशा नहीं होने के कारण उन लोगों को मैट्रिक पास करने के बाद या कालेज की परीक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी केलिए दर दर भटकना पड़ता है इससे देश को खतरा पैदा होता है। देश में आज इसी वजह से अराजकता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ठीक से काम पर लगाने के लिए या कहीं पर नौकरी में लगाने के लिए जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे हमारे लिए और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि जब तक इस देश के अन्दर और हमारे राजस्थान के अन्दर टैक्नीकल एजूकेशन की समुचित व्यवस्था

(श्री कनकराज मेहता)

नहीं की जाएगी तब तक वह एजूकेटेड क्लास ज्यादा फायदा उठा नहीं सकेगी और दुखी हो जाएगी। यह देश के लिए बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाएगी जिसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो देश में प्राथमिक एजूकेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारा एजूकेशन ढांचा प्राथमिक शाला से शुरू होता है जब तक वह मजबूत नहीं होगा देश मजबूत नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा प्राथमिक शालाओं और प्राथमिक विद्यालयों को बढ़ाने की ओर खर्च करना चाहिए और उनको अधिक से अधिक व्यवस्थित करने की ओर जोर देना बहुत जरूरी है।

अक्सर होता यह है कि जो शालायें खोली जाती है मास्टर इनमें इन्ट्रेस्टेड नहीं होते हैं वे वहां पर जाते नहीं है घरों पर बैठे रहते हैं जिससे शालायें तो खुल जाती है लेकिन मास्टर वहां रहते नहीं हैं और लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार लाखों रुपया खर्च किया जाता है वह इसमें फालतू जाता है व्यर्थ जाता है और एजूकेशन को बढाने में उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के अन्दर प्राईमरी एजूकेशन को देने के कारण हमारे देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यह प्राईमरी एजुकेशन जो पंचायत समितियों को दे रखी है उसको तुरन्त बदला जावे और अगर नहीं बदला जाएगा तो मेरे खयाल में जो गांवों के अन्दर स्कूल खोले जा रहे हैं उनका पूर्ण लाभ देश को नहीं होगा। उनको अगर उठाये रखते है तो ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज गांवों के अन्दर जाते हैं तो पढ़े लिखे बहुत कम मात्रा में मिलते है। राजस्थान में आज बीस-तीस साल से स्कूल चल रहे हैं लेकिन मुश्किल से शिक्षित आदमी मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि इसका खयाल बहुत जरूरी है। जब तक अध्यापक लोग यह एजूकेशन संस्थाएं अपना कर्तव्य समझकर नहीं चलायेंगे, तब तक एजुकेशन की कोई वेल्यू नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है कि हमारी एक गुदाऊ पंचायत है, इसकी आबादी बहुत भारी है, इस क्षेत्र की मांग के अनुसार उच्च माध्यमिक स्कूल खोला जाना बहुत जरूरी है। एक दांता क्षेत्र के आस पास कोई स्कूल नहीं है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक उच्च माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया जावे क्योंकि इन विद्यालयों का खोलना बहुत जरूरी है। जहां पर हमारे मिडिल स्कूल हैं, हायर सैकण्डरी के वहां पर छात्रों के ठहरने की और रहने की कोई व्यवस्था आपने नहीं की हुई है। हमारी तहसील में कोई सार्वजनिक छात्रावास नहीं है। बाहर से आने वाले बच्चों के रहने के लिए तहसील हैडक्वार्टर में एक सार्वजनिक छात्रावास का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है ताकि पढ़ाई से फायदा मिल सके।

**श्री सभापति** : श्री नानाराम।

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था, मैं बाहर चला गया था।

**श्री सभापति** : आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

**एक माननीय सदस्य** : उपस्थित नहीं था, इसलिए कह रहा हूं...

**श्री सभापति** : मैं बाद में समय दे दूंगी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदया, आसन से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी परीक्षा है, जिसके लिए जाना जरूरी ......

**श्री सभापति** : इसके बाद आपको समय दे दिया जायगा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, से जानकारी ली थी, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत हो तो बता दें। 18 तारीख से मेरी परीक्षा है।

**श्री सभापति** : इसके बाद मैं आपको समय दे दिया जायेगा।

**श्री नानालाल** (राजसमंद) : सभापति महोदया, शिक्षा की मांग पर कटौती प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं इन कटौती प्रस्तावों के आधार पर।

माननीय सभापति महोदया, प्राथमिक शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों का आग्रह रहा है। और मैं चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाय। आज गांवों में जिस प्रकार प्राथमिक शालाओं की हालत है, उसको देखकर दया आती है। वहां स्कूलों में टीचर के बैठने को कुर्सी नहीं है। टीचर नीम के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं, और यदि शहरों के उन स्कूल से जो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं, उनकी तुलना की जाये तो जमीन आसमान का अन्तर है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री से अर्ज करूंगा कि इस दूरी को कम से कम, कम किया जाय। आप इसको बिलकुल खत्म नहीं कर सकते हैं तो मैं अपील करता हूं कि इस दूरी को थोड़ा कम किया जाय। आप जितना पैसा नगर क्षेत्रों में लगा रहे हैं, उन गांव वालों की तरफ भी देखिये, जो आपसे आस लगाये बैठे हैं, किसी प्रकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाय। आज वहां बैठने को जगह नहीं है, मकान नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, फर्नीचर देखने को नहीं मिलता है। यदि वह पब्लिक सेक्टर के स्कूल के अन्दर आ जाय, चक्कर खाने लग जायेंगे कि कोई अजायबघर है।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि यहां कितना पैसा प्रौढ़ शिक्षा पर आपने बजट में रखा है, 70 लाख का प्रावधान गत वर्ष किया था यह क्या मखौल है? शिक्षा के नाम पर मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि आप इस पैसे का दुरुपयोग न करें। यह पैसा प्राथमिक शिक्षा में लगाया जाय और इन स्कूलों में आपको और ध्यान देना चाहिये। हम नहीं चाहते और दें, लेकिन स्तर बढ़ाया जाय। उनमें जिस ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। प्राईमरी स्कूल है, वह पंचायत समिति के स्तर पर चलते हैं वहां 500 छात्र शिक्षा पाते हैं, आज वहां कर्मचारी टाइम पर नहीं आते हैं, यह एक अव्यवस्था प्राईमरी स्कूल में है। शहरों में 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थायी चलते

(श्री नानालाल)

हैं, और वहां एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं मिलता है। उन लोगों को पानी पीने को नहीं है। स्कूल में पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्राइमरी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये आप देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा का स्तर, मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि दस वर्ष से राजस्थान में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की कहीं भी इजाजत नहीं हुई है और सैकण्डरी स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं सैकण्डरी स्कूल खोलिये, लेकिन कुछ उधर भी ध्यान दीजिये। हम हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हमारी पी. यू. सी की क्लास खतम कर दी गई है। आपके जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं, उनसे निकलने वाले छात्रों की दशा देखिये, वह कहां जायेंगे, कुछ एक हायर सैकण्डरी स्कूल हैं. उनमें प्रवेश के लिये वह चक्कर लगाते रहेंगे। ये जरूर बढ़ायें। आप इस ओर ध्यान दें। कुछ ऐसे स्कूल हैं, जो हायर सैकण्डरी के काबिल है, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, कम से कम जितना आप कर सकें उनको अपग्रेड कर देंगे तो काफी स्कूल मिलेंगे। हायर एजूकेशन के बारे में, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें। हायर एजूकेशन के बारे में मेरा विचार है जितने महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाते हैं, उनको शहरों की तरफ न ले जाकर गांवों की तरफ लायें, क्योंकि न गांव में इस प्रकार के स्कूल मिलते हैं, और न उन बच्चों को को जो चाहते हैं, उनका पढ़ाई है मन लगाता है। मैं चाहता हूं आप इस ओर ध्यान दें। सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जैसे भी करके आप इन स्कूलस का स्तर बढ़ाया जाये, जो भी प्राइमरी स्कूल चल रहे है, उसमें आप कुछ करना चाहे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सभी परिवर्तन की मांग करते हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि नीति में जो लोग परिवर्तन की मांग करते हैं, मैंने कई शिक्षा मंत्रियों के भाषण सुने हैं हर कोई परिवर्तन की मांग करता है। शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन की परिभाषा हो इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये फिर वह विचार करके बतायें कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, मैं आग्रह करूंगी 10-2-3 की शिक्षा प्राणाली को अन्य प्रदेशों ने तय कर दिया हमारे यहां यह अभी तक तय नहीं हुई है। सैकेण्डरी स्कूल हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है तो फिर हम क्या करें? एडमिशन मिलने तक एक वर्ष के लिये बच्चा बैठा रहें। उसके लिये क्या किया जाय यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें यह मैं आग्रह करूंगी। यह जो प्रशासनिक और शैक्षणिक निदेशालय हैं इनको अलग अलग करने की व्यवस्था कर दें या स्थानान्तरण का विभाग अलग से बना दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर एक नीति तय कर लें कि कितने अरसे में किसका ट्रांसफर किया जाय क्योंकि जो नीति है वह इसको स्पष्ट नहीं करती कि किस समय में स्थानान्तरण किया जाय लोग इसकी आलोचना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करते हैं, मैं भी करती हूं। मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार कितने स्थानान्तरण हुए हैं इसकी अधिकृत जानकारी तो मंत्री महोदय ही दे सकते हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगी आग्रह करूंगी कि स्थानान्तरण के लिये कोई निश्चित नीति तो वे विशेष रूप से बनायेंगे ? यह निदेशालय अलग से बना दिया जाय।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस वर्ष महिला शिक्षा के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई गई है महिलाओं के लिये पोलीटेक्निक शिक्षा का मैंने आग्रह किया था। मंत्री महोदय से मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिये पोलीटेक्निक जयपुर में अवश्य खोला जाय और भी राजस्थान में जो 4-5 प्रमुख शहर है वहीं महिला पोलिटेक्निक खोली जांय तो बहुत अच्छा होगा। एक तो जयपुर में खोला जाय अन्यथा पांच खोले जायं यह मेरा आग्रह रहेगा।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी औद्योगिक प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसके लिये लड़कियों के लिये अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। और उनको जो मैटीरियल दिया जाता है शिक्षण के लिये वह बहुत थोड़ा होता है और यदि काउन्टर खोलने के लिये अनुमति दे दी जाय तो बच्चों के लिये जो पढ़ते हैं और जो उनको भत्ता मिलता है तो वे अपने लिये पैसे भी पैदा कर लेंगे इस ओर विशेष रूप से विचार करें।

विश्वविद्यालयों में यह भी नहीं सोचा जाता कि कब परीक्षाएं होंगी। 18 अगस्त से एम. ए. की परीक्षा हो रही है गत वर्ष भी यही हालत रही, 18 की बजाय 1 अगस्त की तारीख थी तो ये शिक्षण संस्थाएं नहीं सोच सकती कि हमारे देश का कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है। जलवायु के अनुसार यहां अप्रेल तक परीक्षाएं हो जानी चाहिये। मैं निवेदन करूंगी शिक्षा मंत्री जी से कि वे इस ओर ध्यान देकर यहां विधान सभा के माध्यम से कोई तारीख तय करलें कि किस महीने में परीक्षाएं होंगी यह एक अहम सवाल है और इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा पाठ्य पुस्तक मण्डल है वह पुस्तक किस प्रकार की हो यह तय करता है। नैतिक शिक्षा जो चरित्र विकास के लिये बच्चों के लिये शिक्षा का एक आवश्यक अंग है उसके लिये पुस्तकों में कोई पाठ नहीं जोड़ा जाता। शराब की क्या बुराइयां है या अन्य असामाजिक कृत्यों से क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती है इस तरह के पाठ पुस्तकों में बच्चों के लिये शुरू कर दिये जायं तो बहुत अच्छा होगा। आजकल जो पाठ लिखते हैं, मैं समझती हूं वे पेशेवर लोग हैं इसलिये जो रिटायर अध्यापक हैं उनके अनुभवों को लेकर पाठ लिखवाये जा सकते हैं जो चरित्र का निर्माण करने में सहायक हो सकें शिक्षा को उन्नत कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी रिसर्च की पुस्तक है। जो अनुभव प्राप्त कर रिसर्च करते हैं उन पुस्तकों को प्रकाशित करने की कोई भी प्रवृत्ति हमारे यहां नहीं है उनके अनुभव लोगों को, आम आदमी को नहीं

(120)



(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मिलते। इसके लिये बजट तय करें और आगे आने वाले समय में उनका सब लोगों को लाभ मिल सके ऐसे प्रयास करें।

एक मैं कहना चाहूंगी हमारे यहां बहुत अच्छी संस्था है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल। उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पिछली बार 15 हजार रुपये इस शिक्षण संस्था को दिये गये थे। 15 हजार की एडहॉक ग्रांट से दूध की व्यवस्था की थी बच्चों के लिये स्कूल में मैं कहूंगी इस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को शिक्षा मन्त्री महोदय जरूर देखें और इसमें जो उपयोगी चीजें हैं, स्कूल में जो पांच हाउसेज और खोले जायेंगे उनको खुलवाने की विशेष रूप से व्यवस्था करेंगे।

गत वर्ष बाल वर्ष मनाया गया। गोष्ठियां हुईं। योजनाएं बनी लेकिन बालकों की ओर देखा जाय तो कोई उपलब्धि नहीं। मैं कहना चाहूंगी हमारे देश में जो वीर बालक हुए हैं वीर अभिमन्यु, भरत, प्रहलाद, गोरा बादल आदि हुए हैं जिनके प्रेरणा देने वाले चरित्र हैं उनके बारे में अगर ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करें और बच्चों को टूर्नामेंट आदि प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन के लिये इनाम दी जायं तो मैं समझती हूं उनका चरित्रनिर्माण होगा आगे जाकर वे तपस्वी होंगे, वीर बालक बनेंगे और ऐसे बनेंगे जिन पर पूरे देश भारतवर्ष को गर्व हो सके।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा पुस्तकालय जो खुले हुए हैं उनके लिये अलग से निदेशालय बनाया जाय। जो एक बार पुस्तकालयाध्यक्ष बन जाते हैं उनका आगे उन्नति के लिये कोई मार्ग नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पुस्तकालयों में अच्छे पदों की बहुत कमी है और पुस्तकालयों का शिक्षा मन्त्री जी, कोई भौतिक सत्यापन नहीं होता। मैं एक घटना बताना चाहूंगी, एक पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन हुआ तो पुस्तकालयाध्यक्ष को आत्म हत्या करनी पड़ी क्योंकि जो पुराने पुस्तकालयाध्यक्ष थे उसके जाने पर भौतिक सत्यापन हुआ तो वहां के पुस्तकाध्यक्ष को आत्महत्या करके मरना पड़ा क्योंकि वहां जितनी पुस्तकें गायब थीं उनकी वे कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते थे। तो हर पुस्तकालय का दो वर्ष बाद भौतिक सत्यापन किया जा सके यह माननीय शिक्षा मन्त्री जी करायेंगे।

मैं यह भी चाहूंगी कि हमारे जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाले पुस्तकालय हैं ;ये केवल मात्र ऐसी दूकानें बन कर रह गये हैं जैसे रोजगार निदेशालय। मैं चाहूंगी इनका हमें विस्तार करना चाहिये ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके, लोग इससे लाभ उठा सकें। आज शिक्षा सस्ती हो गई है। शिक्षा का मजाक उड़ाया जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी भाषा की जो पुस्तकें हैं या अन्य भाषा की पुस्तकें है उनका पुस्तकालयों से पूरा फायदा उठाया जाय तो लोग सुसंस्कृत होंगे और देश का भविष्य बनेगा जैसा कि हम चाहते हैं।

मैं कहना चाहूंगी राजस्थानी भाषा के बारे में। इसके भविष्य के बारे में कोई भी दिशा संकेत नहीं है। जिस भाषा का प्राचीन साहित्य इतना आगे बढ़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि इसके बारे में कोई दिशा संकेत नहीं हैं कि इसके उत्थान के लिये आगे क्या किया जायगा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सरकारी कार्यालयों में सरकार के सारे नोटिस इंगलिश में आते हैं जब कि कार्यालय में हिन्दी में कागजात निपटाये। ऐसे कैलेण्डर लगे हुए हैं। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि हिन्दी में कार्य हो इस बात को सख्ती से लागू करें।

यह भी मैं कहना चाहती हूं माननीय सभापति महोदया मैं थोड़ा सा टाइम और चाहूंगी हमारी जो एकेडेमीज हैं उन पर कोई नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है और न कोई विकास कार्य हो रहा है। मैं चाहूंगी जयपुर में या किसी जगह एक ही जगह पर उनको लाया जाय। इसकी वजह से हमारी जो लोक कलाएं हैं उनकी प्रगति के लिये उदय-पुर में एक संस्थान बना हुआ है लेकिन वह वहीं तक सीमित है मैंने वहां तक देखा कि कठपुतली वाले लोग केवल उन्हीं को रोज-गार देते हैं जो वहीं के हैं। हमारे समय में लोग जर्मन और जापान से कठपुतली का खेल देखने आये। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगी कि जो लोक कलाएं हैं उनके विकास के लिए निश्चित रूप से धन का प्रावधान करेंगे। साथ ही साथ उसको क्रियान्वित भी करेंगे।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जिस समय चुनाव हो रहा था, मैं यहां कोई राजनीति की बात नहीं कहना चाहती हूं, विपक्ष के नेता कांग्रेस दल के नेता ने चुनाव लड़ा था मेरे निर्वाचन क्षेत्र से और उन्होंने मेरे क्षेत्र की जनता से यह वायदा किया था कि वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जायगा। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को यह अनुरोध करूंगी कि मेहरबानी करके उनके कांग्रेस दल के अध्यक्ष ने जो वायदा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से किया था उसको पूरा करें। मैं उनके वायदे को यहां पर दोहरा रही हूं। आशा है आप कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर क्राफ्ट्स का स्कूल है। यह विश्व में विख्यात है, यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं परन्तु आज साल्ट का दफ्तर उसमें है और आज भी वह क्राफ्ट स्कूल का एक हिस्सा है। इसको ठीक किया जाए। पिछले दिनों जो नृत्य कला का केन्द्र है वहां पर जो मंच है वह ऐसा है कि पांव में मोच आ जाए। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारा जाए। वरना बाहर से आने वाले इसके बारे में क्या धारणा लेकर जाएंगे यह आप सोच सकते हैं।

सभापति महोदया मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो संगीत शिक्षा के लिए टीचर्स लगाए जाते हैं उनकी भी गति वही होती है जो पुस्तकालय कर्मचारियों की होती है। उनकी आगे पदोन्नति रुक जाती है। मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके बारे में सेवा नियमों में संशोधन किए जाएं ताकि उनकी पदोन्नति न रुके। हमारे यहां संगीत की जो शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में उसके लिए एक ही शिक्षक रखा जाता है या तो वह बजाने वाला होता है या गाने वाला होता है या नृत्य करने वाला होता है। नृत्य, गायन और वादन ये तीनों मिलकर संगीत बनते हैं। जब एक ही मास्टर रखा जाएगा तो वह किस प्रकार की शिक्षा दे सकता है? इसलिए यदि संगीत शिक्षा देनी है तो हमें स्कूल में तीन तरह के टीचर्स उपलब्ध

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कराने होंगे। इसलिए मैं यह आग्रह करूंगी। मेरी यह व्यावहारिक बात है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को फिर आग्रह करूंगी कि वे जरा इस पर ध्यान दें।

गांवों में जो शिक्षक हैं उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है ग्रामीण भत्ता शुरू कर देंगे तो निश्चत रूप से इस ओर आकर्षण होगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि गांवों के अन्दर जो महिला शिक्षक है उनके लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। यहां पर एम. एल. एज. के लिए एम. एल. एज. होस्टल है, एम. एल. एज क्वाटर्स हैं, विधायकपुरी है, धाभाई जी की हवेली है परन्तु जो वर्किंग गर्ल्स हैं उनके लिए किसी प्रकार के होस्टल की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए इस प्रकार की होस्टल की व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिये। मैं पूछना चाहती हूं कि जो जयपुर में वर्किंग गर्ल्स आती है क्या उनके लिए आवासीय सुविधा मिलती है? मन्त्री महोदय जरा ध्यान दें। मैं यह बात कोई बोलने के लिए नहीं कह रही हूं। यह जो वर्किंग गर्ल्स आती हैं उनके लिए होस्टल का निर्माण होना चाहिए। यहां पर उनको मकान किराये पर नहीं मिलता है। वे यहां पर मकान बनाकर नहीं रह सकती हैं। यहां पर आवासीय सुविधा के लिए प्लाट का आवंटन नहीं होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि आप कृपा करके अपने समय में एक दो वर्किंग महिलाओं के होस्टल का निर्माण करावें। मैं आशा करती हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो वर्किंग गर्ल्स, महिलाएं हैं उनकी आवास की सुविधा की आप व्यवस्था करेंगे। यह सुविधा देने की सरकार की जिम्मेदारी है।

अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं निवेदन और करना चाहती हूं कि बाल वर्ष मनाया गया था, उसमें हमारे जो वीर बालक हुए है वीर अभिमन्यु, प्रह्लाद, जिनसे देश का चरित्र निर्माण होता है उनकी याद में टिकट निकाले जा सकें तो उचित होगा। राजनेताओं पर तो कई टिकट निकल चुके हैं परन्तु देश का चरित्र निर्माण करने वाले बालकों जो देश को आगे बढ़ाएंगे, पर भी टिकट निकाले जाएं। यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक)**: सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आज की मांगें पारित हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

**श्री सभापति**: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री सी० पी० जोशी।

**एक माननीय सदस्य**: सभापति महोदय, मने भी टाइम बोलबा वास्ते द्यो सो मूं मारां क्षेत्र की बात कह सकूं।

श्री सभापति : ये बोल जाय जहां पाछे आपने टाइम दे दूंगा।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदया, शिक्षा, कला, संस्कृति के मद पर होने वाले कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान राजस्थान में प्राइमरी, सैकण्डरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजूकेशन में जो प्राब्लम्स हैं, उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है और मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में केवल स्कूलिंग का ही विकास हो। मेरी मान्यता है कि ईवान विच का कन्सेप्ट है रि-स्कूलिंग का, रि-स्कूलिंग के साथ-साथ इसलिए हमें लर्निंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आज 80 लाख रुपया प्रौढ़ शिक्षा के मद में रखा गया है परन्तु वनिस्पत एडल्ट एजूकेशन के इसमें राजनैतिक गतिविधियों ज्यादा हुईं। इसको प्रारम्भ करने के लिए प्रदेश में एक रूरल आर्टिजन स्कूल की स्थापना होनी चाहिए जिसके माध्यम से लर्निंग का एक कनसेप्ट स्टेट में हम प्रारम्भ कर सकें। बाकी जो रकम है उसे प्राथमिक विद्यालय की तरफ डाइवर्ट करे तो यह स्टेट के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज जो सिस्टम हमारे अन्दर मौजूद है, शिक्षा के अन्दर मौजूद है, सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो हमारा सिस्टम है इवेल्यूशन का, वह इवेल्यूएशन सिस्टम एक तरह का नहीं है। आज प्राइमरी एजूकेशन के टीचर की जो समस्या है वह सैकण्डरी स्कूल के टीचर की समस्या नहीं है और जो सैकण्डरी स्कूल के टीचर की समस्या है वह महाविद्यालय के टीचर की समस्या नहीं है और महाविद्यालय के टीचर की समस्या विश्वविद्यालय के टीचर की समस्या नहीं है। मैं विपक्षी दल के नेता, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय से और जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ हमारे राजस्थान की लिट्रेसी पर्सेन्टेज 19 है, जो आंकड़े बताये गए हैं इनमें कहीं 19.7 प्रतिशत है, 19.9 प्रतिशत लिख रखा है, मैं मान लेता हूं, सारे हिन्दुस्तान में हमारा लिट्रेसी में 16 वां स्थान है और 19.1 हमारा शिक्षा का प्रतिशत है यदि हम इस शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाना चाहते है तो हमें शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा। यह सोचना पड़ेगा कि हमें संख्यात्मक परिवर्तन भी करें संख्यात्मक परिवर्तन के लिए जितने प्रयास हम कर सके हैं। वह अच्छे है परन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षा का गुणात्मक परिवर्तन करें। आज जो हमारा प्राइमरी एजूकेशन है, सैकण्डरी एजूकेशन है इनमें सबसे पहलेजो समस्या है वह रिक्रूटमेंट की है। यह रिक्रूटमेंट पालिसी कैसी हो, सबसे पहले हमें इसकी ओर ध्यान देना होगा। यदि प्राथमिक शाला के अध्यापक को हम केवल मिनिमम वेजेज दें और दूर दरांज तक हम उसका ट्रांसफर करते रहें तो हम उससे यह एक्सपेक्ट करें कि वह हमारे बच्चों को सबसे बढ़िया एजूकेशन इम्पार्ट करेगा, मैं नहीं समझता हूं कि यह संभव हो सकेगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है। राष्ट्र का निर्माण बच्चों पर निर्भर करता है और बालकों के विकास में निर्माण में प्राइमरी एजूकेशन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आज शिक्षा का जो गांवों के अन्दर माध्यम है, हम छोड़

(124)



(श्री सी. पी जोशी)

है शहर की बात लेकिन गांव के अन्दर जो पिगमेलियन, भोलेपन का कन्सेप्ट डवलप हुआ है. वहां आदिवासी, जनजाति के जो छात्र है जो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल का झगड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में जो कम्पीटिशन चल रहा है, वहां आदिवासी बालक अपने आप को पिगमेलियन, बौना समझते हैं। इसलिए हम चाहते है कि यूनिफार्म इक्विपमेंट की पालिसी रद्द की जाय, इसका एक ही तरीका है कि प्राइमरी स्कूल से लगाकर सैकण्डरी स्कूल तक टीचर की एक रनिंग ग्रेड रखी जाए और इसके लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड स्थापित कर दिया जाए। यह चुने हुए अध्यापक पर छोड़ दिया जाए कि वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहता है या हायर सैकण्डरी में पढ़ाना. हमें इन्सेन्टिव के रूप में रखना चाहिए। जो लोग प्राइमरी स्कूल को एडाप्ट करें उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें उनको अलग भत्ता दें। किसी भी बालक के निर्माण में प्राइमरी एजूकेशन की बहुत ज्यादा इम्पार्टेंस होती है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे व्यूज रेडिकल व्यूज हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि आमूल-चूल परिवर्तन की तो बात करें परन्तु आमूल चूल परिवर्तन का ढांचा क्या होगा यह नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए मैं इस ओर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप तीस साल से चली आ रही शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़ी गम्भीरता से सोचें, हमें प्राइमरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल में जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट की पालिसी है वह चेन्ज करनी होगी और उनके लिए हमें रनिंग ग्रेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। महाविद्यालयों की जो शिक्षा है उसका एक उदाहरण मैं यहां पर बताना चाहता हूं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय को उदयपुर विश्वविद्यालय एक तरह से रेजीडेन्सल यूनिवर्सिटी है। वहां पर आलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं चल रही है परन्तु किन्हीं राजनैतिक कारणवश मीरा कन्या महाविद्यालय में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गई। जहां विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में दो छात्र पढ़ते हैं और 25 मीरा कन्या महाविद्यालय में। विश्वविद्यालय को प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा था, मुझे बताया जाय, 3 वर्षों के शासन में क्या किया। 30 वर्ष के शासन में, कांग्रेस के शासन में जितना राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है उतना राजनीतिक हस्तक्षेप आपके 3 वर्ष के शासन में हुआ था। जिस तरह से उपकुलपतियों का चयन किया गया था, मैं बहुत गम्भीरता से और नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बतायें कि जो उपकुलपतियों के पद पर चयन हुआ था वह उनकी गरिमा के अनुकूल हुआ था? दूसरा, मैं खुले रूप में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है यह मत समझिये कि मुझको मेरिट फार्मूले का पता नहीं है, आता नहीं है मैं भी एक अध्यापक हूं और मुझे मेरिट का फार्मूला आता है। डाइरेक्टोरेट के अन्दर आपका मेरिट का फार्मूला निश्चित है। हायर सैकण्डरी में फर्स्ट क्लास का 2%. बी.ए. में फर्स्ट क्लास का 3% और एम. ए. में जो नम्बर आते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। इस तरह मेरा निवेदन है कि आपने जो अपाइंटमेंट दिये थे।

(श्री सी.पी. जोशी)

लेकिन विश्वविद्यालय की बात भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी कहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी धांधली और गड़बड़ी विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में आपने की है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के साठ अध्यापक' घर घर घूम रहे हैं केवल मात्र इसलिये कि उनके द्वारा नियुक्त उपकुलपति महोदय, और प्रोवाइसचासलर हैं, नहीं चाहते हैं कि चयन कमेटी द्वारा चुने हुये अध्यापकों को रोजगार दिया जाय । वही भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जो एक बिल लाते हैं आर्डिनेन्स जिसके तहत उन्होंने नियम बनाये कि 25 जून, 1975 के पूर्व काम करने वाले हर अध्यापक को हम कन्फर्म कर देंगे । आप कहते हैं । कि शिक्षा में राजनीति नहीं लाये है परन्तु आपने 25 जून, 1975 की क्या अहमियत है ? केवल इसलिये कि 25, जून, 1975 को इमर्जेन्सी लगी थी । इसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने किसी शिक्षक को बाहर नहीं निकाला, अन्दर ही लिखा है । राजस्थान विश्वविद्यालय के कम से कम 4 अध्यापकों, जिनकी नौकरी 15 साल की थी, को इस आर्डिनेंस के बाद बाहर निकला गया ? मैं खुली चुनौती के रूप में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कोई भी विरोधी दल के नेता इसको खंडित करें कि राजस्थान विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स आने के बाद लोगों को रोजगार से बाहर निकाला है या नहीं निकाला गया है । आप कहते हैं कि हम शिक्षा में राजनीति नहीं चाहते हैं यह बात तो हम भी बड़े गम्भीर रूप से कहते हैं । यह कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा है कि प्रायोरिटी में एजूकेशन बहुत लोएस्ट में आती है । पहली बार ऐसे शिक्षा मंत्री आये हैं जिन्होंने शिक्षा को प्रायोरिटी में लेकर भारतीय जनसंघ को हिट किया है स्थानान्तरण के मामलों में बी. जे. पी. जिस सिस्टेमेटिक ढंग से इनफिल्टर कर रही थी एजूकेशन के अन्दर उसको पहली बार हिट कांग्रेस ने किया है । जिसे हम बार बार कहते हैं स्थानांतरण बहुत ज्यादा हुए । मैं बहुत ही गम्भीरता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जितने स्थानान्तरण किये गये थे और फिर सरकार बनने के बाद जो स्थानान्तरण किये गये उनमें कोई सामंजस्य है या नहीं ? मैं भी मानता हूं कि कोई नीति होनी चाहिये, हम इसके लिये प्रयास करें । इसमें मेरा निवेदन यह है कि इंडियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेंट में पहले भी यह प्रश्न किया गया था कि एक हम कम्प्यूटर मोडल बना लें । हमारे स्कूल्स की नीड्स क्या हैं उसी के आधार पर स्कूल में जो आदमी आने वाला है, डिस्टेंन्स क्या है एन्ट्री करने वाले का इस संबंध में हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कन्सेप्ट आफ मेनकट दिया था, जो अध्यापक पास रहता है उसे पास में रोजगार मिले । हमें जो नीति बनानी है स्थानान्तरण की बनालें लेकिन उसके बाद लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में जो विश्वास रखते हैं । क्योंकि यह तो आपने भी माना है गांधी जी की समाधी पर शपथ खाकर और हम भी मानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय संविधान में लिखा है कि जो शिक्षक शिक्षा इम्पार्ट करे वह धर्म निरपेक्षता लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास रखता हो और अपना कार्य निश्चित रूप से करता हो फिर वह किसी भी विचारधारा का हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मतभेद होना चाहिये; मन में भेद नहीं होना चाहिये । हम इस सरकार से आशा करें कि

126



(श्री सी.पी. जोशी)

शिक्षा में प्रगति होनी चाहिये और फिर विधायक के रूप में मांग करें कि कोटा में पोलिटेक्निक कालेज बनना चाहिये तो इससे तो काम चलेगा नहीं। मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, कि विश्वविद्यालय का जो एक्ट बना हुआ है उसमें चेन्जेज करने चाहिये। सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि जो डिसीजन मेकिंग बाडीज है, एकेडेमिक कौंसिल है और एक्जीक्यूटिव हैं उनको भंग किया जाय। माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी शपथ ग्रहण करने के बाद में जो सबसे पहले अन डेमोक्रेटिक काम किया था वह यह था कि विश्वविद्यालय को सिंडीकेट को भंग कर दिया था। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाय इसके लिये आवश्यकता है कि जो डिसीजन मेकिंग बाडीज है चाहे वह एक्जीक्यूटिव हो या फिर सीनेट हो उनके जो एक्ट में लेकूना है उसमें सुधार किया जाय। हम यह भी चाहते हैं कि माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ठंडे दिमाग से सोचें कि बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन में किस तरह के आदमी आपने नामीनेट किये थे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह के आदमी आपने बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन के डायरेक्टर्स नामीनेट किये थे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम राजनीति चाहते नहीं दूसरी तरफ आप उनके नाम उठाकर के देख लीजिये कि उनका एजूकेशन में कन्ट्रीब्यूशन क्या था। क्या यह निश्चित नहीं था? उन्हीं लोगों को आपने बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन का डायरेक्टर नामीनेट किया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है इस पर 90 लाख रुपये खर्च किये। आप आंकड़े देकर बता दीजिये कि आपने कहां काम कराये। केवल मात्र सरकार से यह आशा करें कि यह नहीं होना चाहिये। मैं इस बात का समर्थक हूं कि हम एक बार नेशनल कन्सेन्सस पर आ जायें कि राजस्थान प्रदेश को हम शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें कुछ मूलभूत सिद्धान्त स्वीकार करने पड़ेंगे। वह मूलभूत सिद्धान्त यह है, राजनीति में जो लोग शामिल है वह एक बात मान लें कि शिक्षा छात्र से अलग नहीं है। है। हम छात्रों के माध्यम से राजनीति चलाना चाहें और हम शिक्षा में सुधार करना चाहें तो यह बात साथ साथ नहीं चल सकती पहले भी मेरी मान्यता थी और आज भी मेरी मान्यता है कि छात्रों के चुनावों के द्वारा, छात्रों का छात्रों के लिये रहने दीजिये आप। अपने आप उनमें समझौता हो जायगा। मैं अपने भूतपूर्व साथियों से और अपने साथियों, जो सत्ता में है, कहना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा में प्रगति हो छात्र आंदोलन नहीं हो वे चाहते है कि प्रदेश में जातिवाद नहीं बढ़े तो उन्हें भी उतना कमिटमेंट देना चाहिये जितना कमिटमेंट हम देना चाहते है। आप सरकार की हर बुराई के लिये हमको भागीदार समझें और हर अच्छाई के लिये अपने आपको जिम्मेदार मानें और उसको फायदा उठाना चाहें तो उससे देश का कोई भला नहीं होगा।

मैं बड़े ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्राइमरी एजूकेशन, सैकण्डरी एजूकेशन रिक्रूटमेंट, पालिसी को बदलिये। मैं यह भी चाहता हूं कि इस

(श्री सी. पी. जोशी)

प्रदेश में अधिक विश्वविद्यालय बनें, मैंने पहले भी कहा मेरा कोई आग्रह भी नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का विकास हो तो हमें शिक्षा एक अलग ऐजुकेशन स्कीम बनानी होगी। इसके अलावा इस प्रदेश की कोई नियति नहीं हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार बड़ी गम्भीरता से सोचे। आई. सी. आर और ऐसी संस्थायें हैं इन सबने सरकार को बराबर निवेदन किया है कि हर वर्ष करोड़ों रुपये लैप्स हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट एजूकेशन स्कीम नहीं है।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ट्रेडीशनल कन्सेप्ट है यूनिवर्सिटीज का इसको बदल जाय। मैं यह चाहता हूं कि इस ट्रेडिशन में एक नया डायमेन्शन क्रियेट किया जाय। क्यों नहीं प्रोफेशनल एजूकेशन के लिये एक अलग यूनिवर्सिटी बना दी जाय? क्यों नहीं राजस्थान में एग्रीकल्चरे रिसर्च और हायर एजूकेशन के लिये एक अलग यूनिवर्सिटी बना दी जाये? मैं यह भी चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर को-आर्डिनेटर की पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। प्रजेन्ट स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में कहीं भी आवश्यकता है तो केवल उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर है क्योंकि मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो, श्रीमान्, जब हम हायर एजूकेशन की बात करें तो बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक्ट में लेकूना है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज जितनी बनी हुई हैं उनको भंग कर दिया जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि अगर हम शैक्षणिक सत्र को बराबर करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप लेने पड़ेंगे उसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम छात्र संघों के चुनाव एक साल तक नहीं करायें। अगर हमने यह करा दिये तो जो शैक्षणिक सत्र उदयपुर विश्वविद्यालय का 2 साल का 3 साल और 4 साल का होने जा रहा है उससे छात्रों और अभिभावकों का बहुत नुकसान होने वाला है। मैं चाहता हूं खुले दिमाग से बैठ कर के बात करें कि अगर हम राजस्थान में शैक्षणिक वातावरण पैदा करना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि राजस्थान शिक्षा में आगे बढ़े तो हमें खुले दिमाग से मानना पड़ेगा कि प्राथमिक शिक्षा ज्यादा बढ़े इसका एक ही इलाज है कि प्रौढ़ शिक्षा बन्द कर दी जाय। प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जो पैसा आया है मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं हम वियतनाम को देखें आखिर प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर केवल चाक, पट्टी स्टिक दे दी तो यह कोई प्रौढ़ शिक्षा का माध्यम नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा में लोकल सोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको आप किस तरह से प्रेस करके लोगों को ट्रेन्ड करना चाहते हैं, यह सोचा जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि हम हायर एजूकेशन को जितनी डीलिंक कर सकते हैं उतना हायर सैकण्डरी के बाद स्टार्ट करें। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, लर्निंग का नया एक्सपेरीमेंट करने के लिये केवल मात्र 1980-81 के बजट में रूरल आर्टिजन इन्स्टीट्यूट की स्थापना करें। उसके अन्दर किसी को भी नियुक्त नहीं करें। जो आदमी बेस्ट अपने ट्रेन्ड में मास्टर है उसको प्रोफेसर की तनख्वाह देकर प्रोफेसर बना दें। उसके विवेक पर छोड़ दीजिये कौनसा आदमी

(128)



(श्री सी. पी. जोशी)

अध्ययन कर सकता है, कौनसा आदमी अध्ययन नहीं कर सकता है। लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नया आयाम शिक्षा का हम बना सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है एजूकेशन का उसमें लेकूना आ गया है। हमारी जो फिजिकल फैसेलिटी में कमी है उसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल यहां होना चाहिये, सैकण्डरी स्कूल यहां होना चाहिये, इससे शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। रेडिकल व्यू है उसको बदलना पड़ेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिये यह आवश्यक है कि कम से कम दो ढाई साल में एक सब्जेक्ट के लिये एडवान्स सेंटर खोले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हायर एजूकेशन में कम से कम एक विषय ऐसा हो जिसमें हम अनडिसिप्लिन को कमपीट कर सकें। इसलिये यह भी आवश्यक है कि हम एक विश्वविद्यालय के सेन्टर बनायें और राजस्थान के हायर एजूकेशन का री स्ट्रक्चर करें। डिसीजन मेकिंग बाडीज हैं उनको एक साथ गियर अप करें। छात्रों को यह समझायें कि तुम्हारा काम केवल शिक्षा ग्रहण करना है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता जहां हमारी कोई गलती हो तो निकालें और अगर अच्छी बात करते हों तो उसमें सहयोग दें। तभी हम देश में; प्रदेश में शिक्षा में जो हमारा 16वां स्थान है उसमें आगे बढ़ कर इस प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर सकेंगे। मैं चाहूंगा, गम्भीरता से हम बात करें बनिस्बत हम यह बात करें कि स्कूल यहां होना चाहिए, वहां होना चाहिये। यह मैं मंत्री महोदय के विवेक पर छोड़ता हूं कि स्कूल कहां हो कितने होने चाहिये। वे जितने भी चाहें, प्रदेश के लिए निर्णय करें, विश्वविद्यालय कहां होना चाहिये, कैसा होना चाहिये, इसका निर्णय वे करें लेकिन भगवान के लिए शिक्षा में रेडिकल चेंज, आमूल चूल परिवर्तन के लिये कुछ सम्भव है तो ठीक है अन्यथा इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। करोड़ों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रुपया आपने अकाल राहत के नाम पर खर्च कर दिया लेकिन अकाल आज भी पड़ता है। उसी प्रकार करोड़ों रुपये की अनुदान की मांग हर साल हमसे पास करा लीजिये लेकिन हर साल इसी तरह की बात करेंगे कि यह होना चाहिये। एक बार आप शिक्षा में रेडिकल चेंज करने का मानस बना लीजिये। उसके बाद आप चेंज करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इसी आशा के साथ कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

## समिति का प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन

**श्री सभापति** : मन्त्री महोदय।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक दि. 7 अगस्त 1980 को अपराह्न 3 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दि. 11 अगस्त, 1980 को बैठक नहीं रखी जाय और दि. 14 अगस्त, 1980 को विचारार्थ ली जाने वाली मांग स. 33—

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग सं.-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग सं. 23-श्रम और रोजगार दि. 20 अगस्त, 1980 को विचारार्थ ली जाने वाली मांग सं. 36-सहकारिता के साथ ले ली जावे।"

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का जो तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्रीमती विद्या पाठक।

### मांग सं. 24 पर विचार

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बजट पर चर्चा हो रही है। मैं एक विशेष विषय पर, विशेष कर इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूं कि विकास कार्यों पर बजट प्रावधान किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आज की मांग में शिक्षा, संस्कृति और कला है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में बहुत से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान हैं। इन ही स्थानों से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे यहां मोनूमेन्ट है। जो पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत है। अब प्रश्न इस बात का है कि हमारे जो मोनूमेन्ट्स हैं उनकी स्थिति पैसे के अभाव में बहुत खराब हो रही है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो क्या देखें ? केन्द्रीय आर्कोलोजिकल डिपार्टमेण्ट के भी हैं। चित्तौड़गढ का किला है। जयपुर में आमेर है। इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनके आफिसों में जो कर्मचारी हैं, वह इनसफिसिएण्ट और इन एफिसिएण्ट हैं। केन्द्रीय दफ्तरों की जो लोकेशन है, वह बहुत खराब है। मेरे मंत्रित्व समय में केन्द्रीय मन्त्री महोदय से मेरी बात हुई थी। उन्होंने वायदा किया था कि चित्तौड़गढ़ का विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। उन्होंने कुछ पैसा स्वीकृत किया है, उसकी जानकारी आपको, मंत्रीजी, होगी। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से राजस्थान में बहुत से मोनूमेन्ट्स हैं, संग्रहालय हैं। पुरातत्व के पुराने मोनूमेन्ट्स के रख-रखाव के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि आपके विभाग में कुल एक इंजीनियर है। उनके पास एक असिस्टेन्ट है वह स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक यह है कि इसके लिए एक अलग आफिस रखा जाय। विशेष रूप से एक इंजीनीयरिंग सैल की स्थापना की जाय। पुराने मोनूमेन्ट्स पर ध्यान दें, जो उस विषय का जानकार हैं उनको appoint करिये। बजट के अभाव में कितना ध्यान दिया जा सकता है ? मसूरिया पहाड़ी है, जोधपुर में। उस समय भी पर्यटक विभाग के पैसे से इस सड़क का विकास किया गया। इसी प्रकार से जयपुर के नाहरगढ़ के बारे में भी कहा गया है कि

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर्यटक विभाग के धन में से इस सड़क का विकास किया जाय। मेरा निवेदन है कि आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्ट को ही ज्यादा पैसा दिया जाय। वरना जिस किसी विभाग से कटौती होगी उसका इफेक्ट दूसरी जगह जरूर पड़ेगा। सभापति महोदय, यहां जो भी दर्शक आते हैं, ये हमारे मोनूमेन्ट्स देखने आते हैं। अगर यहां टिकट लगे हैं तो ठीक हैं। नहीं हैं तो उनसे टिकट अवश्य लिया जाय। उन पर जिस सीमा में टिकट लगाते हैं, उससे आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्ट में सुधार की आवश्यकता है। मोनूमेन्ट्स में जो सुधार करते हैं, वह एनवायरमेन्ट से मेल खाता हुआ होना चाहिये। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो मेल खाता सुधार हो वही किया जाना चाहिए। वरना मोनूमेंट्स खराब हो जाते हैं। इस पर अधिक से अधिक कितना पैसा लेगा जिससे कि मोनूमेंट्स का रख रखाव ठीक हो सके। इस बारे में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी, यह विभाग राजस्थान में बहुत बड़ी विरासत है। जैसे कि जोधपुर का मण्डोर की सालें हैं। वहां पर विदेशी लोग देखने के लिए आते हैं। वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा एक तालाब बना दिया गया है। जिससे वहां का सारा महत्व ही समाप्त हो गया है। मेरा निवेदन है कि विभिन्न विभागों में को-आर्डिनेशन होना चाहिए। सांस्कृतिक मिनिस्ट्री अलग से बनाई जावे, यह मैं सोचती हूं, समय की मांग है और समय रहते इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और इसके महत्व को समझा जाना चाहिए। विभिन्न एकेडेमीज मीन्स क्या हैं, वे क्या काम करती हैं, उसको भी हमें देखना है। लोक कला और लोक संस्कृति पर रिसर्च की जावे, पर जो उसको माडर्नाइज करने के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है उन को रोका जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समय और चाहूंगी।

इसी तरह से स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विशेषकर जो स्थानीय और दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन कौंसिलों व संस्थाओं के अन्दर जो अपाइन्टमेंट्स चेयरमैन या अन्य पदों के अधिकारियों के होते हैं वह पालिटिकल होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति में जिस तरह की रुचि हो, उसमें जिस प्रकार की एफिशियेन्सी हो, या वह जिस प्रकार से जितना उस डिसिप्लिन इंकंट्रीब्यूट कर सके उसी तरह के लोगों को, जिनका जिस तरफ एप्टीट्यूट हो, उन्हीं को उसी क्षेत्र में लगाना चाहिए। थोड़े से लाभ के चाव में कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को लगा दिया जाता है जिससे आगे जाकर बड़ा नुकसान होता है। मैं समझती हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे।

शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि जिस तरह से विद्यार्थियों का, मेन पावर का और पैसे का लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है उसको रोका जाना चाहिए, यह जरूरी है। उच्च शिक्षा के लिये एक हाई पावर कमेटी बनायी जानी चाहिए। यह कमेटी इस तरह की शिक्षण संस्थाओं में

(श्रीमती विद्या पाठक)

क्या 2 समस्यायें हैं, क्यों हैं, विद्यार्थी आन्दोलन क्यों हो रहे हैं, क्या उससे कितना लाभ हो रहा है, इस चीज को असेस करके इसे पब्लिसिटी दी जाय ताकि विद्यार्थी और नागरिक दोनों ही इस हानि पक्ष को समझ सकें। फिर विद्यार्थियों को जो एक ही कक्षा में पांच पांच साल रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा समय पर ही इम्तिहान भी हो जाने चाहिए। जिसके न होने पर कई विद्यार्थी कई कम्पीटीशन से महरूम रह जाते हैं, अगर समय पर इम्तिहान हो जायं और रिजल्ट भी समय पर निकल जावें तो फिर ऐसा नहीं होगा, इसलिए यह भी जरूरी है कि समय पर इम्तिहान हो और रिजल्ट भी ठीक समय पर आ जावें।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि विद्यार्थी यूनियन भी जरूरी है, स्टूडेन्ट्स में यूनियन भी होनी चाहिए, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता लेकिन इसका पालिटिकलाइजेशन होने से बर्बादी होने लगती है। सदन इस बात से सहमत होगा कि स्टूडेन्ट्स यूनियन को पालिटिकेलाइज करने की जिम्मेदारी भी हम पालिटिशियन्स की ही होती है। आज हम देखते हैं कि यूनियन्स के चुनाव में जो खर्चा होता है वह हमारे चुनावों से ज्यादा भी हो सकता है, यह फण्ड्स कहां से आता है? उसका आडिट होना चाहिए इस बात की आवश्यकता है। इसी तरह से स्टूडेण्ट्स की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिए और एक वार्षिक कलंडर बनाना चाहिए स्कूल्स की तरह और कालेज के बच्चों के लिए जिससे डिसिप्लिन बना रहे, इसके कुछ ड्रास्टिक और प्रेक्टिकल कदम उठाये जाने जरूरी हैं। इसके अलावा एक बात और सोचती हूं; कुछ क्रोनिक स्टूडेण्ट्स होते हैं जो परसिस्टेन्टली कई साल तक एक ही कक्षा में कालेजों में पड़े रहते हैं, इसका बुरा असर दूसरे अच्छे विद्यार्थियों पर पड़ता है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से कोई आवश्यक नहीं है कि सबको हायर एजूकेशन दी जावे हाईस्कूल के बाद केलिबर और एप्टीट्यूड को देखते हुए हायर एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि अनएम्पलायमेंट पर काबू पाया जा सके। टेक्निकल एजूकेशन की तरफ हमको ज्यादा जोर देना चाहिए जिससे स्टूडेन्ट जल्दी से जल्दी सेटल हो सके। आर्थिक वोकेशनल कोर्सेज शुरू किये जाने चाहिये।

सबसे ज्यादा मुश्किल जब आती है जब टीचर्स में चाहे स्कूल हो या कालेज के हों, आपस की राइवलरीज होती है, इससे स्टूडेण्ट्स में भी भेदभाव हो जाता है। इसलिए स्टूडेण्ट्स में किसी प्रकार की मिसअण्डर स्टैंडिग नहीं हो इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। हम सारा दोष विद्यार्थियों को ही देते हैं लेकिन टीचर्स का भी असेसमेंट स्टूडेण्ट्स के माध्यम से किया जाना चाहिए, कई जगह विदेशों में इस प्रकार से होता भी है। इसमें अच्छे केलिबर के विद्यार्थियों को ही लिया जाना चाहिये जो यह बता सकें कि किस टीचर का किस प्रकार का काम रहता है। और किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अध्यापक के सर्विस रूल्स और सर्विस कण्डीशन्स में भी बहुत फर्क है,

( श्रीमती विद्या पाठक )

डिस्पेरिटी है। रूल्स हैं पर एक प्रकार से आब्सोलीट और कहना चाहिए डिफन्क्ट हो गये हैं, उनको फिर से बनाये जाने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से डी. ए. में डिस्पेरिटी भी है यह एनामलीज समाप्त की जानी जाहिए

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने बहुत समय ले लिया है।

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय सभापति महोदया, केवल दो मिनट।

शिक्षा की नीति के बारे में भी यहां चर्चा हुई। मैं सोचती हूं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात का ध्यान होगा कि सेन्टर ने शिक्षा नीति के विषय में कुछ आंकड़े और रिपोर्ट राज्य से मांगी थी, मैं सोचती हूं वह गई होगी और उसी के आधार पर शिक्षा नीति निर्धारित की जायगी। इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी मेरे क्षेत्र में दो स्कूल खोले गये थे मथलपुरा और शिवदासपुरा में। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार हमारी थी, पर वे खुले केवल कागजों में आदेश निकालने के बाद वहां पर कम्पलायन्स का होना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले केवल यह पता लगा कि वहां पर स्कूल ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल आदेश पास कर देने से ही कुछ नहीं होगा उसकी कम्पलायन्स भी होनी चाहिये, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक और इम्पार्टेन्ट बात है, आपने स्कूलें खोलने का निर्णय लिया है, बड़ी खुशी की बात है। यह एक ऐसी विकास की बात है, जिसमें बच्चे पढेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, देश और प्रदेश का विकास होगा। इसको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिये, जो आधार बना लिया है, चाहे आप किसी भी कान्स्टीट्यूएन्सी में खोलें, उस आधार को देखते हुए नीड बेस्ड तरीके से स्कूल खोले जाय। स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है उनकी रख रखाव की भी नितान्त आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में दो लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किये जायं, एक वाटिका में और दूसरा गोनेर में। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्या।

22 सदस्यों की सूची है, आप सबका समय ले लेंगी तो······

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय कृपा 10 वीं क्लास तक उसको बढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरह से पब्लिक स्कूल के बारे में भी कहा गया है। कम से कम मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि उनको बन्द किया जाना चाहिए। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। मगर उनको पब्लिक स्कूल की आवश्यकता है और उनके समानान्तर हम अपने दूसरे स्कूल्स को लायें यह ठीक है परन्तु बड़े को छोटा करें। इसका मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता माननीय सदस्य एक पोल्यूशन की बात कर रहे थे। मैं एक बात कहूंगी कि सरकार आपके पास है, नियम आपके पास रखे हुए हैं। अगर आपके पास कहीं कोई खामी

133



( श्रीमती विद्या पाठक )

नजर आती है तो एक्शन आपके बस की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने विकास को पालिटिकल रंग में नहीं नहीं लिया था, और आगे से आप भी इसे पालिटिकल दृष्टि से नहीं लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विकास में पालिटिक्स नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री रामसिंह विश्नोई।

**श्री मेघराज तावड़ :** एक मिनट, सभापति महोदय, मेरा नाम पुकार लिया गया है लेकिन ..

**श्री सभापति :** आपने अवसर खो दिया आपको इन्तजार करना होगा।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :** सभापति महोदया, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग जो सदन में प्रस्तुत है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कई तरह से अपने विचार प्रकट किये हैं। यहां कई सदस्य, बुद्धिमान माननीय सदस्य बैठते हैं। पिछले 30 वर्षों में कई सुझाव शिक्षा के बारे में इस सदन को देते रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, जो कुछ भी सुझाव माननीय सदस्य देते हैं उसकी पालना या उसको मानना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। कुछ मजबूरी होती है, कुछ हालात होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका समाधान होना चाहिए जो देश और प्रान्त के हित में होता है।

आज 30 सालों के बाद अगर गांव का अनपढ़ किसान, एक नागरिक गांव के अन्दर शिक्षा के लिए किसी जगह पर प्राइमरी स्कूल चाहता है तो यह कोई ऐसी मांग नहीं है जिसकी पूर्ति न हो सके। आज जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता एक तो वह शहर हैं, वहां पर अनेक प्रकार की सहूलियतें आम नागरिक को मुहैया हैं। वहां आसानी से एक नागरिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वह नाना प्रकार के विषयों में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक गांव का आम आदमी, गरीब आदमी— यहां पर आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर कि हमारी जो तत्कालीन सरकार थी उसने हमारे यहां स्कूल और कालेज खोलने की बात कही थी। लेकिन आज वहां पर आर्ट्स कॉलेज नहीं है। वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को परीक्षा के लिए कामर्स पढ़नी पड़ती है। वहां सैकण्डरी स्कूल हैं, 10 वीं तक स्कूल हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह कॉमर्स लेंगे। आर्ट्स का कोई कालेज नहीं, कामर्स नहीं, साइन्स नहीं, बायलोजी नहीं तो नाना प्रकार के आम आदमी, जो रेगिस्तानी लाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जो आम आदमी को मिलनी चाहिए।

आज गांव के अन्दर कहने को तो कुछ कह सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर 5 परसन्ट जो बुद्धिजीवी हैं, वह हिन्दुस्तान में राज करते हैं। लेकिन गांव में कोई आदमी काम करना चाहते हैं वह काम नहीं कर पाते हैं। यह मजबूरी है। कहीं स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल खोल सकते हैं। उसमें बुरी बात क्या है? यह बात नहीं है, हमारी मजबूरी है। उसका बजट में प्रावधान नहीं है। इसके कारण से पिछले 30 सालों से लोग अपने गांवों से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं जहां पर आज स्कूल की व्यवस्था नहीं है। कितने बच्चों को स्कूल जाने के लिए 10-10 मील जाकर पढ़ने जाना पड़ता है। क्या वह नागरिक नहीं, क्या वह समान नहीं हैं तो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? आज 10-5

(134)



(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रतिशत उच्च अधिकारी हैं, आ.ई. ए. एस. हैं, आई.पी.एस. हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके बच्चे हैं उनका आई. ए. एस., आई. पी. एस. में सलेक्शन होता है।

आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां 6 साल के बाद में बच्चा स्कूल में जाता है। वहां अच्छे से अच्छे अध्यापक हैं, वहां पर 50-50 अध्यापक हैं, वह वहां पर अच्छा पैसा देते हैं। यह हमारे गांवों में वहां के आदमी को नहीं मिल पाती है। अध्यापक स्कूल्स में जाते नहीं हैं। गांव का आदमी होता है तो वह जाता नहीं है। जो सड़क के किनारे के स्कूल होते हैं वहां जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा। जो 5 प्रतिशत हमारे हिन्दुस्तान के लोग हैं उनका हिन्दुतान में विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा और शिक्षा को समानताओं को प्राप्त करके जो सहूलियतें आपने दे रखी है जहां पर नाना प्रकार के ज्ञान, खेल कूद की जो सहूलियतें हैं वह आपको अब समाप्त करनी होगी। मैं आपको ठीक कहता हूं। आपको भूल जाना चाहिए कि इसके बिना राज चल सकता है। आज गांवों में स्कूल उपलब्ध नही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए आप अगर कर नहीं सकते यदि मजबूरी है तो मैं सुझाव देता हूं। आपकी मजबूरी हो सकती है। यदि राष्ट्र-हित के मामले में हमारे पास पैसा नहीं है तो तय तो कर सकते हैं। हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। आप तो एक पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल को 90-90, 80-80 पर्सेन्ट या 200-200 पर्सेन्ट तक एड दे देते हैं। झूठे आंकड़े अध्यापकों के बताकर जैसे मान लीजिये महीने का 20 हजार खर्चा होता है तो 3-4 फालतू बताकर के वह पैसा ले लेते हैं जिससे वह अपना काम चला लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए. ..

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

अगर इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते तो मैं आपको सुझाव देता हूं। आज राजस्थान के अन्दर पूरे गांव के अन्दर इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 बातें कहूंगा। राजस्थान के अन्दर जो बजट पेश किया उसके अन्दर चार हजार, पांच हजार हों, तमाम गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल मुहैया करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जहां पर ढाई हजार की आबादी के गांव है, जहां पर पंचायत का मुख्यालय है वहां सैकेंडरी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सब सुविधायें होनी चाहिए। उसमें कामर्स, सांइस, बायलोजी जो भी सहूलियतें हों वह मिलनी चाहिए। जिस शहर में भीड़ होती है जहां पर गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। वह एक एक बच्चे का 2 सौ 3 सौ रुपया खर्च करे वहां पर बच्चा जाकर चुनाव के चक्कर में पड़ जाता है। कॉलेज के अंदर जो बच्चा बढ़ता नहीं है पढ सकता नहीं है जो पढ़ना चाहते है, उसको पढ़ने देते नहीं हैं। आपका फर्ज है कि गांवों में इसका विस्तार करें, शहरों में जो भीड़ लगी हुई है और 10 हजार की संख्या में बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप उनको रोकें और गांव के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्तर पर और जिला स्तर पर आपको व्यवस्था करनी चाहिये ताकि आपकी भीड़ कम हो जाय और बच्चों को कम से कम समय में कम से कम पैसा खर्च करके उच्च शिक्षा प्राप्त करा सकें...... ..

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

एक मिनट। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। आज चीन के बाद आबादी की दृष्टि से हिन्दुस्तान दूसरे नम्बर पर है दुनियां में लेकिन जब आप रूस में मास्को में पधारते है तो सिवा एक के कोई खेल नहीं जीत सके इससे शर्म आती हैं। अपने अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है। अपने यहां खेलकूद में जिन लोगों की मोनोपोली है, दूसरे लोगों को नहीं आने देते हैं। इसलिए आपको खेलकूद लाजिमी करना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रत्येक स्कूल में खेलकूद में भाग लेना लाजिमी हो। जिनकी स्थिति ठीक नहीं है तो इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे भारत का नाम रोशन करने के लिए, आपका फर्ज है, खेलकूद को लाजिमी करना चाहिए, इससे खेलकूद का महत्व बढ़ेगा लोगों की बुद्धि और स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए शिक्षा का लाजिमी तौर पर राष्ट्रीयकरण करते हुए खेलों के महत्व को देखते हुए इनको महत्वपूर्ण स्थान दें और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सुझाव दिये है जवाब देते समय उनका उत्तर दें।

**श्री सभापति** : श्री चन्द्रवीरसिंह

(अनुपस्थित)

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)**: एक मिनट। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इस साल प्रेमचन्द शताब्दी का साल है, सारे देश में जगह जगह 31 जुलाई से 8 अक्टूबर प्रेमचंद समारोह मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। मैं सदन को याद दिलना चाहती हूं कि अपने यहां ऐसी परम्परा रही है रविन्द्रजी की जब शताब्दी मनाई गई तो रविन्द्र भवन बनाया गया। इसलिए प्रेमचंद शताब्दी में अपने राज्य के अनुरूप यह समारोह राज के द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा मनाया जाए, इसकी ओर ध्यान दें।

**श्री सभापति** : श्री लच्छूराम।

**श्री लच्छूराम (मंडावा)** : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर काफी चर्चा की है। प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल और कॉलेज एजुकेशन पर अपने अपने विचार रखे हैं। मैं किसी प्रकार की आलोचना में न जाकर कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे आशा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री उनकी ओर ध्यान देंगे।

किसी भी शिक्षा संस्थान या किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र है, उसमें सबसे पहले नींव की आवश्यकता होती है। मकान भी नींव पर आधारित होता है। इसी प्रकार से सब प्रकार की शिक्षा, मिडिल, हाई स्कूल, कालेज शिक्षा सभी प्राइमरी शिक्षा पर आधारित है। आज जिस प्रकार प्राइमरी शिक्षा से राजस्थान में खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं, इतना खिलवाड़ शायद किसी भी दूसरे प्रांत या विभाग में किसी भी संस्थान में, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। आज पाठशालाओं

(श्री लच्छूराम)

की संख्या तो प्राए दिन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी की तरफ उनकी पूरी पठन और पाठन सामग्री का बिलकुल प्रभाव है। मकानों का प्रभाव तो था। माननीय सदस्य इस पर थोड़ा एतराज करें, सत्ता पक्ष में बैठने वाले, जनता पार्टी के ढाई साल के शासन में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ लेकिन कुछ गांवों में पाठशालाओं के मकान बने हैं परन्तु मकानों से कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तक शिक्षा के लिए अध्यापक और पाठन सामग्री का प्रबंध नहीं होगा तब तक शिक्षा के लिए हमें ज्यादा आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं। तो मैं शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि प्राइमरी शिक्षा में एक मोटी, बेसिक कमी यह है कि प्राइमरी स्कूल्स में किसी भी प्रकार पिग्रोन व पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। प्राय: प्राइमरी स्कूल्स देहातों में हैं, पेयजल उपयुक्त है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पानी लाने व पिलाने का काम बच्चे कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल्स में ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं। इसलिए इनको 6 वर्ष की उम्र में ही भर्ती किया जाता है। तो माननीय सदस्य मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या 5-6 साल का बच्चा, जिस कुएं की गहराई 150 फीट है, रस्सी से पानी निकाल सकता है? तो मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि छात्रों की संख्या को आधार न लेकर अगर हमें प्राइमरी स्कूल खोलने हैं, जैसे 300 स्कूल बजट में हैं चाहे 300 के बजाय चाहे 100 स्कूल खोलें, चाहे स्कूल न खोलें लेकिन जितने स्कूल चलते हैं कम से कम पार्ट टाइम चपरासी या यदि पूरे समय की क्षमता है तो पूरे समय के लिए चपरासी रखें लेकिन प्राइमरी स्कूल्स में पानी का इंतजाम निश्चत रूप से होना चाहिए।

दूसरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूल्स में 40 बच्चों पर एक अध्यापक का प्रावधान है तो 80 पर 2, मैं इसका विरोध करता हूं। एक स्कूल में पांचवीं तक कक्षायें होती हैं उसमें तीन अध्यापक से कम होने चाहिए। अगर लड़कों की संख्या कम है तो स्कूल को बंद किया जाए लेकिन एक स्कूल में तीन कक्षायें 4,5 और कक्षा 3 एक इकाई के लिए। इसलिए जो स्कूल खोलते हैं, तो तीन अध्यापक काम करते हैं। प्राइमरी स्कूल में निश्चित रूप से होने चाहिए। इसके लिए बजट की आवश्यकता होगी।

मैं, माननीय सभापति द्वारा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह प्रौढ़ शिक्षा का बजट है बिलकुल सुपरफ्लुअस है किसी भी काम का नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ है बिलकुल झूंठ है। इसको आप या तो प्राइमरी शिक्षा में लगा दें नहीं तो इसका और रास्ता है। हमारे यहां बी. एससी. ट्रेन्ड अध्यापक 1974 से मारे मारे फिरते हैं इसलिए उनको बेकारी के भत्ते के रूप में जितना भी संभव हो, सके जब तक उनका अपाइंटमेंट नहीं हो जो ट्रेन्ड हैं, दें। ऐसा नहीं देते हैं तो जैसे कमियां बताई हैं पानी वगैरह की उस पर खर्चा करना चाहिए।

(श्री लच्छूराम)

करीब करीब राजस्थान में पंचायतें जन संख्या के हिसाब से हैं। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर बाकी करीब करीब सभी पंचायतें कम्पेक्ट हैं। एक गांव में या दो गांव में एक पंचायत है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में एक पंचायत में करीब 10-12-15 गांव हैं। इसलिए हर पंचायत मुख्यालय में जैसे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि एक हाई स्कूल होना चाहिए, यह बिलकुल लाजिमी है। इसको सिद्धांत रूप से स्वीकार करना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री, से अनुरोध करूंगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर एक हाई स्कूल और हर गांव में प्राइमरी स्कूल करीब करीब रेवेन्यू विलेज में है लेकिन एक और समस्या है। रेवेन्यू विलेज एक है वह है छोटा और उसके तन में आने वाली उस क्षेत्र में आने वाली ढाणियां रेवेन्यू विलेज से दुगुनी, तिगुनी हैं। इस प्रकार से कई ढाणियां रह जाती हैं। जैसे पेयजल की बात है। उदाहरण के लिए आपके पास सभी जगह रेवेन्यू विलेज में पानी आ गया, आबादी है 100 ढाणियां और ढाणियों में 500 की आबादी बसती है, वह आज भी वैसे के वैसे पानी के लिए तरसते हैं। इसलिए रेवेन्यू विभाग से मिलकर रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए, यह एक खामी है। इसलिए जो रेवेन्यू विलेजेज नहीं हैं उनके लिए अगर आबादी ज्यादा है तो पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है मिडिल स्कूलों को खोलने के क्राइटेरिया के बारे में। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सुझाव देना चाहूंगा कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक मिडिल स्कूल कम से कम होना चाहिये। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिये। लेकिन जैसा कि मेरा प्रस्ताव था कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर कम से कम एक हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिये वह अगर आप कोई वित्तीय कारणों से नहीं खोल सकें तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक मिडिल स्कूल तो कम से कम खोला जाना चाहिये।

सभापति महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि आज हमारे गांव के अन्दर पढ़ने वाले जो लड़के हैं शहर में पढ़ने वाले लड़कों से कम्पीटीशन में बराबरी नहीं कर सकते हैं। सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज हमारे गांवों में पढ़ने वाले लड़के जिस तरह से पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका कम्पीटीशन होता है हमारे गांव में पढ़ने वाले लड़कों से तो वह निश्चित रूप से उनसे ज्यादा होशियार होते हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा व सुझाव दूंगा कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर पब्लिक स्कूल की तरह वैल इक्विप्ड स्कूल खोला जाय जिससे कि हमारे गांव के लोग भी शहर के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों से कम्पीटीशन में बराबरी कर सकें। इसके लिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में 235 पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स हैं। तो राज्य

(श्री लच्छूराम)

सरकार को चाहिये कि 235 वैल इक्विप्ड स्कूल वहां पर खोले जाने चाहिये जिससे कि वहां पर मेधावी छात्र पढ़ाई कर सकें और वह भी कम्पीटीशन में भाग लेकर उत्तीर्ण हो सकें।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमारे को यह रोजाना सुनने को मिलता है कि कालेजों में कुछ वर्गों में आपस में पार्टी बाजी की वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके लिये मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन लड़ाई झगड़ों का मुख्य कारण यह है कि गांव में कालेजेज, अच्छी स्टेण्डर्ड की पढ़ाई नहीं होने के कारण वहां से लोग शहरों में आते हैं और फिर वहां पर पार्टी बाजी की वजह से झगड़ा होता है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से यह सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में भीड़ कम करने के लिए और लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिये आप अधिक से अधिक गांवों में कालेज खोले जाये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुंझुनूं जिले में आज तक पिछले तीस साल तक कांग्रेस राज में और उसके बाद में ढाई साल तक जनता सरकार के राज में एक भी कालेज में नहीं खोला गया। कोई भी गवर्नमेंट कालेज झुंझुनू जिले में नहीं है। सभापति महोदय, वहां पर कालेजेज हैं पर वह प्राइवेट कालेजेज हैं, सरकारी नहीं हैं वहां जितने भी कालेजेज हैं वह कालेजेज हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक गवर्नमेंट कालेज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर खोला जाय। और इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो मोतीलाल कालेज है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में पदोन्नत किया जाय। सभापति महोदय, हमारे जिले में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है यह कितने खेद की बात है क्योंकि पिछले तीस सालो में सैंकड़ों जगह पर कालेजेज खोले गये हैं पर झुंझुनूं जिले में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं खोला गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

**श्री महाराम चौधरी** : सभापति महोदय, मेरा समय भी इनको दे दिया जाय।

**श्री लच्छूराम**: तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनू जिला हैड क्वार्टर पर एक गवर्नमेंट का कालेज खोला जाय और वहां पर मोतीलाल कालेज को पी.जी. कालेज में पदोन्नत किया जाय। इसके साथ हर पंचायत समिति पर वैल इक्विप्ड स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गांवों में झुंझुनू जिले में जहां कि प्राथमिक स्कूल नहीं है वह तुरन्त खोले जाय।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

**श्री लच्छूराम** : इसके अलावा मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राथमिक शालाएं आप खोलें उनमें कम से कम बच्चों को पीने के लिये पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। ऐसा नहीं हो कि आप 5-10 रुपये रेकरिंग खर्चा इसके लिये रख कर काम चलावें। कम से कम बच्चों को पानी पिलाने वाला एक चपरासी तो होना ही चाहिये। यहां पर, सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव के रूप में यह भी कहा कि कालेजेज खोले जायं और कई माननीय सदस्यों ने तो संगीत अकादमी और दूसरी एकेडेमीज खोलने की बात कही है पर मेरा तो निवेदन यह है कि सर्वप्रथम तो हर गांव में प्राथमिक स्कूल होना अनिवार्य है। बस इतना ही मेरा निवेदन है कि जो भी मैंने सुझाव दिये हैं उनकी ओर शिक्षा मन्त्री ध्यान रखें।

**श्री सभापति** : श्री श्रीराम गोटेवाला।

**श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर)** : सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री श्रीराम गोटेवाला का नाम पुकारा है आप स्थान ग्रहण करें। आपका नाम जब पुकारा गया था तब आप नहीं थे। आप अपनी बात कहने के लिये जागरूक नहीं थे। आसन से नाम पुकारा तब आप कहां थे ?

(व्यवधान)

**श्री त्रिलोक सिंह** : आपकी जागरूकता का यही बैरोमीटर है क्या ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको समय दूंगा। पर अभी आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)**: सभापति महोदय, आप हमें यह बता दें कि क्रम का हिसाब क्या है ताकि हमें जानकारी मिल जाय।

**श्री सभापति** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके दल के तीन सदस्य हैं उसमें से एक माननीय सदस्य आपके दल के बोल चुके हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री मोहन लाल मोदी** : सभापति महोदय, हमारे दल का 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया था आप बता दें कि जो भी माननीय सदस्य बोला है उसने कितना समय लिया उसके बाद में जो समय बचता है वह मुझे दे दिया जाय।

**श्री सभापति** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री श्रीराम गोटेवाला आप जारी रखें।

**श्री मोहन लाल मोदी** : सभापति महोदय, आप तो हमें बता दें कि हमारा कितना समय अब बचा है।

**श्री सभापति** : आप आसन को टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। प्रोसिडिंग्ज मंगा कर देखकर बता सकता हूं कि आपके माननीय सदस्य ने कितना समय ले लिया है। श्री श्रीराम गोटेवाला आप जारी रखें।

**श्री मोहन लाल मोदी** : सभापति महोदय, टर्म्स डिक्टेट कराने की बात नहीं है। मैं तो जानकारी चाह रहा हूं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार)** : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है और मैंने भी शिक्षा की मांगों पर कटौती प्रस्ताव

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दिये हैं। मैं उन्हीं कटौती प्रस्तावों के बारे में आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके शिक्षा विभाग के द्वारा जो ग्रान्ट इन एड दी जाती है उसका केटेगराइजेशन क्या है? आपके उसके बारे में क्या रूल्स हैं? सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज कई स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट शत-प्रतिशत आता है उनको तो आप 50 प्रतिशत की सहायता देते हैं और जिन स्कूलों का रिजल्ट 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत ही रहता है उन शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार 90 प्रतिशत ग्रान्ट इन एड देती हैं। सभापति महोदय, जो शिक्षण संस्थायें 90 प्रतिशत ग्रान्ट इन एड प्राप्त करती है वह अपने बच्चों से फीसें बढ़ा कर और इधर-उधर से घपला करके शत प्रतिशत एड ले लेते हैं। सभापति महोदय, वह उलटी सीधी रसीद काटकर और दूसरी गड़बड़ियां करके इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिनका रिजल्ट खराब है और जिनको 90 प्रतिशत एड मिलती है और कितनी बार भी वह बच्चों से 20-20 रुपये फीस ले लेते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार राजकीय धन की लूट मचा रखी है, उनको विशेष तौर से यह पिछले तीन सालों में बहुत हुआ है। उनको तो आप मेहरबानी करके यह एड देना बन्द कर दें तो उचित होगा। इसके अलावा, सभापति महोदय, यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजकीय धन का बहुत दुरुपयोग हुआ है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ भी राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

**एक माननीय सदस्य** : आर.एस.एस. की बात।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : माननीय सदस्य आप चिन्ता नहीं करें। मैं आर. एस. एस. का नाम लेना चाहता हूं पर माननीय सदस्य अगर कह ही रहे हैं तो मैं सिर्फ आर.एस.एस. के सदस्यों का ही नहीं बल्कि जो आर.एस. एस. के माध्यम से यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने जो घपले किये हैं उनकी भी सब लिस्ट मेरे पास मौजूद है उन्होंने क्या-क्या कारनामें किये हैं वह भी मैं पेश कर सकता हूं। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जयपुर में एक मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, जिसको हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने बहुत प्रयत्न करके यहां पर खुलवाया था। सभापति महोदय, यह मालवीय इंजीनियरिंग कालेज सन् 1963 में सुखाड़िया साहब के प्रयत्नों से खुला था और उसकी स्थापना के बाद उस कालेज के संचालक मण्डल के अध्यक्ष जब तक वह मुख्य मन्त्री रहे वह रहे और उनके बाद बरकतुल्ला खां साहब मुख्य मंत्री थे वह जीवित रहे तब तक वह इस के संचालक मण्डल के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में जो शिक्षा मन्त्री होता था वह इसका संचालक मण्डल का अध्यक्ष होता था। सभापति महोदय, चाहे शिवचरण जी माथुर रहे, चाहे और कोई शिक्षा मन्त्री रहा वह इसके संचालक मण्डल का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में जब जनता पार्टी का राज आया तो ललित किशोर जी, जो कि शिक्षा मंत्री थे, भी इस संचालक मण्डल के

(141)



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अध्यक्ष रहे पर इसके बाद में भगवान जाने क्या बात हुई कि भंवरलाल जी शिक्षा मंत्री हुए पर न जाने क्यों भैरोंसिंह जी ने, जो कि मुख्य मंत्री थे, जब भंवरलाल जी शर्मा शिक्षा मंत्री हुए तब उनको मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के संचालक मण्डल का अध्यक्ष नहीं बनाया। सभापति महोदय, मुझे ललित किशोर चतुर्वेदी उस संचालक मण्डल के अध्यक्ष बने उसका कोई दुख नहीं है पर दुख इस बात का है कि भंवर लाल जी में ऐसी क्या अयोग्यता थी कि उनको मालवीय इंजीनियरिंग कालेज का संचालक मण्डल का अध्यक्ष नहीं बनाया और ललित किशोर चतुर्वेदी को ही मालवीय इंजीनियरिंग कालेज का संचालक मण्डल का अध्यक्ष ही रहने दिया। सभापति महोदय, वहां पर ललित किशोर चतुर्वेदी ने टेक्निकल कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर श्री धर्मेन्द्र को बुरी तरह से परेशान किया और अन्त में दुखी होकर मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य में डाक्टर धर्मेन्द्र को वहां से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में उन्होंने उस टेक्निकल कालेज के लिये अपने ही गुरुजी, कि केमेस्ट्री में डीन थे, उनको वहां प्राचार्य बना दिया। श्री राम सहाय सक्सेना को इन्होंने वहां प्रिंसिपल बना दिया। उनको डेपूटेशन पर बुलाया गया और उन्होंने वहां पर बहुत गड़बड़ियां कीं जिससे दुखी होकर वहां कालेज की महिला परिषद् उनके खिलाफ प्रदर्शन करके तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी के घर पर गयीं। पर, सभापति महोदय, भैरोंसिंह जी तो आप जानते ही है कि XXX बोलने के लिये मुख्य मन्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे।

**श्री सभापति** : X-X शब्द को एक्सपन्ज किया जावे।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : XXX नहीं तो असत्य मानिये, उसको आप झांसा मानिये।

और आप सुनना चाहते हैं मैं सारे तथ्यों के बारे में जो जो काम हुए हैं उन सब बातों को यहां पर कहना चाहूंगा। अभी श्री ललित किशोरजी, ऐसा प्रवचन कर रहे थे जैसे उनके राज में तो राम राज आ गया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि श्री सक्सेना के विरुद्ध 13 अक्टूबर, 1978 को वहां के सारे लेक्चरर्स ने मुंह पर पट्टी बांध कर यहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने भूख हड़ताल की। उसके बाद में जैसा मैंने निवेदन किया कि कालेज परिषद् की सारी महिलाओं ने आकर श्री भैरोंसिंहजी से मांग की कि यहां पर हो रही धांधलियों को रोका जाय। नतीजा कुछ नहीं निकला और बाद में असंतुष्ट होकर वहां के छात्रों ने उनकी पुत्र वधु की कार खड़ी थी उसको जला दिया असंतोष यहां तक बढ़ा और उस कार को जलाने का खामियाजा किस को भुगतना पड़ा? खामियाजा भुगतना पड़ा मामूली करदाता को 42,858 रुपये का चेक श्रीललित किशोरजी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनी संचालक समिति ने अत्यावश्यक मीटिंग बुलाकर उसका खामियाजा दिया। आज तक जब कि दुनिया भर में कायदा है कि इस प्रकार की बात होती हैं तो एल. आई. सी. या किसी भी इन्श्योरेन्स कम्पनी, जिससे

---

XX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार अपलोपित किया गया।

(142)



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भी कार इन्श्योर्ड होती है, से उसका हर्जाना लिया जाता है लेकिन इनको तो पक्षपात करना था। अगर पक्षपात का शब्द भी आप कहते हैं कि यह भी असंसदीय है तो उसको भी मैं मान लूंगा लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इतना बड़ा पक्षपात करके 42858.56 का पेमेंट यहां पर तुरन्त करवा दिया गया और पुत्रवधु भी आई. टी. ओ. है और यहां मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज से उनका कोई लेना देना नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज की दुनिया भर में साख थी, बहुत ऊंची रेपूटेशन थी जहां 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जा सकता था आज भी मैं थोड़े दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी के पास एक बच्चे की सिफारिश लेकर गया था। उन्होंने टेलीफोन भी किया तो शिक्षा मंत्रीजी को जवाब मिला कि यहां पर 88 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 छात्रों को माइग्रेट करवाकर इन्होंने प्रिन्सिपल से मिल कर प्रवेश दे दिया और इस प्रकार से ऐसी धांधली की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती।

**एक माननीय सदस्य :** भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी नहीं बोले नहीं तो भंवरलालजी आ जाते।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** भंवरलालजी को तो इस लायक ही नहीं समझा श्री भैरोंसिंहजी ने वरना आज तक सारे शिक्षा मंत्री ही मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के संचालक समिति के अध्यक्ष रहते आये हैं।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि प्रवेश के मामले में जिस प्रकार की धांधलियां बरती गई और जो मालविय इन्जीनियरिंग कॉलेज का स्तर था कि 88 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले को प्रवेश नहीं दिया जा सकता था वहां 11 छात्रों को, यदि आप, माननीय सभापति महोदय, इजाजत दें तो मैं शिक्षा मंत्रीजी को उनके नाम भी देने के लिए तैयार हूं, माइग्रेट करके यहां पर प्रवेश दिया गया और बैकडोर एन्ट्री देकर मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के स्तर को गिराने का दुष्चक्र किया गया। और भी बहुत सारी धांधलियां हैं मेडिकल बिलों की और भी हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स के उपर भी कहना है इसलिए मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरी एक डिमाण्ड है, जिन डाक्टर सक्सेना के बारे में मैंने निवेदन किया कि इनको गलत तरीके से प्रिन्सिपल बनाकर के यहां पर इस कालेज के स्तर को गिराने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय, सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करता हूं आज शिक्षा मंत्रीजी सदन को यह आश्वासन दें कि इस प्रकार की धांधली करने वाले प्रिन्सिपल को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं किया जायगा और उनको हटाये जाने की घोषणा आज शिक्षा मंत्रीजी को यहां पर करनी चाहिए।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, यहां पर एजूकेशन के बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं उस सारी बात के बारे में दो तीन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बातें ही आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगा राजस्थान के अन्दर 19 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत केवल मात्र 4 है। हमारी यह योजना थी कि किस प्रकार से सारों को शिक्षित करने के लिये अधिक से अधिक धन उपलब्ध करवाकर सारी व्यवस्था करा सकें। राजस्थान में 32 हजार गांवों में स्कूल खुलवाये जाने का लक्ष्य था। उस सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया व्यय करके राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराने की हमारे मन में इच्छा थी लेकिन जो मुझे लगता है और यह तथ्य भी है कि केवल मात्र 3 प्रतिशत छात्रों पर, जिनको यूनिवर्सिटी के अन्दर शिक्षा मिलती है उनके ऊपर करीब करीब सारा रुपया व्यय हो रहा है। मैं इसके बारे में अनुरोध करता हूं, मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारा योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिस योजना के अन्तर्गत हम इस बात को कम से कम देखें कि जितना भी सारा खर्च हो रहा है उस खर्च का समाज को लाभ मिल रहा है। आज भी बेकारी की समस्या शिक्षित नौजवानों में है और सभापति महोदय, मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में और दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में और पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्था है। उनके जिम्मे अलग से काम सौंपे जाते हैं। मान लीजिये कि किसी इण्डस्ट्री का सर्वे करना है तो उस इण्डस्ट्री के लगवाने की बात है तो वहां पर प्रोफेसर के जिम्मे, हैड आफ दी डिपार्टमेंट के जिम्मे इस बात की व्यवस्था रखी जाती है कि इण्डस्ट्री को रा मेटीरियल कहां से मिलेगा, क्या मार्केट का स्कोप है, उसकी वह रिपोर्ट दे। उसके बाद में यह जिम्मेदारी होती है कि इसका वहीं से खर्च अर्जित करें और सारे खर्च को चलाने की व्यवस्था करें। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां भी इस बात को सोचा जाना चाहिए। जो फैकल्टी वर्क कर रही हैं उनमें किस ढंग से क्या हो रहा है। आज राजस्थान के औद्योगीकरण की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा का ढंग इस प्रकार का होना चाहिए कि जो लड़के शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना चाहिए। हम योजनाबद्ध तरीके से विकास कर रहे हैं और उसके अन्दर यदि हमारे यहां से पढे लिखे आदमी बेरोजगार रहते हैं तो बहुत ज्यादा फस्ट्रेशन आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और फस्ट्रेशन आया हुआ आदमी बड़ी गड़बड़ियां पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात को भी देखें। यह बात तो सही है कि यूनिवर्सिटी में हमारा अभी दखल नहीं है लेकिन यह भी सही है कि सारा का सारा खर्चा चाहे भारत सरकार दे या राज्य सरकार दें।

खर्चा यूनिवर्सिटीज को सरकार की तरफ से मिलता है और राजस्थान के अन्दर क्या हिन्दुस्तान के अन्दर यह व्यवस्था नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज अपना खर्चा स्वयं ही कहीं से से डवलप कर सकें। तो मैं आपके माध्यम से इसके बारे में भी अनुरोध करूंगा।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

यहां पर कामर्स फेकल्टी के बारे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : कृपया जल्दी समाप्त करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : दो मिनट में में समाप्त कर रहा हूं। श्री के. एस. माथुर थे। लड़कों की जब परीक्षायें हो रही थीं उन्होंने खुद प्राध्यापकों को भड़काकर हड़ताल करवा दी। लाखों रुपया बरामद हुआ। उनको नाजायज तरीके से तरक्की दी गई। सारी व्यवस्थाओं को इस ढंग से जमाना चाहते थे। सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करें और जो भी अपराधी पाये जायं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की बात करें। श्री के. एन. चन्द्रशेखर, जिन्हें इन्होंने इसी प्रकार से नाजायज तरक्की देकर बैठाया था। उनके पीरियड में एक वर्कशाप लगाया था, हजारों रुपयों का गबन हुआ। मेरे पास तथ्य है। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सारे तथ्य उनको दे दूंगा जांच करायें ....

**एक माननीय सदस्य** : अब तक क्यों नहीं दिये ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : एक पुरातत्व विभाग के बारे में आपसे अनुरोध करूंगा, समय बहुत कम है। इतना ही कहूंगा कि थोड़ा बहुत समय और दिया जाय तो मैं समझता हूं पुरातत्व विभाग के माध्यम से राजस्थान की ओर अधिक तरक्की करवा सकते हैं। जहां जहां अच्छे स्थान है, टूरिस्ट सेन्टर डेवलप किये जा सकते हैं।

अन्त में मुझे यह बात निवेदन करनी है, सभापति महोदय, कि यह किस तरह से छोटे छोटे बच्चों में जहर पैदा करते हैं। भारत सरकार ने इस बात को समझ लिया है। सार्वजनिक स्थान पर भारत सरकार ने आर. एस. एस. की शाखा लगाने पर पाबन्दी लगाई है। इस बात के लिये निर्देश दे दिये हैं कि सार्वजनिक स्थान पर आर. एस. एस. की शाखा न लगे। मैं इस बात की घोषणा चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी घोषणा करें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर आर्डर···

**एक माननीय सदस्य** : आर. एस. एस. के नाम से क्यों चिढ़ रहे हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री बाढ़दयाल जोशी** : आप लोगों के···

**श्री सभापति** : आसन पैरों पर है·····

**श्री भैरोंसिंह गुर्जर** : यह सारे····

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य·······

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सभापति महोदय.

**श्री सभापति** : आप समाप्त करें माननीय सदस्य। एक मिनट से अधिक नहीं दूंगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सार्वजनिक स्थानों पर आर. एस. एस. की शाखा के लिए भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं क्योंकि इनकी तो योजना थी, पहले ललितकिशोर जी रहे, ये इसी घटक के रहे, श्री भंवरलाल शर्मा भी आर. एस. एस. के घटक के रहे···

(व्यवधान)

**श्री बाऊदयाल जोशी :** आपका लड़का आर. एस. एस. में जाता है ...

**श्री सभापति :** आप बड़े तजुर्बेकार सदस्य हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** सभापति महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं इन्होंने गांव गांव के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वहां पर आर. एस. एस. की शाखा लगती है। भारत सरकार ने इस बात को गलत समझा है। अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पाबन्दी लगा दी। स्वयं उनके गुरूजी ने कहा है। आपको याद दिलाऊं श्री देवरस जी ने कहा था कि 77 में हमने कांग्रेस को हराने के लिए प्रयत्न किये थे लेकिन 80 में हम चुप रहे। आर. एस. एस. एक राजनैतिक संस्था है जो देश में प्रजातन्त्र को खतरा पहुंचाने वाली जमात है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहां पर कोई भी शिक्षण संस्था हो, आर. एस. एस. से चाहे सीधा संबंध हो, चाहे परोक्ष रूप से हो, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

प्राइवेट संस्थाओं में हम पालिटिकल लेवल पर लड़ाई लड़ेंगे। स्कूल जैसी पवित्र संस्थाओं में इस प्रकार की जो शाखायें चलती हैं इसके लिये शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उस पर रोक लगायें और इस प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** एक मिनट में समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति :** एक एक मिनट करके आप 6 मिनट ले चुके हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** यह मसला ऐसा है ...

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आप शीघ्र समाप्त करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** यह इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके निकले हैं जैसा मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के बारे में उदाहरण दिया ...

**श्री मोहनलाल मोदी :** आपका लड़का आर. एस. एस. में जाता है उसका खण्डन आपने नहीं किया ....

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** सभापति महोदय, नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य को खुद को इस बात की जानकारी है कि मेरा लड़का आर. एस. एस. में जायेगा या आर. एस. एस. से लड़ेगा। 12 साल साल का बच्चा है। पता नहीं मेरे से क्यों कन्डेम करवाना चाहते हैं। सभापति महोदय, इसलिए आर. एस. एस. के लिए निवेदन करना चाहता हूं आदर्श विद्या मन्दिर नाम की संस्था है। पिछली बार हमने उसकी जांच करवाई। वहां के अध्यापकों के साथ....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** मैं यह अनुरोध कर रहा था, यहां इसी सदन के अन्दर बड़ी मांग हुई कि जांच हो। कई अध्यापकों ने शाखा लगाने से मना किया था उन अध्या—

(146)



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पकों को हटा दिया गया। उसके बारे में कार्यवाही हुई। इनका राज आया। शुरू से लेकर अन्त तक इनके मन में भावना थी, यह तो अच्छा हुआ, ढाई साल में कृष्णमुख हुआ नहीं तो इस मुल्क को कहां तक ले जाकर छोड़ते....

(समय, समाप्ति सूचक घण्टी)

आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे घोषणा करें इस बात की कहीं पर सार्वजनिक स्तर पर, किसी भी स्कूल में जो स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त है, आर. एस. एस. की शाखा नहीं लगने दी जायेगी और आर. एस. एस. की शाखा लगाते हैं तो सरकारी सहायता बिलकुल बन्द कर दी जाये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : एक सैकण्ड के लिए।

नाथूसिंह जी के बारे में स्पोर्ट्स कौंउ- सिल की बात करनी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं स्पोर्ट्स कौंउ- सिल में जो आपने 23 लाख रुपये रखा है केवल मात्र सरकार के अन्तर्गत छोड़ रखा है। स्पोर्ट्स कौंउसिल में किसी भी खिलाड़ी को चेयरमैन बनायें तो शायद ठीक ढंग से चल सके। पहले स्पोर्ट्स कौंउसिल के उपाध्यक्ष श्री नाथूसिंह जी थे। बड़े बड़े प्रक्रिया के कायदे कानून उठाया करते हैं। उनके जमाने में रूरल गेम के नाम से जो हजारों की गड़बड़ हुई, शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसकी जांच करवाई जाय, जो आरोप हैं, वे सत्य हैं या असत्य है उसके बारे में यह नहीं कहता कि वे आरोप सत्य ही होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो आरोप इन संस्थाओं में रहने वालों पर लगते हैं ये सत्य हैं। जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया है, उसके दुरुपयोग की जांच होनी चाहिये। और नयी स्पोर्ट्स कौंउन्सिल का गठन किया जाना चाहिए। यही बात कहकर मैं संस्कृत एजूकेशन के बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा। संस्कृत एकेडेमी की स्थापना की आवश्यकता यहां है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एकेडेमी चलाते हैं, उनका काम ठप्प पड़ा है। मैं इसके बारे यह निवेदन करूंगा कि उन एकेडेमी को सक्रिय करें ताकि हमारे यहां शिक्षा का जो नियम है वह सारा ठीक ढंग से काम चले और यहां पर जो यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक और प्रौढ़ शिक्षा तक आर. एस. एस. के लोगों ने घुस करके सारी एजूकेशन को बर्बाद किया है उसको ठीक करवाने की बात करें। छोटे मोटे ट्रांसफर्स को लेकर के पता नहीं कितना इन्होंने वो किया है लेकिन मैं कहता हूं कि यह ऐसी जड़ यहां लगाकर गये हैं कि अगर इसको मजबूती के साथ नहीं उखाड़ा गया तो यहां यह जड़ हमारे प्रजातन्त्र के ढांचे को भ्रष्ट करने वाली जड़ है इसको जितनी जल्दी कुचल सकें उतना ही जल्दी हमारे राजस्थान के ऊपर कार्यवाही कम करेगी।

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : सभापति महोदय, आपको पहले पता नहीं हुआ ये तो तब से ही थे।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मुझे तो कांग्रेस का पता है या नहीं है पर आप को तो आर. एस. एस. का जन्म दिवस ही ज्ञात नहीं है। मुझे यह मालूम है कि आपने कभी भी आजादी के आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। एक भी आदमी का नाम ले लें।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मैंने आजादी में हिस्सा लिया था। आप कह रहे हैं आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गये थे, हम गये थे ...

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय जोशी जी, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : आजादी के तहत आपको बन्द नहीं किया था, आपको तो इमर्जेंसी के अन्दर बन्द किया था।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय जोशी जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी मुझसे जानकारी चाही थी विपक्ष दल के नेता महोदय,ने टाइम के बारे में, आपके दल का समय 15 मिनट था, आपने 14 मिनट का समय ले लिया है परन्तु फिर भी इसके बावजूद मैं आपको समय दूंगा। धैर्य रखें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : श्री त्रिलोक सिंह।

**श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर)** : सभापति महोदय, यह देश के लोगों के साथ क्या मखौल हो रहा है, इधर वाले कहते हैं कि इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया और फिर इधर वाले कहते हैं कि इन लोगों ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। हकीकत क्या है ?

(व्यवधान)

जो किसान और मजदूर थे, उन लोगों को आप लोगों ने लूटा है। पहले हमें जागीरदार गांव में स्कूल नहीं खोलने देता था और तीस साल तक कांग्रेस ने गांव के किसानों को शिक्षा से वंचित रखा है।

(व्यवधान)

आज भी देश जैसा है, जो लोग हमें रोटी देते हैं, जो किसान लोग आप लोगों को मक्खन देता है और जो ठण्डी रोटी और छाछ पीकर अपना गुजारा करता है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। हालात ऐसे बनाये हैं आप लोगों ने, शिक्षा का ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि किसान का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। 32 साल के बाद अगर किसान का बच्चा सो में से 95 स्कूल नहीं जा सकता है तो आग लगे ऐसी आजादी में, ऐसी आजादी से गुलामी अच्छी। क्या मिला देश के किसानों को। आज गांव की बच्ची पांचवीं तक स्कूल में पढ़कर कहां जायेगी। शहर में क्या व्यवस्था है उसके ठहरने की। आज अगर वह कस्बे में जाय, किसी भी जगह पर जाय, जयपुर में जाय, 400 रुपया खर्चा है, कहां ठहरेगी गांव की बच्ची, इसका जवाब दें शिक्षा मन्त्री महोदय, देश के साथ क्या किया ? न तो इलाज इसका इससे है कि स्कूल कम खोले जायें या ज्यादा खोले जायें, इलाज यह है कि यह शिक्षा पद्धति खतम की जाय। कुल शिक्षा का नेशनलाईजेशन किया जाय। शिक्षा प्राइवेट हैण्ड्स में खतम की जाय और यह पब्लिक

(148)



(श्री त्रिलोक सिंह)

स्कूल्स खतम किये जाये। याद रखो जब आपको खेत में भेजा जायगा और तब आप लोगों की अक्ल ठीक होगी।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री त्रिलोक सिंह :** जनता का खून पीने वालों का, लोगों के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने देने वालों का, खेतों में बच्चे उनका हाल क्या हुआ? हिन्दुस्तान भी उस हालत में बरी नहीं रह सकता पर आज किसान क्या कहता है कि 32 साल तक आप लोगों ने क्या किया। आप इस अपराध से बरी हो सकोगे क्या? आप कहते हैं ढाई सालों में इन लोगों ने गड़बड़ी की, ढाई सालों में मान लीजिए इन लोगों ने गड़बड़ी की। क्या भूल गये, कहते हैं नेकर वालों ने और चोकी वालों ने गड़बड़ी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को मैं तस्लीम भी कर लूं कि ढाई साल में इन्होंने गड़बड़ी की, 32 साल में आपने क्या किया?

(व्यवधान)

आप अपराधी हैं वोह जुल्म किये जनता के साथ, देश के आवाम के साथ, देश की उस जनता के साथ जो आपको रोटी देती है, वक्त मुसीबत में आपकी हिफाजत करती है और देश की खातिर खून देती है पर उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। उसका बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसकी बच्ची पढ़ नहीं सकती। यह कैसी व्यवस्था, यह कैसी आजादी इस तरह की आजादी का वोह क्या करेगा। इसलिए आज अगर चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार कुछ कर जाय तो हमें सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें और ये पब्लिक स्कूल्स जहां शैतान पाले जाते हैं जहां लोगों के मुंह से रोटी छीनकर ऐसे भ्रष्ट लोगों, लुटेरे लोगों को पैदा किया जाता है जो हकूमत का ख्वाब देखते हैं।

इतिहास बतायेगा कि हकूमत कौन करेगा, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला करेगा या खेती करने वाला मजदूर करेगा। जागीरदार का लड़का करेगा या वह चमार का लड़का करेगा। यह इतिहास बतायेगा, हिन्दुस्तान में। हमारे पर हरिजन का लड़का चीफ मिनस्टर बना, यह ढोंग है, अव्वल दर्जे का ढोंग है, यह लोगों को धोखा देने का ढोंग है क्या मिला गरीब को, गरीब चमार को क्या मिला, खटीक को क्या मिला?

**एक माननीय सदस्य :** आज चीफ मिनिस्टर बन गया।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री त्रिलोक सिंह :** जो जायदाद है, जो जमीन है ...... (व्यवधान) ......

एक श्री पहाड़िया को चीफ मिनिस्टर बनाने से गरीब का क्या भला हो जायगा। कितने गरीब के लड़के आज स्कूल नहीं जा सकते। वोह पहाड़िया जी हैं नहीं अगर होते तो मैं कहता आपने जाकर; उन मोहल्लों में जाकर गरीबों की कॉलोनीज में उन्होंने जो झोंपड़ियां बनायी थीं वो ताकत से, पुलिस के जरिये तोड़ दी गयीं और ये टोपी लगाकर कहते हैं कि हम गांधी के चेले हैं। अगर गांधी का यह ख्वाब था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने ही तोड़ी हमने तो एक भी नहीं टूटने दी ।

श्री त्रिलोक सिंह : अगर यह गांधी का ख्वाब था, अगर 32 साल के आजादी के बाद गरीब का लड़का स्कूल नहीं जा सकता तो मैं कहूंगा कि × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य पुनरावृत्ति नहीं करें । कोई नई बात कहनी हो तो कहें ?

श्री त्रिलोक सिंह : नई बात यह है कि गरीब का लड़का स्कूल जा सके, इसकी आप व्यवस्था करें और ये प्राइवेट स्कूले बन्द करें प्राइवेट स्कूल खत्म किये जाय, यह नई बात का सुझाव देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति आर्डर प्लीज ।

श्री त्रिलोक सिंह : सरकार 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसी कीमत पर निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करें और सरकार उनकी शिक्षा का खर्चा उठाए । यह कानून बनाए कि हर बच्चे को . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोकसिंह : जो स्कूल आने लायक है, वह स्कूल जाएगा, यह सरकार कानून बनाए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न डालें आप ।

श्री त्रिलोक सिंह : आप लोग किसानों के वोट लेकर के आये हो । किसानों ने आपको इसी उम्मीद पर वोट दिया है कि आप उनकी जिन्दगी के लिए, उनके बच्चों के लिए, बच्चों की जिन्दगी के लिए आप कुछ बोलोगे, कुछ करोगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांइन्ट आफ आर्डर ।

श्री त्रिलोकसिंह : इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं . . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब पोइन्ट आफ आर्डर हो तो कृपया आप स्थान ग्रहण कर ले ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने भी भाषण देते हुए जोश में आकर यह कहा है कि × ×

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं नहीं, ऐसा कुछ नही कहा है । मैने खुद ने सुना है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य आर्डर प्लीज....माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कार्यवाही देख लें । गांधीजी हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम जानते हैं कि गांधीजी के नाम पर ये सी. पी. एम. के लोग कही पर भी कुछ भी कह देते है .

---

× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गयी

**श्री सभापति :** अगर गांधीजी के प्रति कोई भी अपशब्द कहा गया है तो कृपया उसे एक्सपंज कर दें।

आप आरम्भ करें माननीय सदस्य।

**श्री त्रिलोक सिंह;** सभापति महोदय, यह गलत बात है कि गांधीजी के प्रति मैंने कोई अपशब्द कहा है। जो भाषण में मैंने कहा वह यह था कि गांधीजी के राज में बतीस सालों के बाद भी गरीब का लड़का स्कूल नहीं जा सकता और वह जागीरदार का लड़का कुलक का लड़का पब्लिक स्कूल में जाता है और वहाँ उनका खून चूस कर ...

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री त्रिलोक सिंह :** एक मिनट और बोल लूं।

**श्री सभापति :** हां, एक मिनिट बोल लीजिए।

**श्री त्रिलोक सिंह :** मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बिना परेशानी के किसानों के वोट लेकर आये हो, अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी शिक्षा पद्धति के लिए क्या आप बल देंगे....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री त्रिलोक सिंह :** अपनी ओर से इस सदन में इस बात के लिए बल दोगे, वोट दोगे, राय दोगे, कि वह गरीब का बच्चा स्कूल जा सके इसकी व्यवस्था हो सके। और यह प्राइवेट धन्धों की वजह से एक तो वे इलाके बर्बाद होते है और दूसरा हमारा मास्टर वर्ग है, टीचर वर्ग है वह लुट जाता है कालेजों में स्कूलों में। हमारा पैसा सरकार से प्राइवेट संस्थायें लेती हैं और उधर उन मास्टरों की जिन्दगी पर तलवार टंकी रहती है। चाहे गांव का स्कूल हो, चाहें विश्वविद्यालय हो और चाहे वह महाविद्यालय हो, जिनकी जिन्दगी, जिनकी नौकरियों का कोई भी पता नहीं, प्राइवेट संस्थायें चाहे जब निकाल देती हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि देश के उन आम लोगों जिनकी संख्या सौ में से 95 है, के बच्चे भी स्कूल जा सकें और इन प्राइवेट स्कूलों का

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नेशनेलाईजेशन करें।

**श्री सभापति :** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री त्रिलोकसिंह :** और इन संस्थाओं को आप अपने हाथ में लें।

**श्री सभापति :** श्री चन्द्रवीरसिंह।

**श्री मेघराज तावड़:** माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है....

**श्री सभापति :** अभी मेरे पास बहुत लम्बी सूची है माननीय सदस्य, मैं आपको भी अवसर दूंगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा।

**श्री मेघराज तावड़:** मेरा नाम तो पहले ही आ चुका था। मैं कमेटी में गया हुआ था।

**श्री सभापति** : मैं आपको भी अवसर दूंगा। मेरे पास लम्बी सूची है। आप धैर्य रखें।

**श्री मेघराज तावड** : मेरी पार्टी के हिसाब से मेरा नम्बर पहले ही आना चाहिए था।

**श्री सभापति**: आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : सभापति महोदय, मेरा नाम भी पहले आ जाना चाहिए था। आप महिलाओं के साथ तो प्राथमिकता देते हैं लेकिन जो हम कम उम्र के सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी बहुत भी प्राथमिकता नहीं देते। हमें भी बोलने का अवसर दीजिए।

**श्री सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : सभापति महोदय, हम नाबालिगों की तरफ ध्यान दें...

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। आप आरम्भ करिये माननीय सदस्य। पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

**श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर)** : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का विकास किसी भी राष्ट्र के पूर्ण विकास, चरित्र निर्माण और आत्म विश्वास को पैदा करने का आधार है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई असंतोष की स्थिति और बेरोजगारी की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो कि इस तरह बढ़ती हुई इन समस्याओं के अनुरूप नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**एक माननीय सदस्य** : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य पढ़ करके भाषण दे रहे हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें माननीय सदस्य। आप आरम्भ करें मेरी जानकारी के अनुसार आप प्रथम बार बोल रहे हैं। आप आरम्भ कीजिए।

**श्री चन्द्रवीरसिंह** : उसका आमूलचूल परिवर्तन करके अधिक से अधिक कार्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण बनाये और उसके लिए शिक्षा प्रणाली को....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप पढ़ें नहीं। आप कंसल्ट कर लें नोट्स को।

**श्री चन्द्रवीर सिंह** : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की जो प्रणाली इस देश में तीस वर्षों से चलती आ रही है वह अब इस युग में अनुकूल नहीं है। आज की शिक्षा प्रणाली वर्क ओरियेंटेड होनी चाहिए न कि डिग्री ओरियेन्टेड हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अपनी कुछ यूनिवर्सिटीज जिनसे छात्र पास आउट करके जाते हैं उनको हिन्दुस्तान की कई व्यापारिक संस्थाये लेने में संकोच करती हैं और इन यूनिवर्सिटीज जिनसे छात्र पास करते है व्यापरिक संस्थाये अपने इश्तहार में यह लिखती हैं कि फलां फलां यूनिवर्सिटी के छात्र कृपया इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके बारे में, इस सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी करें क्योंकि राजस्थान की इज्जत का सवाल है। श्रीमान्, शिक्षा की आज जो नीति चल रही है अगर यही चलती रही तो हिन्दुस्तान

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

में बड़ी भारी विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। इस नीति से अगर आप चले तो मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जब इसका विस्फोट होगा तो आप लोग इसको कोई भी नहीं संभाल सकोगे।

शिक्षा की नीति के साथ साथ स्थानान्तरण की नीति है। आपकी स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानान्तरण की जो नीति आपने बनाई है, यह डेफिनेट आउट लाईन पर होना चाहिए। अगर आपने डेफिनेट आउट लाइन नहीं दी तो यह स्थानान्तरण की जो नीति है आपकी ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज : आपस में बातें नहीं करें माननीय सदस्य।

व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य के बीच में।

श्री भैरूसिंह गूजर : आपके समय में ऐसा ही होता रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान होता है। आपस में बातें नहीं करे। आप आरम्भ रखिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह : स्थानान्तरण की नीति आपने निर्धारित नहीं की तो ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीर सिंह : बड़ा भारी असंतोष होगा और बच्चों की पढ़ाई में बड़ा भारी व्यवधान पैदा होगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा और अन्त में यही निवेदन करूंगा कि आप भारत सरकार को आपके माध्यम से अनुरोध करे कि पूरे राष्ट्र की एक ही एजुकेशन पालिसी होनी चाहिए। चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह कालेज हो। नहीं तो होता क्या है कि कोई यूनिवर्सिटी के छात्रों को तो प्राथमिकता दी जाती है और कोई यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस प्राथमिकता से वंचित रखा जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर के जो सम्भाग हैं, ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं आप जो भी शिक्षा की नीति निर्धारित करें, इस पिछड़े हुए सम्भाग और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे यह अनुरोध नहीं करना चाहता कि आप कहां स्कूले खोलें, कहां कालेज खोले। आप स्वयं इस क्षेत्र से परिचित तो शायद नहीं है लेकिन अब जरूर हो जावेंगे। इस क्षेत्र में क्योंकि पापूलेशन कम है ...... ......

(व्यवधान)

मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप इस क्षेत्र का पूरा ध्यान रखें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को कृपया बोलने दीजिए। जारी रखें।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में 28 वर्ष बाद पहली दफा यह सांस ली गई कि हम भी राजस्थान के एक अंग हैं। लेकिन आज जो पश्चिमी राजस्थान के साथ हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आप फिर

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

उसी पुरानी नीति के सहारे, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को राजस्थान का भाग नहीं माना जाता है, उतर आये हैं, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ पश्चिमी राजस्थान के बारे में बातें कही हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। श्रीमान्, शिक्षा की नीति आप जो भी निर्धारित करें, हमें उसमें बीच में नहीं पड़ना है। लेकिन स्कूल खोलते समय आप इतना जरूर ध्यान रखें कि इस क्षेत्र की अवहेलना नहीं हो। इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कालेजेज खोले जायं। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद

**श्री सभापति** : श्री वृजसुन्दर शर्मा।

**श्री वृजसुन्दर शर्मा** (बून्दी) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में कहूं, दो बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, ताकि रह नहीं जायें। पहली बात तो यह है कि यहां बून्दी जिले में दसवीं कक्षा तक तो सब स्कूलों में एग्रीकल्चर का विषय है, लेकिन उस जिले में किसी भी हायर सैकण्डरी स्कूल में एग्रीकल्चर का विषय नहीं है। दूसरी बात, यहां दसवीं कक्षा तक तो बैंकिग है, लेकिन ग्यारहवीं कक्षा में टीचर न होने की वजह से बैंकिग नहीं है। तीसरी बात, एक दूसरा हाई स्कूल है, संख्या तो बहुत हो गई है, लड़के बहुत बढ़ गये, एक बालचन्द पाड़ा स्कूल है, उसमें साइन्स की कक्षा खोलने की कृपा करेंगे हमारे शिक्षा मंत्री जी। इतनी बात कहकर मैं अपने दूसरे कटमोशन पर आता हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान की यूनिवर्सिटी को देखकर के बड़ी मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है कि हमारे यह सरस्वती के मन्दिर आज के दिन राजनीति के अखाड़े बन गये हैं। आये दिन वहां के प्राध्यापकों में झगड़े होते हैं, शिक्षार्थी दो गुटों में बंटे हुए हैं। पक्षपात, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में इस असंतोष के कारण पढ़ाई तो कम होती है, लेकिन आपाधापी ज्यादा।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े काबिल लोग इसके वाइस चांसलर रहे हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर इतना गिर चुका है, यहां के प्रोफेसरों में शायद सातवें-आठवें नम्बर पर आने वाले, माननीय श्री इकबाल नारायण जी हैं उनको यहां पर वाइस चांसलर बनाया गया। क्या उनमें ऐसी बात थी? कौन सी ऐसी उन्होंने शिक्षा की सेवा की है? क्या उनका इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में नाम है? लेकिन वह नियुक्तियां केवल इसलिए की जाती हैं कि बदलते हुए जमाने में बदलते हुई सरकार है, वह सरकार की बात को मानें, उनकी नीतियों के ऊपर चलें।

1977 में, माननीय सभापति महोदय, सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने यह समझा एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को जीत लिया है। इन सब लोगों को हटा दिया जाना चाहिये। जो हमारी नीतियों में हमारे असूलों में, हमारे अधिनायकवाद तरीके में विश्वास नहीं करके केवल अपने आप की एक दूसरी दिशा में ले जाने वाले हैं। कई प्रोफेसरों, कई लेकचरर्स को जबर्दस्ती, उनके यहां पर शिक्षार्थियों को भेजकर उनके स्तीफे लिये गये और अपने आदमियों की जगह करने के लिए 1977 में आप देखेंगे, कितने आदेश इस

(154)



(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यूनिवर्सिटी से पारित हुए हैं, जिसके जरिये 120 प्राध्यापकों को यूनिवर्सिटी से निकाला गया। और उनके लिए जो शाखाओं में जाते हैं, शाखाएं लगवाते हैं, उनकी क्वालीफिकेशन कुछ भी हो, जगह पैदा करने के लिए 120 व्यक्तियों की भर्ती ऐसे लोगों से की गई, जो न शैक्षणिक योग्यता रखते थे और न उनका बाकायदा किसी तरह से चयन ही हो सकता था।

प्रमोशन में धांधलियां, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, और हमारे शिक्षा मंत्री जी के, कहां पर हैं आज पाण्डेयजी, कहां गये हरगोविंद पंथ, कहां है आगले, कहां है भल्ले, ऐसे ऐसे लोग जो क्रियेटिव जीनीयस के लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी की है, उनको निकाल करके, राजीव शर्मा, अशोक भल्ले, प्रकाश परमिल, ऐसे ऐसे लोगों को निकाल करके, भर्ती किन लोगों की की गई प्रमोशन किन लोगों का किया ?

आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गये। क्या उनमें प्रोफेसर बनने की योग्यता थी ? और बैक डोर एन्ट्री से अपनी बीबी को वहां पर लेक्चरर्स बनवा दिया।

**एक माननीय सदस्य :** डूब मरो।

**श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह :** आपके लिए कह रहे हैं। नटराज होटल।

**एक माननीय सदस्य :** सुनिये सुनिये, सुनने की हिम्मत रखिये।

**श्री सभापति:** आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में बात न करें। माननीय सदस्य जारी रखें।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, वे चीजें नहीं हैं, डॉ० अमरजीत सिंह, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, उनकी योग्यता क्या है ? क्या वह इलीजेबल थे ? कैसे इलीजेबल हुए ? जब उनमें योग्यता नहीं थी, उनको बुलाना नहीं चाहिये था, बुलाया गया, रखा गया, और आज मैं कह सकता हूं, इस बात की जांच की जाये तो यह पता लगेगा कि वह इलीजेबल नहीं थे, क्या योग्यता थी डॉ. आर. एन. सिंह, जो बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको क्यों प्रमोशन दिया गया ? मेरे पास दसों मिसालें प्रोफेसर्स की मौजूद हैं, जिन्हें प्रोसेसर्स की योग्यता के मुताबिक नहीं बनाया गया। और दीक्षित साहब ठीक हैं, आपके आर. एस. एस. के हैं, लेकिन सलेक्शन कमेटी के सामने गये थे ? आकर कर दी गई प्रोफेसरशिप की। सलेक्शन कमेटी के सामने गये ? लेकिन वह अपने थे। मैं इसी तरह से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कई इंजीनियर्स के बारे में कई लेक्चरर्स के बारे में, जो अयोग्य हैं लेकिन उनको क्वालीफिकेशन केवल यह है कि वह एक अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं। आर. एस. एस. के सपोर्टर्स हैं जनता पार्टी का उन्होंने खुल कर समर्थन किया है इसलिए वहां पर उनको नियुक्त किया गया है। इस अर्से में, मैं सभापति महोदय, देखता रहा, हाई कोर्ट में कितनी रिटें दायर हुई है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में रोज कोई न कोई मिलता कि आज यूनिवर्सिटी की फलां रिट है, आज

( श्री बृज सुन्दर शर्मा )

फलां रिट है, और उन फलां रिट्स में क्या क्या आरोप लगाये हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन वह सारा विवरण देना मेरे लिये, सभापति महोदय, इस समय में बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, खर्च आज हम अनुदान देते हैं, यूनिवर्सिटी को। क्या यूनिवर्सिटी की फाइनेन्सियल कंडीशन सुधरती जा रही है ? क्या वहां पर खर्चों पर नियंत्रण हैं ? हम यूनिवर्सिटी में अपने एकाउन्ट आफिसर भेजते है. फाइनेन्स वाले हैं, एक अग्रवाल साहब, उनकी टर्म खतम हो गई। यूनिवर्सिटी ने नाम मांगे सरकार ने कह दिया उनका एक्सटेन्शन कर दिया जाय, आजकल किसी को एक्सटेन्शन नहीं मिलता है वहां पर, लेकिन मिल गया क्योंकि एक अमुक नीति के समर्थक थे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं आज डिपार्टमेंट आफ ड्रेमेटिक्स क्रियेटिव हाबीज और इन सब बातों के लिए जो डिपार्टमेंट के लिए पैसा नहीं है उनको बढ़ाने के लिये कोई पैसा नहीं है। जो जरूरतमन्द लड़के वहां जाते हैं वे वहां जाना बन्द कर देंगे उनके दिमाग दूसरी तरफ लग जायेंगे इसलिए उनका ध्यान एक ही तरफ जाता रहे इसके लिये कोई क्रियेटिव एक्टीविटीज के लिये उनको पनपाने वालों को कोई पैसा नहीं देंगे बल्कि उन डिपार्टमेंट्स को बन्द करने की बात की जाती है।

आप ताज्जुब करेंगे कि यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के लिये रजिस्ट्रार है अलग से। एक लाख का हर साल खर्चा हो जाता है कोई देखने वाला नहीं है इस चीज को। अगर आपको पता लगाना है अपने रिजल्ट का तो 200 रुपये खर्च कर दें, पता लग जायगा। सीक्रेट डिपार्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई प्रोफेसर विरोध करता है तो उसको पिटवाना बायें हाथ का खेल है। कितने लोगों को परेशान, विक्टिमाइज किया गया, निकाला गया वहां से और कैसे लोगों को रखा गया इस बारे में मैं समझता हूं एक कमेटी बना कर जांच करेंगे तो पता लगेगा। गोल्ड मेडलिस्ट वहां रह जाते हैं और कम योग्यता वालों को ले लिया जाता है। कहां जायगा गोल्ड मेडलिस्ट ?

शिक्षा में सुधार की बात की जाती है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कितने लड़कों को जाब मिली ? क्या उनकी कोई क्रियेटिव वर्क है ? कितने आई. ए. एस. में गये या दूसरे कंपीटिशन में कामयाब हुये ? उसको देख कर पता लगेगा, राजस्थान का पर्सेंटेज है वह बहुत कम मिलेगा और वह इस कारण से है कि हमारी यूनिवर्सिटी में शिक्षा का जो क्रम है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों को वहां पर सिखाया जाता है उससे वे शिक्षा ग्रहण नहीं करते। वे दूसरी प्रवृत्तियों में चले जाते हैं।

मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में अनुशासन क्यों नहीं है। छात्र दो गुटों में क्यों बटे हुये हैं इसका श्रेय किसी को है तो वहां के प्रोफेसर और स्टाफ को है।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

कितने लोगों को यहां आने के बाद डीग्रेड किया गया। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को सेक्शन आफिसर बना दिया गया। कितने लोग वहां पर जो प्रवृत्तियां हैं उनको ··

( व्यवधान )

(156)



(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

आप सुनिये, कितनी मीटिंग होती है। इनके ग्रुप बने हुये हैं जिसके जरिये एडमिनिस्ट्रेशन पर छाये हुए हैं इसलिए अगर यूनिवर्सिटी में सुधार करना है और यहां की शिक्षा को आगे बढ़ाना है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : तो मेरा कहने का मतलब यह था कि डेफिनेट आइडियोलोजी वालों को इस यूनिवर्सिटी में कितना परेशान किया जाता है जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं उनको कितना परेशान किया गया है और जो आर. एस. एस. से सम्बन्धित लोग है उनके साथ क्या पक्षपात हुआ। इसकी मिसाल मैं शिक्षा मन्त्री जी को दूंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि वास्तव में ढाई साल में किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की हालत इतनी खराब हुई है इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य नाराज होते हैं लेकिन हकीकत क्या है किस तरह से हम बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं। एक तरफ अधिनायकवाद की शिक्षा देते हैं, उनको कहते हैं अनुशासन की बात मत मानो, इस तरह की शिक्षा आज वहां पर है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : छात्र लोग एक प्रोफेसर के कहने पर दूसरे प्रोफेसर के मकान पर हमला करने को उतारू हो जाते हैं, झगड़े होते हैं और इसका एक मात्र कारण है हमारी यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर न रह कर राजनैतिक अखाड़ा बनती जा रही है और किस तरह से फासिज्म की प्रवृत्ति वाले लोग शिक्षण संस्था को बर्बाद करते हैं। दकियानूसी शिक्षा से दिमाग का विकास नहीं होता, दिमाग की खिड़कियां बन्द कर दीं और उम्मीद करते हैं कि नई हवा का प्रवेश हो उनमें, तो वे किस तरह से देश को प्रगति पर ले जा सकते हैं?

आज धर्म के नाम पर बड़ी-बड़ी बात होती है जो दकियानूसी दिखाई जाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों से बच कर शिक्षण संस्थाओं में ऐसी शिक्षा दी जाय, छात्र ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि वे योग्य से योग्य बन सकें और देश की सेवा कर सकें।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : सभापति महोदय,

(व्यवधान)

कोई बात नहीं, हंसिये मत। माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा के ऊपर मांग संख्या 24 पर, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस ओर कि हम शिक्षा की बात करते हैं। 31 साल से बात करते आ रहे हैं और आजादी के पहले यह था कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में लोगों को कम से कम प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था थी। श्रीमन्,

( श्री मेघराज तावड़ )

30 साल में, मैं कहना चाहूंगा आज 14 साल के, 10 साल के बच्चे होटलों में काम करते हैं, उनके मां-बाप छोड़ कर जाते हैं कप-प्लेट धोते हैं, उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं फिर भी जूते मार कर काम लिया जाता है और 15–20 रुपये देते हैं। जहां कम्पलसरी शिक्षा दी जाय, जहां 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने की हमारी नीति होती तो हमारे बच्चों की यह हालत नहीं होती।

श्रीमान्, प्राईमरी शिक्षा की हमारी हालत यह है। सबसे पहले मैं गांवों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके द्वारा, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा हमारे इलाके में, मैंने पहले भी कहा कि कोटड़ा में 27 स्कूलें बंद हैं। जहां 27 स्कूलें बन्द हैं, श्रीमान्, शिक्षा की बात करते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, साथ-साथ यह भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्राईमरी स्कूलों में जहां 60–70 बच्चे हैं वहां एक शिक्षक है और श्रीमान्, उन बच्चों को पानी पिलाने के लिए चपरासी की व्यवस्था नहीं। एक चपरासी को पानी पिलाने के लिये रखा जाता है उसको 7 रुपये देते हैं जबकि मिनिमम् वेजेज भी इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा. श्रीमान्, क्या बात हो सकती है और इन बच्चों को क्या सुविधाएं दिला-पाएंगे। श्रीमन, सैकण्डरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का आप गांवों में जाकर मुआयना करें तो मालूम होगा कि आपके बच्चे छप्पर के नीचे पढ़ते हैं। बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। काम के बदले अनाज योजना में कहीं पर स्कूल भवन बने हैं। काम शुरू हो गया स्कूल भवन का लेकिन स्कूल बन्द हैं। जहां भी सरपंच ने घोटाला किया, वहां के स्कूल भवन का पहली बरसात में नाम मिट गया। इनका नाम आप चाहेंगे तो सदन की टेबल पर रख दूंगा। स्कूल भवन बरसात आते ही गिर गया। बच्चे स्कूल में होते तो क्या होता ? श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे जनता पार्टी वाले हों, यह जो प्रजातन्त्र की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं तीस साल में जो भ्रष्टाचार हुआ परन्तु समाजवाद का नाम लेकर इन लोगों ने किस तरह से शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार किया है, वह हर डिपार्टमेंट में फैल रहा है। जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं वे इस तरह की बात करते हैं। वे समाजवाद और गरीबी को मिटाने की बात करते हैं। आज जो घोटालों की बात है। तीस साल से ये राज कर रहे हैं। शिक्षा में राजनीति के अखाड़े खुल गये। दूसरे श्रीमान्, ढाई साल में भी इस तरह के घोटाले हुए वे तीस साल से ज्यादा घोटाले हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि वे आर. एस. एस. के ऊपर बेन लगावें। मैं शिक्षा मंत्री जी, आपको कहना चाहता हूं जिस तरह हनुमान ने लंका को ढहाया था, जलाया था, उसी तरह आपका नाम भी हनुमान है। शिक्षा जगत में हनुमान बन कर क्या आप इस आर. एस. एस. को जला पाएंगे ? नहीं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री मेघराज तावड़** : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सैकण्डरी स्कूल, गांवों के लम्बे क्षेत्र में चले जाइये वहां पर ये सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल बहुत ही कम हैं। मैं

(158)



( श्री मेघराज तावड़ )

शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री जी, जो गांव के इलाके हैं, आदिवासी इलाके है, उस इलाके में मिडिल स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल खोले जाएं और हर स्कूल में कामर्स, साइंस, बायलोजी खोली जाय ताकि वहां के बच्चे पढ़ सकें क्योंकि वे शहर में आकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है। यह महंगी शिक्षा है। प्राइवेट स्कूलों की बात की जाती है। आज प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से भ्रष्टाचार है.......

( समय समाप्ति सूचक घण्टी )

अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए है।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य आपको 6 मिनट हो चुके हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

**श्री मेघराज :** आप मुझे बोलने दीजिए आज जितने प्राइवेट स्कूल हैं इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके रिश्तेदारों से फीस वसूल की जाती है उनसे भारी चन्दा वसूल किया जाता है। और दूसरी तरफ सरकार से वे 90 प्रतिशत, 60 प्रतिशत एड लेते हैं। क्यों एड दी जाती है ? दूसरी तरफ इन प्राइवेट स्कूलों को कहा जाता है कि आप एड लेते है तो जो सरकारी नीति है, जो सरकारी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ाई करानी होगी। यह जो सरकार की नीति है वह मिटानी चाहिए। आप कहते हैं हम प्रयोग करना चाहते हैं अगर प्रयोग करना है तो उनको राज की नीति से मत बांधो। उनको खुला छोड़ दो। उनको चरित्र निर्माण की बात करने दीजिए उसके बाद आप एड दीजिए। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में सोचे और इन प्राइवेट स्कूलों की एड बन्द की जानी चाहिए। आज जो प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है। सेन्ट मेरी, सेन्ट पाल में गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है। गरीब बच्चे को कम्पीटिशन में लाना है तो ये प्राइवेट स्कूल बन्द करने होंगे जब तक ये स्कूल रहेंगे कोई गरीब बच्चा आई. ए. एस. आई.पी.एस नहीं बन सकता है। उनके मुकाबले कम्पीटिशन में नहीं आ सकता है। आज शिक्षा कितनी मंहगी हो गई है। एक डाक्टर की पढ़ाई पर पचास हजार रुपया खर्च करना होता है। एक इन्जीनियर की पढ़ाई पर पचास हजार रुपया खर्च होता है मैं कहना चाहता हूं, जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि वे अपने बच्चे को डाक्टर, इन्जीनियर बना सकें ? बड़े बड़े आई.ए.एस., आई. पी. एस. के बच्चे या पूंजीपतियों के बच्चे ही बनेंगे। फिर कहते है कि हमारा कानून लागू नहीं होता। ये लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। संविधान के अन्तर्गत जो यह भेद भाव है वह मिट जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल बन्द किए जाने चाहिए।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

सभापति महोदय, मैं आई. टी. आई. शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देश की गरीबी मिटाने के लिए यह शिक्षा बहुत आवश्यक है। बच्चे पढ़ लिख कर जवाब कर सकते हैं लेकिन आई. टी. आई. के ट्रेनिंग स्कूल बहुत ही कम हैं। जो गरीब बच्चे टेक्निकल एजूकेशन

( श्री मेघराज तावड़ )

करना चाहते हैं वह दर दर भटकते है। उनको एडमिशन नहीं मिलता है। एक बार एडमिशन न हो तो उनकी जिन्दगी बेकार हो जाती है। वह किसी काम का नहीं रहता है। श्रीमान मैं आपका ध्यान कला की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। हम जिस कला और संस्कृति की बात करते हैं, श्रीमन्, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह जो कत्थक कला केन्द्र है जयपुर घराने का जो व्यक्ति संसार प्रसिद्ध था, आज उसकी हालत क्या है? हम कला की दुहाई देते हैं। वह किस तरह से मजबूर है और वह हिन्दुस्तान छोड़ कर जाने को तैयार है। हमारी अकादमी की ओर से 100 रुपये की वृत्ति दी जाती है। आज हम कलाकार, विद्वान के सम्मान की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसके लिए ज्यादा बजट रखा जाए।

श्रीमन्, हमारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की क्या हालत है। श्रीमन्, राजकीय विद्यालयों और प्राइवेट विद्यालयों में क्या फर्क है वही पाठयक्रम वहां पर है और वही पाठ्यक्रम प्राइवेट कालेज में है। दोनों जगह पर एक ही पाठयक्रम की शिक्षा दी जाती है परन्तु उनको तनख्वाह कम दी जाती है। न उनको कोई पदोन्नति दी जाती है। 15 साल की सर्विस होने पर भी तीन महीने की तनख्वाह देकर उसको निकाल दिया जाता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक मिनट। उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के जो प्रोफेसर, लेक्चरर हैं क्या आप उनकी सेवा की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं?

श्रीमन्, आज इन लोगों को मकान भत्ता मिलता है। चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता और सरकार या विश्वविद्यालय के शिक्षकों में और इनमें भेदभाव किया जाता है। दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था शिक्षकों का, कालेजों और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के महासंघों का उसमें इस पर चिन्ता प्रकट की है उन्होंने आन्दोलन का निर्णय लिया है। आज शिक्षा में जो वातावरण है सरकार उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट संस्थायें, जो प्राइवेट संस्थाओं के लेक्चरर और प्रोफेसर हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वह बंद किया जाये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उनको नये वेतनमान दिये जायं और जो कोर्ट का स्टे है उसे वापस लिया जाय।

**श्री सभापति** : आप समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

**श्री मेघराज तावड़** : आप बीच में बोलते हैं इसलिये मेरे दो मिनट तो खराब हो गये।

**श्री सभापति** : आपकी इस बात से काम चलेगा।

**श्री मेघराज तावड़** : मैं यह कहना चाहूंगा पुरजोर शब्दों में अपनी मांग पेश करना चाहूंगा कि जो शिक्षा में 'बड़ी हुक्म' शब्द है, जो हमारे यहां लिखा जाता है। जो यह प्रवृति पड़ी हुई 'बड़ी हुक्म' कहने की। आपका मास्टर तो गाय है उसको तो बख्श दीजिये। आपकी जो किताबें छपी हुई हैं उनमें बड़ी हुक्म की बात है यह जागीर-

(160)



( श्री मेघराज तावड़ )

दारी और सामन्तशाही का प्रतीक है। वह अध्यापक ऐसी किताबें पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि अनुशासन नहीं है। आप अनुशासन चाहते हैं। ऐसी किताबें पढ़ाते हैं फिर कहते हैं कि महाविद्यालयों में हड़तालें हो रही हैं, अनुशासन नहीं है। श्रीमान् ऐसी शिक्षा नीति हैं। सरकार जब तक ऐसी किताबों को बन्द नहीं करेगी और जब तक प्रगतिशील साहित्य नहीं छापेगी तब तक ये लोग ऐसा ही करेंगे।

श्रीमान् मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि ऐसी प्राइवेट संस्थाओं को, प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाय और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये।

**श्री सभापति** : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मैंने निवेदन किया था कि मेरे दल का एक ही सदस्य बोला है। विपक्षी पक्ष के सदस्य को बोलने का मौका दें।

**श्री सभापति** : अभी सी. पी. आई. के सदस्य बोले हैं अब कांग्रेस (आई) के सदस्य बोलेगें।

**श्री मोहनलाल मोदी** : पहले भी कांग्रेस (आई) के सदस्य बोले थे। दो सदस्य बोल चुके हैं। कम से कम सबको समय मिलना चाहिये।

**श्री सभापति** : आपको भी मिलेगा।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री का ध्यान मांग संख्या 24 की ओर आकर्षित करता हूं। मैं पुरजोर शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति खारची, मारवाड़ जंक्शन जिसमें 46 पंचायतें उस क्षेत्र खारची तहसील में एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। जबकि मारवाड़ जंक्शन जैसा महत्वपूर्ण जगह जहां चारों तरफ से रेलें आती हैं उसके आसपास के इलाकों के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसका एक मात्र कारण हायर सैकेण्डरी स्कूल का नहीं होता है। वहां से 50 मील दूर पढ़ने जाते हैं। वहां से 33 किलोमीटर दूर सोजत में जाते हैं और 4 किलोमीटर दूर वाली में पढ़ने हेतु जाते है। खारची तहसील में एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। इसलिए मेन मांग तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार से मारवाड़ जंक्शन में हायर सैकेण्डरी स्कूल चालू करवादें तो चारों तरफ के खारची तहसील के विद्यार्थी वहां आकर हायर सैकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भूतपूर्व जनता पार्टी की सरकार के शिक्षा मन्त्री श्री भंवरलाल जी शर्मा यहां बिराजमान हैं इन्होंने स्कूल खोले यह बात तो मैं जानता हूं। लेकिन स्कूल में जहां पांच पांच कक्षायें थी अध्यापक कितने लगाये ? पांच कक्षायें और अध्यापक आपने लगाये एक। क्या एक अध्यापक पांच कक्षायें चला सकता है? कदापि नहीं चला सकता है। फिर कैसी शिक्षा आप देना चाहते थे ? इसलिये मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कम से कम हर स्कूल

(161.)



(श्री भैरुसिंह गुर्जर)

में जहां पांच कक्षायें हों और एक अध्यापक हो और अधिक अध्यापक लगाने की व्यवस्था करें जिससे शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सके ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूं कि मैं भी अध्यापक हूं । चाहे एक दो साल ही रहा हूं पर नये अध्यापक 2-3 एक साथ नयी जगह लगा दिये जाते हैं, जो कि अनुचित है । इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि नये अध्यापक के साथ कम से कम एक शिक्षक ऐसा लगायें जिसे 30 साल, 25 साल पढ़ाने का अनुभव हो । ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि नयों को उतना अनुभव नहीं होता है ।

मैं एक मांग और करूंगा कि गांवों के अन्दर अध्यापक लगा तो दिये जाते हैं परन्तु उनके लिये वहां पर आवासीय सुविधा बिलकुल नहीं है । कई जगहें ऐसी हैं जहां कि उसको बिलकुल आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है जैसे मान लीजिये कि आपने किसी एक अनुसूचित जाति के अध्यापक की नियुक्ति दे दी और अनुसूचित जाति का अध्यापक दुर्भाग्य से ऐसे गांव में जाता है जहां पर कि कोई भी अनुसूचित जाति का घर नहीं होता है तो उस गांव में उसको कोई मकान नहीं देगा तो वह क्या करेगा ? ऐसी स्थिति में आपसे मांग करूंगा कि अध्यापकों को गांवों में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

इसके बाद एक और मुख्य मांग है कि पंचायत समिति के अन्दर जो शिक्षक हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, वह शिक्षक अगर शिक्षा विभाग में चला जाता है और मानलो कि पंचायत समिति में 10 साल की सर्विस होती है तो भी उसको शिक्षा विभाग में मेरिट में अंतिम स्थान दिया जाता है । इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार पंचायत समितियों से शिक्षक शिक्षा विभाग में आते हैं वे एक ही राज्य के हैं एक ही शिक्षा है पर इस शिक्षा में 2 विभाग हैं एक पंचायत समिति और दूसरा शिक्षा विभाग । मैं आपसे मांग करूंगा कि पंचायत समितियों के पास जितने स्कूल हैं उनको शिक्षा विभाग को सौंप दें ताकि स्थिति में सुधार हो । वरना तो पंचायत समितियों के अन्दर जो विकास अधिकारी हैं वे विकास करने के बजाय विनाश ज्यादा कर रहे हैं । विकास अधिकारी की मोटर स्कूल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और बेचारे अध्यापक पढ़ाना तो भूल जाते हैं और विकास अधिकारी की आवभगत में लग जाते हैं इन सब पंचायत समितियों के स्कूलों को शिक्षा विभाग में ले लेना चाहिये ।

मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह सूचना देना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने सदन में यह घोषणा तो कर दी थी कि जो अध्यापक बी. ए., बी. एड. कर लेगा उसको दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जायेंगी पर वह अभी तक दी नहीं हैं । मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे कम से कम जिन्होंने बी. ए., बी. एड कर ली है और जो अभी तक तृतीय वेतन श्रृंखला में बैठे हैं उनको दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाय ।

मैं आपसे और मांग करता हूं कि अध्यापक को उसके खुद के गांव में नहीं लगायें वरना वह अपने घर का काम ही करता रहेगा और बच्चों को नहीं पढ़ायेगा और न ही शिक्षा का कोई ध्यान ही रखेगा । इसके

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

साथ साथ यह भी करना चाहिये कि एक अध्यापक को 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रखा जाना चाहिये । उसके बाद उस अध्यापक को दूसरी जगह लगा देना चाहिये उसका अन्यत्र स्थानान्तरण कर देना चाहिये ।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि पिछली सरकार ने कई गांवों में नये स्कूल तो खोल दिये थे जैसे बालोतरा गांव में मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वहां पढ़ाया करता था पर वहां पर कोई भी भवन नहीं था । मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया करता था । इसलिये कम से कम भवन की सुविधा उपलब्ध करादी जानी चाहिए ।

बाली तहसील में एक सैकण्डरी स्कूल पिछली सरकार ने खोला था वहां पर आज भी 17 विद्यार्थी पढ़ते हैं जब कि वहां पर 6 से 10 तक की कक्षा लगती हैं तो जहां पर ऐसे विद्यालय हैं उनकी जांच करायें और अगर विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते हैं तो वे स्कूल और किसी स्थान पर खोले जाने चाहियें ।

इसके बाद मैं मारवाड़ स्कूल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । मारवाड़ जंक्शन में एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया है । वहां के बालिका विद्यालय की हालत बहुत खराब है । उसकी हालत ऐसी है कि वह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है । कम से कम ऐसी चेतावनी शिक्षा विभाग को दे दी जाय । वहां जो छात्राएं हैं, उनके भविष्य को देखते हुए, अध्यापिकाओं के भविष्य को देखते हुए कि यह विद्यालय गिर नहीं जाय उस बिल्डिंग के जो और कमरे हैं, उन पर राजस्व विभाग ने कब्जा जमाया हुआ है । तो मेरा निवेदन है कि राजस्व विभाग से कमरे खाली कराकर विद्यालय को दे दिये जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है । मैं यह पुरजोर मांग करता हूं कि स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय बनाया जाय । आपको इस पर विचार करना होगा । राजस्थानी का एक विषय रखा जाय । खेलकूद के बारे में मेरा यह निवेदन है कि गांवों में खेलकूद बिलकुल नहीं होते हैं शहरों के लड़के इनाम ले जाते है । भू. पू. शिक्षा मंत्री ने जब यह देखा कि खेलकूद नहीं होते हैं तो उन्होंने आर. एस.एस. की शाखाएं लगाना आरम्भ कर दिया ।

( व्यवधान )

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : खेलकूद के बजाय आर. एस. एस. को शाखाएं शुरू कर दीं ।

**श्री सभापति** : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे कम उम्र का हूं इसलिए मुझे और समय दिया जाय ।

**श्री सभापति** : समय आपको काफी दे दिया गया है ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : आपने जो ट्रांसफर्स किये है, किसी को जैसलमेर किसी को बाड़मेर हम तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं । हम उनको

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

वापस उनके बाल बच्चों के पास ला रहे हैं जिनको आपने दूर दूर फेंक दिया था ताकि वह अपना सुख का जीवन बसर कर सकें।

सभापति महोदय, पब्लिक स्कूलों के बारे में मेरा निवेदन है कि वे बन्द होने चाहिए। क्योंकि इनमें मिनिस्टरों, विधायकों और बड़े लोगों के लड़के ही पढ़ते हैं। वही पढ़ पाते हैं। वही कम्पीटिशन में बैठते हैं। इसकी जगह ग्रामीण क्षेत्र में 7 वीं कक्षा से अंग्रेजी रखी जाय ताकि वहां के बच्चों को कम्पीटिशन में बैठने के लिए तैयार किया जा सके। जो छात्र अंग्रेजी पढ़ना चाहें वह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी के मामले मे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अन्त में मैं अपना भाषण यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं, इनके होने से इनकी बेरोजगारी दूर हो गई थी। अब ये बेरोजगार हो गये। उनकी नहीं इनकी बेरोजगारी है।

**श्री सभापति** : प्रगतिशील दल के नेता श्री मोहनलाल मोदी।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है। मैं भी उसमें अपनी बात सम्मिलित करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान अन्य प्रांतों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। कालेजों में जो छात्र हैं, उनमें संख्या कम है। छात्र क्लास में जाते नहीं हैं। आपको यह विचार करना होगा कि आपकी शिक्षा में कितना दोष है। आपकी पढ़ाई पहले भी होती थी। आज इन बच्चों के माता पिता को देखिए। बड़ी मुश्किल से फीस जमा करा पाते हैं। किताबों पर पैसे खर्च करते हैं उसके बाद पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद डिग्री भी हासिल कर लेते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। मेरे यहां आरक्षण के मामले को लेकर बच्चों ने वहां बड़ा उधम किया। दफा 144 लगाई गई। स्ट्राइक हुई। फायरिंग हुई। फायरिंग से तीन आदमियों की मृत्यु हो गई। जब जाकर यह अध्याय समाप्त हुआ। तो मै आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा की पद्धति में चेंज लाइये। बच्चों के दिमाग में ऐसी शिक्षा पद्धति लाइये जिससे बच्चे अनुशासन में रहें। पढ़ने की ओर ध्यान दें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नीम के थाने में काफी दिनों से यह मांग चली आ रही है कि वहां पर पी. जी. कालेज खोला जाय। जनता पार्टी के भू.पू. मन्त्री ने यह वायदा किया था।

**श्री चन्द्रवीरसिंह** : माननीय सभापति महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि जब अनुदान की मांगें चलती हैं तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय को उपस्थित रहना चाहिये। सदन में इस समय मन्त्री महोदय नहीं हैं।

**श्री सभापति** : उप मंत्री जी मौजूद हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।........ आर्डर प्लीज। आप जारी रखें।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मन्त्री महोदय को सदन में उपस्थित रहना चाहिए वह सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं।

(164)



**श्री सभापति** : तीन घण्टे से मन्त्री महोदय, यहां पर थे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**श्री हंसराज शर्मा** : वह आपकी अनुमति लेकर दूसरे को बैठाकर जा सकते हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री जी आ गये हैं।

**श्री मोहनलाल मोदी** : माननीय सभापति महोदय, नीम का थाना में पी. जी. कालेज खोला जाय। भू. पू. मन्त्री महोदय ने वायदा किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वहां सारे देहात से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहां एक पी. जी. कालेज खोलने की व्यवस्था की जाय। नीम के थाने में मेरे क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां इसी सत्र में गर्ल्स स्कूल जरूर खुलना चाहिये साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि कालेज में छात्रों की संख्या अधिक होने से एडमीशन नहीं मिल पाता है। मेरा निवेदन है कि जहां कालेज है वहां एक हायर सैकेण्डरी स्कूल और खोल देना चाहिए ताकि कालेज में संख्या कम हो सके। दूर भी ज्यादा नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, घण्टी बजायेंगे तो मैं बोलना बन्द कर दूंगा। तो मेरा यही निवेदन है कि पी. यू. सी. क्लासेज कालेज में बन्द करके हायर सैकेण्डरी क्लासेज खोलनी चाहिए।

मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज शिक्षा जगत में जो कुछ भी हो रहा है उससे बड़ा भारी असन्तोष है। उसमें मेरा प्रश्न यह है कि प्राइमरी एजूकेशन जो पंचायत समितियों के माध्यम से है, वे सारे राजनीति में लिप्त है और उसी की वजह से आपको भी ट्रान्सफर करने पड़ रहे हैं। जनता पार्टी के राज में भी यही हुआ था, उन्होंने यह नहीं सोचा कि आज हम कर रहे हैं कल ये करेंगे। मै निवेदन यह कर रहा था कि जो आपने ट्रान्सफर्स किये हैं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आप भी घर-गृहस्थी वाले हैं। आपको अधिकार दिया गया है अध्यापकों का स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति के अन्दर करने का, यह अधिकार कांग्रेस के भूतपूर्व मन्त्री दामोदरजी व्यास ने लिया था, लेकिन सूक्ष्म रूप में दिया गया था इसलिए नहीं कि आप उनको बाड़मेर भेजकर उनके बच्चों को तबाह कर दो। आज आप राजनीति में हैं, आप बदले की भावना भी रख सकते है, हो सकता है किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया हो, लेकिन उनकी बददुआएं ऐसी लगेंगी कि आप कहीं के नहीं रहोगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसी बात है कि आज दोपहर में ही सीकर जिले के थर्ड ग्रेड के अध्यापक मुझसे मिलने आये थे, उनको दूसरे जिले में भेजा जा रहा है, एक प्रकार से उनको सजा दी जा रही है, आप उनको जिले में ही दूसरी जगह भेजें तो ठीक है लेकिन उनको 100 और दो सौ कोस दूर भेज रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको चैक करिये और करना ही है तो आप दो

(श्री मोहनलाल मोदी)

सौ और तीन सौ कोस दूर क्यों भेजते हैं, जिले से बाहर क्यों भेजते हैं ? एक ही बात है कि जो बात जनता पार्टी के शासन में हुई थी वही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान देंगे। आपने कहा कि विधायकों के कहने से करते हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है इसलिए बहुत ही कम शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देवें।

मैंने गर्ल्स स्कूल के लिये निवेदन किया, पी. जी. कॉलिज के लिये निवेदन किया आपने 600 प्राइमरी स्कूल खोलें, आज हमारे राजस्थान में फिर भी कमी है। ढाणियों में, छोटे-छोटे गांवों में सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहां पर प्राइमरी स्कूल खोलें। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहली बार मन्त्री बनकर आये हैं, आप मुख्य मन्त्रीजी से बात कर लीजिये, कम से कम दो हजार प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिये अगर ऐसा हुआ तो लोग आपको याद करेंगे, राजनीति में समय आता जाता है, आज आप शिक्षा मन्त्री हैं, कल दूसरे होंगे। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो लोग

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपको याद करेंगे कि फलां शिक्षा मन्त्रीजी आये हैं उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के बारे में इतना काम किया।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर ट्रान्सफर करके बर्बाद कर दिया, यह सत्य है या असत्य है, यह सत्य है तो बाड़मेर की उन्नति करनी चाहिये या नहीं करनी चाहिए ?

श्री सभापति : वे दूरी के संदर्भ में कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : बाड़मेर खराब जगह नहीं है, जहां वे रहते हैं, इतनी दूर है कि....

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय सभापति जी, वैसे इस चर्चा में बहुत ही राजनीतिक आदान-प्रदान हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि हम जो भी सुझाव दें यदि सूक्ष्म और सुदृढ़ सुझाव दें तो उनको माननीय मंत्री महोदय, ध्यान में रखें। मुझे आशा है माननीय शिक्षा मंत्रीजी उनको राजनीतिक रूप से नहीं सोचते हुए बजट में उचित स्थान देने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, स्कूलों को खोला लेकिन स्कूलों के लिए भवनों की व्यवस्था बहुत कम है, यह एक सही तथ्य है। स्कूल तो जनता पार्टी ने प्रचुर मात्रा में खोले और उनके भवनों का प्रबन्ध भी किया, लेकिन समय के कार्यक्रम से सब जीर्ण-शीर्ण हो गया। भवन आज टूटी फूटी अवस्था में हैं; बारिश में छतें टपकती

(166)



(श्री पुष्पा जैन)

है तो छुट्टी करदी जाती है और धूप के अंदर बच्चे दरख्तों के नीचे पढ़ते हैं। हमको स्वतन्त्र हुए इतने साल हो गये उसके बाद भी गांवों में स्कूलों की यह हालत है निश्चय ही यह हमारे लिये शर्म की बात है। मैं यह जानती हूं कि बजट की सीमायें बहुत कम हैं इसके बावजूद भी जो हमारे गांव हैं, जो रूरल कान्स्टीटुएन्सीज हैं वहां पर आप को अधिक से अधिक व्यवस्था करनी चाहिए मेरे कहने से नहीं, इस सदन के माननीय सदस्यों के कहने से नहीं; आप स्वयं जाकर निरीक्षण करें। मैं आमेर के बारें में आप को निवेदन कर रही हूं, आपको दावत दे रही हूं, विरोधी पक्ष में होने से आपको खयाल नहीं करना चाहिए, बल्कि वास्तविकता देखनी चाहिए, आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिये, आप कहेंगे तो आपके साथ मैं भी चलूंगी।

सभापति महोदय दूसरी बात कहना चाहती हूं पानी की व्यवस्था नहीं है दरी की व्यवस्था नहीं है; बेंचों की कोई व्यवस्था नहीं है; बच्चों के लिए बैठने का उचित प्रबन्ध नहीं है, दो सौ बच्चों पर एक अध्यापक हो तो वह क्या कर सकता है। यह आप खुद ही सोच सकते है कि यदि पूरे राजस्थान में आप अकेले ही मन्त्री हों तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे। इसलिए संख्या के हिसाब से अध्यापकों की पूर्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय, ट्रान्सफर्स का बहुत हवाला दिया गया और इसका राजनीतिक रूप से आदान प्रदान भी हुआ। मैं समझती हूं ट्रान्सफर्स देश के स्वच्छ प्रशासन के लिए आवश्यक है लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से नहीं होने चाहिए। कई अध्यापक ऐसे हैं जो जहां जन्मे वहीं उनका प्रमोशन हो गया और रिटायर भी हो गये, यह किसी भी पार्टी से चाहे ताल्लुक रखते हों, गलत है। ऐसे जो भी अध्यापक हैं जो बहुत वर्षों से अपने जिलों से दूर हैं, उनको अपने जिलों में लाया जावे और जो कई वर्षों से अपने जिले में ही हैं उनको दूसरे जिले में भेजा जाना चाहिए। अगर आप यह नीति रखेंगे तो सफल शिक्षा मन्त्री के रूप में कहे जायेंगे। बधाई के पात्र होंगे अन्यथा राजनैतिक दुर्भावना आपको ही नहीं आपकी सरकार को ले डूबेगी।

सभापति महोदय, स्त्री शिक्षा पर मैं बल देना चाहती हूं। मैं यह चाहूंगी कि जो गांवों में स्कूल खोलें या क्रमोन्नत करें उन में कन्या शालाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जनरल एजूकेशन का पर्सेन्टेज हमारे यहां पर 20 पर्सेन्ट है इसमें महिलाओं का पर्सेन्टेज कम से कम 15 पर्सेन्ट तो होना ही चाहिये। जयपुर में एक गवर्नमेंट कालेज की भी मैं उम्मीद करूंगी।

सभापति महोदय, पिछली गवर्नमेंट में मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों को एक पुरस्कार देने की नीति रखी थी जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। अब की बार भी बहुत से ऐसे बच्चे है जो मेरिट लिस्ट में आये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप उनको पुरस्कृत करें ताकि गरीब बच्चों को प्रोत्साहन मिले और शिक्षा में आगे उन्नति कर सकें।

सभापति महोदय, जो नये स्कूल खोले जायं, हालांकि बजट की सीमा होती है, जैसाकि मैं पहले ही कह चुकी हूं, यह सब जानते हैं, इन पर मेरा कोई दबाव नहीं है

(सुश्री पुष्पा जैन)

लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों और गरीबों की संख्या को देखते हुए, वित्तीय साधनों को देखते हुए, अगर इन स्कूलों को खोलेंगे या क्रमोन्नत करेंगे तो आपका आभार मानूंगी।

अब, मैं पुरातत्व विभाग के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, राजस्थान में कई प्राचीन किले और मन्दिर ऐसे हैं, जैसे आमेर का जगत शिरोमणीजी का मन्दिर, शायद मन्त्रीजी ने और माननीय सदस्यों ने इसको कभी नहीं देखा होगा लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे तो गद्गद् हो जायेंगे लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि किसी भी सरकार का ध्यान आज तक वहां नहीं गया। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप दर्शन करने जायें और आशीर्वाद प्राप्त करें उस मन्दिर की व्यवस्था करें और पुरातत्व विभाग को खास तौर से आगाह करें। उसके लिए बजट में प्रावधान दें ताकि उस मन्दिर की तरफ ध्यान दें। दूसरे जो पर्यटक हमारे यहां आते हैं उन्हें दिखाने का प्रावधान किया जाय।

कुम्भलगढ़ का किला है, कैलाशपुरी के पास का मन्दिर है। ऐसे बहुत से दार्शनिक, ऐतिहासिक स्थल है जिनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने रविन्द्र मंच में घोषणा की थी कि वह उन अकादमियों का पुनर्गठन करेंगे और उनका एक ही निदेशालय कायम करेंगे। मैं इस घोषणा की याद दिलाते हुए उनसे अनुरोध करती हूं कि वह उन अकादमियों का पुनर्गठन करें और कला को राजनीति से बहुत-बहुत दूर रखें। वह राजस्थान की धरोहर है, हमारी संस्कृति है।

संगीत नाटक अकादमी आज जोधपुर में बसी हुई है। शिक्षा मंत्री जी, यदि आप गौर करेंगे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाखों रुपये का सामान है, उस संगीत नाटक अकादमी में। कई वाद्य यंत्र है, लेकिन उनका उपयोग नहीं। आज हम तो क्या राजस्थान के अनेक व्यक्ति जानते भी नहीं कि आखिर संगीत नाटक अकादमी है क्या और इसका कार्य क्या है? हम जो सदन में बैठे हैं, हमें यह नहीं मालूम कि संगीत नाटक अकादमी साहित्य अकादमी, ललितकला अकादमी, इनका क्या काम है, यही नहीं है, यह वास्तव में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। इन्हें आप नयी गति दीजिये, इन्हें वास्तव में बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इस ओर ध्यान दीजिये। इसका अवलोकन कीजिए स्वयं जाकर और इनमें गति दीजिये। राजस्थान को नयी दिशा मिलेगी।

सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी से उन कलाकारों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी जो बहुत छोटे-छोटे हैं। जिन्होंने राजस्थान का कला को आगे बढ़ाया है लेकिन आज देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप कलाकारों को प्रोत्साहन देंगे जो छोटे-छोटे कठपुतली वाले हैं, नट हैं, लोक संगीत के कलाकार हैं वह आज सड़कों पर घूमते है, भीख मांगते हैं उनको कोई नहीं पूछता। यदि आप वास्तव में कला के पुजारी हैं, आप कला के मंत्री हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप छोटे कलाकारों को प्रोत्साहन

(168)



(सुश्री पुष्पा जैन)

दीजिये। कोई ऐसा प्रावधान रखिये जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले, वह आयें आये और राजस्थान की कला को, संस्कृति को उजागर करें। सभापति महोदय···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बिल्कुल अन्त में आ रही हूं। सभापति महोदय, मैं पिछली सरकार का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री जी का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने कत्थक केन्द्र, जो जयपुर घराने से सम्बन्धित है, खोला था। कत्थक केन्द्र खुल गया लेकिन अभी तक उसमें वह आत्मा नहीं आयी जो आनी चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कत्थक केन्द्र का आप अवलोकन करें, उसमें गति दें। जो विरासत के रूप में जयपुर घराने की संस्कृति हमको मिली है और उन कलाकारों को, जिनका सम्बन्ध वास्तव में जयपुर घराने से है, जो प्रोत्साहन न मिलने की वजह से राजस्थान से दूर-दूर गये हुए हैं, उन्हें लायें, उन्हें प्रोत्साहन दें और हो सके तो इस कत्थक केन्द्र की तरफ ध्यान दें।

इन सब बातों के साथ मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, शिक्षा मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगी कि मेरे इन सब सुझावों को राजनैतिक रूप में न लें। हो सके तो जितना भी सम्भव हो उनमें गति लाने की कोशिश करें और अपने बजट में इसका प्रावधान करें।

**श्री सभापति** : श्री हेमाराम चौधरी।

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया।

**श्री सभापति** : मैं आपको अवसर दूंगा·····

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : मैं थोड़े समय में समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : एक मिनट माननीय सदस्य आप शीघ्र बोल लें, आप एक-दो मिनट में बात समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

मैंने काल कर लिया है। इसके बाद अवसर दे दूंगा।

**श्री हेमाराम चौधरी** : सभापति महोदय, आज सभी माननीय सदस्य करीब-करीब शिक्षा के बारे में समस्या रख रहे थे। बाड़मेर जिले के क्षेत्र में जो शिक्षा के बारे में समस्यायें हैं उनके बारे में मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान की सीमा से आया हुआ है और जो राजस्थान के एक किनारे पर आया हुआ है उस बाड़मेर जिले के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है। बाड़मेर जिले में, विशेषकर जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, एक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। केवल सैकण्डरी स्कूल है जिसमें केवल आर्ट्स सब्जेक्ट है। उसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। और चार जो सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें से 2 सैकण्डरी स्कूल केवल कार्नर पर जो गांव आया हुआ है उस पर अड़े हुए हैं जिनका लाभ मेरे क्षेत्र के रहने वाले छात्रों को नहीं मिल पा रहा है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है सब गांव और उसमें कोई शहर नहीं है। ढांणियों में बसे लोग हैं और एक-एक विद्यार्थी, 10-10 किलो मीटर तक, कहीं तो 15-15 किलो मीटर तक, नजदीक कोई स्कूल नहीं होने के कारण से पढ़ाई से महरूम रह गया है। वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो यह 6 सौ प्राइमरी स्कूल खोले हैं, यह बहुत कम हैं। उनमें बढ़ोतरी कर कम से कम डेढ़ हजार प्राइमरी स्कूल खोलें और बाड़मेर के लिये कम से कम 50 स्कूल दें। तभी वहां कुछ हो सकता है। अभी जो 6 सौ स्कूल खोले हैं तो एक विधान सभा क्षेत्र में 3 स्कूल खोलने का जो नियम किया गया है उस हिसाब से मेरे क्षेत्र में केवल 3 आयेंगे तो उससे कहां खोलेंगे वह 3 स्कूल। कम से कम 40-50 गांव हैं जिनमें स्कूल नहीं हैं। 3 स्कूल को किस गांव में खोला जाएगा। यह भारी समस्या हो जायेगी। इसलिये माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल को बढ़ायेंगे। सैकण्डरी स्कूल की आगे भी कमी है और नहीं खोलेंगे तो . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हायर सैकण्डरी स्कूल आवें उतनी प्राइमरी स्कूल में बढ़ोतरी करें कुछ और खोलिये। गांवों में प्राइमरी शिक्षा का बहुत अभाव है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। उनकी प्राइमरी एजूकेशन नहीं हो सकती है तो वह उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री जी आप इस ओर ध्यान दें। ताकि जो गांव के छोटे-छोटे किसान के बच्चे हैं वह 15-15 किलोमीटर दूर जा नहीं सकते हैं इसलिए हर गांव में एक-एक स्कूल खोलने की व्यवस्था करें। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक स्कूल खोला जाय और उसमें अध्यापक लगाया जाय ताकि यह तो हो सके कि एक गांव में स्कूल खुल गया, एक अध्यापक लग गया, बच्चे स्कूल जाना सीख लें और बाद में वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा मांग नहीं करता हूं। मैं केवल प्राथमिक शिक्षा की मांग करता हूं क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है जब तक आप प्राथमिक शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तो उच्च शिक्षा कैसे मिलेगी। गरीब किसान के और मजदूर के जो छात्र हैं वह हमेशा पीछे रहेंगे और कभी भी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पायेंगे। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, मैं यह आशा करता हूं कि आप ग्रामीण शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देंगे और वहां पर ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोलने की मेहरबानी करेंगे।

माननीय शिक्षा मन्त्री जी, पिछले टाइम में जनता पार्टी ने स्कूल काफी खोले लेकिन उनके अन्दर अध्यापक नहीं हैं। एक भी अध्यापक नहीं हैं। अगर एक अध्यापक हो तो हम उसको मान लें। बाड़मेर पंचायत समिति का यह उदाहरण देता हूं कि वहां पर 103 स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल और उनके अन्दर अध्यापकों के 97 पद। तो इस तरह से 6 स्कूल ऐसे हैं जो बन्द पड़े

(170)



(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं। अध्यापक नहीं हैं। एक स्कूल में एक से ज्यादा होते हैं। जब स्कूल वहां पर 103 हैं तो इस तरह से वहां अध्यापकों का अभाव है। इसलिए शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक स्कूल के लिए केवल एक अध्यापक दे दें। जनता पार्टी ने स्कूल बहुत खोले, अध्यापक नहीं दिये। कागज़ों में खोल दिये। जनता को बता दिया कि हमने स्कूल खोल दिए हैं। . . इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी जिसकी घोषणा तो करती रही लेकिन अध्यापक नहीं लगाये। नये स्कूल भी खोलें और जो नये स्कूल खोलें उनमें एक अध्यापक जरूर दें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक और निवेदन करूंगा कि जो नए प्राइमरी स्कूल खोलें वे आबादी के आधार पर नहीं खोलें। इस समय 15-15 पंचायतों के बीच में स्कूल नहीं है। अगर आबादी कम है, अगर 100 घर हैं आबादी कम है तो उनके बच्चे कहां पढ़ने जायेंगे? चाहे एक ही अध्यापक हो। मेरे यहां ऐसे गांव हैं जहां आबादी कम है इसलिए स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। इसलिए आबादी को न मान कर यदि दूरी को आधार मानें कि एक बच्चे को कितना दूर जाना पड़ता है तो ऐसी व्यवस्था करें। गर्मी के दिनों में बाड़मेर जिले में ऐसी गर्मी पड़ती है शायद राजस्थान में और कहीं नहीं पड़ती है . . .

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री हेमाराम चौधरी** : दो मिनट।

**श्री सभापति** : आपने दो मिनट का आश्वासन दिया था . . .

**श्री रामसिंह बिश्नोई** : लंबा एरिया है।

**श्री हेमाराम चौधरी** : जैसा की प्रगतिशील दल के नेता ने कहा कि किसी को सजा देनी हो तो उसको बाड़मेर भेजो, बाड़मेर को काला पानी मानते हैं। तो बाड़मेर से यह काला पानी का नाम तो हटा दें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर।

**श्री हेमाराम चौधरी** : हमारे बाड़मेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा चल रही है, बिलकुल फेल है। एक भी आदमी को शिक्षा नहीं मिली है। एक भी व्यक्ति सदन के सामने खड़ा कर दें तो मैं मानूं। कुछ नहीं है। सिर्फ आर. एस. एस. के पदाधिकारी हैं 8-10 हैं और एक गांव में अपना एक आदमी लगा रखा है। 50 रुपए तनख्वाह बैठे बैठे देते हैं, एक पैसे का काम नहीं करते है। बाड़मेर के 6 सदस्यों से पूछ लिया जाए कि मेरी बात सही है या नहीं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, नो इन्टरप्शन।

**श्री हेमाराम चौधरी** : बाड़मेर जिले के एक गांव में भी प्रौढ़ शिक्षा का कोई काम नहीं चल रहा है केवल 50 रुपये तनख्वाह अपने एक कार्यकर्ता को दे रहे हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा को खत्म कर दें और होने वाले व्यय को हमारे प्राइमरी स्कूलों पर लगा दें, छोटे बच्चों को सजा दी

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाए जो भारत के भावी नागरिक हैं, जो देश का भविष्य है, उनको शिक्षा नहीं देंगे तो देश का भविष्य अंधकार में रहेगा इसलिए आप ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देकर शिक्षित नहीं बनायेंगे तो देश की हालत क्या होगी ? आज 70-80 वर्ष का बुड्ढा देश का भला नहीं कर सकता। जो आज का बच्चा है, आने वाली पीढ़ी है इसलिए उस ओर विशेष ध्यान दें।

तो प्राइमरी स्कूलों की तरफ ध्यान दें, प्रौढ़ शिक्षा खतम करें और दूरी की तरफ ध्यान दें, तीन बातें मोटी तौर पर शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं बाड़मेर जिले की, जो पिछड़ा हुआ है, उस ओर विशेष ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र में हमको महत्व देकर दूसरे जिलों के बराबर लाने की कोशिश करें। पहले से ही हमारा जिला पिछड़ा हुआ है . . .

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री हेमाराम चौधरी** : मैं शिक्षा मंत्री से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले की ओर शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और प्राइमरी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की कृपा करें।

**श्री सभापति** : श्री समर्थ लाल

(अनुपस्थित)।

श्री राम करण।

**श्री राम करण** (जायल) : सभापति महोदय, मैं शिक्षा के विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जायल क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं है, उधर नागौर बहुत दूर पड़ता है, डीडवाना भी बहुत दूर पड़ता है। महात्मा गांधी छात्रावास अनुसूचित जाति का एडेड हॉस्टल जायल में है, वहां पर लड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, सबसिडी थोड़ी मिल रही है, किताबें व कापियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, गड़बड़ी हो रही है। जायल कस्बा है, बड़ा है, पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, औषधालय है, सब कुछ होते हुए भी उस जिले में हाई स्कूल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने की कृपा करें। दूसरा, गांव खयाला में मिडिल स्कूल है, भवन बहुत अच्छा बना हुआ है। 14 कमरे बने हुए हैं, गांव काफी बड़ा है इसलिए उस मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करके सैकण्डरी स्कूल खोला जाए।

तीसरा, एक बूकंस बूकमसोत गांव है, वहां मेघवालों की ढाणियां हैं 60-70, वहां एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। वह नागौर तहसील में है। वहां एक ही गांव में ढाणियां हैं, उनमें एक भी पाठशाला नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर।

**श्री राम करण** : एक गांव है रोटू वहां से तीन कोस की दूरी पर ढाणियां नायकों की हैं, 60-70 ढाणियां हैं, स्कूल नहीं है, स्कूल है बहुत दूर पड़ता है इसलिए वहां एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए।

नागौर जिले में 4 छात्रावास चलते हैं जिनमें व्यवस्थापक लम्बे अर्से से समाज कल्याण अधिकारी कार्यरत है। उनके यहां भी गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मनमानी हो रही है, जिससे छात्रों को वह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। वे लड़के शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि चारों छात्रावासों में प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करके व्यवस्था ठीक कर ली जाए।

**श्री सभापति** : श्री गुलाब चंद कटारिया

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में गत 32 सालों में क्या उपलब्धि है मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को एक विचार रहता था कि कहीं शिक्षा का प्रचार हो जाएगा तो पता नहीं वे पढ़े लिखे लड़के मेरे खिलाफ कोई बगावत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने भी गत 32 सालों में यह विचार रखा हो कि कहीं राजस्थान में शिक्षा का प्रचार हो गया तो हम बेवकूफ नहीं बना सकेंगे अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकेंगे ...

( व्यवधान )

... ऐसी कौनसी आफत आ गई कि हम 30 साल तक योजना बनाकर कम से कम 30-32 साल के नौजवान को भी शिक्षा नहीं दे सके। उससे अधिक उम्र वाले लोग हो सकते हैं उनकी शिक्षा नहीं हुई हो . . .

**एक माननीय सदस्य** : आपने स्कूल तो खोले लेकिन अध्यापक नहीं भेजे।

( व्यवधान )

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर।

**श्री भंवर लाल शर्मा** : माननीय सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं।

**श्री सभापति** : कृपया बोलने वाले माननीय सदस्य और आसन के बीच आने का का कष्ट न करें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया**: इस बात को कहने में मेरा उद्देश्य यह है कि किस गति से हम चल रहे है, अगर वास्तव में हम इस गति से चलें तो राजस्थान की शिक्षा का प्रतिशत कैसे बढ़ा पायेंगे। लेकिन आगे हम ऐसा कोई टाइम तय करें कि कम से कम 10-15 सालों में सारा जो एजूकेशन का क्षेत्र है उसमें राजस्थान को भारत की लेवल पर ले जाकर पहुंचा दें। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सर्वे करायें, राजस्थान में फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन दी जाए तो हमारे बजट पर कितना अधिक भार पड़ जाएगा, उस भार को कहीं से भी पूरा करके उठाना चाहिए, हमारी सरकार दो तीन तीन चार साल में कम से कम जो आवश्यकता है, अक्षर ज्ञान उस तक पहुंचा जाए, हायर एजूकेशन की बात तो छोड़िए, फंड्स इतने नहीं हैं कि हम ज्यादा धन दें लेकिन फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन कर सकें, इस सीमा तक पहुंच सकें।

( व्यवधान )

**श्री सभापतिः** आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डालें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : श्रीमान, यह विधान सभा है पर कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह विधान सभा नहीं होकर कोई डिबेट का स्टेज हो। जिसमें पक्ष और विपक्ष वाले बैठ कर तर्क करते हैं। यहां पर, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों आपस में चोर, बदमाश, झूठे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह तो ऐसा कहते है जैसे जनता पार्टी की सरकार वाले सभी खराब थे सिर्फ यही कांग्रेस वाले ही सारे सफेद पोश हों और इनके ऊपर जैसे कोई दाग नहीं हो लेकिन मैं सभापति महोदय, इनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर वह चाहें तो यहां कभी एक दिन आप डिबेट रख ले और फिर बहस हो जाय तो आपको पता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लग जायगा कि आप जो हजारों धब्बे लगाने की बात करते हो आपको उलटे आपके दल वालों पर ही हजारों धब्बे मिलेंगे और हमारे ऊपर एक भी धब्बा नहीं लगा सकोगे ।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष वाले जो यह चार्ज लगाते हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति घुसेड़ दी । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के अन्दर राजनीति की शुरूआत कांग्रेस सरकार ने उस दिन से की जिस दिन से उन्होंने प्राथमिक स्तर तक की एजूकेशन को गांवों में पंचायत समितियों के नीचे दे दिया । सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि जो अध्यापक पंचायत समिति में होता है वह यह जरूरी नहीं कि बच्चों को पढ़ावे पर उसके लिए यह जरूरी है वह सरपंच साहब के घर पर जाकर उनकी जी हजूरी करे । आज हजारों गांवों में अध्यापक ऐसे हैं जो कि इन सरपंचों की दया पर निर्भर करते हैं । सभापति महोदय, उन अध्यापकों का कितना मनोबल इससे गिरता है । ऐसे मनोबल गिरे हुए अध्यापक वहां गांवों में क्या बच्चों को पढ़ायेंगे ? उस अध्यापक से आप क्या उम्मीद करें कि वह किसी प्रकार की ज्ञान उन बच्चों में पैदा कर सकेंगे । तो अब आपको पता लग गया होगा कि राजनीति का प्रवेश शिक्षण संस्थाओं में आपने किया हमने नहीं किया । मेरे पास में ऐसे आर्डर्स मौजूद हैं, श्रीमन्, हजारों टीचर्स के ट्रान्सफर्स किये गये हैं । सभापति महोदय, न केवल हैड मास्टर्स के न केवल सीनियर टीचर्स हायर सैकेण्डरी स्कूल बल्कि बेचारे गरीब थर्ड ग्रेड टीचर्स को उनके जिलों में एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया गया ।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य व्यवधान नहीं करें ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार आने के बाद दस हजार ट्रांसफर्स किये गये हैं । सभापति महोदय थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए यह आदेश हैं राज्य सरकार के कि उनको उनके जिले से बाहर स्थानान्तरण नहीं किया जाय । सभापति महोदय, मेरे पास इसकी लिस्ट मौजूद है अगर उन लिस्टों को भी को शामिल किया जाय तो वह बहुत हो जायेंगी । पर मुझे बड़ दुख के साथ कहना पड़ता है

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें ।

**श्री सूरजपालसिंह :** आपने शिक्षा को आर. एस. एस. का अखाड़ा बना रखा था ।

**श्री सभापति :** आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । कृपया माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें । व्यवधान नहीं डालें ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग क्रमांक 139/8-1 प्रशा-3/80 जयपुर दिनांक 24-7-80 को अकेले सीकर जिले से 9 अध्यापकों के अन्य स्थान पर ट्रांसफर्स दूसरे जिलों में किये गये हैं । इसमें सभापति महोदय, सीकर से चूरू, सीकर से खेतड़ी, झुन्झुनू, सीकर से डूंगरगढ़, सीकर से सुजानगढ़ सीकर से खेतडी, झुन्झुनू और सीकर से सुलतानगढ़ चूरू और सीकर से खेतड़ी ट्रांसफर किये गये हैं । इतना ही नहीं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सभापति महोदय, लोगों को डूंगरपुर भरतपुर जिले में भी ट्रान्सफर किये ऐसे एक नहीं और कई ट्रान्सफर्स दूसरे जिलों में किये गये हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार के आदेशों की ट्रान्सफर्स लिस्ट जो निकली है उसमें 56 टीचर्स है जो कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किये गये हैं। पर इसमें आप देखेंगे कि एक अध्यापक के दो जगह आर्डर हो गये है। जल्दी जल्दी में आदेश करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि एक अध्यापिका जो नम्बर 22 में है श्रीमती यशोदादेवी को भीम उदयपुर जिले से जवाजा अजमेर लगाया गया और उसी श्रीमती यशोदादेवी मेहता का नाम 56 नंबर पर उसी लिस्ट में है। श्रीमती यशोदादेवी मेहता को भीम से अजमेर ट्रान्सफर किया गया है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप कृपया माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। आर्डर आर्डर माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डालें। इसी प्रकार सभापति महोदय, इन आदेशों में 19 अध्यापकों का पाली जिले से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, वगैरह स्थानान्तरण किया गया।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं मेरे पास सरकारी आदेशों की प्रतिलिपि है आप चाहें तो देख लें। सभापति महोदय, इन आदेशों के खिलाफ एक व्यक्ति मोहनवतसिंह अध्यापक, जो कि पंचायत समिति सुमेरपुर में था, ने शिक्षक संघ को लिखा कि मेरी उम्र 55 वर्ष की हो रही है सेवा मुक्ति में केवल 6 माह ही शेष है मैं सन् 1981 की अप्रेल में सेवामुक्त होने वाला हूं मुझे यहां से नहीं हटाया जाय। मेरा निवेदन है कि एक अकेला व्यक्ति ऐसा क्या था कि आपको वहां से स्थानान्तरण करने की जरूरत पड़ी वह क्या अकेला 6 माह में आपकी सरकार को उलट देता ?

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। व्यवधान नहीं डालें।

**श्री शिवराम शर्मा** : आपने जो ट्रान्सफर्स किये थे उन्हे ढाई साल बाद जैसलमेर बाड़मेर से उनके निजी जिलों में बुला रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें।

**श्री . गुलाबचन्द कटारिया** : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के बारे में थोड़े सुझाव देना चाहूंगा।

( व्यवधान )

**श्री सभापति** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं आप सदन का अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, जिस तरह हमारे यहां पर सैकण्डरी बोर्ड है उसी तरह हमारे यहां मिडिल बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि आज जो विद्यार्थी नवीं व दसवीं में 32 प्रतिशत-33 प्रतिशत 34 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रिजल्ट रहता है अगर आठवीं का बोर्ड हो जायगा तो उन लड़कों को हम इम्प्रूव कर सकेंगे। वरना होता ऐसा है कि लोग गांवों से शहरों में पढ़ने आते हैं उनके गरीब माता, पिता अपने बच्चों को पढ़ाने शहर में भेजते हैं और उन पर खर्चा करते हैं पर वे आगे जाकर फेल हो जाते हैं। तो उनके लिये उनके माता पिता का पैसा फिजूल खर्चा नहीं हो और उन बच्चों की नींव भी मजबूत हो सके इसके लिये मिडिल बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये ऐसा मेरा राज्य सरकार को सुझाव है।

इसके अलावा एक सुझाव और मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी को देना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज जो प्राइवेट स्कूल हैं पब्लिक स्कूल है वहां बच्चे पढ़ते हैं उनकी हालत और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले की हालत में बहुत फर्क है। सभापति महोदय, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के, जो कि अमीरों के बच्चे होते हैं टाई वगैरह पहनकर बड़ी बड़ी अट्टालिका और बड़ी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वे बेचारे गरीब मां बाप के होते हैं दूसरे, उनकी स्कूल के भवन की हालत यह है कि पांचवीं कक्षा तक पांच अध्यापक रहे पर उनके बैठने को जगह नहीं है एक इधर बैठा है दूसरा उधर अपने बच्चों को दूसरे कोने में पढ़ाने बैठता है। बड़ी दुर्दशा है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम उन बच्चों के लिए भवन तो ठीक होना चाहिए। मेरा शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप भी मेरे ही जिले के हैं वहां पर, सभापति महोदय, नगरपालिका का एक करोड़ 20 लाख का बजट है आप एक किलोमीटर डामर रोड बनाने के लिये एक लाख रुपया खर्च कर देते हैं तो क्या आप बच्चों के भवन के लिये उस एक करोड़ बीस लाख रुपए से एक लाख रुपया नहीं निकाल सकते ? हमने सभापति महोदय, पिछले साल यह प्रयत्न किया था कि नगरपालिका के बजट में से स्कूल भवन बनवाने हेतु धनराशि का प्रावधान करने के लिये राज्य सरकार को लिखा पर पता नहीं वह कागज एजूकेशन डाइरेक्टर साहब के आफिस में कहां खो गया ? आज तक उसका कोई पता नहीं है। एक लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे देश का एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस देश में सबसे कमजोर कोई व्यक्ति है सरकारी नौकरी में तो वह अध्यापक है। पहले तो उनको नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी तक नियुक्ति के आदेश नहीं मिलते हैं उसके बाद में ज्यों ही सेशन समाप्त होता है तो उसकी नौकरी को समाप्त कर दिया जाता है। सभापति महोदय, ऐसा शायद ही कोई सलेक्शन बोर्ड होता होगा जिसके द्वारा एक बार सलेक्शन किया हुआ व्यक्ति बाद में नौकरी से हटा दिया जाता है। सभापति महोदय, एक ओर तो स्कूलों में अध्यापक नहीं होते हैं बच्चे बिना टीचर्स के अक्टूबर नवम्बर तक बैठे रहते हैं दूसरी ओर अध्यापक बेचारे नौकरी के लिए अक्टूबर नवम्बर तक आदेशों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की राह देखते हैं। मेरा, सभापति, महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को यह सुझाव है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे जुलाई मास के अंत तक अध्यापकों को नौकरी मिल सके।

श्रीमन्, यही नहीं अध्यापक बाहर कब जायेगा जब उसे लगे कि वहां जाने से उसे लाभ है। एक अध्यापक जंगल की खाक छानता है. एक अध्यापक जो कि बहुत इन्टीरियर में रहता है चाहे इतना ही आप कीजिये कि ट्राइबल एरिया में जो अध्यापक दूर कोने में जाता है तो उसको कुछ ग्रामीण भत्ता दें जिससे उसका इन्ट्रेस्ट वहां जाने के लिए पैदा हो।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं उदयपुर विश्वविद्यालय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी परिपाटी सी बन गई है कि एम.ए., एस.एमसी. और एम. कॉम में दो साल में चार सेमेस्टर होते हैं लेकिन यह चार सेमेस्टर अब चार साल में होने लगे हैं। साल भर में इतनी प्रगति जरूर हुई है कि चार साल से तीन साल पर पहुंच गये हैं आप इस बात का प्रयत्न कीजिये कि जो दो साल का कोर्स है वह निश्चित काल में ही हो। इसके अलावा मैं आपको हमारे यहां उदयपुर यूनिवर्सिटी की बात बताना चाहता हूं कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि किसी लड़के को अपने नम्बरों पर सन्देह है और वह रीकेलकूलेशन कराना चाहता है तो उसको अपनी एप्लीकेशन लगाने का समय एक महीने का होता है मान लीजिए कि वह थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देता है और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है तब तक उसको उस रीकेलकूलेशन के रिजल्ट का इन्तजार कराया जाता है और वह लड़का चौथे सेमेस्टर में किस पोजिशन पर आता है उसको देखकर उसके नम्बर लगाये जाते हैं। क्या यह नहीं बताता कि इसमें किसी की बदनीयति है। ऐसे केसेज संस्कृत में हुए हैं। फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला है उसके आने के बाद में थर्ड सेमेस्टर में 12 नम्बर बढ़ाये गये उसको थर्ड से सैकिण्ड पोजिशन पर लाया गया है। क्या जो सही मायने में द्वितीय स्थान पर आना चाहिए और इसके कारण थर्ड पोजिशन पर आ गया तो उस लड़के में कुंठा नहीं होगी। श्रीमन्. मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कापियां जांचने के लिए जाती हैं जिस विद्यार्थी में इन्ट्रेस्ट होता है उसी के नम्बर बढ़वाये जाते हैं। इस बात को केवल रजिस्ट्रार जानता है या एक दो आदमी ही जानते हैं। इस तरह की बदमाशी उदयपुर में लम्बे अर्से से चल रही है। आप इसको ठीक ढंग से कराने का प्रयत्न करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमन्. यही नहीं उदयपुर विश्वविद्यालय का आडिट हुआ। उस आडिट में कई आब्जेक्शन्स हैं। आप आडिट रिपोर्ट मंगा कर स्वयं देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। घोटाले करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, पहला घोटाला तो, सभापति महोदय, वाइस चान्सलर का जो मकान है उसकी साइज आई.सी.आर. के नार्म्स के अनुसार 5025 वर्ग फीट में होनी चाहिए लेकिन उसको 7933 वर्ग फीट बनाया है। लगभग 2900 वर्ग फीट अधिक बना। वह पैसा जहां कालेज की बिल्डिंग बनाने में खर्च होना चाहिये था वहां वाइस चांसलर के मकान बनाने में लगा दिया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने पिछली बार भी कहा कि वहां नेहरू होस्टल है वहां पर 300 फुट लम्बी पाइप लाइन निकाली गई उसका आज भी पता नहीं कि कहां है। उसको लोगों ने बेच खाया है। आडिट रिपोर्ट में एक पर्टीकूलर आदमी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है। आप कृपया रिपोर्ट को निकलवा कर जांच करायें और जांच के बाद यदि आपको लगे कि व्यक्ति दोषी है तो निश्चित रूप से आप उस आदमी को सजा दें।

यही नहीं, श्रीमन्, वहां जो पर्चेजेज हुई हैं, मैं केवल एक केस की बता रहा हूं। आडिट में कई अन्य केसेज हैं, मैं तो एक ही केस की बात बताना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** समाप्त करें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** श्रीमन्, केवल दो तीन मिनट और लूंगा। वहां जो ट्यूबलाइट फिक्सचर के साथ खरीदी गयीं तो लोगों ने टेण्डर्स दिये थे। एक जयपुर की कोई कम्पनी थी और एक उदयपुर की थी, जयपुर वालों ने 224 रुपये प्रति ट्यूबलाइट फिक्सचर के साथ देने की बात कही और उदयपुर वालों ने 267 रुपये....

**सैयद मोहम्मद अयाज महाराज :** किस समय का है यह ?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** आप उसमें हाथ नहीं डालें। सबको जैसे डर लग रहा है। हम पैसा देते हैं उसके आधार पर यूनिवर्सिटी चलती है उसमें इस प्रकार के घपले चलें ? उसमें हमारा आदमी हो या आपका हो उसमें क्या फर्क पड़ता है ? मैंने पहले ही बता दिया कि जनता पार्टी के राज में इन्टरनल आडिट हुआ। इसके पहले कभी आडिट भी नहीं हुआ था और उसके आधार पर यह सारी चीजें निकल करके आई हैं।

( व्यवधान )

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री विष्णुप्रकाश बजारी :** कौन से साल का आडिट है ?

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** इसमें लगभग 42 हजार रुपये का सामान खरीदा गया जिसके बारे में जांच होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि रजिस्ट्रार पूरी तरह से क्वालीफाइड नहीं हैं। ए. ई-एन. है और उसने आई. टी. आई. से डिप्लोमा कोर्स किया है वह आज ए.ई-एन. है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सारी स्थिति स्पष्ट है आप जरूर एक्शन लिजिए।

यही नहीं, श्रीमन्, मैं आपको एक अजीब घटना जो अभी अभी हुई है वह बताऊंगा। यानी इस सरकार के बदलने के बाद हुई है। यूनिवर्सिटी रोड बनाई गयी और उसमें जितनी झोंपड़ी आई थीं वह एक बार में सब गिरा दी गयीं। लेकिन, श्रीमन्, एक कागज मेरे पास आ गया उसको मैं पढ़ कर बताता हूं कि किस तरह से मैनुपुलेशन करते हैं। सौभाग्य से यह कागज मेरे हाथ आ गया। इसमें एक ठेकेदार लिखता है। वहां के एस्टेट आफिसर को पत्र लिखा है कि बालकराम की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

झोंपड़ी को हटाने के बारे में—उपरोक्त विषय में जो यहां झोंपड़ी हटाने का कार्य बी.एस.आर. की रेट से करने को तैयार हूं और यह रेट उन्होंने दी है 79 में और यह कागज है मार्च के महीने का, 25-3-80 का जो झोंपड़ी हटाई गयी। श्रीमन, रोड बन चुकी है उसके लिए वह मांग रहा है कि इस रेट पर करने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर इस कागज को भी रफा-दफा करके पैसा लेने की बदनीयति उस आफिसर की है। यह कागज सौभाग्य से हाथ लग गया इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस केस को मंगवा कर कार्यवाही करें। जो आप लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आर. एस.एस. घुस गया तो आपके पास तो 30 साल राज था वह गलती तो आपकी गलती है और अब फिर आपके पास राज है आप कोशिश करना कि अब नहीं घुसे। केवल आपके घुसने नहीं घुसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी लाइन को छोटा करना चाहते हैं तो आपका प्रयत्न होना चाहिए कि बड़ी लाइन पहले खींचे तो वह अपने आप छोटी हो जायगी ऐसा नहीं हो कि आप जितना उसको बन्द करने का प्रयत्न करें वह उतनी ही बढ़ती जाय। आपकी दो पीढ़ियों ने तो प्रयत्न किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह आपकी दया या मेहरबानी से नहीं है। आपके राज में दया के आधार पर हम जिन्दा नहीं हैं। जिन्दा हैं तो अपने संगठन की शक्ति के आधार पर। आपके स्वर्गीय नेता जवाहर लाल जी नेहरू ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी उस समय...

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना आप इसके खिलाफ अनर्गल प्रचार करेंगे उतना ही जनता इस बात को समझेगी।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** आपकी दया पर जिन्दा रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री माधवसिंह दीवान।

**श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):** सभापति महोदय, जो भी बहस हुई है, उसमें ज्यादातर यही मामले सामने आये कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति या शिक्षा की पद्धति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन जरूरी है। आजाद हुए 30 साल हो गये, कोई शिक्षा मंत्री आमूलचूल परिवर्तन

(श्री माधवसिंह दीवान)

नहीं कर पाये। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री उधर बैठे हैं वे भी आज कह रहे हैं आमूलचूल परिवर्तन हो, वे अपने समय में क्यों नहीं कर पाये, क्या कारण हो सकते हैं? या तो शिक्षा मंत्री अकेला रह जाता है और जो आफिसर्स हैं, जो इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, परिवर्तन करने नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी को आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेना पड़ेगा और अगर यही नीति रही तो कुछ नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी में, प्राइमरी एजूकेशन में चेन्जेज करना है तो जन प्रतिनिधियों की सरकार कमेटी बनाये ताकि वह पक्का और ठोस सुझाव दे सकें। आज जो जो बोले हैं, स्पष्ट सामने हैं किन को लेना है या किन को इन्ट्रेस्ट है उनकी समिति बनाइये और उनके सुझाव लीजिये ताकि ठोस सुझाव, ठोस काम कर सकें नहीं तो तीस साल पहले गुलामी जो अंग्रेज छोड़ गये थे, आज भी यही हालत नहीं करें कि अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठा सकें। उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सके। उस बाबत मुझे आशा है कोई न कोई ठोस कार्य आपके मंत्रित्व काल में कर पायेंगे। जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल है कोई नया वाइस चांसलर आता है उसका मकसद रहता है अपने चहेते आदमियों को प्रोफेसर बनाये, प्रमोशन दे। सबसे इम्पोर्टेन्ट काम एक ही करते हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जाते जाते जयपुर में बैठकर 30-40 लोग भर दिये। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कभी भी यूनिवर्सिटीज के अन्दर सर्विस सलेक्शन बोर्ड कायम नहीं हुआ। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरी सेवाओं के लिये है, तीनों यूनिवर्सिटीज के लिये सर्विस सलेक्शन बोर्ड कायम कर दो। नहीं तो यू. पी. का वाइस चांसलर आया तो यू. पी. के आदमी भर लिये, बिहार का वाइस चांसलर आया तो बिहार के आदमी भर लिये। यूनिवर्सिटीज के लिये शीघ्र ही सर्विस सलेक्शन बोर्ड कायम कर दें वही सलेक्शन करे, वही प्रमोशन दे ताकि जो पुराने-पुराने प्रोफेसर्स भर रखे हैं वह व्यवस्था न पनप सके।

आज प्राब्लम यह है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बाहर के राज्यों के आदमी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पदासीन हैं। आर. पी. एस. सी. में एक्सपर्ट बनकर जाते हैं, अपने आदमियों को भर्ती करते हैं। इसका इलाज यही है कि जल्दी से जल्दी सलेक्शन बोर्ड कायम कर दें ताकि वाइस चांसलर के ऊपर से यह हट जाय कि किसको लेना है, अपना पूरा ध्यान एकेडेमिक साइड में और मैनेजमेंट साइड में दे सके। टीचर्स का जब एक बार सलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कोई पूछता नहीं है चाहे लड़के को पढ़ाये चाहे न पढ़ाये। शिक्षा के नये तरीके क्या आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। टाइम पर आ गये तो ठीक है, नहीं आये तो कोई पूछता नहीं है। कभी लड़के भी नहीं आते हैं, कभी टीचर्स नहीं आते हैं। उसके उपरांत भी नये क्या तरीके चल रहे हैं इसके लिये रेगूलरली हर साल, दूसरे साल ट्रेनिंग रखी जाये, रेफ्रेशर कोर्स रखे जायें ताकि सही तरीके से, नये तरीके से लोगों को पढ़ाया जाये। वे सीख सकें। राजस्थान का आधा क्षेत्र रेगिस्तान का है। मरु विकास की बात आ जाय, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट नहीं है। डेजर्ट के लिये क्या उपाय करने चाहिये, इस

(श्री माधवसिंह दीवान)

तरह का कोई स्पेशलाइज्ड संबजेक्ट या डिप्लोमा कहीं न कहीं खोलें तो अच्छा रहेगा जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है राजस्थान के अन्दर 3 कालेज हैं उसमें भी कालेज के हिसाब से सारे राज्यों से पीछे है। जिसमें खास तौर से पिलानी का निजी इन्स्टीट्यूट है। मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में 50 पर्सेन्ट बाहर वालों को स्थान देने पड़ते हैं। इस तरह राजस्थान में सिर्फ एक-आध कालेज है। एम.पी. में 7, गुजरात में 8, इसके मुकाबले राजस्थान में इन्जीनियरिंग कालेज होना जरूरी है। टेक्निकल सर्विसेज में जितना भी सलेक्शन होता है उसका 40, 50 प्रतिशत बाहर वाले आदमी ले जाते हैं। हमारे यहां के लोग मेरिट में अवेलेबल नहीं होते। चाहे आर.एस. इ.बी., हो चाहे पी. डब्ल्यू. डी., हो बाहर वाले सर्विस में आ जाते है।

यूनिवर्सिटीज की हालत यह है कि दिन ब दिन टीचर्स की टू एसोसियेशन्स बनी हुई हैं। स्टूडेण्ट्स की यूनियन और बनी हुई है जिनका रिजल्ट जितना बाहर नहीं है जितना यूनिवर्सिटीज के अन्दर है। सब से बढ कर के यूनिवर्सिटीज के अन्दर इस चीज को खत्म किया जाये तो एजूकेशन के लिये बहुत बड़ा कदम होगा और यह बहुत जरूरी है। पी. एच. डी. का स्टेण्डर्ड उसमें भी अब सिफारिश चलती है। पी- एच. डी. के लिये सिफारिश यूनिवर्सिटी में चलने लगी है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है थीसेज को कोई पढ़ता भी है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है।

अन्त में, 30 साल में एजूकेशन में वृद्धि काफी हुई है लेकिन फिर भी महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि नगण्य है। आज भी गांवों में जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें लड़कियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। बहुत बार हमने भी कोशिश की लड़कियों को कम से कम पहली दूसरी तक पढ़ाये किन्तु आज तक हम सफल नहीं हो पाये हैं। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी, चाहे इन्सेन्टिव दीजिये। लड़कियों को पढ़ाई के अन्दर लाना बहुत जरूरी है तभी हम सही रूप से विकास कर सकते हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यह 70 लाख रुपया लगाया जा रहा है। यह शीयर वेस्टेज है। इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाये। यह सारा पैसा खड्डे में जा रहा है. इस पैसे को दूसरी जगह यूटिलाइज करने की कोशिश करें।

और अन्त में एक बात और है। सोजत के अन्दर कालेज का होना जरूरी है। दो सौ लड़के रोज पाली अप एण्ड डाउन करते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल कालेज खोलने का प्रावधान कर दें।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : जेठमल जी। 5 मिनट में समाप्त कर दें।

**श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, नागौर जिले में मकराना है। सभापति महोदय, आप जानते हैं संगमरमर का औद्योगिक नगर है और मकराना परबतसर सब डिवीजन में आता है। परबतसर सब डिवीजन के अन्दर चार म्यूनिसिलिपैटीज हैं, 3 विधान सभा क्षेत्र हैं और 3 पंचायत

(श्री जेठमल बरवड़)

समितियां हैं और करीब 6 लाख की जनसंख्या का सब डिवीजन है। यहां पर कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं हैं। मकराना, परवतसर, कुचामन, नावां, बड़े बड़े कस्बे हैं इस सब डिवीजन के बच्चे आज जयपुर, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, सांभर कई स्थानों पर 500,700 बच्चे बाहर शिक्षा ले रहे हैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज मकराना के अन्दर हजारों मजदूर जो वहां काम कर रहे हैं, उन हजारों मजदूरों के जो बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह रहे हैं। अगर आप इस क्षेत्र में एक कालेज की स्थापना कर दें तो वहां के मजदूरों के बच्चों को, वहां मकराना के जो लड़के शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा मिल सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप वहां एक कालेज खोलने की घोषणा करेंगे तो मकराना के लोग इसके लिए भवन बनाने के लिए काफी तादाद में आपको धन दे सकते हैं। यह मैं आपको सभापति महोदय, आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहूंगा। इसके अलावा जो परवतसर के अन्दर, मेरे कान्सटीट्यूएन्सी के अन्दर कई ऐसी बड़ी बड़ी ढाणियां हैं जिनमें कोई भी प्राइमरी स्कूल न होने के कारण वहां के किसानों के बच्चे शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो ऐसी बड़ी बड़ी ढाणियां हैं वहां एक प्राइमरी स्कूल खोलकर वहां के किसानों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने की व्यवस्था करें क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है और वहां जो विशेषकर परवतसर सीट है, यह परवतसर सीट भी रिजर्व है। यहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल का खोलना जरूरी है।

इसके अलावा जो आपकी प्रौढ़ शिक्षा है इसके इतने स्कूलों पर जो खर्चा होता हैं जितना धन प्रौढ़ शिक्षा में लग रहा है. मैं, सभापति महोदय, यही निवेदन करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा जितनी भी ऐसी संस्थाओं को दे रखी है, उन संस्थाओं के नेताओं को तनख्वाह देने का, फायदा पहुचाने का एक काम किया गया था। सभापति महोदय, इससे हरिजन और पिछड़े किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये लोग पुराने महात्वीणा लोग हैं। वही पुराने लोग हैं, कई जनता पार्टी में हैं जो सर्वोदयी हैं, जो अपने आपको सर्वोदयी बताते हैं। उन लोगों के बच्चों को नौकरियां देने के लिए यह कार्यक्रम खुला है? इसके अलावा इधर बैठने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि ट्रान्सफर्स अध्यापकों के हो रहें हैं। यह परम्परा डाली किसने? यह इन्होंने डाली, यह परम्परा इन लोगों ने जब जनता पार्टी का राज आया उस वक्त इन लोगों ने सबको निकालकर बाहर कर दिया।

(व्यवधान)

अौर अब यह कह रहे हैं कि हमारे को, आज मंत्री महोदय के पास एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिस पर साफ न लिखा होगा कि हमको जनता पार्टी के राज में फेंका गया था।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(व्यवधान)

(श्री जेठमल बरबड़)

जो बात है, उसको मैं सच्चाई के साथ कहूं इस बात में मैं झुकना नहीं चाहता तो आज यह भी होगा....

(व्यवधान)

जिस अध्यापक के साथ...

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज । आप जारी रखें ।

**श्री जेठमल बरबड़ :** जिन अध्यापकों को, सभापति महोदय, इन अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है । मैं उनकी तरफ से कहना चाहता उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है । उनको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो परम्परा आप लोगों ने डाली है, उसका परिणाम है...

(व्यवधान)

मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आप भी गलत परम्परा डालेंगे तो आपका भी वही परिणाम होगा जो जनता पार्टी का हुआ । इस तरह से मेरा आपसे यही

(व्यवधान)

निवेदन है कि हमारे मकराना, जो नागौर जिले में है, में हिन्दुस्तान के अन्दर मकराना की मार्बल की जो खाने हैं आज उन खानों का पत्थर निकलता है वह हिन्दुस्तान के हर किसी भवन के अन्दर, हर मन्दिर के अन्दर, हर मस्जिद के अन्दर, हर गिरजे के अन्दर, हर गुरुद्वारे के अन्दर लगता है । चाहे जैसे भवन हों उन भवनों की शोभा बढ़ाता है । और वहां के मजदूरों के बच्चों को आज उच्च विद्याध्ययन से वंचित रहना पड़ रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि मकराना के अन्दर एक कॉलेज का होना बहुत आवश्यक है । इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय दिया ।

**श्री सभापति :** श्री अमराराम चोधरी ।

**श्री अमराराम चोधरी** (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, प्रजातन्त्र और जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के हर व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा । मेरा जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है और सरकार 6 दिन भी उस कान्स्टीट्यूएन्सी में जीप लेकर घूमे तो हर गांव में नहीं घूम सकती क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है । भारत गांवों का देश है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा जब तक गांवों में स्कूल नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा देश के विकास के लिए गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा । मेरे इलाके के अंदर हीरा की ढाणी और किलानपुर की ही बात नहीं, माननीय सदस्य आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे बहुत से गांव हैं, ऐसी बहुत सी ढाणियां हैं जहां आज एक भी व्यक्ति नहीं है । ऐसा आपको उदाहरण मिलेगा कि शिक्षित नहीं मिलेगा । उनके वहां किसी रिश्तेदार का पत्र आता है तो वे पढ़ाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं या किसी बनिये की दुकान होती है वहां जाकर वे पत्र को पढ़ाते हैं । ऐसा हाल है मेरे क्षेत्र के अन्दर । जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सवाल है मिडिल स्कूलों का प्रश्न है, हायर सैकण्डरी स्कूलों का प्रश्न है, मेरे क्षेत्र के अन्दर में जनता राज के अन्दर कुछ

(श्री अमरराम चौधरी)

स्कूल खोले गये, कांग्रेस के राज में खोले गये थे, उनको जनता सरकार ने बन्द कर दिया। मेरे वहां दो हायर सैकेण्डरी स्कूल खोले गये, हीरा की ढाणी और किलानपुर के अन्दर। जनता सरकार ज्यों ही पावर में आयी तो उसने क्या किया कि सबसे पहले यह काम किया कि यहां स्कूल हैं यहां के लोग शिक्षित हो जायेंगे तो फिर हमारे आर.एस.एस. वाले उनका मुकाबला करेंगे जिससे हमारी जो नीति है, वह पनप नहीं सकेगी। इसलिए सबसे पहला काम यह किया कि हीरा की ढाणी और किलानपुर में जो सैकण्डरी स्कूल खोले थे, उनको इन्होंने बन्द कर दिया। आज हीरा की ढाणी के आस पास कहीं भी 20 मील या 30 मील के अन्दर कोई भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है, जो एक सबसे बड़ा गांव है। वहां आज भी बहुत से छात्र हैं जो पढ़ने के लिए उत्सुक हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे शहर में जाकर पढ़ नहीं सकते। इसलिए वहां के जो लोग हैं वे आठवीं तक पढ़कर वहीं किसान के काम में लग जाते हैं। जो होनहार विद्यार्थी होते हैं वहां हायर सैकण्डरी स्कूल न होने के कारण वे पढ़ नहीं सकते।

मेरे क्षेत्र में बालोतरा एक बहुत बड़ा शहर है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत पुराना है। यह पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुराना जालौर का आज से चार साल पहले यहीं लगता था या जालौर जिले के अन्दर, सूरज पाल सिंह जी नाराज न हों, बालोतरा में था। ये लोग हमारे यहां पर पेशियां कराने आया करते थे क्योंकि हमारा जो बालोतरा है वह ऐसी मण्डी है, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब प्रकार से लोगों के आने जाने के हिसाब से ठीक होने के कारण वहां पर ही रखा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया है।

जालौर जिले में दो कालेज हैं। भीनमाल का कालेज और जालौर में कालेज है। लेकिन बालोतरा इतना पुराना कस्बा होने के बावजूद भी आज दिन तक वहां कालेज नहीं खोला गया। तो, श्रीमान्, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बालोतरा वालों की हमेशा यह मांग रही है, आज से नहीं, दस सालों से यह मांग रही है कि बालोतरा के अन्दर एक कालेज खोला जावे। बाड़मेर जिले के अन्दर कोई भी सैकण्डरी के अन्दर ऐसा विषय नहीं है कि जो प्रोफेशनल हो। मेरे क्षेत्र में दस गांव ऐसे हैं जहां डबल क्रोप होती है। वहां वेरे हैं। असाडा और आसोतरा, वहां सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां जमीन है, कुआं है, सब कुछ देने को तैयार हैं, वहां एग्रीकल्चर यानी कृषि विषय खोला जावे। इन दोनों सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर हमारे पास जमीन उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है और क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी कि जिससे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको नौकरियां नहीं मिले तो कुछ ऐसा ज्ञान हासिल करा दें कि कम से कम खेती से ही तरक्की कर सकें। इसलिए इन ग्रामों के अन्दर कृषि का विषय खोलना बहुत जरूरी है।

(184)



(श्री अमराराम चौधरी)

इसके अलावा आज मैं देखता हूं कि विश्वविद्यालयों में और विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता बढ़ रही है। इसमें इस शिक्षा पद्धति का दोष है।

( समय समाप्ति-सूचक घण्टी )

लेकिन साथ साथ अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जो संबंध है उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। अध्यापक भी वैसे नहीं रहे जो पुराने समय में थे। वे चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले लेकिन वह सम्मान के अनुसार जब तक वातावरण नहीं बनायेंगे, स्वयं नहीं बनेंगे, अपने आपको सुधारेंगे नहीं और केवल यह चाहें कि विद्यार्थी हमें सम्मान देते रहें। विद्यार्थियों को कम से कम इस प्रकार से बनना चाहिए कि वह अध्यापकों से ज्ञान हासिल करने के लिए अपना जो मोरल है उसको ऊंचा उठावें और उनका सम्मान करें। विद्यार्थियों के अभिभावक अपने बच्चों को जो कि लड़ाई करते हैं, सुधारें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

हड़तालें करते हैं तो अभिभावकों की भी यह तैयारी होनी चाहिए कि वह अपने लड़कों को सुधारें कि इस प्रकार से तुम पढ़ने के लिए जाते हो, देश का पैसा खर्च होता है। उसका खुद का टाइम बर्बाद होता है, यह कीमती समय विद्यार्थी का जाता है तो यह विद्यार्थी जीवन का समय हड़तालों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। इसके लिए जगह जगह पर अभिभावकों की और अध्यापकों की कमेटी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो विद्यार्थियों के अन्दर और अध्यापकों में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं उनको शीघ्र ही दूर कर दिया जावे।....

**श्री सभापति** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम चौधरी** : ताकि हड़तालें नहीं हों। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, हमारे गांव के जहां पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई के अन्दर भी बाधा नहीं पड़े।

मैं इसके अलावा यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर जो मिडिल स्कूल हैं, अभी एक मिडिल स्कूल के लिए जो हिसाब से आ रही है वहां पर मैं अपने शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वहां कम से कम तीन या चार मिडिल स्कूल मेरे क्षेत्र में खोले क्योंकि पहले ही मेरा क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे रहा है। इसके अलावा वहां पर एक ही सैकण्डरी स्कूल है, गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल। मेरे पूरे क्षेत्र में एक ही लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल है और इस लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल में फील्ड भी अच्छा बना हुआ है। हमने कई वर्षों से कोशिश की है।

( 8.43 रात्रि )

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कर रहे हैं कि इसको हायर सैकण्डरी बनाया जाय। मेरा शिक्षा मन्त्री जी को यही निवेदन है कि हमारा जो बालिकाओं का विद्यालय है, सैकण्डरी स्कूल है उसको हायर सैकण्डरी बनाया जावे क्योंकि उसके लिए हमारे वहां के जो शहर के लोग हैं, उसके लिए कुछ भी खर्चा देने को तैयार हैं, सिर्फ आपको रेज करना होगा हायर सैकण्डरी में रेज करना होगा।....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

**श्री अमराराम चौधरी :** मैं आपको अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया और यह निवेदन करता हूं कि मेरे यहां पर जो शिक्षा का विकास हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है उसके लिए आप पूरा इसकी ओर ध्यान देंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी :** मैं आशा करूं कि हमारा भी ध्यान रखेंगे आप।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अब समय काफी हो गया है। इसलिए 9 बजे सरकार का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। अब जो भी सदस्य बोलें पांच मिनट से अधिक समय नहीं लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** हमारे दल से एक ही सदस्य बोले।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** पांच पांच मिनट में समाप्त करें, संक्षेप में।

**श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर कुछ सुझाव देणो चाहूं हूं आपणा कटौती प्रस्ताव के जरिये। मैं आपसे आ अरज करणी चाहूं शिक्षा मन्त्री महोदय सूं कि एक तो आप आ व्यवस्था कराओ कि गांव की जठे प्राइमरी स्कूलां में वीरे मायने गर्मी रे मायने छुट्टियां होवे, वे छुट्टियां गर्मी रे मायने नी होकर बरसात के समय पर कर दी जावे तो जी रे टाबरां पढ़वाने जावे वांसू फायदा मिल सके है। गर्मी रे मायने सब लोग गांवा में आयोड़ा व्हैवें और वा बच्चा भी भेला हो कर परिवार के आगे हाजिर हो सके। बरसात में सब किसान खेतां में, ढाणियां में चल्या जावे है। ई वास्ते मैं सुझाव देणूं चाहूं कि मन्त्री महोदय ई बात री ओर ध्यान दिलावे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरो सुझाव मैं आ अरज करणो चाहूं कि अबार री शिक्षा पद्धति मांये जोर दियो जावे कि विद्यार्थियां ने पढ़ाओ, टाबरां ने स्कूल भिजवावो, आपरां बच्चा ने स्कूल ने भेजो। अच्छी बात है पण विशेष तौर पर आ अरज करूं मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि सिर्फ पढ़ाई के नाम मत करो। जीकी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है वी रे मांयने आप पूरो ध्यान दिलाओ। उच्च शिक्षा प्राप्त ट्रेंड टीचर्स वठे भेजो और जव नींव पक्की होगी तो देश रो विकास और प्रदेश रो विकास हो सकेलो। ई वास्ते मैं आपरो ध्यान दिलाऊं। विशेष तौर से लड़कियां री पढ़ाई वास्ते आप पूरो ध्यान दिलाओ। ई वास्ते मैं आपरो ध्यान दिलाऊं। जिका परिवार में एक लड़की पढ़ लेसी वह मां पढ़ लिख कर, पत्नी मां, बण कर सभ्य नागरिक बणावेगी देश के सामने। अगर एक लड़को पढ़ले तो वो एक सभ्य नागरिक बणेला जब कि एक लड़की मां बण कर कम से कम तीन टाबरां ने देश का सभ्य नागरिक बणावेली।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय कोनी लेणो चाहूं। इत्तो ही केणो चाहूं के प्राइमरी स्कूलां में सरकार के द्वारा स्लेटा री, किताबां री, कापियां की तो कम कम व्यवस्था कराओ। गरीब लोग बसे है, गरीब किसान हरिजन बसे हैं वांरी इतनी पूंजी कोनी कि जीको आपरा टाबरां रे वास्ते कपड़ां रे साथे किताबां कापियां की व्यवस्था कर सकें, ई मंहगाई के समय में आपरे आप व्यवस्था कर सकें। तो शिक्षा मंत्री जी बजट में यह प्रावधान जरूर राखो कम से कम। पश्चिमी राजस्थान के बारे में, मैं अरज करूं कि वठेरा किसान बहुत गरीब है। वां री तरफ जरूर ध्यान राखो।

186



(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूल के मांये अध्यापकों री उपस्थिति बहुत कम रैवे है। तो वीरे वास्ते आप विशेष रूप सूं हिदायत दिलाओ अधिकारियों ने कि जठे दूर-दराज क्षेत्र हैं, जठे स्कूलां हैं, अफसर तो पोंच नहीं सके, कम से कम जन प्रतिनिधियां ने या बठे रा सरकारी कर्मचारियां ने यह हिदायत दिराओ कि माहिक रिपोर्ट देवे और गांवों में जाकर जांच करे कि मास्टर बठे स्कूल में पढ़ाई करावे या कोनी करावे। अध्यक्ष महोदय, प्रामइरी स्कूल रे मायने जठे टाबर पढ़णरे वास्ते जावे तो बठे भवन री व्यवस्था कोनी। तो जित्तो सहयोग हो सके बित्तो तो सरकार देवे और बाकी गांव वाला देवे ....

**श्री अध्यक्ष :** समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी :** कम से कम भवन री व्यवस्था होनी चाहिजे। अध्यक्ष महोदय, इं वास्ते जीत्तो होसी, सब ग्रामीणां सूं बातचीत म्हारी हुई तो वे केयो कि जित्तो सहयोग मांसू होसी मैं देवांलां। सरकार कम से कम आधो सहयोग देवे। जो भवन बनाये तो म्हारा टाबरां धूप में सर्दी में बाहर बैठे और मास्टर एकाध कुर्सी लगाय कर बैठे। वीरे वास्ते शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करणो चाहूं कि म्हारा जित्ता सुझाव है वां पर जरूर ध्यान दिलावो।

**श्री अध्यक्ष :** हंसराज शर्मा। माननीय सदस्य, पांच मिनट।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो वहां अच्छे अच्छे विद्वानों ने राजनैतिक तलवार से शिक्षा के सम्बन्ध में खूब कटौती की है। आपसी मतभेदों के सम्बन्ध में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारा राजस्थान छोटे छोटे गांवों में बंटा हुआ है। प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से इसका गांव में ज्यादा उत्थान होना चाहिये। छोटे छोटे गांवों में जहां दो सौ की आबादी है उस पर एक प्राइमरी स्कूल का प्रावधान होना चाहिये। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दो सौ की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल खुलवायें। छोटे छोटे गांवों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के काश्तकार लोग रहते हैं और वहां शिक्षा की दृष्टि से स्कूल बहुत कम पड़ते हैं। इसलिए दो सौ की आबादी पर प्राइमरी स्कूल का प्रावधान किया जावे तो अति सुन्दर होगा।

इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि गांवों में मिडिल स्कूल 1500 की आबादी पर खोल दिया जाय। क्योंकि वह छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांवों के लोग उन्हीं मिडिल स्कूलों में शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें पन्द्रह सौ की आबादी पर मिडिल स्कूल का प्रावधान किया जावे।

इसी प्रकार हाई स्कूलों के लिए, 2000 की आबादी पर निश्चित किया जावे। जहां दो हजार की आबादी है, वहां हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था की जावे और यदि इस बजट में इस प्रकार से प्रावधान न किया गया तो गांवों में जो शिक्षा का अभाव है, वह ज्यादा बढ़ेगा, जो विद्यार्थी पढ़ने में असमर्थ रहते हैं, वहां पर पहुंच पायेंगे ?

(श्री हंसराज शर्मा)

इसी प्रकार मेरा शिक्षा के सम्बन्ध में एक निवेदन है कि हमारा राजस्थान एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत आगे है। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि गांव में हाई स्कूल की शिक्षा तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक या दो स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने की व्यवस्था है, किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान सरकार ने कोई भी साल एग्रीकल्चर कालेज का बजट में प्रावधान नहीं रखा है। राजस्थान में एक भी एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, कृषि को आगे बढाने की दृष्टि से, उपज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, यदि हमारे लोगों के बच्चे शिक्षित होंगे, ज्यादा एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो ज्यादा काश्तकारों को शिक्षा देंगे। लेकिन इस बजट में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा जाय। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण चारों भागों में चार कालेज राजस्थान सरकार की तरफ से होने चाहिये। इस संदर्भ में, मेरा निवेदन है पोलिटेक्निक के सम्बन्ध में हमारे यहां पोलिटेक्निक की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था है। पोलिटेक्निक कालेज में जब विद्यार्थी के इन्टरव्यू होते हैं, तो पांच या छः जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें अलग अलग लोगों के इन्टरव्यू लिये जाते हैं। सभी विद्यार्थी वहां एक साथ अलग-अलग संस्थाओं में फार्म भरते हैं। जब अलग-अलग इन्टरव्यू के नाम देते हैं, अलग-अलग जिलों में जाते हैं वहां इस प्रकार होता है, कम नम्बर वाले से ज्यादा नम्बर वाले को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन उदयपुर में अगर 30 नम्बर वाला पहुंच गया और कोटा का 40 नम्बर वाला पहुंच गया और 40 से 45 नम्बर वाला पहुंच गया, ये तो 45 संख्या जितनी ली हैं, उसके समान 35 वाले को ले जाते हैं, यह इसमें दोष है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पोलिटेक्निक में इस प्रकार की व्यवस्था है उसको हटाया जावे। और राजस्थान के कालेजों का एक साथ इन्टरव्यू किया जाय ताकि सीनीयरिटी के आधार पर ज्यादा नम्बर प्राप्त करने वाला विद्यार्थी वंचित न रह जाय और जो कालेज नजदीक पड़ता है, उस कालेज में उसका नाम एडमिशन के के लिये भेज दिया जाय। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रत्येक जिले में जैसे सवाई-माधोपुर जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। वहां 26 सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी स्कूल हैं। और उनमें संस्कृत की व्यवस्था है, वहां पर करौली और सवाईमाधोपुर में कालेज हैं, उनमें संस्कृत की व्यवस्था नहीं है। ऐसे क्षेत्र में विद्यार्थियों को हायर सेकण्डरी से संस्कृत में पास होने के बाद बहुत दूर जाना पड़ता है।

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत है और संस्कृत कालेज नहीं है, जो मैंने निवेदन किया, कालेज में संस्कृत खोलने का आप स्वीकार करेंगे तो अति सुन्दर होगा। अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन है कि हमारे यहां सवाईमाधोपुर में लॉ कालेज की व्यवस्था नहीं है। जबकि जिला हैडक्वार्टर होते हुए भी एम. ए. की क्लासेज और लॉ कालेज की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एम. ए. की क्लासेज और लॉ कालेज खोला जाय। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर में कन्या पाठशाला है, वह शहर के एकांत के क्षेत्र में है; वहां पर आये दिन बच्चों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार होता रहता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में जांच करायें और जांच कराने के बाद उस कन्या पाठशाला को, जो जिस जगह है, वहां पर से अन्यत्र स्थान पर खोली जाये ताकि बच्चियों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट नहीं एक मिनट।

श्री हंसराज शर्मा : दो मिनट। मेरा निवेदन है कि आये दिन देखा जाता है कि जब भी सरकारी कोई काम होता है, बेगार का काम होता है, मेहनत का काम होता है, हमारे राजस्थान के शिक्षक समाज के ऊपर डाल दिया जाता है। मर्दुम शुमारी करो तो वह, वोटर लिस्ट बनाओ तो वह, गांवों की किसानों की शुमारी करो तो वह, इस प्रकार के सारे काम अध्यापकों पर डाल दिये जाते हैं। जिससे अध्यापक गांवों में आसानी से नहीं पढ़ा सकता है। कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, और सरकार का बेगार का काम आता है, उसमें सबसे सस्ता और सबमें सीधा देश का जो अध्यापक है, वह सबको सामने दिखता है। उसके माध्यम से बेगार ली जाती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार उनको बेगार से दूर रखें। इस संबंध में, मैं अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय कुछ वक्ताओं और जो बूंदी से पधारे थे, ने शिक्षा की कई बातों पर प्रकाश डाला और प्रकाश डालते डालते वह आर. एस. एस. पर चले गये। वह वहां हैं नहीं, अन्य व्यक्तियों ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि उनका उनसे रोष था। रोष यह था कि जब वह यहां पर मिनिस्टर थे, इस वक्त सीमेंट फैक्ट्री के साथ साहू जैन के सैक्रेटरी से मिलकर वहां के कर्मचारियों का गला घोंटा, और उस पैसे में से अनधिकृत रूप से पैसा खाया था, उसका आर. एस. एस. वालों ने विरोध किया, भंडाफोड़ किया इंटक का नाम लेकर साहू जैन की सीमेंट फैक्ट्री से जो पैसा खाया उस पर लांछन लगाया था और ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य। समय समाप्त हुआ।

श्री हंसराज शर्मा : गवर्नमेन्ट होस्टल के के पीछे लाखों रुपए की बिल्डिंग बनायी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये आर्डर।

( व्यवधान )

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता सिर्फ शिक्षा मंत्रीजी से यह घोषणा कराना चाहता हूं कि एक तो प्राइमरी स्कूल जहां-जहां डिमाण्ड हो, बीस-पच्चीस लड़के होते ही वहीं आप सीमित करदें और विविध स्कूल जहां जरूरत हैं, वहां खोलें।

श्री अध्यक्ष : श्री बिहारी लाल ।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आज शिक्षा की मांग है, उस पर दिलाना चाहता हूं। मेरी लगातार 7 घंटों से माननीय सदस्यों ने, जो इस बजट से अपने क्षत्र में किस तरह से ज्यादा लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा वहां पर शिक्षा का हिस्सा बंटा सकें, इस पर सबने विचार दिये, मैं इन सब की कद्र करता हूं । मैंने भी आज आपके माध्यम से इस सदन में शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाने हेतु विधानसभा मांडल क्षेत्र में गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बने, इस विषय पर चर्चा हेतु मैंने निवेदन किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज की अनिवार्य आवश्यकता जिसमें शिक्षा एक प्रथम है, जो समाज इससे पिछड़ा रह जाता है मैं समझता हूं वह देश में बहुत पीछे रह जाता है, विकास नहीं कर सकता है।

अभी जो शिक्षा के संबंध में वर्तमान स्थिति है, दयनीय स्थिति है और शिक्षा की जो पद्धति है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं कि शिक्षा के प्रसार की काफी आवश्यकता है। मैं समझता हूं शिक्षा की स्थिति अभी जो बनी हुई है उससे सभी गांव पिछड़े हुए रह जायेंगे। शिक्षा का जो बजट है, पहले जो बजट बना वह 13 करोड़ का जब बनाया, मैं समझता हूं महंगाई को देखते हुए उस बजट के बराबर स्थिति है।

मेरे क्षेत्र पर प्रकाश डालूं । श्रीमान्, वहां पर करीब 550 गांव हैं और केवल 110 प्राइमरी और 2 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं । स्थिति बड़ी नाजुक है। गांव ज्यादा हैं और प्राइमरी स्कूल बहुत कम हैं। मैं समझता हूं राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, विरोध में बोलना अलग बात है। इस महंगाई की स्थिति में, घाटे की स्थिति में भी, मैं समझता हूं, शिक्षा मंत्री जी उदारतापूर्वक ध्यान देंगे। गांव-गांव की जिम्मेदारी आप पर है । जनता ने मुझे आपके पास मांग के लिये भेजा है तो मेरा फर्ज है कि आपका ध्यान दिलाऊं कि स्थिति बहुत दयनीय है। 550 गांवों में केवल 110 स्कूल हैं और जिनमें भी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल शामिल हैं। मेरे पास आंकड़े हैं । जो म्यूनिसिपैलिटी बनी छह छोटे-छोटे गांवों को मिला कर बनाई गई है जिसमें 95 या 99 प्रतिशत कह दें तो वे गांव है शहर की स्थिति नहीं है। वहां पर प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोलें और इस आधार पर स्थिति को देख कर मेरी मांग पर ध्यान दें जितना ज्यादा दे सकें तो मैं समझता हूं शिक्षा के बारे में विकास ज्यादा होगा । इन स्कूलों की स्थिति मैं निवेदन करता हूं पांचवीं कक्षा के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं । अगर वहां लड़कों की कमी है तो स्कूल तो चल रही है मेरा सुझाव है वहां एक अध्यापक की संख्या बढ़ा दें तो मैं समझता हूं बच्चों को ज्यादा लाभ होगा । जहां एक मास्टर हो और पांच क्लासेज चलती हों तो आप सब जानते हैं बड़ी दयनीय स्थिति है उन बच्चों की शिक्षा एक मास्टर कितनी करा सकता है। मैं समझता हूं, जो सत्ता में होते हैं, राज में होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं माननीय सदस्यों की निंदा और बुराई नहीं कर रहा हूं। बहुत से सदस्यों ने कहा कि एक गांव में 200 लड़के और एक मास्टर है। यह कहना और बात है लेकिन जहां 40 लड़के हैं और

(श्री बिहारी लाल पारीक)

एक मास्टर है तो वह ठीक नहीं है लेकिन 200 लड़कों की स्थिति मैंने नहीं देखी। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने काफी स्थिति पर पर विचार किया। मैं समझता हूं शिक्षा का विषय है इसलिये मैं सारे माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि जो सदन का समय है, मैं बराबर कई घंटे से विचार कर रहा था कि कब मेरा नम्बर आयेगा और मेरे क्षेत्र की समस्यायें कब मैं पेश करूंगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि अध्यक्ष महोदय पधारें और मना कर दें क्योंकि कटौती प्रस्तावों पर अपनी बात कहने के लिए हर माननीय सदस्य चाहता है। मेरे मन में पीड़ा हुई कि आज शिक्षा का विषय है और समय बहुत कम है। शिक्षा से संबंधित होने के नाते अर्ज कर रहा हूं फिर भी बीच में व्यवधान से काफी समय बर्बाद होने के कारण मैं अपने विचार नहीं कह सका।

मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र के ऊपर दिलाऊं कि वहां की स्थिति मैंने बताई है कि वहां पर दो हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें केवल एक जगह पर कृषि विषय है। मैं प्रार्थना करता हूं कम से कम एक स्कूल हायर सैकण्डरी का है वहां कृषि का विषय खोलें। माण्डल नगर है उसमें मैं प्रार्थना करता हूं कृषि विषय तो है पर सैक्शन नहीं है। 110-115 लड़के हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सैक्शन खोलें। वहां उर्दू विषय की भी मांग की है। 10 लड़कों पर उर्दू विषय खोलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां विषय खोलने की बात है। मैं प्रार्थना करता हूं जितने सैकण्डरी स्कूल हैं वहां विषय बढ़ा दें। सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान मेरे क्षेत्र में एक का रखा है। मैं आपकी व्यवस्था में व्यवधान नहीं करता।

**श्री अध्यक्ष** : एक भी पक्की नहीं है।

**श्री बिहारीलाल** : दो सौ के हिसाब से एक आती है। मैं प्रार्थना करता हूं आपने मेरे क्षेत्र में तीन प्राइमरी स्कूल बजट में रखे हैं उनको बढ़ाया जाय और मिडिल स्कूल सिर्फ एक का रखा है उसको बढ़ाया जाय और उसमें विषय खोले जायं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, शांत रहें।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : मैं एक मिनट में....

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलें।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : मैं समझता हूं कि जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले लौर अन्य पार्टी वाले और एक माननीय सदस्य जो बुजुर्ग है बड़े जोर शोर से कहा उन्होंने। 32 वर्ष की बात कही जो शायद पधार गये हैं वे शायद भूल गये है, कांग्रेस का राज 30 साल तक रहा और जनता पार्टी का दो ढाई साल तक राज रहा। जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्होंने बहुत स्कूल खोल दिये। हो सकता है उनको समय नहीं मिला या व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी। कुछ जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डल की होती है, उनकी जिम्मेदारी की बात होती है। यह जिम्मेदारी अपने पर भी लागू होती है। मैं समझता हूं हर राज वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं परन्तु दुर्भाग्य से सत्ता हट जाती है भगवान की कृपा की बात है उसके लिये क्या कह सकता हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही वह बड़ी दयनीय बात थी अखबार में नाम लाने के लिये या तालियां बजवाने के लिये बात करते हैं। मैं समझता हूं ऐसा कुछ भी

(श्री बिहारी लाल पारीक)

नहीं है माननीय सदस्य बोल रहे थे, बड़े बुजुर्ग हैं शिक्षा की बात न कह कर अपने अधिकार की बात कह रहे थे इसलिये मैं ध्यान दिलाता हूं कि जब जनता पार्टी राज में आई तो एक ऐसी स्थिति बनी कि जय-प्रकाश बाबू ने कहा कि आप एक घर के नेता को प्रधान मन्त्री बना दो परन्तु दुर्भाग्य की बात रही कि जे.पी. की बात किसी ने नहीं सुनी। जब पार्टी टूट गई तो सभी ने कहा कि हम हरिजन नेता को प्रधान मन्त्री बनायेंगे। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, समझ गई कि ये हरिजन नेता को प्रधान मन्त्री नहीं बनायेंगे इसलिये जनता पार्टी को जनता ने वोट नहीं दिया। स्थिति स्पष्ट है बिल्कुल देख रहे हैं और ताली बजाने के लिये, उनको बदनाम करने के लिये मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं थी। जब कांग्रेस पार्टी आई तो किसी ने वादे नहीं किये। किसी ने नहीं कहा कि ऐसी स्थिति बना देंगे। मैं समझता हूं बिल्कुल स्थिति साफ है। राजस्थान की जब विधान सभा बनी, आप सब माननीय सदस्य आये तो सबसे पहले हरिजन नेता को आपका नेता बनाया। इससे स्पष्ट हो गया कि जो कहते हैं वे करते नहीं और जो नहीं कहते वे करते हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और मैं आशा करता हूं मेरी मांगों पर ध्यान दिया जायगा। जिस के पास राज होता है उसे जहां दयनीय स्थिति है उसकी देख कर ही करना चाहिए। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से अशिक्षा का अंधकार है, मैंने अपने जो सुझाव दिये हैं इससे समाज में उन्नति हो सके ऐसी मैं आशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री महावीर प्रसाद। केवल पांच मिनिट।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** अध्यक्ष महोदय, जनतांत्रिक समाज में शिक्षा का विशेष महत्व है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकारी प्रतिवेदन है मैं इसको कोट करना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि जनतांत्रिक समाज में शिक्षा का विशेष महत्व है। अतः सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। इसका दायित्व जनतांत्रिक सरकार पर है जिसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने गत वर्षों में बहुत प्रगति की है और वर्तमान में अन्य राज्यों की भांति शिक्षित समाज की संरचना में अग्रसर रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कई राजनीतिक दल इसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं परन्तु आपकी सरकार ने इसको स्वीकार किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गति राजस्थान में जनता शासन में आई वह जनतांत्रिक सरकार का परम कर्तव्य था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा हमारे हिन्दुस्तान और खास-कर के हमारे राजस्थान के अन्दर है, उसमें

192



(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आज गांव की उपेक्षा हो रही है। हमारी अधिकांश जनता गांवों में बसती है इसलिए कम से कम प्राथमिक पाठशालाएं वहां पर खोली जानी चाहिए। पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर कई ढाणियां है। ऐसे कई गांव, ढाणियां रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं आती हैं। इस कारण से वहां पर कोई स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी जो बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं, जहां पर दो-दो सौ, चार-चार सौ आदमी रहते हैं वहां पर प्राथमिक शालाएं खोली जानी चाहिए। टौंक जिले में ऐसी कई ढाणियां हैं, झोपड़ियां हैं जिनका रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। ये गांव शिक्षा से वंचित हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं खोलने की गति तेज की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को जो स्कूल दे रखे हैं और जो उनकी व्यवस्था है इसके कारण वे आज राजनीति के अखाड़े हो गये हैं। प्रतिदिन अध्यापक को सरपंच को मुजरा करने जाना होता है। अध्यापकों की ऐसी दयनीय स्थिति है। इसका शुद्धिकरण किया जाना चाहिये। हमारी शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो स्कूलें पंचायत समितियों के पास में है वे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिये जाने चाहिए। मेरे क्षेत्र में चांदलाई, सेनाला आदि में मिडिल स्कूल खोलना आवश्यक है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। सैकण्डरी स्कूल बोम्बूदा में खोलना बहुत जरूरी है। गांव में एक कन्या शाला दो माइल दूर है। दूसरे छोर पर भी एक कन्या शाला खोली जानी चाहिए। कालेज में एम. ए. तक की कक्षाएं हैं उनमें राजनीति शास्त्र, हिन्दी और एल- एल. बी. की कक्षाएं और चालू करनी चाहिए क्योंकि सरकार की मंशा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी हो। इसलिए आवश्यक है कि कानून की पढ़ाई का वहां के लोगों को लाभ मिले। टौंक जिला पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। वे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए वहां पर एल-एल. बी. की कक्षाएं शुरू की जाएं।

अध्यक्ष महोदय मैंने एक प्रश्न की सूचना, जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी। प्राइमरी स्कूल में कितने अध्यापक हैं और उनके कितने पद रिक्त हैं। उसके उत्तर में यह बताया गया कि 2546 पद रिक्त हैं पहले तो अध्यापकों का माप दण्ड 40–50 विद्यार्थी पर एक अध्यापक का है चाहे वहां पर तीन चार कक्षाएं हों। वह पढ़ाना चाहें तो पढ़ावें चाहे न पढ़ावें। पहले ही यह व्यवस्था अधूरी है उसमें भी रिक्त पद पड़े रहें तो यह उचित नहीं है। इसी तरह से एल.डी.सी. यू.डी.सी. के पद रिक्त हैं। मैं चाहता हूं कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए।

कई हमारे विरोधी माननीय सदस्य राजनीति से प्रेरित होकर सरकार से याचना करते हैं कि आर.एस.एस. पर बेन लगाया जाए। मैं समझता हूं कि उनको इतिहास का स्मरण करना चाहिए। हमारे विरोधी यह कोशिश पहले भी कर चुके हैं। आपके आका कर चुके हैं। आपके नेता कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आपकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी कर चुकी हैं। स्वर्गीय संजय गांधी कर चुके हैं। यदि आप में हिम्मत है, पुरुषार्थी हैं तो कोई इस प्रकार का कार्य करके बतावें। समाज में आकर खड़े हों। क्यों आर.एस.एस. चिल्ला रहे हो। आपके अन्दर कोई कमी है, खामी है इसलिए आर.एस.एस. नाम का कीड़ा आपके दिमाग में घुस गया है। इसको निकालने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ऐसे माननीय सदस्यों को सलाह देता हूं कि वे डाक्टर के पास जाकर अपने दिमाग के कीड़े को निकलवायें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामनारायण, समय का ध्यान रखें।

**श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने भी शिक्षा, कला और संस्कृति की जो मांगें हैं उस पर अपने कट मोशन दिए हैं। देश आजाद हुआ उसके पश्चात हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातांत्रिक तरीके से देश को चलाने का काम कांग्रेस पार्टी के हाथ में आया। हमारा विचार था कि देश के अन्दर माकूल शिक्षा नीति लागू की जाए मगर जो पुराना पेटर्न था, जो अंग्रेजों से हमको विरासत में मिला था उसी परम्परागत आधार पर हम चलते रहे। आज तक 1952 से लगाकर 80 तक जितने भी माननीय सदस्य यहां पर आये उन्होंने हमेशा इस बात की आवश्यकता महसूस की कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। उन सुझावों पर अमल किया गया या नहीं यह तो शिक्षा मंत्रीजी बताएंगे परन्तु हमें इस बात का दुःख है, दर्द है कि आज शिक्षा के अन्दर गांव और शहर में अन्तर किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र एक तरह से पवित्र मन्दिर है। समानता के आधार पर सब को शिक्षा मिलनी चाहिए। गांव का जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है उसको नीचे बैठने के लिए, बिछाने के लिए टाट पट्टी नहीं मिलती है। पढ़ने के लिए स्कूल में कमरे नहीं है। किसी प्रकार का साधन नहीं है। तो यह समानता कैसे आएगी यह सोचने का विषय है। हमको मजबूर होना पड़ेगा यदि समय रहते आप लोगों ने इस ओर ध्यान न दिया, यदि समान शिक्षा नीति लागू नहीं की गई तो मजबूरन गांव के अन्दर असन्तोष पैदा होगा। जिस प्रकार यूनिवर्सिटीज के अंदर असन्तोष का वातावरण बनता जा रहा है, जो झगड़े हैं, लड़ाई है उनका एक मूल कारण है कि हमारा एक वर्ग तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ा है और दूसरा वर्ग इस प्रकार के कुंठित वातावरण में पढ़ा है, उसको यदि हमने दूर नहीं किया तो यह वक्त बहुत ही जल्दी आने वाला है कि जो वक्त खतरनाक वक्त होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है उसको दूर करने के लिये राष्ट्रीयकरण करना होगा शिक्षा का। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा मंत्री महोदय जितने भी यहां पर सुझाव दिये गये हैं गांवों से लेकर शहर वालों तक ने उन पर अमल किया जावे। उन सारी बातों को हमें देखना होगा और किस आधार पर हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन करने होंगे।

शिक्षा मंत्री महोदय, आज आवश्यकता इस बात कि है कि यदि हमें शिक्षा नीति को मजबूत करना है तो हमें चाहिये कि

(श्री रामनारायण चूंडी)

प्राइमरी एजूकेशन को ठीक करें। जिसमें अभी केवल मैट्रिक पढ़े लिखे लोग ही हैं, अध्यापक हैं जो अध्यापक 10 वीं तक पढ़ा लिखा है जो व्याकरण शुद्ध नहीं लिख सकता है, ऐसा मुझे मालूम है, वह हमारे बच्चों को क्या पढ़ायेगा क्या व्याकरण पढ़ायेगा, क्या हिन्दी पढ़ायेगा और क्या और पढ़ायेगा? इसलिये जितनी भी लोअर एजूकेशन देने वाली इन्स्टीट्यूशन हैं उनके हाईएस्ट एजूकेशन के व्यक्ति भेजे जाय, शिक्षक भेजे जायें। ताकि उनकी नींव शुरू से ही मजबूत बन सके।

श्री अध्यक्ष : गांव के आदमी को शहर में भेज दिया जाय।

श्री रामनारायण चूंडी : हमारे यहां जो वातावरण बना हुआ है, जो गरीब लोग हैं, इस देश के अधिकतर गांवों में ज्यादातर लोग गरीब हैं। वहां आई.ए.एस. के बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहां पर केवल 2 पर्सेन्ट ही ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर अच्छी जगह पर पढ़ने के लिये भेज सकते हैं, शहरों में भेज सकते हैं। आज इस प्रकार के लोगों की बात उठ रही है। 30 साल के बाद हमारी यही आवाज उठ रही है। हम यह कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो हम किस क्षेत्र में आकांक्षा कर सकते हैं?

मैं निवेदन करना चाहूंगा दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राइवेट संस्थायें जो चल रही हैं उनमें वेतन ठीक नहीं है, शिक्षा की संस्था का धन्धा कुछ इस प्रकार का है कि उसमें मैं यह कहूंगा कि शिक्षक का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको और तरीके से धन नहीं कमाना पड़े। उनको ट्यूशन आदि करने की जरूरत नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षकों के जो वेतनमान हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिये। खेलकूद की तरफ भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी कैम्प लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं खेलकूद में उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनको सहूलियत देनी चाहिए, उनको कुछ इस प्रकार के वजीफे वगैरह देने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा शिक्षा में सुधार के लिए कम से कम हमारे इस क्षेत्र में तो सुधार करें ताकि उनका विकास हो सके।

प्रौढ़ शिक्षा है उसको तो अविलम्ब खत्म कर देना चाहिए। कन्या पाठशालाओं का बजट में प्रावधान नहीं है इसलिए जो प्रौढ़ शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बन्द करके उस पैसे से कन्या पाठशालायें और नई पाठशालायें खोली जानी चाहिये।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र के लिये निवेदन करूंगा, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोले जाने चाहिए। इसके साथ साथ मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र दिलावा में कॉलेज खोला जाना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां कालेज का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि आने वाले वक्त में इसको भी ध्यान में रखा जाय।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो माहौल बना हुआ है,

(श्री रामनारायण हूंडी)

अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में क्या हालत थी और है। पहले जो व्यक्ति वाइस चांसलर थे उनको राजनीतिक आधार पर वहां से हटा दिया गया। उसको हटाने के बाद जिस व्यक्ति को वहां लाये उसको भी वहां नहीं रहने दिया। फिर बाद में कानसिंह जी को लाये, उनको भी विशुद्ध राजनीतिक रूप से लाये। विश्वविद्यालय की इस स्थिति के कारण वहां के अधिकारियों के अन्दर रोष उत्पन्न हो और फिर नये आयें। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। श्रीमान् जोधपुर के अनेक विद्यार्थी जयपुर आये हुए हैं वे चाहते हैं कि वाइस चांसलर चेन्ज किया जाये। मगर मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री महोदय से कि वे निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करें और इस पर विचार करें। आखिर में जो माहौल है वह वाईस चांसलर को हटाने से या किसी अधिकारी को वहां से हटाने से ठीक नहीं हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग, शिक्षामंत्री महोदय, इसमें हस्तक्षेप करें और जो प्राब्लम है उसको सुनें उसका समाधान करने की कृपा करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : अभी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उससे मैं कहूं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा, इसके द्वारा ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसके कारण यह जो शिक्षा है वह इस देश को खत्म किये जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा के बारे में बहुत ही पहले से यह सवाल उठाए गए हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है। इसको परिवर्तित किया जाय। इसमें, माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत ही बड़े साहस की जरूरत है। आज कई राज्यों में 10 + 2 प्रणाली है। करीब 6 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़ कर बाकी ने अपना ली है और हमने भी सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इसमें मेरा यह निवेदन है कि जब हमने इसको सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तो इसको अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए। ग्रामों में शिक्षा का विस्तार तो हुआ है परन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार की बहुत जरूरत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा का विस्तार करें और इसका भी ध्यान रखें कि जो विकास हो वह सुव्यवस्थित हो। उनकी व्यवस्था चल रही है या नहीं इस और भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आज हालत यह है कि हमारे यहां दहेज की प्रथा बहुत से गांवों के अन्दर अपना स्थान, महत्व बनाती जा रही है। गांवों के अन्दर आज सामन्ती प्रथा के कारण ग्रामीण इलाकों में दहेज की समस्या बढ़ती जा रही है। या तो बहुत बड़ा दहेज दो या फिर लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कन्या पाठशाला खोलना बहुत जरूरी हो गया है। कन्या पाठशालाओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों के लोगों के सामने दहेज की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी। इसको कुछ हद तक कन्या पाठशालाओं की संख्या बढ़ाकर कम किया जा सकता है। वर्तमान

196



(श्री रामकिशोर मीणा)

में जो कन्या पाठशालायें हैं, मेरे क्षेत्र में 4 मिडिल स्कूल हैं लेकिन वहां पर 22 अध्यापिकायें महिला हैं। यह बहुत पुरानी समस्या है कई बार इसका जिक्र भी हो चुका है कि ये महिला अध्यापिका हमारे यहां के नाम से लगाई हुई हैं लेकिन वह कार्य करती हैं जिला शिक्षा अधिकारी के यहां और वेतन उठाती हैं हमारे यहां के नाम से। इसके अन्दर ध्यान दिया जाये। मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाये। जो प्रशिक्षण के केन्द्र आई. टी आई. की तरह से हैं, उनका विस्तार किया जाय। यदि शिक्षकों को वहां लगाया जाता है तो उनको रोजगार मिलेगा दूसरी ओर नैतिकता की भावना भी जाग्रत होगी। वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से बदल सकेंगे। इसी तरह से शिक्षकों की अलग से व्यवस्था हो तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय घण्टी नहीं बजायें उससे पहले ही समाप्त करता हूं। इसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री धाराराम।

**श्री धाराराम फुलवारिया** (सिवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बड़ा महत्व होता है भारत गांवों का देश है। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। गांवों का विकास ही भारत का विकास है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि गांवों के विकास के लिए जरूरी है कि वहां प्राथमिक विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खोले जायें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाये ताकि गांवों का विकास हो सके।

अध्यक्ष महोदय, स्कूलों की वैसे अपने अपने क्षेत्रों के लिए सभी मांग करते हैं तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा शिक्षा की दृष्टि से वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। प्राथमिक विद्यालयों व अध्यापकों की कमी है। हमारा क्षेत्र गांवों का क्षेत्र है इसलिए सही रूप में विकास चाहते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व कमजोर तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोलें समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बार छात्रावास तो वहां खोलना अत्यावश्यक है। इसलिए सही रूप से शिक्षा का विकास चाहते हैं, गांवों का विकास चाहते हैं तो स्कूल अवश्य खोलें जायें, छात्रावास खोले जायें ताकि उनको सुविधा मिले, वह शिक्षा हासिल कर सकें और वह अपना जीवन ठीक बना सकें।

दूसरा, मेरा सुझाव इस सम्बन्ध यह भी है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा चल रही है उसको बन्द कर प्राथमिक विद्यालयों पर उसका बजट खर्च किया जाये ताकि उस बजट का सही उपयोग किया जा सके।

एक दूसरा महत्वपूर्ण निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कोई भी कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो या कोई भी मास्टर हो उसका स्थानान्तरण दो दो साल में कर दिया जाये क्योंकि एक साल तो वह सेवा ठीक तरह से करते हैं दूसरी साल लगते ही वह गांव का वीक पाइन्ट या कमजोरी

(श्री धाराराम फुलवारिया)

महसूस करती है कई बार राजनैतिक अड्डे जमा लेते हैं इसलिए उनका स्थानान्तरण दो साल में कर दिया जाना चाहिए तो स्थिति सुधारने में यह लाभदायक सिद्ध हो सके। इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री महाराम।

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्रीजी आज ही यह घोषणा कर दें कि ये पब्लिक स्कूल बन्द हो जाने चाहिए। गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल के ग्रामीण लड़कों के लिए छात्रावासों की सुविधा करनी चाहिए। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम गांवों में चल रहा है हमने तो उसका नाम ही नहीं सुना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों से जानकारी की जा सकती है, अगर प्रौढ़ शिक्षा से एक अक्षर भी किसी ने कुछ पढ़ा हो। इसके अतिरिक्त गांवों में जहां 20-25 ढाणियां है 15-20 बच्चे जहां हो जायें, वहां प्राथमिक शाला खोल देनी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों की सीमा तो आपको बांधनी ही नहीं चाहिये। प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल, ग्रामपंचायत क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल की स्थापना करें। शहरों में जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को मकान की सुविधा देते हैं वैसी की वैसी ही सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों को वहां के मास्टरों को भी दें। उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायें।

जिन माननीय सदस्य महानुभावों ने बदले की भावना की बात ट्रान्सफर के बारे में कही है उस बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। यह ट्रान्सफर जनता पार्टी वालों ने जैसे किये वैसे ही कांग्रेस ने किये हैं। अब ट्रान्सफर किये जायें व उन्हीं लोगों के किये जायें जो जनता पार्टी वाले है अन्य लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : अब तो समय बिलकुल कम रह गया है। कितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं?

**एक माननीय सदस्य** : आसन को थोड़ा उदार रहना चाहिए।

**एक माननीय सदस्य** : हमको भी थोड़ा अवसर मिलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, आगे भी विधान सभा होगी?

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ये भगवानदासजी बोलना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इतने माननीय सदस्य बोलेंगे। अगर दो दो मिनट भी बोलें तो भी काफी समय हो जाएगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं वह छोटा सा सुझाव महत्वपूर्ण भी हो सकता है। मैं खास तौर से गांवों से आया हूं गांवों में जो मास्टर जाते हैं वह आमतौर से सुबह जाते हैं, जो क्लास का टाइम होता है उससे आधा घंटा देर से आते हैं और आधा घंटा पहले ही अपने गांव चले जाते हैं।

198



(श्री भैरूंलाल मीणा)

उनकी एक समस्या है जो हमने देखी वहां पर उनको रहने के लिए कोई मकान नहीं मिलता है। गांवों में रहते हैं झोंपड़ा होता है, वृक्षों के नीचे बैठ कर पढ़ाते हैं। ऐसी हालत है वहां टीचर्स के रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। मेरा एक सुझाव है, जो 58 लाख रुपया प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए रखा गया है उसके बजाय साल साल में अध्यापकों के रहने की व्यवस्था करा दें जिससे कि गांवों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि मास्टर जाता है फिर आने की फिराक में रहता है, कौन सी गाड़ी कब मिले, कौनसी गाड़ी कब मिले उसका पढ़ाने में दिमाग रहता नहीं, इससे गांव के बच्चों को अक्सर नुकसान रहता है मेरा इतना ही कहना है कि आप इसके बजाय आवास की व्यवस्था करें।

**श्री अध्यक्ष** : बहुत उपयोगी सुझाव है। इस प्रकार के सुझाव आने चाहिए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा उद्योग की तरह है जिसमें लगभग लाख व्यक्ति कार्यरत है यह बुद्धिजीवियों का सृजन करने वाली शिक्षा है इसके अन्तर्गत प्राथमिक माध्यमिक, महा-विद्यालय, विश्वविद्यालय सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

मैं सर्वप्रथम शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर अनेक बुद्धिजीवी और विद्वान आज तक करते आये हैं लेकिन वह शिक्षा नीति में कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका क्या प्रारूप होगा इसके बारे में वे सब मौन हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति जॉब ओरियेन्टेड होनी चाहिये और उसमें दसवीं कक्षा से, बल्कि 9वीं कक्षा से ही वेल्डिंग, मैकेनिकल काम इलेक्ट्रोनिक वर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन से सम्बन्धित कुछ ऐसे जॉब होने चाहिये ताकि शिक्षा प्राप्ति के बाद अगर सरकार कोई धन्धा उनको उपलब्ध नहीं करवा सकें तो वह स्वयं उसको ढूंढ सकें।

वर्तमान में टेन प्लस टू की स्कीम के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और एक्सपेरीमेन्ट के रूप में कुछ स्थानों पर इस योजना को चालू भी कर रखा है लेकिन यह अधरझूल में लटक रही है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से अपने वक्तव्य में इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि क्या वे टेन प्लस टू की स्कीम लागू करना चाहते हैं या वर्तमान पद्धति पर ही राजस्थान में शिक्षा का विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से उत्तर जानना चाहूंगा।

वर्तमान में देश और प्रदेश के अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत आप जो भी शिक्षा नीति रखना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट घोषणा करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के अभाव के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 88 पर्सेन्ट मार्क्स वालों को भी एडमिशन नहीं मिलता है तो युवकों में तनाव के अलावा कोई भी बात नहीं रहती है इस बारे में मेरा निवेदन है कि डिस्टिन्क्शन मार्क्स पाने वाले व्यक्तियों को कम से कम एडमिशन मिल जाना चाहिये। इसके लिये इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना राजस्थान में आने वाले समय में अवश्य होनी चाहिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को वेतन दिया जाता है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं प्राइवेट स्कूलों में एक शिक्षक को एक महीने में 100 रुपये दिये जाते हैं जब कि एक मजदूर को 10 रु. प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, लगभग 300 रु० एक महीने में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक सुबह सात बजे जाते हैं और 5 बजे वापस लौटते हैं. उनको बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता है, उनको पूरी तनख्वाह और मेडिकल फेसिलिटीज मिलनी चाहिए। सरकारी अध्यापकों के समान उनको सुविधाएं मिलनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें मान-नीय, सदस्य।

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: मेरे सात कटौती प्रस्ताव हैं, मुझे सात मिनट का समय तो दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज, दो मिनट से ज्यादा हो गये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया समाप्त करें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: एक कटौती प्रस्ताव पर एक एक मिनट का समय तो दिया जावे कम से कम।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: यह विषय इतना गंभीर है, शिक्षा, अकादमी इन सभी के बारे में आधा-आधा एक मिनट तो मैं कहूंगा। मैं अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: दो मिनट हो चुके हैं, माननीय सदस्य। मैंने बहुत रिलेक्सेशन दे दिया है, कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: मैं बहुत शीघ्र समाप्त कर रहा हूं। या तो कटौती प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। अगर होती है तो एक-एक मिनट....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने तो रिलेक्स करते हुए....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: दो मिनट और दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: इसके अति-रिक्त शिक्षण समितियों की मनमानियां प्राइवेट कालेजेज में होती हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि संशोधित रूप में एजूकेशन बिल को रखा जाना चाहिये। इसके अन्तर्गत खासतौर से पब्लिक स्कूल से कानवेन्ट स्कूल को 80 प्रतिशत सरकारी मदद देती है उनमें बच्चों से ज्यादा फीस ली जाती है, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में सरकार के समकक्ष शुल्क लिया जाना चाहिए और उनमें व्याप्त असुविधाओं को दूर किया जाना चाहिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भ्रष्टा– है उसको दूर किया जाना चाहिये। चेयरमैन ने तो इस्तीफा दे दिया है। इसके सुपरसेशन की बात अभी तक नहीं हुई है, पिछले तीन वर्षों से पर्चे आउट हो रहे हैं, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको भी दूर किया जाना चाहिये।

तीनों विश्वविद्यालयों में लगभग पांच करोड़ रुपया खर्च होता है। राजस्थान का उत्तर-पश्चिमी इलाका हमेशा शिक्षा के अभाव में रहता है। राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत एक बहुत बड़े भू-भाग में कृषि कार्य होते जा रहे हैं, उनसे सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य जब तक नहीं होंगे तब तक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का विकास नहीं होगा। लगभग 400 किलो मीटर की परिधि में कोई विश्वविद्यालय नहीं है·······

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इसलिए मेरा सुझाव है कि बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त बीकानेर में जूनागढ़ का जो किला है वह पुरातत्व·······

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर! केवल दो मिनट माननीय सदस्य।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना करने के बजाय कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : यह बहुत उपयोगी होगा।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर**: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, हमारा झालावाड़ जिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। झालावाड़ जिले में केवल मात्र झालावाड़ जिले में एक कालेज है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवानी मण्डी कस्बे में एक प्राइवेट कालेज चलता है और वह प्राइवेट व्यक्तियों के पैसों से ही चलता है। मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि वह कॉलेज सरकार अपने अन्तर्गत ले ले तो वह सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बिड़ला के नाम से वह कॉलेज चल रहा है। अगर सरकार उसको ले लेगी तो आस-पास के विद्यार्थी, अल्पसंख्यकों और हरिजन तथा शिड्यूल्ड कास्ट अथवा अन्य लोग जो वहां रहते हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते है, ऊंची फीस के कारण उनको सुविधा हो जायगी। इसलिए यदि राज्य सरकार उसको अपने अन्तर्गत ले लेगी तो विद्यार्थियों को इससे सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

इसी प्रकार सुनेल और डग कस्बों में सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चहता हूं कि आपके राज में इन सैकण्डरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाये तो कृपा होगी।

इसी प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने यह ध्यान दिलाया कि गांवों में जो अध्यापक जाते हैं, वे स्कूल सेन्टर पर

(२०१)



(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

नहीं ठहरते हैं, गांवों में रहना पसन्द नहीं करते हैं। कई अध्यापक स्कूल टाइम में भी शहरों में घूमते फिरते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको स्कूल सेन्टर पर ही ठहरने के लिये बाध्य किया जावे। अगर वे लड़कों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते हैं तो उनको व्यर्थ ही तनख्वाह दी जाती है, इसलिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में और स्कूलों में चुनाव के पहले और बाद में कई प्रकार के मनमुटाव हो जाते हैं, इसको खत्म किया जाना चाहिए, कई प्रकार के झगड़े भी इसीलिये चुनाव को लेकर होते रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसी कारण से आज कल शिक्षा में अराजकता पैदा हो रही है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : उदाहरण तो अब जाने दीजिये, कृपया समाप्त कीजिये।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : झालावाड़ जिले में एक हैडमास्टर है। अध्यापक जो होता है वह गुरू नाम से जाना जाता है, वह हैडमास्टर सटोरिया और जुएबाज है, जब गुरू ही इस प्रकार का काम करेंगे तो वे शिक्षा क्या दे पायेंगे ? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अध्यापकों को सजा दी जाये जिससे वे दुबारा इस प्रकार का काम नहीं करें।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज.

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के 3 आयाम होते हैं। प्राइमरी एजूकेशन, स्कूल एजूकेशन और कालेज एजूकेशन। प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों के हाथ में है। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जैसा उसे बनाना चाहिए था, वह आप अब बनाये। अगर वह स्कूल ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उसको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

दूसरा सैकण्डरी स्कूल के बारे में मेरा निवेदन है। उसमें एन. सी. सी. की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन आये...

**श्री अध्यक्ष** : जल्दी समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : कालेज शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि सन् 62 में चाइनीज अग्रेसन के टाइम में एन.सी.सी. शिक्षा की नीति प्रतिपादित हुई थी वह बन्द हो गयी। उसको दोबारा चालू किया जाये ताकि आये दिन जो झगड़े होते रहते हैं, वह खत्म हो और छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा हो।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जॉब ओरियेन्टड होनी चाहिए, ताकि 10 वीं कक्षा के बाद में सैट हो सके, लोग बाग अपने कामों में लग सकें।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

एक शिक्षा के बारे में यह निवेदन है कि कहीं 10 प्लस 2 चलती है और कहीं पर दूसरी चलती है। यह जो दोहरी नीति है वह अच्छी नहीं है। इससे लोगों में भेद-भाव पैदा होता है। यह ठीक नहीं है। सबसे महत्व का जो सवाल मेरा है उसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से, जिस जिले से मैं आया हूं उस जिले की अधिकांश जनता सैनिक परिवारों की है। हम लोगों का निवेदन है, हमारे क्षेत्र में 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सैनिक है फिर भी उनके बच्चों के लिए जो एजूकेशन होनी चाहिए, वह नहीं है। अगर हम भी यह चाहे कि वह बच्चे भी आगे चलकर के सेना में अच्छे अफसर बने तो उसके लिए हमारे झुंझुनू जिले में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। यह मांग हमारे यहां के आये हुए कई एम. एल. एज. ने उठाई है परन्तु आज तक इस पर विचार नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे क्षेत्र की यह ज्वलन्त समस्या है। इसको आप उठाइये और आपका जो प्रभाव और सम्पर्क केन्द्रीय सरकार से है, उससे वहां पर सैनिक स्कूल अवश्य खुलवाइये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी अभी घोषणा करें तो हमारे जिले में लोगबाग बड़े खुश होंगे और महसूस करेंगे कि सरकार से जो हमारी आशायें हैं वह पूरी होंगी।

मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत पिछड़ा हुआ है। कई सालों से हम लोगों की मांग है कि वहां कालेज खुलना चाहिए परन्तु अभी तक नहीं खुला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कालेज होना चाहिए।

एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की शिक्षा देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। मेरे क्षेत्र में बारकिया और धमेरा दोनों ऐसे स्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। वहां सैकण्डरी स्कूल हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कृषि विषय खोला जाय जिससे हमारे क्षेत्र के जो लोग बाग कृषि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके लड़के कृषि विषय पढ़कर....

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और कृषक बन सकें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवदान सिंह।

**श्री शिवदान सिंह (पिड़ावा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यह तो मालूम है कि विरोधी दल के नेता××× हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य बैठे हैं, वह××× हैं। खम्भाधणी की सरकार के शिक्षा मन्त्री जी बिराजे हुए हैं और उनकी पार्टी के

---

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदानसिंह)

के जो सदस्य बैठे हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। उन्होंने ऐसे अध्यापकों की भर्ती की जो बीमार थे। डाक्टरों ने उनके लिये लिखकर दिया था कि इनका इलाज चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब तो कोई गलती नहीं हो रहा है।

श्री शिवदान सिंह : इन अध्यापकों की भर्ती इन्होंने की। एक-एक महीने में एक-एक अध्यापक की 4–4 दफे बदली की। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये ट्रांसफर की बात करते हैं जबकि उन्होंने 70-70 हजार ट्रांसफर किये। बड़े शर्म की बात है। इन्होंने पाली जिले से झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। मैं शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो बेचारे इस प्रकार परेशान हुए, उन्हें आप वापस लगा रहे हैं और उन्हें राहत दे रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो अध्यापक जनता पार्टी के समय में परेशान हुए उन्हें वापस लें और उन्हें न्याय दिलायें। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा में जो पैसा फिजूल खर्च कर दिया है उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनसे वह पैसा वसूल किया जाये।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहने जा रहा हूं। एक ऐसा बुजुर्ग मास्टर है, उसका तबादला जनता पार्टी के लोगों ने किया था। मैं उसको सदन में लाकर खड़ा कर सकता हूं....

( व्यवधान )

यह जनता पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में जहां से मैं चुनकर आया हूं, हमारे विरोधी दल के नेता का एक XXX है....

( व्यवधान )

रामकिशन उसका नाम है। मेरे क्षेत्र में कम से कम उसकी पार्टीबाजी से 500 मास्टरों के तबादले हो गये....

( व्यवधान )

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहे जा रहा हूं....

( व्यवधान )

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप शब्दों को देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं शब्दों को देख लूंगा।

एक माननीय सदस्य : एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री चतुर्भुज।

( व्यवधान )

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। श्री चतुर्भुज।

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार हमारी मान्यता है कि शिक्षा का विकास होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के विकास पर इस राज्य सरकार को विचार करना चाहिये । हमारे क्षेत्र देवली में जो कालेज है उसमें कृषि का विषय है और टोडारायसिंह में भी कृषि सब्जेक्ट देना जरूरी है। एक हमारा क्षेत्र घतोब है वहां कृषि का सब्जेक्ट देना अति आवश्यक है ।

प्रौढ़ शिक्षा का जो बजट रखा है वह कन्या शिक्षा में परिवर्तित कर दिया जाय ताकि उसका विकास हो, उपयोग हो । नहीं तो प्रौढ़ शिक्षा का काम नहीं होने के कारण उसे काम में नहीं लिया जा रहा है । इस बजट को कन्या शिक्षा में परिवर्तित करने से विकास होगा ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं अब इजाजत नहीं दूंगा, 10 बजे है । आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

क्या फर्मा रहे हैं मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं एक माननीय सदस्य कहना चाहें तो कहें ।

(व्यवधान)

**श्री हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हमें यदि मौका नहीं देंगे··

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । जितना अवसर आज दिया गया है, इतना पहले नहीं दिया गया, इतने माननीय सदस्यों ने कभी चर्चा नहीं की । इतने माननीय सदस्य को अवसर दिया गया इसलिए कि बहुत से माननीय सदस्य एजूकेशन की जो बड़ी डिमांड है उस पर अपने सुझाव दे सकें । सभी पक्षों को बराबर अवसर दिया गया, आखिर यह फाईनेन्शियल मैटर है । इसमें समयावधि में कार्य सम्पादन होता है ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : भंवरलाल जी पहली बार बोल रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : वह मन्त्री रहते हुए बहुत बार बोल चुके हैं ।

(व्यवधान)

मैं क्षमा चाहता हूं, आर्डर प्लीज । अब मैं इजाजत नहीं दे सकता । स्थान ग्रहण करें समय का तो खयाल रखें, 10 बजे हैं, आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : एक बार सदन रात को डेढ़ बजे तक चला था

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही 2 बजे तक चले ।

**श्री अध्यक्ष** : 11 बजे तक चली होगी लेकिन इतनी लम्बी चर्चा नहीं हुई होगी, अन्य बातों में समय गया होगा ···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । जितने माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स दिए हैं, आर्डर प्लीज, यह कतई अनिवार्य नहीं है कि जितने कट मोशन्स आये सभी....

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाए। इसलिए तो यह व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ में सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया सदन में जो माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे ऐसे माननीय सदस्यों को लिखित में सूचना दे दी जायगी। अधिक से अधिक सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को मैंने अवसर दे दिया। अब चर्चा समाप्त की जाती है, मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मैं संस्कृत भाषा में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने सवा आठ बजे ही सूचित कर दिया था कि 9 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** यह सूचना नहीं दी गई थी।

**श्री अध्यक्ष :** क्या बात कर रहे हैं, प्रोसिडिंग्स देख लीजिए। यदि प्रोसिडिंग्स में हो तो ?

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष की बात को भी आप ठुकरा रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आज जितने माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया पूर्व में कभी नहीं लिया।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** हमारे दल के केवल दो सदस्यों को···

**श्री अध्यक्ष :** आसन ने समय सीमा बांधने की कोशिश की, 10-10 मिनट फिर 5-5 मिनट, फिर 2-2 मिनट, अब उसका पालन नहीं हो तो क्या किया जाए? नेतागण ही लंबा भाषण दें तो मैं क्या करूं ? अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

आप में से एक बोले।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** हर सदस्य को 5-5 मिनट बोलने का समय दिया गया था ?

**श्री अध्यक्ष :** 15 मिनट के बाद···

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मैं सदन में संस्कृत में बोलना चाहता हूं, मैं संस्कृत भाषा में बोलने की पूरी तैयारी करके आया हूं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर आर्डर। सरकार की ओर से उत्तर। आप चाहते हैं क्या कि एक माननीय सदस्य बोले ? आप में से एक माननीय सदस्य बोलें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आपने यह व्यवस्था दी थी, जब समय बढ़ाया था तो कहा था कि जब तक आज की चर्चा समाप्त न हो जाए, तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

**श्री अध्यक्ष :** चर्चा कहीं न कहीं समाप्त होगी, यह हमारा अधिकार है···

200



**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपके अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता। आपका अधिकार है चर्चा बंद कर दें। आपने कहा था कि जब तक आज की चर्चा समाप्त न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है। आप विराजमान थे ....

(व्यवधान)

**श्री बनवारी लाल** : 9 बजे के लिए कहा था।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपने कहा था कि 9 बजे सरकारी उत्तर आयेगा हमने रिक्वेस्ट की थी कि समय कम है, यदि 9 बजे उत्तर आयेगा तो सदस्य बोल नहीं पायेंगे' तो आपने कहा था 5-5 मिनट का समय दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: तो 5--5 मिनट का पालन नहीं हुआ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : फिर आपने कहा 2--2 मिनट दूंगा

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** :दो दो मिनट का भी पालन नहीं हुआ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अब हमारा निवेदन यह है कि आप 2 2 मिनट तो दें....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। सुनने तो दीजिए।

**श्री बिहारी लाल** : आपने 3 4 बार कहा था....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय एक एक सदस्य को दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलने का समय नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ न्याय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, थोड़े सदस्य ही बाकी हैं। सिर्फ 12 सदस्य बोलना चाहते हैं। आप दो मिनट का समय हर सदस्य को दे दें।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : न्याय होना चाहिये। हमारे दल के सिर्फ दो सदस्य ही बोले हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में सदस्य बाकी नहीं हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की बात कहनी है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : हमारे भी काफी सदस्य बोलने को रह गये हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा सदन में हो चुकी है। अब रात के दस बजने का समय है। जब तक मन्त्री महोदय का जवाब आयेगा तब तक 11 बजे जायेंगे। इसके बाद में सचिवालय वाले कल का काम क्या होगा उसके लिये भी कार्यवाही करेंगे। आखिर आप माननीय सदस्य दो दो मिनट कह रहे हैं आप बोलेंगे तो फिर कांग्रेस वाले भी बोलेंगे। इस तरह काफी समय हो जायेगा। फिर

(श्री अध्यक्ष)

दो दो मिनट में माननीय सदस्यों को आनन्द भी नहीं आयेगा। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि काफी सदस्य बोल चुके हैं। मेरे खयाल से अब मन्त्री महोदय का जवाब आ जाये तो ठीक रहे। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आप जरा आसन से सहयोग करें।

(व्यवधान,)

आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितना मैं आप लोगों को एकोमोडेट करता हूं उतना ही आप लोग कठिनाई पैदा कर रहे हैं। यह फाइनेंशियल मैटर है इसमें समय सीमित होता है। एक ही दिन में मांगें पास करनी पड़ती हैं अगर आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने सभी को मौका दिया है फिर भी आप लोग कठिनाई पैदा कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आइन्दा पांच बजे बाद मुख बन्द हो जाये और फिर मांगें पारित कर दी जायें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यों तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं आसन को पावर्स बहुत हैं आप उसके बाद भी मांगें पारित करवा सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : फिर तो इतनी दिक्कत ही नहीं जो भी माननीय सदस्य पांच बजे तक बोल सकें बोल लिये उसके बाद में पांच बजे बाद मांगें पारित करवा कर छुट्टी कर लें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप 13-14 सदस्य हैं दो मिनट का समय लेकर आप लम्बा लम्बा भाषण करने लग जायेंगे। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय शिक्षा मन्त्री जी।

(व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें। मुझे बात सुनने दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 15 मिनट का समय दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: नो, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

**श्री शिवराम शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, अगर यह 15 मिनट का समय लेंगे तो हम भी 15 मिनट का समय लेंगे। कांग्रेस वाले भी बोलेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ज्यादा मुझ पर जोर नहीं डाले मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार की तरफ से उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

208



**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के 40 सदस्य थे उनमें से अधिक लोग नहीं बोल पाये हैं। हमने देखा आप सभी को पांच पांच मिनट का समय देंगे। जैसा कि आसन द्वारा कहा गया था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ठीक है। मैं 15 मिनट का समय देता हूं। साढ़े सात मिनट आपको और साढ़े सात मिनट कांग्रेस वालों को। क्योंकि इधर के माननीय सदस्य बोलेंगे तो उधर के भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसा उस पर आप हमें बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री शिवराम शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह वाक आउट करना चाहते हैं इसलिये व्यवधान डाल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

**श्री बाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना भाषण संस्कृत में तैयार किया है मैं संस्कृत में बोलना चाहता हूं। संस्कृत देश की दूसरी भाषा है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री बाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, रात को सदन यहां पर डेढ़ बजे तक चला है। आप मुझे 15 मिनट का समय दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं मजबूर हूं। सदन के माननीय सदस्यों की बैठने की इच्छा नहीं है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। राज्य सरकार की तरफ से उत्तर।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

**श्री शिव राम शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी वाले जानते हैं कि अब हमारी पोल खुलने वाली है इसलिये व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर आर्डर। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप शान्त रहें। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सदन में इतनी देर पहले बहुत अच्छी तरह से चर्चा चल रही थी। सभी सदस्यों ने लगभग वाद-विवाद में भाग लिया। अन्त में इस मामले में इस प्रकार का व्यवधान आप लोग डाल रहे हैं। मैंने बहुत ही एकोमोडेट किया है पर उतना ही माननीय सदस्य मुझे कठिनाई में डाल रहे हैं। मुझे निराशा इस बात की है कि 11 बजने को जा रहे हैं आप इस प्रश्न के लिये 15 मिनट का समय मांग रहे हैं। आप काफी समय बोल चुके हैं और 15 मिनट में क्या कह सकेंगे.

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा में आज तक कोई सदस्य इस सदन में नहीं बोला है मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा संस्कृत भाषा में।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर आर्डर। कृपया माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

फिर मैं मांग को वोट पर पुट कर देता हूं।

**श्री विष्णुप्रकाश बजारी :** भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, घबराते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य :** बैठ जाओ, बैठ जाओ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** यदि आप मंत्री जी का उत्तर सुनना चाहते हैं तो मैं उनको उत्तर देने के लिए पुकार सकता हूं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** आप हमको दस मिनट का समय दे दीजिए।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** इसका मतलब यह है कि जो बात आप कहते हैं उससे आप टस से मस नहीं होना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

**कई माननीय सदस्य :** बैठो, बैठो।

**श्री बनवारीलाल :** और तुम नहीं सुनोगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे।

**श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर आज सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखें...

(व्यवधान)

**श्री शिवराम शर्मा :** अरे, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज,.......

(व्यवधान)

मांग पर मतदान। अगर अब भी चाहते हैं तो मैं मंत्री जी का भाषण करवा सकता हूं?

(व्यवधान)

मांग संख्या 24 का पारण

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पारित की जाय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,34,21,11,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी

सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11-25 बजे शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त, 1980 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 386 के आंकड़े)

### सूची

गत 3 वर्षों में जो घाटा हुआ वह निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | घाटा (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| 1977-78 | 187-24 |
| 1978-79 | 146-84 (सबजेक्ट टू आडिट), |
| 1979-80 | 390-00 (लगभग) |

212



## परिशिष्ट 2

### समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

**जयपुर को बस सेवा से सभी विधान सभा क्षेत्रों के मुख्यालयों से जोड़ना**

390. **श्री शिवसिंह** (बाड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार का प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय को राजधानी जयपुर से पथ परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा जोड़ने का विचार है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे निर्णय के संदर्भ में बाडी को सीधी बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। करौली से धौलपुर मार्ग की राष्ट्रीयकरण की योजना निगम के विचाराधीन है जिसके अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर से बाड़ी सीधी बस सेवा चलायेगा।

**पलाना थर्मल पावर स्टेशन**

391. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पलाना में जो थर्मल पावर स्टेशन प्रस्तावित है उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और इस संबंध में योजना और कार्यक्रम क्या है ?

(2) क्या सरकार इस योजना की क्रियान्विति में बीकानेर क्षेत्र के निवासियों को नौकरी देने में प्राथमिकता दिए जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पलाना थर्मल पावर स्टेशन की परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है और योजना आयोग से वित्तीय नियोजन की स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(2) विभिन्न पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं, न कि क्षेत्रीय आधार पर।

**उदयपुर की झीलों के पानी को जलकुम्भी से हो रही क्षति से बचाना**

392. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर की झीलों में जलकुम्भी के फैलाव से उत्पन्न समस्या को दूर करने हेतु विभाग ने पिछले पांच वर्षों में क्या प्रयास किया और उस पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जलकुम्भी के फैलाव से पानी खराब हो रहा है एवं पानी तेजी से सूख रहा है ? यदि हां, तो इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु विभाग ने क्या कोई योजना बनाई है ?

(सिचाई मंत्री)

उत्तर

(1) उदयपुर में पिछोला झील (स्वरूप सागर) पर ही जलकुम्भी फैली हुई है जिसके निकालने के लिये विभागीय स्तर पर मजदूर लगाकर निकालने का कार्य किया जाता है जिसमें निम्न प्रकार व्यय किया गया है वर्ष ।

| | |
|---|---|
| 1975-76 में | 4900/- |
| 1976-77 में | 34000/- |
| 1977-78 में | 25172/- |
| 1978-79 में | 31207-/ |
| 1979-80 में | 14570/- |

(2) जी हां

इस समस्या के स्थाई हल के लिये सरकार विचार कर रही है।

### सीकर नगरवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था

393. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर नगर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु अधिशाषी अभियन्ता सीकर ने कोई योजना सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की है ?

(2) सीकर नगर में पानी के कितने कनेक्शन हैं ?

(3) सीकर की जनसंख्या के लिए कितना पानी चाहिए और कितने भंडारण की इस समय क्षमता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार को कोई योजना प्रेषित नहीं की गई है।

(2) सीकर नगर में लगभग 8,500 जल सम्बन्ध हैं।

(3) वर्तमान में सीकर नगर की जनसंख्या हेतु 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से लगभग 22 लाख गैलन जल की आवश्यकता है। योजना में इस समय उत्पादन क्षमता 18.75 लाख गैलन प्रतिदिन एवं भंडारण क्षमता लगभग 8 लाख गैलन प्रतिदिन है।

### अजमेर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

394. श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अजमेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किन-किन पंचायतों में चल रही है ?

(2) सन् 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत किसानों को बिजली देने के लिए बजट में कितनी राशि किस किस ग्राम की विद्युत योजना के लिए प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में आर.ई.सी. की विद्युत योजनाएं इस समय केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, अराई, श्रीनगर, भिनाय एवं पीसांगन पंचायत समितियों में चल रही है।

(2) वर्ष 1980-81 में योजनावार क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :

| | (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1. केकड़ी (ओ. एस.) | 2.08 |
| 2. मसूदा | 2.40 |
| 3. किशनगढ़ | 3.09 |
| 4. अराई | 2.65 |
| 5. श्रीनगर (लघु कृषि) | 0.77 |
| 6. ओ. एण्ड एम सब-डिवीजन (विजयनगर एस.पी.ए.) पं.स. भिनाय) | 8.03 |

(214)



**सी-स्कीम, जयपुर के नाले को पाटना**

**395. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सी-स्कीम, जयपुर के नाले को पाटने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसे आवृत्त करने में जो खर्चा आयेगा उससे इसके ऊपर की जमीन दुकानों हेतु बेचकर सरकार बगैर कोई खर्च किये इस नाले के पाटने का कार्य पूरा करवा सकती है ?

(3) क्या टौंक फाटक व हसनपुरा के जल विकास हेतु नाले बनाने की भी सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां यह प्रश्न विचाराधीन है।

(2) यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

(3) यह मामला भी विचाराधीन है।

**मिनी बसेज के राष्ट्रीय परमिट की योजना**

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मिनी बसेज के राष्ट्रीय परमिट की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी मिनी बसेज को राष्ट्रीय परमिट दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) राष्ट्रीय परमिट की योजना केन्द्र सरकार द्वारा मोटर-वाहन अधिनियम की धारा 63 (7) के अन्तर्गत प्रसारित की जाती है। वर्तमान में 35 सीट तक की ओमनी बस के 50 टूरिस्ट परमिट राज्य को आवंटित हैं। मिनी बस इसी में सम्मिलित है जो प्राय: 22 बैठक क्षमता की होती है।

(2) 50 के पूर्व में आवंटित कोटे के विरुद्ध इस वर्ष में पूर्व ही अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। अत: कोई स्थान रिक्त नहीं होने से इस वर्ष नये अनुज्ञा पत्र दिये जाने की योजना नहीं है।

**धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम गोनेर में यात्रियों के लिये समुचित सुविधायें**

**397. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या सांगानेर पंचायत समिति का ग्राम गोनेर धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है ? यहां कितने यात्री प्रतिवर्ष आते हैं ? सफाई व यात्रियों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा वहां क्या व्यवस्था की हुई है ?

**उत्तर**

सांगानेर पंचायत समिति में स्थित ग्राम गोनेर में एक प्राचीन मंदिर श्री लक्ष्मी जगदीश जी का है, जिसमें स्थानीय आस पास के ग्रामीणों की श्रद्धा है। वहां वर्ष में दो बार मेला लगता है, जिसमें लगभग 15-20 हजार दर्शनार्थी आते हैं। यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबन्धित राजकीय मंदिर नहीं है। मेले की व्यवस्था ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा की जाती है। सफाई एवं यात्रियों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत एवं मंदिर द्वारा व्यवस्था की जाती है। जल व्यवस्था के लिये मंदिर की ओर से प्याऊ एवं टोंटियां लगी हुई हैं।

**छात्र सहायता कोष में से गबन के प्रकरण की जांच**

398. **श्री त्रिलोक सिंह** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सेठ मोतीलाल कालेज, झुन्झुनू के छात्र सहायता कोष से लगभग 18,000/- रुपये के गबन की जांच करने के लिए जिलाधीश, झुन्झुनू को सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

जी, नहीं।

छात्र संघ झुन्झुनू ने छात्र सहायता कोष में लगभग 18000 रु. गबन के आरोप के सम्बन्ध में एक पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं जिलाधीश, झुन्झुनू को प्रेषित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त पत्र को को-आर्डिनेटर राजस्थान विश्वविद्यालय को जांच हेतु प्रेषित किया तथा को-आर्डिनेटर ने उक्त पत्र को दिनांक 13-6-80 को निदेशक, कालेज शिक्षा को विस्तृत जांच हेतु भेजा तथा निदेशक महोदय ने इसकी जांच दिनांक 17-6-80 को आडिट पार्टी भेजकर कराई। वर्ष 74-75 से 77-78 तक कुल रुपया 8,750 विद्यार्थी सहायता कोष के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से स्वीकृत किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1974-75 | 1750/- |
| 75-76 | 1750/- |
| 76-77 | 1750/- |
| 77-78 | 3500/- |
| योग | 8750/- |

नियमानुसार इतनी ही राशि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी सहायता कोष में छात्रों को पुस्तकें खरीदने हेतु एवं नकद राशि का भुगतान करने हेतु एकत्रित की गयी थी। इस राशि में से रुपया 14,397-49 की 1032 पुस्तकों की खरीद की गयी जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | राशि | पुस्तकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1974-75 | 2632-03/- | 211 |
| 75-76 | 3617-21/- | 284 |
| 76-77 | 2986-93/- | 238 |
| 77-78 | 5161-32/- | 299 |
| | 14397-49/- | 1032 |

रु. 2359/- की धनराशि छात्रों को नकद भुगतान सहायतार्थ दी गयी है तथा शेष 743-51 राशि अन्य कार्यों में उपयोग की गयी। उक्त समस्त पुस्तकें ज्यादातर महाविद्यालय को-आपरेटिव स्टोर से खरीदी गई हैं समस्त किताबों के बिल रजिस्टर (स्टाक-रजिस्टर) में अंकित हैं तथा समस्त पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। पुस्तक विक्रेताओं को भुगतान किया गया है वह रिकार्ड बही में दर्शाया गया है।

**रामगंज मंडी के ग्रामों हेतु सिंचाई सुविधा का विस्तार**

399. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी):

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील की आतुनदी से ग्राम सलावद, बडोदिया, नयागांव, खालसा, कालियां, कुडेउ, पामा खेड़ी आदि अनेक गांव को

216



(श्री हरीश शर्मा)

सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार का रामगंज मंडी तहसील की नदियों व खालों पर एनीकट बनाने का विचार है जिससे सैंकड़ों ग्रामवासियों की भूमि सिंचित हो सके ? यदि हां, तो सरकार द्वारा एनीकट बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इलाका पथरीला है एवं सिंचाई योजना बनाने से पत्थर की खानों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(2) जी हां। लेकिन इसका क्रियान्वयन सिंचाई विभाग के माध्यम से न होकर विकास विभाग के माध्यम से प्रस्तावित है।

**बूंदी के न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर स्थापन**

400. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी के न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने तथा कब से ?

(2) उक्त रिक्त पदों के भरने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस समय अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं० 1, अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं० 2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं० 2, बूंदी क्रमशः 13-2-80, 16-4-80 एवं 6-2-80 से रिक्त है।

(2) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिनका दिनांक 29-7-80 से दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो चुका है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद बूंदी न्याय क्षेत्र में पद राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यथा संभव भरे जावेंगे।

**कन्या स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में वाणिज्य कक्षायें**

401. श्री राधेश्याम (गंगानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कन्याओं के स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में किन किन स्थानों पर कॉमर्स की कक्षायें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर में अन्य महाविद्यालयों की भांति लड़कियों के लिये एम.ए. व कॉमर्स की कक्षायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस सत्र से ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों पर विचार करते समय इस पर भी तुलनात्मक रूप से गुणावगुण के आधार पर विचार कर लिया जावेगा।

(शिक्षा मंत्री)

राज्य में महिला स्नातक एवं स्नातकोत्तर कालेजों की सूची जहां कॉमर्स की कक्षायें हैं:—

1— राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।

2— जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा।

3— महारानी कालेज, जयपुर।

4— सतसाई कालेज, जयपुर (अनुदान प्राप्त)

**चौमूं क्षेत्र में उदयपुरिया नाला से कृषि भूमि को क्षति**

402. **श्री तेजपाल (चौमूं):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुरिया का नाला प्रतिवर्ष बरसात में ग्राम लोहरवाड़ा को क्षतिग्रस्त करता है जिससे हजारों बीघा कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है?

(2) क्या सरकार द्वारा ग्राम लोहरवाड़ा को बचाने के लिये अब तक कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए? नहीं, तो कौन-कौन अधिकारी इसके लिये दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) चालू वर्ष में ग्राम लोहरवाड़ा को वर्षा की क्षति से बचाने के लिए क्या सरकार स्थायी समाधान कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल ज़्यादा बरसात वाले सालों में ही इस नाले का पानी लोहरवाड़ा क्षेत्र में फैल जाता है।

(2) ग्राम लोहरवाड़ा को बचाने के लिए सिंचाई एवं सहायता विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं इस कार्य को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण दल को अक्टूबर, 78 में दिखाया गया जिससे उपरोक्त कार्य की स्वीकृति नहीं दी। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है।

(3) सिंचाई विभाग इस कार्य को बाढ़ नियंत्रण कार्य के रूप में लेने का विचार कर रहा है। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में पैसा मिलने पर कार्य किया जा सकेगा।

**महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में आवश्यकतानुसार आक्सीजन गैस सिलेण्डर्स का प्रदाय**

403. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में प्रतिदिन कितने आक्सीजन गैस सिलेण्डर की आवश्यकता रहती है?

(2) दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 20 जुलाई, 1980 तक कितने गैस सिलेण्डर मंगाये गये?

(3) क्या वांछित गैस सिलेण्डर अस्पताल को नियत समय पर नहीं मिल रहे हैं? सरकार उसकी व्यवस्था के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा हेतु आक्सीजन सिलेण्डर की खपत औसतन 2–3 प्रतिदिन रहती है।

(2) 60 सिलेण्डर मंगाये गये।

(3) जी हाँ। परन्तु जब जब भी बिजली की कटौती से आक्सीजन का उत्पादन कम हो जाता है तब कमी आ जाती है।

218



**पाली जिले की ग्राम सहकारी समितियों में गबन के प्रकरण**

श्री सुखलाल सेणचा ( रायपुर ): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सबलपुरा विराटियाकलां एवं पुरानी बावड़ी में तत्कालीन सहायक निरीक्षक, श्री भंवर सिंह द्वारा लाखों रुपये फर्जी बान्ड भर कर गबन करने व उनकी सांठगांठ से प्रबन्ध समिति ने सदस्यों द्वारा गबन करने की शिकायतें हैं ?

(2) यदि हां, तो कुल कितनी राशि गबन होना पाई गई है ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? नहीं, तो अब क्या विचार है ?

**उत्तर**

(1) सबलपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में श्री भंवरसिंह भू. पू. सहायक निरीक्षक द्वारा एवं विराटियाकलां एवं पुरानी बावड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा गबन व दुरुपयोग के मामले आडिट रिपोर्ट से प्रकाश में आये हैं।

(2) कुल 3,86,247.95 रुपये की राशि का गबन एवं दुरुपयोग वर्ष 76 से 79–80 तक की आडिट रिपोर्ट में पाया गया है। सबलपुरा व पुरानी बावड़ी की आडिट रिपोर्ट 30–7–80 को प्राप्त हुई विराटिया कलां की ऑडिट रिपोर्ट मार्च, 80 में प्राप्त हुई थी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 74 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पूर्व वर्षों की आडिट रिपोर्ट पर देरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सभी मामलों में नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायगी।

**जिला नागौर में काला बाजारी व मिलावट के मामलों में कार्यवाही**

405. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में सन् 1975 से जून, 1980 तक किन-किन के विरुद्ध काला बाजारियों व मिलावट सम्बन्धी मुकदमें दर्ज हुए और उनमें से कितनों पर फैसला हुआ ?

(2) अधिकृत राशन की चीनी का वितरण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कितने मुकदमें दर्ज हुए और कितने फैसले हुए ? कृपया दोनों मांगों से सम्बद्ध नामजद सूची सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) नागौर जिले में सन् 1975 से जून, 1980 तक कुल 38 मुकदमें कालाबाजारियों एवं 187 मुकदमें मिलावट सम्बन्धी दर्ज हुए। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इनमें से 15 कालाबाजारियों के मुकदमों का एवं 143 मिलावट सम्बन्धी मुकदमों का फैसला हुआ।

(2) अधिकृत राशन की चीनी का वितरण करने वाले 542 दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से 57 दुकानदारों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डनायक नागौर के न्यायालय में इस्तगासे पेश किए गए। शेष 485 मामलों में से 320 दुकानदारों

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर प्रतिभूति राशि जब्त की गई तथा 125 के विरुद्ध भविष्य में सही ढंग से कार्य करने की चेतावनी देकर समाप्त किए गए। 40 मामलों में कार्यवाही विचाराधीन है। न्यायालयों में प्रस्तुत मामलों एवं निर्णीत मामलों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई।)

**पुलिस स्टेशन भंवरगढ़ में दर्ज आरोप सं. 22/78**

406. श्री हरसहाय (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस स्टेशन भंवरगढ़, जिला कोटा में दर्ज आरोप संख्या 22/78 जैसे गंभीर अपराध के मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं होने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

(2) उक्त मामला दर्ज करने के लिये पुलिस अधीक्षक, कोटा को एफ. आई. आर. कौनसी तिथि को प्राप्त हुई थी ? मामला कौनसी तिथि को दर्ज हुआ था इतने विलम्ब का क्या कारण था ? इस विलम्ब के लिये कौन विभाग तथा अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या इसकी जांच की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस मुकदमें में अभियुक्तों के हस्तलिखित फर्जी दस्तावेज ग्राम खेरोद, कानपुर, नदबई, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि से संग्रहित किये जा रहे हैं जिनके प्राप्त होने पर विशेषज्ञ की राय प्राप्त होने पर अनुसंधान यथा शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयत्न किये जावेंगे।

(2) प्रथम सूचना दिनांक 12-7-76 को प्राप्त हुई थी मगर उसके साथ आवश्यक संबंधित दस्तावेज एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया जा सका था। दिनांक 15-7-78 को वैद्य श्री श्याम सुन्दर इन्चार्ज आयुर्वेदिक औषधालय बरड़ा के द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित सूचना प्राप्त होने पर अ. सं. 22/78 अन्तर्गत धारा 420, 471, 468 ता. हि. थाना भंवरगढ़ पर पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान में विलम्ब करने पर संबंधित थाना प्रबंधक भंवरगढ़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दंडित किया जा चुका है।

**सवाई माधोपुर नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था**

407. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर नगर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर नगर को 22 लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो कितना पानी दिया जाता है तथा नगर व मेन टाउन को कितना पानी मिल रहा है ? कृपया आबादी के संदर्भ में जानकारी देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर नगर में पेयजल की कमी को देखते हुए योजना के आगमेन्टेशन (क्षमता वृद्धि) के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(220)



(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) वर्तमान में सवाई माधोपुर को 3.75 लाख गैलन व मान टाउन को 2.25 लाख गैलन जल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। वर्तमान आबादी के आंकड़ों के अनुसार सवाई माधोपुर की 26,000 जनसंख्या के लिए 5.20 लाख गैलन व मान टाउन की 34000 जनसंख्या के लिए 6.80 लाख गैलन जल की प्रतिदिन आवश्यकता है।

**पाली व जोधपुर जिले में गत सरकार द्वारा अस्वीकृत नये स्कूल्स पुन: खोला जाना**

**408 श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),**

**श्री माधोसिंह दीवान (सोजत),**

**श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) एवं**

**श्री शिवदानसिंह (जैतारण)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिये नये स्कूल खोलने, नये विषय खोलने व स्कूलों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो पाली व जोधपुर जिले में इस प्रकार के क्रमोन्नत स्कूल्स की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बाद में भूतपूर्व जनता सरकार ने उपरोक्त सूची में अनेक स्वीकृतियां रद्द कर दी थीं ? यदि हां, तो रद्द की गई स्कूलों को कब पुन: खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नये विद्यालय खोलते समय विभिन्न प्रस्तावों पर उनके गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

जिला जोधपुर में वर्ष 1977-78 मे कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गये विद्यालय की सूची:-—

**प्राथमिक विद्यालय**

1 कालीबेरी
2 प्रतापनगर
3 नागौरी गेट
4 अनेली बाड़ी (ग्राम बा तहसील फलौदी)
5 कालूरत रायतं (फलौदी)
6 ग्राम थियारी (शेरगढ़)
7 डाबड़ की ढाणी (शेरगढ़)
8 खिरजामाजा (शेरगढ़)
9 अभयसिंह की ढाणी (शेरगढ़)
10 नया बेरा (शेरगढ़)
11 मले का बेरा (शेरगढ़)
12 खिलों का धारा (शेरगढ़)
13 बेड़ों की ढाणी (भोपालगढ़)
14 पुरोहितों की ढाणी (भोपालगढ़)
15 डेडियों की ढाणी
16 आमटियों की ढाणी
17 बेहुचारण (ओसियां)
18 भाटियाई खुर्द (ओसियां)
19 बासनी (ओसियां)

(शिक्षा मंत्री)

20 भरलाई नाड़ी बन्द (ओसियां)
21 जाटों की ढाणी (नेवरा ओसियां)
22 खांगटा (भोपालगढ़)
23 मागा नाड़ी (शेरगढ़)
24 कुम्हारों का बेरा (शेरगढ़)
25 जाटों का बेरा (शेरगढ़)
26 कनोडिया महासिंह (शेरगढ़)
27 पीरोहितों का बेरा (शेरगढ़)
28 बोलेश्वर दर्गावतां (बालेश्वर)
29 सिलावटों का बास
30 अगबार बेलवा
31 धांधलों की ढाणी
32 केतना पा की ढाणी
33 मोरिया
34 बाबनी बेरा सख मण्डला
35 धायलो की ढाणी
36 उन्देडों की ढाणी
37 उडिया नाड़ा
38 बासनी सक्का
39 बाला कुआ
40 बरेहों का बास
41 सेठ मोतीसिंह की ढाणी
42 बेरीबाला का बास
43 बेरियाबसाबा
44 मटियालाई बारण
45 फाडला की ढाणी रणसीगांव
46 ढाकों की ढाणी कीमरछा
47 बिलाड़ा शहर
48 वार्ड नं. 7 पीपाड़ शहर
49 कुम्हारों की ढाणी (शेरगढ़)
50 मासोर (कन्या)
51 गर्रसिंहपुरा (कन्या)
52 रातकड़िया (कन्या)

उच्च प्राथमिक विद्यालय :—

1 बांनेसर सत्ता (शेरगढ़)
2 जुडिया (शेरगढ़)
3 बिठानियां (शेरगढ़)
4 भगाद बोली की ढाणी (ओसियां)
5 मेसेर बाली (ओसियां)
6 जातक (ओसियां)
7 रेवडी सालवा (बिलाड़ा)
8 जिजगोवलाकर्ता
9 जिलानी
10 नादिया खुर्द
11 निवदा जाटों की ढाणी
12 पांचला खुर्द
13 कुम्हारों का बास
14 नोसर
15 लबरा कलां
16 मानबड़ा
17 गुढिडाला
18 बिरानी
19 रजलानी
20 कुहदा
21 कलाऊ
22 सुराणी
23 भादिया खुर्द
24 भ्रबेरा जांच की ढाणी
25 बिरसालु कलां
26 दयादमी
27 खण्डाला
28 उदयसर
29 बिचेड़ा बास (लूणी)
30 काकुण्डा
31 पीलपाबास
32 कनाडियों पुरोहिताना
33 बुमकला
34 भोलरी
35 हरियाडा

माध्यमिक विद्यालय :—

1 हीरादेसर
2 पंडितजी की ढाणी
3 घनाटीकलां
4 बिलाड़ा (कन्या)
5 तिलवासनी
6 लटियालपुर
7 लोरडिखा
8 बिसलपुर
9 लेटावासकलां
10 जेलवा
11 बनाड़ा
12 रातानाड़ा
13 चामू
14 खिरजावास
15 देवू
16 खाखटा
17 पल्ली
18 पीलबा

(शिक्षा मंत्री)

**जिला पाली में वर्ष 1977-78 में कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गये विद्यालयों की सूची**

| प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | माध्यमिक |
|---|---|---|
| 1 गुडा कल्याणसिंह | 1 हिरों | 1 जैतारण (कन्या) |
| 2 रावलबास | कानेचा | 2 कुशालपुरा |
| 3 प्रतापपुरा (नया गांव) | 3 गरनियां | 3 सुमेरपुर (कन्या) |
| 4 भादड़ी | 4 खेला क्षेत्र | 4 चौभाबाई बालिका विद्यालय |
| 5 नामदा बाचिया | 5 नोयर क्षेत्र | 5 सांडेराव |
| 6 शली | 6 कोलर | 6 बीजापुर |
| 7 फालता स्टेशन (कन्या) | 7 निमली मोही | 7 अटबड़ा |
| 8 भन्दर (कन्या) | 8 सिदरू | 8 बलन्दा जैतारण |
| 9 फोकारिया | 9 बिठुदा | 9 बार्ता |
| 10 करला | 10 बामद | 10 जुजावर |
| 11 आईजीपी की ढाणी | 11 मंडिया | |
| 12 कोरबा | 12 बीमादड़ा | |
| 13 बोकास | 13 रखड़ाबास | |
| 14 बोबाई | 14 नाईदा बेरा | |
| 15 बेगडी अखड़ी | | |
| 16 बाम्बोलाई | | |

**कांग्रेस सरकार द्वारा सत्र 77-78 में खोले गये नये विषयों की सूची जिन्हें जनता सरकार द्वारा रद्द किया गया (जोधपुर व पाली जिला)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तेना (जोधपुर) | वाणिज्य विषय |
| 2 | ,, ,, ,, शेरगढ़ (जोधपुर) | सायन्स, फिजीक्स एवं केमिस्ट्री |
| 3 | ,, ,, ,, डाडलिया ,, | कृषि विषय |
| 4 | ,, ,, ,, नयानियां ,, | वाणिज्य विषय |
| 5 | ,, ,, ,, चाडोल चौतीना (जोधपुर) | ,, ,, |
| 6 | ,, ,, ,, मथानियां (जोधपुर) | ,, ,, |
| 7 | ,, ,, ,, ओसियां ,, | जीव विज्ञान |
| 8 | ,, ,, ,, बिलाड़ा ,, | ,, ,, |
| 9 | ,, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेश्वर (जोधपुर) | ,, ,, |

जिला पाली

| | | |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बेडा (पाली) | विज्ञान विषय |
| 2 | ,, ,, ,, निम्बाड़ा (पाली) | वाणिज्य विषय |

**राजस्थान नहर के बायें किनारों पर पशुपालकों की बस्तियां स्थापित करना**

409. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के बायें किनारों पर पशुपालकों एवं भेड़पालकों की बस्तियां स्थापित करने की मांग लम्बे अर्से से विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि नहर के बायें किनारे के समानान्तर पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि बिजली, नहरी पानी उपलब्ध है जिसका उपयोग करके चरागाह स्थापित करके काफी लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) नहर के बायें किनारे समानान्तर उपलब्ध भूमि के विकास हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

**राजकीय कन्या सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करना**

410. श्री समर्थलाल (रायपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार का राजकीय कन्या सैकण्डरी स्कूल, राजगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

राज्य सरकार द्वारा फिलहाल कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

**गुलवाड़ा से वाया सहेशन—जुरहेरा सड़क का निर्माण**

411. श्री चौंखा (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील कामां में गुलवाड़ा से वाया सहेशन कस्बा जुरहेरा को निकलने वाली सड़क स्वीकृति के बावजूद काफी समय से अपूर्ण पड़ी है ? इसको अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

**उत्तर**

तहसील कामां में गुलपाड़ा से जुरहरा वाया सहेशन सड़क की प्रथम बार 1970 में 2.00 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी। सन् 71–72 में पुनः अमरका से जुरहरा के लिये 3.00 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई लेकिन यह स्वीकृति 1972 में निरस्त कर दी गई। तीसरी स्वीकृति सन् 1972 में 6 हजार रुपयों की फिर दी गई। इसके बाद कुछ अन्य स्वीकृतियां मरम्मत के मद में दी गई, जिनसे निर्माण कार्य कराया गया। शेष कार्य की स्वीकृति आने पर इसे पूरा किया जावेगा इसकी कुल लम्बाई 30 किलोमीटर है तथा अब तक 9 किलोमीटर में निर्माण कार्य हो चुका है।

**मिनी ट्राइबल ब्लाक्स का विकास**

412. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तथा मांगरोल तहसील के मिनी ट्राइबल ब्लाक के विकास हेतु कुछ राशि स्वीकृत हुई थी जिसमें कार्य कराये जाने हेतु पंचायत समितियों से प्रस्ताव भिजवाये गये थे ? सूची कृपया सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव थे तथा इन पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ?

(3) उक्त दोनों मिनी ट्राइबल ब्लाक्स के विकास हेतु अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्य कराये गये ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में पीपल्दा, मांगरोल व दीगोद तहसीलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक मिनी ट्राइबल ब्लाक बनाया गया है, जिसमें मांगरोल तहसील के 21 व पीपल्दा तहसील के 27 व दीगोद तहसील के 9 ग्राम शामिल है।

इस पूरे लघु खण्ड के लिये 1978-79 में 0.44 लाख व 1979-80 में 3.04 लाख रुपये लघु कृषक विकास अभिकरण कोटा को दिये गये है। प्रस्ताव पंचायत समिति द्वारा नहीं भेजे गये थे। लघु कृषक विकास अभिकरण, कोटा से राशि के उपयोग हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हुये है, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) लघु कृषक विकास अभिकरण, कोटा से उपरोक्त राशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे :—

1-पेय जल कूप निर्माण
2-हैण्ड पम्प निर्माण
3-सर्जिकल कैम्प
4-पशुपालन कैम्प
5-तालाबों की मरम्मत
6-एनीकट
7-डिस्पेन्सरी निर्माण
8-छात्रावासों का निर्माण
9-शिक्षा प्रोत्साहन

(3) इनमें से पेयजल कूप निर्माण, हैण्ड पम्प निर्माण एवं शिक्षा प्रोत्साहन प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं शेष राशि के उपयोग हेतु भारत सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार के प्रस्ताव भिजवायें जिनसे इन क्षेत्रों के रहने वाले जनजाति के लोग व्यक्तिगत रूप से एवं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हों। सर्जिकल कैम्प एवं पशुपालन कैम्प के प्रस्तावों पर मदवार खर्च का तखमीना प्राप्त होना शेष है।

पीपल्दा के इटावा पंचायत समिति के ग्राम नारायणपुरा में अधूरे कुएं को पूर्ण कराने हेतु 11,000/-रुपये एवं पंचायत समिति अन्ता के ग्राम चैनपुरिया (तहसील मांगरोल) में नवीन कूप निर्माण हेतु 11,000/-रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। कार्य पंचायत समितियों द्वारा कराये जा रहे हैं।

इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रोत्साहन के अन्तर्गत जनजाति के निम्न कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को निशुल्क पोशाक एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | छात्राए | कक्षा एक से पांचवीं तक |
| 2. | छात्र | कक्षा एक व दूसरी |
| 3. | छात्र | कक्षा 3 से 5 वीं तक-यह सुविधा केवल अन्त्योदय परिवार के बच्चों को ही उपलब्ध कराई जाती है। |

## वर्ष 1979–80 के लघु कृषक विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण

| लघु खण्ड का नाम | पंचायत समिति | प्रस्ताव | ग्राम का नाम | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पीपल्दा–मांगरोल–दीगोद | इटावा | 1– पेयजल कूप निर्माण | 1–मेंदी (166) | 11000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 2–खोरडा (162) | 15000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 3–झाड़ोल (177) | 15000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 4–किशनवास (169) | 25000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 5–मनावता (196) | 5000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 6–कँवलदा (220) | 10000 |
| | | पेयजल कूप निर्माण | 7–भोटीली (218) | 5000 |
| | | हैण्ड पम्प निर्माण | 1–मुमेनी (172) | 15000 |
| | | सर्जिकल कम्प | | 5000 |
| | | पशु पालन कम्प | | |
| | | तालाब मरम्मत | 1–बाणदा (175) | 6000 |
| | | तालाब मरम्मत | 2–नारायणपुरा (169) | 5000 |
| | | | | 132000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | अन्ता | पेय जल कूप निर्माण | 1–ककाखोडी (8) | 10000 |
| | | | 2–बलधन (9) | 10000 |
| | | | 3–खेडीपुरिया (31) | 10000 |
| | | एनीकट निर्माण | 1–घूमरखोडी (7) | 25000 |
| | | डिस्पेन्सरी | 1- जोरदा (47) | 20000 |
| | | पशु पालन केन्द्र | | 5000 |
| | | छात्रावास | 1–तिसाया (34) | 40000 |
| | | शिक्षा प्रोत्साहन (पीपल्दा–मांगरोल–दीगोद) | | 31350 |
| | | | | 151350 |
| | | | | 283350 |

वर्ष 1978–79 में लघु कृषक विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति का विवरण

| क्र. सं. | लघु खण्ड का नाम | पंचायत समिति | प्राप्त प्रस्ताव | ग्राम का नाम | राशि | राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटावा | इटावा | शिक्षा प्रोत्साहन | | 14,010\|– | प्रस्तावानुसार | राज्य सरकार के पत्र क्र0 एफ 1(75)टी एडी/78–79 दिनांक 12–7–79 एवं सम संख्यक पत्र दिनांक 28–7–79 द्वारा स्वीकृति दी गई। |
| 2 | अन्ता | अन्ता | शिक्षा प्रोत्साहन | | 8,130\|– | प्रस्तावानुसार | राज्य सरकार के पत्र क. एफ 1(75) टी एडी/78-89 एव समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 1(75) टीएडी/78–79 दिनांक 12–7–79 द्वारा स्वीकृति दी गई। |
| 3 | इटावा | इटावा | अपूर्ण कूप को पूर्ण कराना | नारायणपुरा | 11,000\|– | प्रस्तावानुसार | राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्र0 एफ 1 जे(9) टीएडी/79-80 दिनांक 14-12-79 |
| 4 | अन्ता | अन्ता | नवीन कूप निर्माण | चैनपुरिया | 11,000\|– | प्रस्तावानुसार | राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क. एफ 1 जे(9)टीएडी/79–80 दिनांक 14 12-79. |

**पंचायत समिति टोंक के गांवों का विद्युतीकरण**

**413. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति टोंक के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) इस कार्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत क्या सरकार ने कोई प्रस्ताव बनाया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोंक के 63 गांवों का विद्युतीकरण माह मार्च, 1980 के अन्त तक हो चुका है।

(2) जी नहीं। इस पंचायत समिति की अन्य कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राज्य-सरकार के समक्ष अभी विचाराधीन नहीं है।

**भादरा तहसील के उपनिवेशन क्षेत्र के ग्रामीण काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देना**

**414. श्री ज्ञानसिंह (भादरा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भादरा तहसील के उपनिवेशन क्षेत्र से 30 गांव आउट ऑफ फ्लो लाइन थे ? क्या उपरोक्त गांवों में से 7 गांवों के काश्तकारों को आउट ऑफ फ्लो लाईन घोषित कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कार्य शुरू है ?

(2) क्या भादरा तहसील के 23 गांव जो आउट ऑफ फ्लो लाइन हैं उनको अभी तक बाहर घोषित नहीं किया गया है ?

(3) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक कर इन ग्रामों के कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

(3) इन 23 गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित किये जाने के उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

**डिग्गी-मालपुरा-टोड़ाभीम—केकड़ी मार्ग पर नई बसों का परिचालन**

**415. श्री रामकंवार बैरवा (फागी):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्ष में निगम द्वारा कितनी बसें खरीदी गई थीं और वे कौन-कौन से मार्ग पर लगाई गयी थीं ?

(2) क्या यह सही है डिग्गी, मालपुरा, टोडारायसिंह, केकड़ी में पुरानी बसेज चल रही हैं ? यदि हां, तो किस कारण से और कब तक नई बसें इस मार्ग पर लगा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा वर्ष 79-80 की अवधि में 170 वाहनें खरीदी गई थी। वाहन आगारवार आवंटित की जाती हैं मार्गवार नहीं की जाती है। वाहनों को आगारवार आवंटन की सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। मार्ग की दूरी कम होने से नई वाहनें लगाया जाना अनार्थिक है।

229

अप्रेल 1979 से मार्च 1980 तक

| क्रम संख्या | आगार का नाम | नई वाहनें आवंटित की गई |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 1 |
| 2. | द्रुतगामी | 17 |
| 3. | कोटा | 2 |
| 4. | झालावाड़ | 4 |
| 5. | बून्दी | 2 |
| 6 | टोंक | 1 |
| 7. | अलवर | 4 |
| 8 | भरतपुर | 2 |
| 9. | सीकर | 7 |
| 10. | झुन्झुनू | 6 |
| 11. | खेतड़ी | 2 |
| 12 | बीकानेर | 2 |
| 13. | हनुमानगढ़ | 11 |
| 14. | गंगानगर | 7 |
| 15. | सरदारशहर | 1 |
| 16. | अजमेर | 7 |
| 17. | नागौर | 19 |
| 18. | ब्यावर | 12 |
| 19 | भीलवाड़ा | 7 |
| 20 | जोधपुर | 8 |
| 21. | बाड़मेर | 4 |
| 22. | सिरोही | 6 |
| 23. | आबूरोड | 7 |
| 24. | जालोर | 5 |
| 25. | फलोदी | 2 |
| 26. | उदयपुर | 15 |
| 27. | डूंगरपुर | 5 |
| 28. | बांसवाड़ा | 2 |
| 29. | चित्तौड़ | 2 |
| | | 170 |

230



## भटिण्डा बांध का निर्माण

416. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिंचाई विभाग जोधपुर के अन्तर्गत रेडिया नदी पर ग्राम भटिण्डा बांध का सर्वेक्षण हुआ था ? यदि हां, तो इस व्यय की अनुमानित राशि कितनी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध पर व्यय की प्रावैधिक स्वीकृति भी मिल गई थी और इस बांध के टेण्डर्स भी विभाग द्वारा आमंत्रित कर लिये गये थे ?

(3) ऐसी स्थिति में भी इस बांध का तत्कालीन सरकार द्वारा निर्माण नहीं कराने के क्या कारण थे और अब सरकार क्या विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी हां।

इस बांध के निर्माण की अनुमानित लागत 17.92 लाख रुपये थी।

(2) जी हां।

तथा निविदा भी विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी।

(3) रेडिया नदी का पानी खारा होने एवं ग्रामवासियों के बांध के निर्माण हेतु विचार आपस में नहीं मिलने के कारण बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। पानी के खारेपन (सैलीनिटी) की जांच, कृषि विभाग द्वारा कराई गई थी, उनकी राय के अनुसार इस भूमि पर बांध बनाना लाभप्रद नहीं था। अन्य काश्तकारों ने इस विषय में आक्षेप किया कि कृषि विभाग द्वारा (सोलह सरवे) इसके सेम्पल का एनेलेसिस किया गया। वह सही नहीं किया गया। अतः उपरोक्त जलाशय में जो नाले आ रहे हैं उनके पानी का परीक्षण सिंचाई विभाग की अनुसंधान शाला जयपुर में करवाया गया है, गत वर्ष 1979 मानसून के समय नालों के पानी का परीक्षण किया गया। परीक्षण कि रिपोर्ट आने के उपरान्त ही यदि यह योजना लाभप्रद होगी तो राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना क्रियान्वित की जावेगी।

## तहसील लाडनूं के समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल सुलभ कराना

417. श्री रामधन (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील लाडनूं जिला नागौर के कितने गांवों में पेयजल सुलभ है ? जहां पेयजल सुलभ नहीं है उनके लिए क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

### उत्तर

लाडनूं तहसील जिला नागौर में मार्च 1980 तक 50 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान में विस्तार जल प्रदाय योजना मीठड़ी-फिरवासी में लाडनूं तहसील के ग्राम इन्द्रपुरा व जैसलान की स्वीकृति दी गई है जिसमें एक ग्राम को इस वर्ष में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 80-81 के लिये क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तंवरा, रोड़, कुणलपुरा जिसमें 10 ग्राम है, का चयन

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

किया गया है जिस पर चालू वित्तीय वर्ष में कार्य चालू करने का प्रस्ताव है।

तहसील के शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

**जिला चित्तौड़गढ़ में डोराई बांध योजना**

418. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू तहसील में डोराई बांध की योजना कब बनी थी तथा इस योजना पर अनुमानित कितना व्यय होना था? इस योजना पर सरकार अब तक कितना व्यय कर चुकी है?

(2) इस योजना पर कब से कार्य बन्द है व किस कारण एवं इस योजना पर कब से पुनः कार्य शुरू होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) यह योजना 1970 में बनी थी। इस पर अनुमानित व्यय 17.78 लाख रुपये होने का अनुमान था। इस पर अब तक 3.37 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(2) इस योजना का कार्य सन् 1970-71 से ही बन्द है कृषकों द्वारा मुआवजा सम्बन्धी विवाद उप खण्ड अधिकारी बेगू के न्यायालय में ले जाने के कारण बन्द करना पड़ा। मुआवजा सम्बन्धी विवाद के फैसला होने के बाद ही बजट आवंटन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

**ग्राम बरनाला में नायब तहसीलदार का हैडक्वार्टर स्थापित करना**

419. **श्री कुन्जीलाल (बामनवास):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में नायब तहसीलदार हैडक्वार्टर बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम बरनाला तहसील बामनवास में नायब तहसीलदार के मुख्यालय कायम करने का निर्णय नहीं लिया गया। जब निर्णय ही नहीं लिया गया तो क्रियान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## परिशिष्ट 3

### अतारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची

### टोंक जिले के स्वीकृत ग्रामों की सूची

| क्र. सं. 1 | गांव का नाम 2 | योजना 3 |
|---|---|---|
| 1 | साली लखनपुरा | बैंक योजना मालपुरा, प्रथम |
| 2 | टान्टीया | ,, |
| 3 | कनतोली | ,, |
| 4 | घाटी | ,, |
| 5 | निबूकिया | ,, |
| 6 | डूंगरी कलां | ,, |
| 7 | करीला | ,, |
| 8 | जानकीपुरा | ,, |
| 9 | गुरोदैयापुरा | ,, |
| 10 | किमान्डा | ,, |
| 11 | घासीपुरा | ,, |
| 12 | आमली पुरोहितान | ,, |
| 13 | श्रीगोपालपुरा | ,, |
| 14 | मालूनी | ,, |
| 15 | खेरा मालूका नगर | ,, |
| 16 | डूंगरी खुर्द | ,, |
| 17 | भावालपुर | ,, |
| 18 | केरवालिया | ,, |
| 19 | तिलान्जू | ,, |
| 20 | बिजलाल नगर | ,, |
| 21 | हाथजी | ,, |
| 22 | रामपुरा बास गवंर | ,, |
| 23 | राजपुरा | ,, |
| 24 | गंवार | ,, |
| 25 | गोविन्दपुरा उर्फ केरिया | ,, |
| 26 | लांबा हरिसिंह | ,, |
| 27 | बागरी | ,, |
| 28 | रामपुरा बास बावरी | ,, |
| 29 | दराबात | बैंक योजना मालपुरा प्रथम |
| 30 | सोतवारा | ,, |
| 31 | कचोलिया | ,, |
| 32 | गनेशपुरा | ,, |
| 33 | बड़ागांव उर्फ जरखिया | ,, |
| 34 | मोरला | ,, |
| 35 | कुहार | ,, |
| 36 | धारी | ,, |
| 37 | लारी | ,, |
| 38 | भाटोली | ,, |
| 39 | भाडूया | ,, |
| 40 | गुल गांव | ,, |
| 41 | आमली चरनान | ,, |
| 42 | डीलेरा | ,, |
| 43 | बुधा डेकल | ,, |
| 44 | महादेवपुरा | ,, |
| 45 | अपठनीय | ,, |
| 46 | हिन्डोली | ,, |
| 47 | लामया जूनरदार | ,, |
| 48 | फूलमालिया | ,, |
| 49 | झारली | ,, |
| 50 | अरण्या रामसिंह | ,, |
| 51 | सनोदिया | ,, |
| 52 | पचेवर | बैंक योजना मालपुरा द्वितीय |
| 53 | बरोल | ,, |
| 54 | स्याह | ,, |
| 55 | बापडून्डा | ,, |
| 56 | सांस | ,, |
| 57 | बनेड़िया चरनान | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58 | मिलकपुर | बैंक योजना मालपुरा द्वितीय |
| 59 | बक्षेरा | ,, |
| 60 | रथाला | ,, |
| 61 | कुम्हारिया | ,, |
| 62 | कुरड | ,, |
| 63 | नगर | ,, |
| 64 | मांग्रोगढ़ | ,, |
| 65 | देघानी | ,, |
| 66 | अबोरा | ,, |
| 67 | पारली | ,, |
| 68 | अजनरी | ,, |
| 69 | डोरिया | ,, |
| 70 | दुन्डारा | ,, |
| 71 | चकनगर | ,, |
| 72 | सीतापुर | ,, |
| 73 | देशमा | ,, |
| 74 | पीन्नी लक्ष्मीपुरा | ,, |
| 75 | देशमली | ,, |
| 76 | धोला का खेड़ा | ,, |
| 77 | आमली सूक | ,, |
| 78 | छवराना | ,, |
| 79 | जगसिंहपुरा | ,, |
| 80 | सीतारामपुरा | ,, |
| 81 | बम्बोरी | ,, |
| 82 | प्रतापपुरा | ,, |
| 83 | अजमेरी | ,, |
| 84 | हरनोदा | ,, |
| 85 | श्रीरामपुरा उर्फ हरनोदा | ,, |
| 86 | चोसला | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 87 | चैनपुरा | बैंक योजना मालपुरा द्वितीय |
| 88 | गरभेरा | ,, |
| 89 | देहवांस | ,, |
| 90 | करथल | ,, |
| 91 | पीपलिया | ,, |
| 92 | चतरन्दिया | ,, |
| 93 | द्वारकापुरा उर्फ बुदी | ,, |
| 94 | अरन्या बरसी | ,, |
| 95 | किरावाल | ,, |

**बैंक की योजना मालपुरा प्रथम एवं द्वितीय**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 96 | भगवानपुरा |
| 97 | कुटका |
| 98 | महाराजपुरा |
| 99 | देवलिया पट्टी गुजरान |
| 100 | देवलिया पट्टी जाटान |
| 101 | सांदरपुरा |
| 102 | श्योपुरा |
| 103 | हीर गनवाड |
| 104 | बड दोराई |
| 105 | आसन जोगियान |
| 106 | शंकरपुरा |
| 107 | सुदा दियारी |
| 108 | बाड गोविन्दपुरा उर्फ किरिया |
| 109 | सवाई मानसिंहपुरा |
| 110 | खेरा कुम्भलाऊ |
| 111 | माधोनगर |
| 112 | बाढ अजमेरी |
| 113 | पंचाना (आर.ई. प्रोग्राम) |

# परिशिष्ट 4

## अतारांकित प्रश्न संख्या 360 का विवरण

### जे.के.समूह द्वारा उत्पादनों का विवरण

(मात्रा टन में)

| वर्ष | नायलोन फिलामेंट | पोलियस्टर फिलामेंट | नायलोन टायर यार्न/फेबरिक | पोलियस्टर स्टेपल फाईबर | एक्रेलिक फाईबर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962-63 | 254-0 | – | – | – | – |
| 1963-64 | 346-0 | – | – | – | – |
| 1964-65 | 390-4 | – | – | – | – |
| 1965-66 | 627-2 | – | – | – | – |
| 1966-67 | 908-1 | 0·4 | – | – | – |
| 1967-68 | 1379-9 | 12-1 | – | – | – |
| 1968-69 | 2676-6 | 21-8 | – | – | 10-0 |
| 1969-70 | 3152-5 | 156-8 | – | – | 85-0 |
| 1970-71 | 5137-6 | 401-0 | 29-8 | – | 206 0 |
| (18 महीने) | | | | | |
| 1972 | 3609-8 | 543-8 | 380-4 | 890-0 | – |
| 1973 | 2783-0 | 763-9 | 660-7 | 962-0 | – |
| 1974 | 2782-0 | 597-3 | 860-5 | 596-0 | – |
| 1975 | 2543-7 | 694-6 | 1654-0 | 1096 0 | – |
| 1976 | 4067-9 | 812-3 | 1740-3 | 1342-9 | – |
| 1977 | 4139-8 | 968-9 | 1901-3 | 2584-5 | – |
| 1978 | 4552-5 | 1004-8 | 2154-7 | 3958-7 | – |
| 1979 | 4752-7 | 1182-0 | 2169-5 | 4343-9 | 6-0 |

# परिशिष्ट 5

## अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची

तहसील झालरापाटन (जिला झालावाड़) में अनुसूचित जाति के लोगों की खेतीबाड़ी पर बड़े लोगों द्वारा किये गये कब्जे की सूची

| क्र. सं. | नाम व्यक्ति व ग्राम जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया | नाम अतिक्रमी व ग्राम | अतिक्रमित रकबा बीघा/बिस्वा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री किशनलाल पुत्र हरिराम यादव झालावाड़ (तहसील पाटन) | श्री भावसिंह पुत्र हेमा बन्जारा साकिन वृन्दावन (तहसील झालरापाटन) | 13 बीघा 15 बिस्वा | धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश झालावाड़ में विचाराधीन है । |
| 2 | श्री नारायण पुत्र भवाना बैरवा झालरापाटन (तहसील पाटन) | श्री रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ झालरापाटन | 4 बीघा 12 बिस्वा | यह प्रकरण राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा इसके स्थगन आदेश हैं । |

235